राष्ट्रीय संस्करण

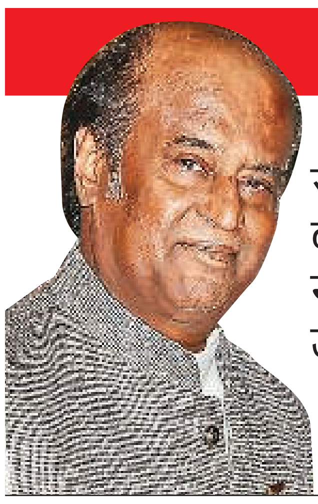

सीएए से मुस्लिमों को कोई खतरा नहीं, एनपीआर बेहद जरूरी : रजनीकांत

>>6

वर्ष 3 अंक 240

दैनिक जागरण

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, गुरुवार, 6 फरवरी 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 16

भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए बना ट्रस्ट

इंतजार खत्म ▸ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में की 15 सदस्यीय ट्रस्ट के गठन की घोषणा

गृह मंत्रालय ने 100 रुपये में ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराकर एक रुपये में ट्रस्टी को सौंपा

नीलू रंजन/ माला दीक्षित, नई दिल्ली

अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में ट्रस्ट के गठन का एलान किया। 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' के नाम से गठित इस 15 सदस्यीय ट्रस्ट में एक ट्रस्टी अनिवार्य रूप से दलित होगा। ट्रस्ट के डीड में ही इसके नौ सदस्यों के नाम दे दिए गए हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील के. परासरन का नाम सबसे ऊपर है। साथ ही 1989 में राम मंदिर का शिलान्यास करने वाले दलित कामेश्वर चौपाल का भी नाम इसमें शामिल है। सरकार ने मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट को एक रुपये का सांकेतिक अनुदान दिया है।

गृहमंत्रालय के अवर सचिव खेला राम मुर्मू ने बुधवार को 100 रुपये के स्टांप पेपर पर ट्रस्ट को पंजीकृत कराया और फिर उसे एक रुपये में परासरन को स्थानांतरित कर दिया। डीड में साफ कर दिया गया है कि इसके गठन के बाद सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी यानी यह सरकारी दखल से पूरी तरह मुक्त होगा। फिलहाल ट्रस्ट का पता परासरन के ग्रेटर कैलाश पार्ट-एक स्थित आवास को रखा गया है, जिसे बाद में ट्रस्ट स्थानांतरित कर सकता है। ट्रस्ट को राम मंदिर निर्माण और उसके रखरखाव के लिए धन जुटाने और उसके प्रबंधन की पूरी छूट होगी।

ट्रस्ट के सभी सदस्यों का हिंदू धर्मावलंबी होना अनिवार्य बनाया गया है। यह शर्त उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत दो सदस्यों और अयोध्या के जिलाधिकारी के पदेन सदस्य होने पर भी लागू होगा। केंद्र की ओर से ऐसे सदस्य को ट्रस्ट में नियुक्त किया जाएगा, जो आइएएस अधिकारी होगा और संयुक्त सचिव के पद से नीचे के स्तर का नहीं होगा। प्रदेश सरकार भी आइएएस अधिकारी को नियुक्त करेगी, जो सचिव स्तर के नीचे का अधिकारी नहीं होगा। अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट के हिंदू धर्मावलंबी नहीं होने की स्थिति में एडिशनल मजिस्ट्रेट ट्रस्ट में शामिल होंगे।

निर्मोही अखाड़े के महंत दीनेंद्र दास भी ट्रस्ट में : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, निर्मोही अखाड़े के प्रतिनिधि के रूप में महंत दीनेंद्र दास को ट्रस्ट में शामिल किया गया है। परासरन ट्रस्ट में शामिल होने की सहमति पहल ही दे चुके हैं। बाकी के सदस्यों की ओर से शाम तक सहमति आनी थी। सहमति के लिए उन्हें 15 दिन का वक्त दिया गया है।

दो सदस्यों का चयन ट्रस्ट करेगा : दो सदस्यों का चयन ट्रस्ट के मौजूदा सदस्य मतदान के बाद बहुमत के आधार पर करेंगे। इन दोनों सदस्यों के चुनाव में मनोनीत आइएएस अधिकारी और अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट के रूप में पदेन सदस्य भाग नहीं लेंगे। ट्रस्ट का 15वां सदस्य भी पदेन होगा, जो ट्रस्ट द्वारा राम मंदिर कांप्लेक्स के विकास व प्रशासनिक देखरेख के लिए बनने वाली कमेटी का अध्यक्ष होगा।

श्रीराम (विशेष) पेज>>5

- ट्रस्ट के नौ स्थायी और एक दलित समेत सभी सदस्यों का हिंदू होना अनिवार्य
- हिंदू पक्ष के वकील परासरन के ग्रेटर कैलाश पार्ट-एक का घर है ट्रस्ट का वर्तमान पता

दक्षिणी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट-1 के आर-20 स्थित इसी मकान को बनाया गया है नव गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का कार्यालय। जागरण

अयोध्या में मस्जिद के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : लोकसभा में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट के गठन की घोषणा के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने भी बुधवार को मस्जिद के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ भूमि देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। वक्फ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत अयोध्या के ग्राम धन्नीपुर में पांच एकड़ जमीन आवंटित की गई है। यह भूमि लखनऊ-अयोध्या राजमार्ग पर जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर थाना रौनाही के 200 मीटर पीछे है। सोहावल तहसील में पड़ने वाली इस जमीन के आसपास मुस्लिम आबादी है। वक्फ बोर्ड के सीइओ सैयद मो. शोएब ने कहा, प्रदेश सरकार की ओर से भूमि आवंटन का प्रस्ताव आएगा, तब उसे बोर्ड मीटिंग में रखा जाएगा। अगली बोर्ड बैठक 24 फरवरी को प्रस्तावित है।

ट्रस्ट के स्थायी नौ सदस्य

- के. परासरन, सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष का केस लड़ने वाले वकील
- कामेश्वर चौपाल, 1989 में राम मंदिर का शिलान्यास करने वाले दलित सदस्य
- स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज
- जगतगुरु माधवाचार्य स्वामी विश्व प्रसन्नतीर्थ जी महाराज, पीठाधीश्वर, पेजावर मठ, उडुपी, कर्नाटक
- युगपुरुष परमानंद जी महाराज, प्रमुख, अखंड आश्रम, हरिद्वार
- स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज, पुणे। ये महाराष्ट्र के विख्यात आध्यात्मिक गुरु पांडुरंग शास्त्री अठावले के शिष्य हैं
- विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र, अयोध्या के राजपरिवार के वंशज, सदस्य रामायण मेला संरक्षक समिति और प्रख्यात समाजसेवी
- डॉ. अनिल मिश्र, अयोध्या के होम्योपैथिक चिकित्सक
- महंत दिनेंद्र दास, अयोध्या के निर्मोही अखाड़े के प्रतिनिधि

नौ से पहले गठित किया जाना था ट्रस्ट पेज>>6

सरोकार

हिम्मताराम की मेहनत को मिला है पद्मश्री सम्मान

जयपुर : राजस्थान के नागौर जिले के हिम्मताराम भाम्भू 1975 से अब तक साढ़े पांच लाख पौधे रोप चुके हैं। साढ़े तीन लाख पेड़ बन चुके हैं। छह एकड़ में 11 हजार वृक्षों वाला एक जंगल भी इसमें शामिल है। हिम्मताराम की इसी मेहनत को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। (पेज-6)

जागरण विशेष

वायरस और बारूद को दूर से सूंघ लेगी यह कृत्रिम नाक

इंदौर : मानव चेहरे पर प्रत्यारोपित हो सकने वाली ऐसी कृत्रिम नाक (बायोनिक नोज) बना ली गई है, जो प्राकृतिक नाक से कहीं बेहतर है। इसका उपयोग युद्ध और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हो सकेगा। अमेरिका में हुए इस शोध में भारतीय वैज्ञानिक भी शामिल है। (पेज-16)

न्यूज गैलरी

महासमर ▸ पृष्ठ 2

जिन्ना वाली आजादी के साथ हैं राहुल व केजरीवाल : शाह

नई दिल्ली : गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में बुधवार को दिल्ली में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में कई सभाओं को संबोधित किया। शाह ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि दोनों नेता जिन्ना वाली आजादी मांग करने वालों के साथ हैं।

राज-नीति ▸ पृष्ठ 3

भागलपुर, भोपाल समेत पांच ट्रिपल-आइटी भी देंगे डिग्री

नई दिल्ली : भागलपुर, भोपाल सहित देश के पांच और ट्रिपल-आइटी भी अब बाकी ट्रिपल आइटी की तरह बीटेक, एमटेक और पीएचडी की डिग्री दे सकेंगे। पीपीपी मोड पर स्थापित इन संस्थानों को इसके साथ ही राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने की भी मंजूरी मिल गई है।

नेशनल न्यूज ▸ पृष्ठ 6

एनआरसी का सभी धर्मों पर पड़ेगा असर : उद्धव ठाकरे

मुंबई : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उनकी सरकार प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) को राज्य में लागू नहीं होने देगी क्योंकि इसका 'असर सभी धर्मों पर' पड़ेगा।

अंतरराष्ट्रीय ▸ पृष्ठ 13

चीन ने कोरोना से निपटने को वुहान में तैनात की सेना

बीजिंग : चीन ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में सेना तैनात कर दी है। इसी शहर से पूरे चीन समेत दुनिया के करीब 27 देशों में यह रहस्यमय वायरस फैल गया है। इन देशों में भी करीब 230 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। चीन में जान गंवाने वालों की संख्या 500 के करीब पहुंच गई है।

सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट सात वर्षों के शीर्ष पर

नई दिल्ली, प्रेट्र : कारोबारी सुस्ती के शोर के बीच बीते जनवरी में देश के सर्विस सेक्टर की गतिविधियों में जबर्दस्त उछाल देखने को मिला। आइएचएस मार्किट इंडिया के मासिक सर्वे के मुताबिक, जनवरी में सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट सात वर्षों के शीर्ष पर पहुंच गई। नए बिजनेस ऑर्डर में तेजी के चलते सेक्टर में नई नौकरियों का सृजन हुआ। समीक्षाधीन अवधि में आइएचएस मार्किट इंडिया सर्विस बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स 55.5 रहा, जो दिसंबर में 53.3 था।

आइएचएस मार्किट की प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट पॉलियाना डि लीमा ने बताया कि सर्विस सेक्टर ने 2020 की शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन किया है। इस दौरान ज्यादातर नए बिजनेस ऑर्डर घरेलू बाजारों से मिले। चीन, अमेरिका और यूरोप जैसे बाजारों से होने वाली मांग में कमी दर्ज की गई है। लीमा ने बताया कि नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए यह अच्छी खबर है। इससे पहले पेश किए गए सर्वे में समीक्षाधीन अवधि के दौरान मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ में भी उछाल दर्ज किया गया था।

इस बीच कंपोजिट पीएमआइ आउटपुट इंडेक्स में भी वृद्धि देखने को मिली। जनवरी में यह 56.3 रहा, जबकि दिसंबर में यह 53.7 फीसद पर था। कंपोजिट पीएमआइ आउटपुट इंडेक्स मैन्यूफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की सम्मिलित गतिविधियों का सूचक है। ज्ञात हो, यह इंडेक्स 50 से नीचे रहने का अर्थ है कि कारोबारी गतिविधियों में गिरावट हो रही है। 50 से ऊपर रहने का तात्पर्य है कि कारोबारी गतिविधियों में वृद्धि हो रही है।

राष्ट्रपति ने खारिज की अक्षय की दया याचिका

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र और दिल्ली सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट
- हाई कोर्ट ने चारों दोषियों को अलग-अलग फांसी देने से किया इन्कार
- चौथे दोषी पवन की क्यूरेटिव और दया याचिका दाखिल होनी बाकी है

दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म कांड के दोषी अक्षय की दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी है। अब तक चार दोषियों में से तीन मुकेश, विनय और अक्षय की दया याचिका राष्ट्रपति खारिज कर चुके हैं। तीनों के सारे कानूनी विकल्प समाप्त हो चुके हैं। दोषी पवन ने अभी तक न तो सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल की है और न ही राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका। वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद केंद्र और दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के दोषियों का डेथ वारंट निरस्त करने को चुनौती देने वाली केंद्र और दिल्ली सरकार की अर्जी बुधवार को खारिज कर दी।

16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली में चलती बस में पैरामेडिकल की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। छात्रा से इस कदर दरिंदगी हुई थी कि बाद में उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक से मुकेश, विनय, अक्षय व पवन को फांसी की सजा दी गई है। हालांकि दोषी मौत से बचने के लिए देरी से एक-एक कर कानूनी विकल्प अपना रहे हैं। इसी के चलते निचली अदालत ने अक्षय की दया याचिका राष्ट्रपति के समक्ष लंबित होने के कारण गत एक फरवरी को चारों को फांसी देने का डेथ वारंट अगले आदेश तक निरस्त कर दिया था।

केंद्र और दिल्ली सरकार ने निचली अदालत के डेथ वारंट निरस्त करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि दोषी जानबूझकर देरी कर रहे हैं। कानून में कहीं नहीं कहा गया है कि सभी दोषियों को एक साथ फांसी दी जाएगी। ऐसे में जिनके सभी कानूनी विकल्प समाप्त हो चुके हैं उन्हें फांसी दी जा सकती है। हालांकि हाईकोर्ट ने सरकार की दलीलें ठुकराते हुए बुधवार को याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट से खारिज होने के कुछ घंटों के भीतर ही केंद्र और दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।

एक साथ ही होगी निर्भया के दोषियों को फांसी पेज>>7

अक्षय (फाइल फोटो) एपी

गुजरात में तीस बरस के बाद होगी किसी को फांसी

अहमदाबाद : निर्भयाकांड के गुनहगारों की फांसी भले ही कानूनी दावपेच में उलझी हो, लेकिन सूरत की तीन वर्षीय मासूम के गुनहगार अनिल यादव को फांसी देने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य में 30 साल बाद किसी गुनहगार को फांसी दी जाएगी। जल्लाद की व्यवस्था के लिए दिल्ली के तिहाड़ और महाराष्ट्र के यरवदा जेल प्रशासन से संपर्क किया गया है। (पेज-15)

मध्य प्रदेश में 10 गुना महंगा होगा जानकारी पाना

मनोज तिवारी, भोपाल : मध्य प्रदेश में सूचना का अधिकार कानून (आरटीआइ) के तहत जानकारी मांगना दस गुना तक महंगा होने वाला है। राज्य सूचना प्रकोष्ठ ने शुल्क वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया है, जो विधि विभाग को परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है।

राज्य में अभी सूचना का अधिकार कानून (आरटीआइ) के तहत आवेदन करते समय 10 रुपये का शुल्क देना पड़ता है पर आने वाले दिनों में इसके लिए 100 रुपये देना होगा। पहली अपील के लिए अभी 50 रुपये शुल्क लिया जाता था, जो 500 रुपये प्रस्तावित किया जा रहा है। दूसरी अपील के लिए आवेदक को 100 के बजाय 1000 रुपये शुल्क देना पड़ सकता है। हालांकि, मांगी गई जानकारी का प्रति पेज शुल्क दो रुपये ही रखा जाएगा। प्रकोष्ठ के अफसरों ने इस बारे में कहा, दूसरे राज्यों में पहले से अधिक शुल्क है। यह आरोप गलत है कि शुल्क वृद्धि के जरिये आवेदनों की संख्या नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है।

खाली न करें सरकारी बंगले तो सड़क पर रख दें सामान : कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकारी बंगलों पर अवैध कब्जों के मामले पर केंद्र को फटकार, दिया 15 दिन का समय

सरकारी बंगलों पर अवैध कब्जा करने वाले पूर्व सांसद, पूर्व विधायक व नौकरशाहों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने केंद्र को दो हफ्तों के अंदर सरकारी बंगलों को खाली करने और कब्जेदारों से बकाया धनराशि वसूलने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया।

पीठ ने कहा, जिन कब्जेदारों के पास किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल से स्टे नहीं है उन्हें दो हफ्ते में हटाएं और अगर वह खाली न करे तो उनका सामान निकालकर सड़क पर रख दें। याचिका पर अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। न्यायिक अधिकारियों के सरकारी आवास की मांग को लेकर एक अधिवक्ता द्वारा दायर याचिका पर मुख्य पीठ ने कहा, अगर कोई सरकारी बंगले पर अवैध कब्जा कर रहा है तो फिर उसे खाली कराने के लिए आपको पंचवर्षीय योजना नहीं चाहिए। क्या आपने कब्जेदारों को बकाए का नोटिस जारी किया था। 600 आवासों पर अवैध कब्जा है। कुछ तो 1998 से कब्जा जमाए हैं। ऐसे हर व्यक्ति पर लाखों का बकाया है। पीठ ने कहा, आम नागरिक टैक्स जमा कर रहा है और आप वर्षों से कब्जेदारों को मुफ्त आवास, बिजली व पानी मुहैया करा रहे हैं। यह और कुछ नहीं आपकी नाकामी है।

11 पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों और नौकरशाहों का है कब्जा पेज>>3

ऑटो एक्सपो-2020 की रंगारंग शुरुआत

ग्रेटर नोएडा : इंडिया ऑटो एक्सपो के पंद्रहवें संस्करण की बुधवार को ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में रंगारंग शुरुआत हो गई। हालांकि, एक्सपो का औपचारिक उद्घाटन गुरुवार को केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ मोबिलिटी की थीम पर आधारित ऑटो एक्सपो के इस संस्करण के पहले दिन कई नामचीन कंपनियों ने कार, ट्रक व दोपहिया के नए मॉडल को लॉन्च किया। रंगबिरंगी रोशनी व संगीत के बीच नए वाहनों को देखने के लिए लोग दीवाने हो उठे। कई कंपनियों ने ऑटो एक्सपो में भविष्य के वाहनों की झलक (कांसेप्ट) पेश की। ऑटो एक्सपो में 104 कंपनियां शिरकत कर रही हैं। दो दिनों के दौरान 70 नए वाहनों की लॉन्चिंग होगी। (पेज-12)

मानवता की सुरक्षा का जिम्मा हमारा : मोदी

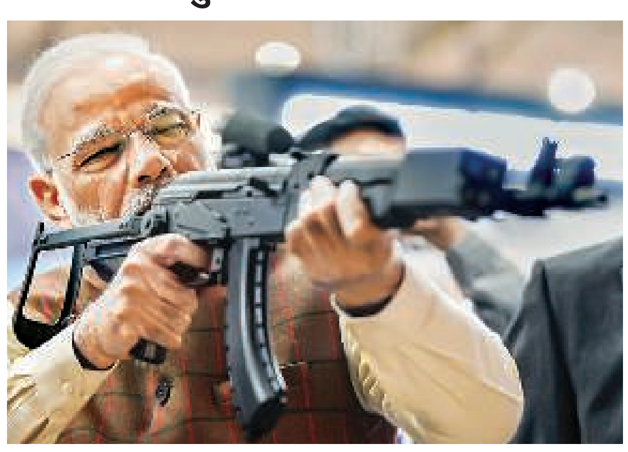

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लखनऊ में 'डिफेंस एक्सपो 2020' का उद्घाटन किया। मोदी ने एशिया में रक्षा उत्पादों की सबसे बड़ी प्रदर्शनी में पहुंचे 40 देशों के रक्षा मंत्रियों, विशेषज्ञों व उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा, 'हमारे ऊपर भारतीय महासागर क्षेत्र के साथ दुनिया के बड़े हिस्से में मानवता को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है। मित्र देशों को सुरक्षा देने का दायित्व भी है। हमारे पड़ोस में ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं जिनसे निपटने के लिए हमेशा तैयार रहने की जरूरत है। पीएम ने प्रदर्शनी में वर्चुअल शूटिंग रेंज में निशाना लगाने का लुत्फ भी उठाया। तस्वीर में मोदी लाइट मशीन गन से निशाना साध रहे हैं। (विस्तृत समाचार पेज-7 पर)। प्रेट्र

श्रीनगर-उड़ी हाईवे पर मुठभेड आइएसजेके के दो आतंकी ढेर

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

- सीआरपीएफ जवान शहीद, जख्मी हालत में एक आतंकी जिंदा पकड़ा

श्रीनगर में बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू-कश्मीर (आइएसजेके) के दो आतंकी जिया और खतीब बुधवार को मुठभेड़ में मारे गए। श्रीनगर-उड़ी राजमार्ग पर हुई इस मुठभेड़ में घायल एक आतंकी को शेर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया है। मुठभेड़ के दौरान बिहार के आरा जिले के निवासी सीआरपीएफ जवान रमेश रंजन शहीद हो गए।

जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह 11:15 बजे नारबल-लावेपोरा में निजी कॉलेज से कुछ दूरी पर सीआरपीएफ व पुलिस जवानों ने संयुक्त नाका लगा रखा था। नाके पर तैनात सीआरपीएफ जवानों ने स्कूटी पर तीन युवकों को बारामुला से श्रीनगर आते देख रुकने का संकेत किया। इस पर पीछे बैठे युवक ने स्कूटी से उतर कर गोली चला दी। इसके बाद भागने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में दो आतंकी मौके पर ही ढेर हो गए। तीसरा गोली लगने के बावजूद भाग निकला। सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी कर घायल आतंकी को परिंपोरा के पास से गिरफ्तार कर लिया। मारे गए आतंकियों की शिनाख्त आरथ वाडवान निवासी जिया और अनंतनाग के खतीब के रूप में हुई है।

डीजीपी ने तीसरे आतंकी की मौत को खारिज किया : सूत्रों के मुताबिक, श्रीनगर के छत्ताबल निवासी उमर फैयाज की मौत हो गई है, लेकिन पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह के मुताबिक उसकी हालत गंभीर है। सिंह ने कहा, खतीब का संबंध आइएसजेके से था जबकि जिया लश्कर का आतंकी था। उमर हिजबुल से जुड़ा था।

अहम सुझाव

संसदीय समिति ने किराए की कोख के लिए नजदीकी रिश्तेदार की शर्त हटाने का दिया मशविरा, कहा, विधवा या तलाकशुदा महिला को भी हो सरोगेसी का लाभ उठाने की अनुमति

अकेली महिला भी बन सकती है सरोगेट मां

नई दिल्ली, प्रेट्र : संसद की एक समिति ने किराए की कोख के मामले मे कई अहम सुझाव दिए हैं, जिसके बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। समिति ने कहा है कि सिर्फ नजदीकी रिश्तेदार ही नहीं, कोई भी महिला अगर चाहती है तो उसे सरोगेट मां बनने की अनुमति दी जा सकती है।

राज्य सभा की 23 सदस्यीय चयन समिति ने सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 में 15 बड़े बदलाव करने के सुझाव दिए हैं। इसमें शादी के बाद पांच साल तक गर्भधारण में असमर्थता को 'बांझपन' बताने वाली परिभाषा को खत्म करना भी शामिल है। समिति ने कहा है कि किसी दंपती के लिए बच्चे के लिए पांच साल का इंतजार बहुत लंबा समय है।

समिति ने कहा है कि नजदीकी रिश्तेदार की शर्त से सरोगेट मां की उपलब्धता की संभावना सीमित हो जाती है, इससे बच्चे की चाह रखने वाले वास्तव में जरूरतमंद लोगों के हित प्रभावित होते हैं। समिति ने 35 से 45 साल की विधवा या तलाकशुदा जैसी एकल भारतीय महिला को भी सरोगेसी का लाभ उठाने की अनुमति देने की वकालत की है।

चयन समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र यादव ने बुधवार को राज्यसभा में यह रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोई भी इच्छुक महिला सरोगेट मां बन सकती है और इस कानून के मुताबिक उसे सरोगेसी की प्रक्रिया से गुजरने की अनुमति होगी। सरोगेट मां के लिए बीमा कवर को प्रस्तावित 16 महीने से बढ़ाकर 36 महीने तक करने का भी सुझाव दिया गया है।

गौरतलब है कि सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 को राज्यसभा की अभी मंजूरी मिलनी बाकी है। राज्यसभा ने इस विधेयक को 21 नवंबर, 2019 को चयन समिति के पास भेजा था, तब से समिति ने 10 बैठकें की थी।

सरोगेसी प्रक्रिया अपनाने के लिए पात्रता के संबंध में भी समिति ने कुछ सुधार के सुझाव दिए हैं। इसमें गर्भधारण में असमर्थता के लिए आवश्यक पांच साल की अवधि के प्रावधान को हटाना शामिल है। समिति ने कहा है कि गर्भधारण में असमर्थता के कई चिकित्सकीय कारण हो सकते हैं, मेडिकल जांच में जिसका पता तुरंत चल सकता है, इसके लिए पांच साल तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है।

समिति ने कहा है, 'ऐसी स्थितियां हैं जिनके तहत किसी एकल व्यक्ति को बच्चे पैदा करने के लिए सरोगेसी विकल्प का लाभ उठाने की आवश्यकता होती है। ऐसी ही एक स्थिति एक युवा विधवा की है, जो बच्चे पैदा करने में सक्षम होने के बावजूद हमारे समाज में विधवा की गर्भावस्था से जुड़े सामाजिक कलंक के डर से बच्चे पैदा नहीं कर सकती है।'

संसदीय समिति ने सरोगेसी बोर्ड से सिफारिशी पत्र लेने के बाद भारतीय मूल के विदेशी नागरिक (पीआइओ) को सरोगेसी का लाभ देने की अनुमति संबधी एक प्रावधान भी विधेयक में जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही समिति ने सरोगेसी के जरिए पैदा होने वाले बच्चे के हित को सुरक्षित रखने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा जारी पितृत्व और बच्चे के अधिकार संबंधी आदेश को सरोगेट बच्चे के जन्म शपथ पत्र के रूप में स्वीकार किए जाने की सिफारिश भी की है।

महिलाओं को बराबरी का प्रयास नहीं करना चाहिए, वे तो पुरुषों से ऊपर हैं : केंद्र

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- लिखित नोट में सेना में महिलाओं की क्षमता पर संदेह जताने के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी सफाई

एक दिन पहले सेना में महिलाओं को कमांडिंग ऑफिसर बनाने के बारे में लिखित नोट दाखिल कर उनकी क्षमता पर संदेह जता चुकी केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सफाई देते हुए कहा, उसका मतलब लैंगिक भेदभाव से नहीं था। महिलाओं को पुरुषों की बराबरी का प्रयास नहीं करना चाहिए क्योंकि वे पुरुषों से ऊपर हैं।

केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस बात से सहमति जताते हुए दो सदस्यीय पीठ की अगुआई कर रहे जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, तो फिर इसे लागू करो। सेना में महिला अफसरों को कमांड दी जा सकती है उसके लिए जरूरी है कि सरकार में प्रशासनिक इच्छा शक्ति हो और वह सोच बदले। कोर्ट ने महिला अफसरों की नियुक्ति में भेदभाव के मसले पर सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रख लिया है। वायुसेना व नौसेना में महिला अफसरों से भेदभाव पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी।

ये टिप्पणियां जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने सेना में महिलाओं से भेदभाव और उन्हें कमांडिंग ऑफिसर नहीं बनाए जाने के मामले पर सुनवाई के दौरान की। मंगलवार को केंद्र की ओर से दिए गए लिखित नोट में महिलाओं की शारीरिक क्षमता और पारिवारिक जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए उनके कमांड करने की क्षमता पर संदेह जताया गया था। उसमें यह भी कहा गया था कि पुरुष महिला कमांडिंग अधिकारी को स्वीकार करने को लेकर सहज नहीं हैं।

बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इससे उनका मतलब लैंगिक भेदभाव से नहीं था। महिलाओं को पुरुषों की बराबरी का प्रयास नहीं करना चाहिए क्योंकि वे पुरुषों से ऊपर हैं। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सरकार इसे लागू करे। समय आ गया है कि सरकार महिलाओं को सेना मे कमांड पोस्ट दे। सरकार ने महिलाओं को कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त करने पर कहा कि सरकार नियुक्ति में महिलाओं की परिवार को लेकर जिम्मेदारियों और उनके युद्ध बंदी बनने के खतरे को भी ध्यान में रखती है। सरकार की दलीलों पर पीठ ने कहा कि अगर सरकार सोच बदलती है तो महिलाओं को सेना में कमांड पोस्ट दी जा सकती हैं।

महिला अफसरों की वकीलों का आरोप, 2006 से हो रहा है भेदभाव पेज>>3

2691 बुजुर्गों व दिव्यांग मतदाताओं ने घर बैठे मताधिकार का इस्तेमाल किया दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए। उन्होंने बैलेट पेपर पर मतदान किया। चुनाव अधिकारियों ने उनके घर जाकर गोपनीय तरीके से मतदान कराया।

न्यूज गैलरी

प्रवेश वर्मा अंतिम दिन नहीं कर पाएंगे चुनाव प्रचार

नई दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर एक टीवी चैनल पर दिए गए बयान पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने भाजपा के स्टार प्रचारक व सांसद प्रवेश वर्मा पर कार्रवाई करते हुए एक बार फिर 24 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया है। इस वजह से वह चुनाव प्रचार के अंतिम दिन किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार नहीं कर पाएंगे। इससे पहले भी चुनाव आयोग ने उन्हें स्टार प्रचारक की सूची से बाहर किया था। उसके बाद उन पर 96 घंटे का प्रतिबंध लगाया गया था। प्रतिबंध की अवधि समाप्त होने के बाद उन्होंने दोबारा प्रचार शुरू किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया। आयोग ने उन पर दोबारा चुनाव प्रचार करने से रोक लगा दी है। (जासं)

विकास के लिए कांग्रेस को दें वोट : शत्रुघ्न सिन्हा

नई दिल्ली : कांग्रेस नेता व फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने वजीरपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हरी किशन जिंदल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने भाजपा और आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली के विकास के लिए सिर्फ कांग्रेस ही है। दिल्ली की बेहतरी के लिए कांग्रेस की सरकार बनाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएए व एनआरसी असली मुद्दों से भटकाने के लिए है। देश की जनता संविधान के साथ है, लेकिन सीएए व एनआरसी के साथ नहीं है। उन्होंने नोटबंदी के फैसले को भी गलत करार दिया और कहा कि इससे बेरोजगारी बढ़ी और छोटे उद्योग-धंधे बंदी के कगार पर पहुंच गए। कई परिवार बिखर गए। लोगों की मेहनत की कमाई एक झटके में बेकार हो गई। हमें वोट देने से पूर्व इन सब बातों को ध्यान रखना होगा। (जासं)

तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर हमला बोला

नई दिल्ली : बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बादली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बजट में बिहार को मोदी सरकार ने सिर्फ ठेंगा दिया है और इसका जवाब उन्हें दिल्ली के चुनाव में मिलेगा। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा सरकार के करीबी दोस्त देश को लूटकर भागना चाहते हैं। आठ फरवरी को दिल्ली में बसे बिहार के लोग भाजपा का निपटारा कर देंगे। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में भी नीतीश और भाजपा की सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। उन्होंने बिहार सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने अब तक यह नहीं बताया कि राज्य में कितने कारखाने व कितनी कंपनियां प्रदेश में खोली गई हैं और कितने युवाओं को रोजगार दिया है? (जासं)

आज शाम थम जाएगा प्रचार, आयोग ने पूरे किए इंतजाम

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के बीच प्रचार के लिए मचा घमासान गुरुवार को थम जाएगा। शाम छह बजे से चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। इसके बाद मतदान खत्म होने तक 48 घंटे कोई भी राजनीतिक दल व उम्मीदवार चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। आठ फरवरी को 2688 मतदान केंद्रों पर सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक मतदान होगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. रणबीर सिंह ने कहा कि जो मतदाता शाम छह बजे तक मतदान केंद्र में प्रवेश कर जाएंगे, वे मतदान कर सकेंगे। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शाहीन बाग के आसपास के मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त अर्धसैनिक बल तैनात रहेंगे।

पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में चार गुना अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बार कुल 2688 मतदान केंद्रों के 13,751 बूथों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं, 516 मतदान केंद्रों के कुल 3841 मतदान बूथ क्रिटिकल (अति संवेदनशील) घोषित किए गए हैं। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद से अब तक हिंसा की नौ घटनाएं हुई हैं। इनमें 13 लोग घायल हुए हैं। हालांकि उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर संतोष जाहिर किया और कहा कि निष्पक्ष, भयमुक्त व शांतिपूर्ण मतदान के लिए पूरी व्यवस्था की गई है।

अर्धसैनिक बलों की 190 कंपनियां तैनात : मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के लिए 42 हजार दिल्ली पुलिस के जवान व 19 हजार होम गार्ड तैनात होंगे। इस बार अर्धसैनिक बलों की 190 कंपनियां बुलाई गई हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 47 कंपनियां तैनात की गई थीं। अर्धसैनिक बलों की इन कंपनियों को फिलहाल शाहीन बाग सहित संवेदशील इलाकों में पेट्रोलिंग के लिए तैनात किया गया है। कुल मिलाकर चुनाव में करीब ढाई लाख कर्मचारी तैनात रहेंगे।

शाहीन बाग में 40 बूथ संवेदनशील : शाहीन बाग के पास पांच मतदान केंद्रों पर 40 बूथ हैं। इन सभी को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। इसलिए इन केंद्रों पर अतिरिक्त अर्धसैनिक बल तैनात रहेंगे।

सर्विलांस रूम से संवेदनशील बूथों पर रखी जाएगी नजर : सभी अति संवेदनशील बूथों पर वेबकास्ट की व्यवस्था होगी। इसके मद्देनजर सीईओ कार्यालय में सर्विलांस रूम बनाया गया है। इस सर्विलांस रूम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अधिकारी शाहीन बाग के मतदान केंद्रों सहित सभी अति संवेदनशील बूथों पर लगतार नजर बनाए रखेंगे।

शाहीन बाग में चुनाव अधिकारियों के लिए रास्ते की दिक्कत नहीं : सीईओ डॉ. रणबीर सिंह ने कहा कि उन्होंने शाहीन बाग इलाके का निरीक्षण किया था। चुनावी ड्यूटी में लगे अधिकारियों व मतदाताओं के मतदान केंद्रों पर पहुंचने के लिए रास्ते की कोई समस्या नहीं है। दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त प्रवीर रंजन ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान पूरी दिल्ली में प्रतिदिन 400-500 कार्यक्रम हुए। बड़ी-बड़ी रैलियां व जनसभाएं हुईं। शाहीन बाग की दो घटनाओं को छोड़कर कहीं कोई घटना नहीं हुई। पुलिस रात के वक्त भी मुस्तैदी से गस्त कर रही है।

सुबह चार बजे से चलेगी मेट्रो : मतदान केंद्रों पर चुनावी ड्यूटी में लगे अधिकारी एक दिन पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन विशेष परिस्थिति में महिला अधिकारियों को इससे राहत देने की व्यवस्था भी है। इसके मद्देनजर सीईओ कार्यालय ने सुबह चार बजे मेट्रो व डीटीसी बसों का परिचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

मतदाताओं से जुड़े आंकड़े

कुल मतदाता	1,47,86,382
पुरुष मतदाता	81,05,236
महिला मतदाता	66,80,277
थर्ड जेंडर	869
सर्विस मतदाता	11,608
नए मतदाता (18 से 19 साल के) जो पहली बार करेंगे मतदान	2,32,815
80 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्ग मतदाता	2,04,830
100 साल से अधिक उम्र वाले मतदाता	147
एनआरआइ मतदाता	498
दिव्यांग मतदाता	50,473
दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर	3875
दिव्यांग मतदाताओं की मदद के लिए नियुक्त वॉलेंटियर	9997

भाजपा सांसद करेंगे झुग्गियों में रात्रि प्रवास

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में भाजपा ने घर-घर जाकर जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। इसमें भाजपा के वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ ही सांसद भी शामिल होंगे। कार्यकर्ता व नेता लोगों के घरों में मतदान पर्ची लेकर जाएंगे और उन्हें भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य बड़े नेता ने बुधवार को भी भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इसके साथ ही पिछले कई दिनों से दिल्ली के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा व उसके सहयोगी पार्टियों के करीब ढाई सौ सांसद चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इन्हें लोगों के घरों में जाने के साथ ही झुग्गियों में रात्रि प्रवास करने को कहा गया है। पार्षदों को भी अपने क्षेत्र और विशेषकर झुग्गियों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है ताकि विरोधी पार्टियों की किसी साजिश को रोका जा सके।

'मोदी व केजरीवाल न सिखाएं देशभक्ति'

वार ▶ राहुल ने महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर भाजपा और आप पर निशाना साधा

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने दोनों ही दलों पर नफरत की राजनीति करने का लगाया आरोप

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर भाजपा और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने दोनों ही दलों पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए, विकास के मुद्दे को भटकाने का भी आरोप लगाया। कहा, मोदी और अरविंद केजरीवाल लोगों को देशभक्ति सिखा रहे हैं। उन्हें हम बताना चाहते हैं कि हर भारतीय देशभक्त है इसलिए वे किसी को देशभक्ति न सिखाएं। इस बीच उन्होंने राजधानी की सफाई और लैंडफिल साइट के मुद्दे पर भी दोनों दलों को निशाने पर लिया। सभा के दौरान मंच से दो बच्चों से सवाल-जवाब भी किए।

राहुल गांधी ने बुधवार को कोंडली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सफाई व्यवस्था बदहाल हो गई है। गाजीपुर लैंडफिल के आसपास मंडराती चील के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि करीब 50 करोड़ रुपये में गाजीपुर की गंदगी साफ हो सकती है। जबकि प्रधानमंत्री ने कुछ दिनों पहले हिंदुस्तान के बड़े लोगों का एक लाख 30 हजार करोड़ रुपये माफ किया है। उन्होंने यहां के लोगों से कहा कि आप गंदे में रहें और वे लोग महलों में हवाई जहाजों में शांति से रहें। इस बीच उन्होंने देश के एक बड़े उद्योगपति को चोर भी कहा।

कल्याणपुरी में आयोजित जनसभा में लोगों का अभिवादन करते कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। उनके बाईं ओर प्रत्याशी अमरीश गौतम और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा। जागरण

राहुल गांधी ने कहा कि देश में जो भाईचारा था, वह खत्म कर दिया गया है। सभी को मालूम है कि देश के मौजूदा हालात कैसे हैं। लोग कहते हैं कि देश का माहौल बिगाड़ने के लिए संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। आज का युवा डरा हुआ है, उसे रास्ता नहीं दिख रहा। पांच वर्षों से युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। युवाओं के गुस्से का प्रधानमंत्री फायदा उठाते हैं। उन्होंने कहा कि चीन की सबसे बड़ी कंपनी में 12 लाख युवा काम करते हैं, जबकि हमारे देश की बड़ी कंपनी में मुश्किल से 12 से 20 हजार लोग काम करते होंगे। अमेरिका और चीन के युवा अपने देश के युवाओं से ज्यादा काबिल, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। राहुल ने कहा कि युवाओं से वह रोज मिलते हैं इसलिए दावे से कह सकते हैं कि अपने देश के युवा सबसे काबिल हैं। बेरोजगारी पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने चुप्पी साध रखी है। ये नफरत की राजनीति करते हैं। यदि ये युवाओं को रोजगार दिलवा दें तो इनकी राजनीति बंद हो जाएगी। दोनों नेताओं ने बोला था कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, जनता ही बताएगी क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया।

सीएए पर भाजपा को घेरा : राहुल ने सीएए पर भी भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने जनता से पूछा कि जिस वक्त लोगों को दूसरी जगह से लाकर कोंडली में बसाया, तब कांग्रेस ने उनकी जाति, धर्म, भाषा, कागजात के बारे में पूछा था क्या, जमीन देते वक्त पंजीकरण शुल्क लिया क्या। कांग्रेस ने कहा था कि आप हिंदुस्तानी हैं, सभी को जमीन मिलेगी। अब ये लोग कौन हैं, जो लोगों को बांट रहे हैं। नया फैशन है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लोगों को देशभक्ति सिखा रहे हैं।

शाहीन बाग पर आप-भाजपा सेंक रहीं सियासी रोटियां : चोपड़ा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने शाहीन बाग के मुद्दे पर भाजपा और आप को घेरा। उनका कहना है कि दोनों ही पार्टियां राजधानी के विकास से जुड़े मुख्य मुद्दों को दरकिनार कर हिंदू-मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने में लगी हुई हैं। उन्होंने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता में कहा कि 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर भाजपा की विचारधारा को मानने वाले जिस गोपाल शर्मा ने जामिया में निहत्थे छात्र पर गोली चला दी थी, उसे दिल्ली पुलिस नाबालिग बता रही है। जबकि अप्रैल 2019 की मतदाता सूची में गोपाल शर्मा नामक युवक वोटर के रूप में रजिस्टर्ड है। वह उत्तर प्रदेश के जेवर विधानसभा क्षेत्र का मतदाता है, जिसका पहचान पत्र नंबर एफ 3264413 है। अगर यह सत्य है, तो कौन सी ताकतें उसको बचाने की कोशिश कर रही हैं, इसकी जांच करके कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

चोपड़ा ने कहा कि शनिवार को कपिल गुर्जर नाम शाहीन बाग में हवा में गोली चलाकर प्रदर्शनकारियों को डराने की कोशिश करता है, जो कि आप का सदस्य है। इसकी ज्वाइनिंग राज्य सभा सदस्य संजय सिंह और कालकाजी से आप उम्मीदवार आतिशी ने कराई। इसलिए पूरे मामले की जांच कराई जाए।

'जिन्ना वाली आजादी के साथ खड़े हैं केजरीवाल और राहुल'

कोंडली विधानसभा के मयूर विहार फेज-तीन में जनसभा के दौरान भारत माता का जयघोष करते गृह मंत्री अमित शाह। उनके दाईं ओर भाजपा प्रत्याशी राजकुमार ढिल्लो। जागरण

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

गृह मंत्री अमित शाह ने कोंडली से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार ढिल्लो, त्रिलोकपुरी से भाजपा प्रत्याशी किरण वैद, कृष्णा नगर से भाजपा प्रत्याशी अनिल गोयल और गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनिल वाजपेयी के समर्थन में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया।

सभा को संबोधित करते हुए शाह ने केजरीवाल पर जमकर हमला बोला और लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि दिल्लीवासियों से मैं अपील करने आया हूं कि 8 फरवरी को जब आप अपने पूरे परिवार के साथ बूथ पर जाएं और कमल के निशान पर बटन दबाएं, तब यह मत सोचिएगा कि आप भाजपा के प्रत्याशी को विजयी बना रहे हैं, बल्कि यह सोचिएगा कि आप दिल्ली और देश के विकास व सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि टुकड़े-टुकड़े गैंग कह रहा है कि मैं शाहीन बाग के साथ हूं। मैं केजरीवाल को बता देना चाहता हूं कि दिल्ली का कोई भी वासी शाहीन बाग के साथ नही हैं, क्योंकि वह राष्ट्रभक्तों की टोली भाजपा के साथ हैं। शाहीन बाग में बैठकर ये लोग जिन्ना वाली आजादी मांग रहे हैं और अरविंद केजरीवाल व राहुल गांधी निर्लज्ज होकर उसका समर्थन कर रहे हैं। शाह ने आगे कहा कि मैं याद दिला दूं कि केजरीवाल और राहुल बाबा वही लोग हैं जो सेना से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे थे। इनको 11 फरवरी के दिन तगड़ा झटका लगने वाला है। केजरीवाल कहते हैं कि मुझसे डिबेट करेंगे। मैं भी उन्हें चुनौती देना चाहता हूं कि वह बताएं कि 2015 से अब तक उन्होंने 50 में से कितने कॉलेज बनाए, उसकी लिस्ट लेकर आ जाएं। अखबार में विज्ञापन देने के लिए पैसे का चेक गौतम गंभीर दे देंगे, वह दिल्ली को बताएं कि उन्होंने कितने कॉलेज बनवाए। दिल्ली की जनता खुद केजीरावल से डिबेट कर लेगी।

क्राइम ब्रांच के डीसीपी को चुनाव कार्य से अलग रखने का निर्देश

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) विरोध में शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन से नाराज होकर गोली चलाने के आरोपित कपिल गुर्जर को आम आदमी पार्टी (आप) का सदस्य बताए जाने के मामले पर चुनाव आयोग ने दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजेश देव पर कार्रवाई की है। आयोग ने पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है कि राजेश देव को दिल्ली विधानसभा चुनाव से संबंधित कोई दायित्व न सौंपा जाए। साथ ही आयोग ने उन्हें चेतावनी पत्र भी जारी करने का निर्देश दिया है। इस चेतावनी पत्र को सीआर डोजियर में संलग्न करने का निर्देश दिया गया है।

आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि डीसीपी ने मीडिया को दिए अपने बयान में कहा था कि आरोपित और उसके पिता ने एक साल पहले एक पार्टी विशेष की सदस्यता ली है। यह बयान तब दिया गया, जब मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में मीडिया को दिया गया उनका बयान अनावश्यक है। इससे चुनाव प्रभावित हो सकता है। आयोग ने छह फरवरी को शाम छह बजे तक कार्रवाई रिपोर्ट भी भेजने का पुलिस को निर्देश दिया है। इस मामले में आप ने चुनाव आयोग में राजेश देव के खिलाफ शिकायत की थी।

कपिल के पिता बोले, बेटा पीएम मोदी और शाह का भक्त

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : कपिल गुर्जर के आम आदमी पार्टी (आप) से जुड़ रहे तार के मामले में नया मोड़ आया है। कपिल के पिता गजे सिंह ने कहा कि आप से उनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन उनका बेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भक्त है। वह उनके विचारों से प्रभावित है। शाहीन बाग में गोली चलाने के आरोपित कपिल गुर्जर को लेकर दिल्ली के चुनाव में घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कपिल के पिता का एक वीडियो ट्वीट कर लिखा कि भाजपा दिल्ली की कानून व्यवस्था और देश की सुरक्षा के साथ गंदी राजनीति और खिलवाड़ कर रही है।

स्वाभिमानी व राष्ट्रभक्त है गुर्जर समाज : नड्डा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का कहना है कि गुर्जर समाज स्वाभिमानी और राष्ट्रभक्त हैं। नई दिल्ली में केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर के बुलावे पर एकत्रित समाज के लोगों को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि इस समाज ने हमेशा अपने भोलेपन और स्वाभिमान को संभाल कर रखा है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी ने सभी जाति धर्म के लोगों को सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के कथन को सार्थक करते हुए सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों देश और समाज सुरक्षित है। भाजपा सरकार बनाएगी तो दिल्ली के गांवों की तस्वीर भी बदलेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली बहुत दिनों से अपने मूल समस्याओं के प्रश्नों से दूर है। इस बार दिल्ली की जनता के पास यह अवसर है कि वो केंद्र और राज्य में एक साथ भाजपा की सरकार देखे। इस मौके पर दिल्ली के 99 गुर्जर बहुल गांवों से आए हुए समाज के प्रमुख लोगों ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आश्वस्त किया कि वे पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का पुरजोर प्रयास करेंगे।

'सीएम चेहरा नहीं है तो शाह से बहस को तैयार'

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

आप के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भाजपा ने अब तक अपना सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया है। इसलिए अब वह गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली के मुद्दों पर बहस की चुनौती देते हैं।

मुख्यमंत्री केजरीवाल दिए गए समय के मुताबिक बुधवार को पार्टी मुख्यालय में मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि जनतंत्र के अंदर जनता को अपना मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार है। लेकिन यह बहुत दुख की बात है कि भाजपा के पास मुख्यमंत्री के लिए कोई चेहरा ही नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि दिल्ली के लोग भाजपा को वोट दें और वह फैसला करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इसलिए मैं अमित शाह को हर मुद्दे पर बहस करने के लिए आमंत्रित करता हूं। वह जहां कहें, जब कहें, मैं दिल्ली की जनता के सामने उनके साथ हर मुद्दे पर बहस करने के लिए तैयार हूं। बहस के बाद जनता खुद तय करेगी कि उनके हितों की रक्षा कौन बेहतर तरीके से कर सकता है।

केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने मंगलवार को भी कहा था कि भाजपा और आप अपना-अपना घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं। अब दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है? भाजपा को इसके लिए 24 घंटे का समय दिया था।

आम आदमी पार्टी कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते अरविंद केजरीवाल। जागरण

- गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली के मुद्दों पर दी बहस की चुनौती
- शाहीन बाग धरने से आसपास के लोग परेशान, शाह क्यों नहीं खुलवा रहे सड़क

अमित शाह अगर अपने मुख्यमंत्री पद के दावेदार का नाम नहीं बताना चाहते, तो संभावित प्रत्याशियों का ही नाम बता दें। क्या विजय गोयल, मनोज तिवारी, डॉ. हर्षवर्धन, स्मृति ईरानी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में हैं। जनता इनमें से किसका चेहरा सामने रखे, जब वह भाजपा को वोट देने जाए।

शाह क्यों नहीं खुलवा रहे शाहीन बाग : अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। वह शाहीन बाग की उस बंद सड़क को क्यों नहीं खुलवा रहे हैं। उन्होंने शाह पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह केवल दिल्ली की सत्ता हथियाने के लिए शाहीन बाग को खाली नहीं करवा रहे हैं। इस प्रदर्शन से वहां रहने वाले लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग यह जानना चाहते हैं कि उन्होंने उनके जैसे सामान्य व्यक्ति को हराने के लिए 200 सांसद, 70 मंत्री और 11 मुख्यमंत्री दिल्ली के चुनाव में क्यों उतारे हैं? इतनी पार्टियों के साथ गठबंधन क्यों किया है? दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल आतंकवादी कैसे है? केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर कहते हैं कि उनके पास इसका सुबूत हैं, यदि सुबूत है, तो जनता के सामने प्रस्तुत कीजिए।

भाजपा नेताओं के हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी

जासं, नई दिल्ली : साकेत कोर्ट ने सीपीआइ नेता वृंदा करात की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से हेट स्पीच मामले में 11 फरवरी तक एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। करात ने कोर्ट से भाजपा नेता अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा पर एफआइआर दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की है। अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी।

करात ने कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा ने बयानों से लोगों को उकसाया है जिसकी वजह से दिल्ली में दो अलग-अलग जगहों पर गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं। कोर्ट ने नई दिल्ली के डीसीपी को मामले में एटीआर दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। करात ने अपनी अपील में दोनों भाजपा नेताओं के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। इसमें दो समुदायों के बीच शत्रुता बढ़ाने और दूसरे समुदाय का अपमान करना शामिल है। करात ने कहा है कि पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी थी। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।

लाइफस्टाइल

शहादरा विस क्षेत्र से आप के प्रत्याशी व दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल की चुनावों के दौरान भी अनुशासित दिनचर्या है

'युवाओं सी स्फूर्ति दे रही है हवाओं में फैली सकारात्मकता'

प्रियंका दुबे मेहता, नई दिल्ली

एक तरफ युवा शक्ति राजनीति को नए आयाम दे रही है, तो दूसरी तरफ उम्रदराज नेता भी अपना दमखम दिखाने में लगे हुए हैं। वे अपनी ऊर्जा से न केवल लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, बल्कि खुद को भी इस रेस में मजबूती से खड़ा कर रहे हैं। ऐसे ही एक नेता हैं दिल्ली के शहादरा विधानसभा क्षेत्र से आप के प्रत्याशी व दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल। उन्होंने अपने आप को चुनावों की चुनौतियों से निपटने के लिए पहले से फिट रखा है और चुनावों के दौरान भी वह अनुशासित दिनचर्या जी रहे हैं।

सैर से रहते हैं फिट : गोयल का कहना है कि उन्हें किसी भी प्रकार की शारीरिक थकान नहीं होती, क्योंकि वह साल भर फिटनेस रूटीन अपनाते हैं। उनकी स्फूर्ति का एक और कारण भी है कि वह एक स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं और टीटी और बैडमिंटन जैसे खेलों से जुड़े रहे हैं। हंसराज कॉलेज की टीम से वह कई यादगार मैच भी खेल चुके हैं। अब भी वह बैडमिंटन नियमित रूप से खेलते हैं और नियमित तौर पर सैर, योग व खेलकूद उन्हें फिट रखने में सहायक है। चुनाव प्रचार में यह सब तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन वह सैर जरूर करते हैं।

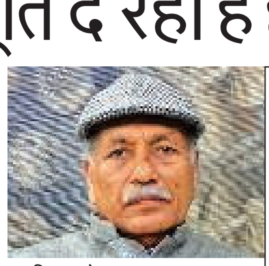
रामनिवास गोयल। सौजन्य : रामनिवास गोयल

डाइट में केवल हल्का भोजन : उनका कहना है कि शारीरिक और मानसिक थकान भले ही उन्हें नहीं होती, लेकिन कई बार बोलने में समस्या जरूरत आती है। इसके लिए वह ज्यादा चिकनाई वाले भोजन से परहेज करते हैं। हल्का भोजन वैसे भी सभी बीमारियों से दूर रखता है। इसके अलावा दिन और रात का भोजन वह लोगों के बीच ही करते हैं।

दिन में आधे घंटे का आराम : लगातार काम करने के बीच गोयल दिन में आधे घंटे का आराम जरूर करते हैं। इसके लिए उन्हें कोई विशेष जगह या एकांत नहीं चाहिए। वह कहीं भी लोगों के बीच आंखें बंद करके आराम कर लेते हैं। उसी में उन्हें ऊर्जा मिल जाती है। रात को देर से सोना और सुबह उठना उनके रूटीन का हिस्सा शुरू से ही है।

कवि भी हैं नेता जी : राम निवास गोयल समाजसेवा से तो जुड़े रहे हैं, लेकिन उनकी रुचि किताबें पढ़ने, बागवानी, कविताएं लिखने में भी है। उनका कहना है कि निराला की कविताएं उन्हें सुकून देती हैं। वह उनके पसंदीदा कवि हैं और लिखने की प्रेरणा भी वहीं से मिलती है। लेखन के लिए किसी विशेष जगह या परिस्थिति की जरूरत नहीं पड़ती। वह प्रेम से लेकर देशभक्ति तक की कविताएं लिखते हैं।

सफारी सूट है पसंदीदा पहनावा : रामनिवास गोयल अपने पहनावे का विशेष ख्याल रखते हैं। उनका कहना है कि सफारी सूट उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है। उनके उनके अधिकतर परिधान सफेद रंग के हैं। सफारी सूट के अलावा विभिन्न अवसरों पर बंद गले के कोट और जैकेट पहनना उन्हें पसंद है।

सकारात्मक माहौल से बढ़ा आत्मविश्वास : गोयल का कहना है कि हवाओं में फैली सकारात्मकता उन्हें थकने नहीं देती और वह निरंतर चलते रहते हैं। सकारात्मक रिस्पांस और युवाओं की ऊर्जा उन्हें पल-पल बेहतर करने की प्रेरणा और उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद बंधाती है।

सोशल मीडिया है वक्त की जरूरत

गोयल सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं। उनका कहना है कि फिलहाल ज्यादा वक्त नहीं मिल पाने के कारण उन्होंने इसका जिम्मा अपने बेटे को दे रखा है। उसमें भी उसे सलाह देना, संदेश पढ़ना और उसका जवाब क्या देना है, इन सभी बातों को तय वह स्वयं करते हैं। उनका कहना है कि सोशल मीडिया हर क्षेत्र के लिए व्यापक मंच साबित हो रहा है।

अंतिम चरण में आप ने चुनाव प्रचार में लगाई पूरी ताकत

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के नेताओं ने अपनी जनसभाओं व नुक्कड़ नाटकों के आयोजन को बढ़ा दिया है। लगातार वह लोगों से संपर्क कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरे हुए हैं।

इन अभियानों में पार्टी की ओर से चलाए जा रहे अभियानों से एक-एक मतदाता तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। आप के वॉलेंटियर मतदाताओं से संपर्क कर पिछली बार की तरह इस बार भी अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाकर राजनीति में परिवर्तन लाने की अपील कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों को आकर्षित करने के लिए चार भागों में बंटकर वॉलेंटियर प्रचार अभियान में जुटे हैं और अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को पार्टी की टोपी भेंट कर चुके हैं।

कैंपेन के कोआर्डिनेटर विकास शुक्ला ने बताया कि चुनाव के आखिरी चरण के प्रचार अभियान में दिल्ली के एक-एक घर तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। हमने प्रचार अभियान को चार भागों में बांटा हुआ है। पहला, नुक्कड़ नाटक की 15 टीमें बनाई गई हैं। प्रत्येक टीम में 10-10 सदस्य हैं। दिल्ली की 70 विधानसभाओं में 1000 से अधिक हॉट स्पॉट चिह्नित किए गए हैं। ये सभी मेट्रो स्टेशनों, बाजारों और कच्ची कॉलोनियों में हैं। यह टीम प्रतिदिन इन जगहों पर जाकर नुक्कड़ नाटक की मदद से लोगों को आप सरकार के कार्यों के बारे में जागरूक कर रही है और लोगों को आप की टोपी भेंट कर रही हैं।

3.5 हजार करोड़ रुपये पिछले दो वर्षों में राज्यों के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत जारी किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने यह जानकारी दी है।

11 पूर्व सांसदों, अधिकारियों व नौकरशाहों का है कब्जा

प्रथम पृष्ठ से आगे

पीठ ने यह आपत्ति केंद्र सरकार द्वारा दाखिल उस शपथ पत्र पर की, जिसमें बताया गया कि वर्तमान में सरकारी बंगलों में कब्जा करने वाले 11 पूर्व सांसद हैं और इन पर 35 लाख रुपये का बकाया है। साथ ही 565 सरकारी आवास ऐसे हैं जिनमें सेवानिवृत्त अधिकारी अवैध तरीके से रह रहे हैं। शपथ पत्र में बताया गया कि कब्जा करने वालों में पूर्व भाजपा सांसद एवं अब कांग्रेस नेता डॉ. उदित राज, पूर्व भाजपा सांसद मनोहर उत्वाल, टीडीपी सांसद मुरली मोहन मोगंती का भी नाम है। मंत्रालय ने पीठ को बताया कि आठ पूर्व सांसदों ने आवास खाली किया, लेकिन उनके नाम की जानकारी नहीं है। टाइप-2 के 565 आवासों में से 244 में सेवानिवृत्त अधिकारियों का कब्जा है।

सचिव पर लगाया 10 हजार का जुर्माना : सुनवाई के दौरान सांसदों और अवैध कब्जेदारों को बकाया का नोटिस भेजने के संबंध में जानकारी नहीं होने पर पीठ ने आवासीय मंत्रालय के सचिव पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया। पीठ ने इसके साथ ही बंगलों में अवैध कब्जेदारों के संबंध में जानकारी नहीं होने पर अदालत में मौजूद अधिकारी का एक दिन का वेतन काटने का भी आदेश दिया।

महिला अफसरों की वकीलों का आरोप, 2006 से ही हो रहा है भेदभाव

प्रथम पृष्ठ से आगे

महिला सैन्य अधिकारियों की वकील मीनाक्षी लेखी व ऐश्वर्या भाटी ने भेदभाव का आरोप लगाया और कहा कि ये भेदभाव तो शुरुआत से 2006 से है जब शॉर्ट सर्विस कमीशन शुरू किया गया था। तभी रक्षा मंत्रालय की ओर से पेश वकील आर. बालासुब्रमण्यम ने कहा कि नियुक्ति प्रोन्नति आदि किसी भी नियम में किसी भी स्तर पर महिला और पुरुष के साथ भेदभाव नहीं किया गया है, दोनों पर समान नियम लागू होते हैं। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि किसी भी तरह का भेदभाव खत्म करने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, प्रशासनिक इच्छा शक्ति और सोच में बदलाव। इस मामले में केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने महिला अधिकारियों की याचिका स्वीकार करते हुए सरकार को उन्हें कमांडिंग पोस्ट देने का आदेश दिया था।

न्यूज गैलरी

लोस उपाध्यक्ष पद रिक्त रहने पर सरकार पर बरसी तृणमूल

नई दिल्ली : तृणमूल कांग्रेस ने मौजूदा लोकसभा की अब तक 62 बैठकें होने के बावजूद उपाध्यक्ष पद अब तक रिक्त रखने पर सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यह उसके संदिग्ध आचरण का एक और नमूना है। तृणमूल के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्य सभा में पार्टी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने एक वीडियो में कहा कि 70 साल के संसदीय इतिहास में औसतन 22 बैठकें होते-होते लोकसभा उपाध्यक्ष का चयन हो जाता था। लेकिन इस लोकसभा की अब तक 62 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन उपाध्यक्ष का कहीं अता-पता नहीं है। तृणमूल नेता ने कहा कि संविधान के 93 व 97 अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चयन की व्यवस्था देते हुए सदन की कार्यवाही संचालित करने में इनकी भूमिका स्पष्ट की है। (प्रेट्र)

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अस्पताल से छुट्टी मिली

नई दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद गंगाराम अस्पताल से बुधवार को छुट्टी दे दी गई। उन्हें पेट में संक्रमण के कारण दो फरवरी को भर्ती किया गया था। वह तीन दिन अस्पताल में भर्ती रहीं। अस्पताल का कहना है कि उन्हें आराम है और संक्रमण भी ठीक हो गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पांच फरवरी को सीलमपुर में उनकी चुनावी रैली प्रस्तावित थी, जो रद कर दी गई। (राब्यू)

राज्यसभा में थमा विपक्ष का हंगामा शांतिपूर्ण तरीके से चला सदन

बजट सत्र ▶ सीएए-एनआरसी पर चर्चा को लेकर दो दिनों से नारेबाजी कर रहा था विपक्ष

शिवसेना सांसद ने यूरोपीय संघ के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की उठाई मांग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राज्यसभा में पिछले दो दिनों से चल रहा विपक्ष का हंगामा बुधवार को पूरी तरह से थम गया। सदन का कामकाज पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चला। हालांकि विपक्ष ने इसके संकेत मंगलवार को ही दे दिए थे। उन्होंने अपने विरोध-प्रदर्शन के तरीके को बदलते हुए सिर्फ सत्ता पक्ष के बोलने पर ही नारेबाजी की। राज्यसभा में विपक्ष का यह हंगामा नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) जैसे विषयों पर चर्चा कराने की मांग को लेकर था।

वैसे भी दिल्ली के चुनावों को देखते हुए विपक्ष इस हंगामे को ज्यादा लंबा खींचने के पक्ष में नहीं था क्योंकि उसे सत्ता पक्ष द्वारा इसका फायदा उठाने का खतरा था। बुधवार को हालांकि तृणमूल कांग्रेस जैसे दल इससे पीछे हटने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब उन्हें विपक्ष के दूसरे किसी दल का साथ नहीं मिला तो वह भी चुप रहे।

राज्यसभा में शिवसेना सांसद अनिल देसाई ने सीएए जैसे मुद्दों को लेकर यूरोपीय संघ में लाए गए प्रस्ताव के खिलाफ संसद के दोनों सदनों से एक प्रस्ताव पारित करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ को यह संदेश देना जरूरी है कि कोई भी हमारे आंतरिक मामलों में दखल देगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। सीएए, एनआरसी और एनपीआर हमारे देश के आंतरिक मुद्दे हैं। हम इसे लेकर सहमत और असहमत हो सकते हैं, लेकिन किसी भी बाहरी देश का इनमें दखल देना ठीक नहीं है। शिवसेना सांसद के इस प्रस्ताव का सदन के ज्यादातर सदस्यों ने समर्थन किया। हालांकि सभापति ने कहा कि वह इस पर चर्चा कराना चाहते थे, लेकिन भारत के कड़े विरोध के बाद उन्होंने इस पर चर्चा नहीं कराई।

मोतीलाल वोरा और रेवती रमण की सभापति ने की तारीफ

संसद के बजट सत्र के दौरान बुधवार को राज्यसभा में बोलते कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा। एएनआइ

राज्यसभा में बुधवार को सभापति ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद मोतीलाल वोरा और सपा सांसद रेवती रमण सिंह की जमकर तारीफ की। दरअसल, सभापति ने दोनों ही वरिष्ठ सदस्यों की तारीफ तब की जब दोनों ने ही जनहित से जुड़े अहम विषयों को उठाया। वोरा ने टिकटों की कालाबाजारी का तो रेवती रमण सिंह ने विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के खाली पड़े पदों का मुद्दा उठाया। सभापति ने इन दोनों ही सदस्यों की सक्रियता को देख सदन के बाकी सदस्यों खासकर नए सदस्यों को इनसे सीखने की सलाह दी जो सदन में तैयारी करके नहीं आते। न ही जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं।

'सोशल मीडिया को आधार से लिंक करने का प्रस्ताव नहीं'

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने बुधवार को संसद में साफ किया कि यूजर्स के सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से लिंक करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सोशल मीडिया के जरिये फेक न्यूज और पोर्नोग्राफी का प्रसार रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि पोर्नोग्राफी खास तौर पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी बेहद गंभीर खतरा है और इस पर रोक लगाने के लिए, कदम उठाए जा रहे हैं। रिवेंज पोर्न भी देश में बढ़ रहा है। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सोशल मीडिया से जुड़े मसलों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। इस पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि निश्चित तौर पर सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। फेक न्यूज और पोर्नोग्राफी का प्रसार करने वाली वेबसाइटों को ब्लॉक करने के सवाल पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत की तुलना चीन या मध्य पूर्व से नहीं की जा सकती क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश हैं।

बजट सत्र के दौरान बुधवार को लोकसभा में बोलते केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद। एएनआइ

वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख को सरकार लाएगी योजना

▶ केंद्र सरकार इससे संबंधित नए कार्यक्रम पर कर रही है विचार

▶ एक नए कानून के तहत डे केयर की सुविधा भी देने की तैयारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने संसद में घोषणा की है कि वह वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख के संबंध में एक नई योजना लाएगी। सरकार अपने घर में अकेले रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करने की अनुमति गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को देने पर विचार कर रही है। साथ ही एक नए कानून के तहत डे केयर की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री थावर चंद गहलोत ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि देश में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 10.38 करोड़ वरिष्ठ नागरिक हैं। 2007 के एक कानून के प्रावधान के तहत सभी वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल की जानी चाहिए। लेकिन सरकार इस विषय में एक नया कानून लाना चाहती है ताकि अकेले रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की बेहतर देखभाल की व्यवस्था हो सके। उन्होंने बताया कि हम एक नया कानून बना रहे हैं जिसके तहत अकेले रह रहे वरिष्ठ नागरिकों के लिए डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिक यहां जा सकेंगे और शाम तक वहां अपना समय व्यतीत कर सकेंगे। इन सेंटरों में लाइब्रेरी, कैंटीन और अन्य सुविधाएं होंगी। साथ ही सरकार एक नया कार्यक्रम शुरू करेगी जिसके तहत एनजीओ अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख उनके घर पर ही कर सकेंगे।

राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को उच्च गुणवत्ता के उपकरण दिए जाएंगे जिनकी वारंटी एक साल से अधिक समय के लिए बढ़ाई जा सके। यह उपकरण सात हजार रुपये तक के होंगे जिसमें स्कॉटलैंड की व्हीलचेयर, आर्टीफिशियल हाथ और पैर लगाए जाएंगे।

संसद में भी दिखी दिल्ली विस चुनाव की सरगर्मी

▶ भाजपा ने एक पार्टी विशेष पर लगाया राजनीति के अपराधीकरण का आरोप

▶ कांग्रेस सांसदों ने जताया एतराज, 'जहां झुग्गी वहीं मकान' की भी हुई चर्चा

विजय गोयल

भूपेंद्र यादव

हरदीप सिंह पुरी। फाइल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही बढ़ रही सियासी तल्खी का असर बुधवार को राज्यसभा में भी देखने को मिला। भाजपा ने राजनीति में अपराधीकरण का मुद्दा उठाते हुए चुनाव आयोग से ऐसे दलों की सदस्यता और पार्टी के रजिस्ट्रेशन को निरस्त करने की मांग की। वहीं, इसे लेकर कांग्रेस ने विरोध दर्ज कराया और कहा कि यहां दिल्ली चुनाव का प्रचार न किया जाए।

राज्यसभा में इसकी शुरुआत वैसे तो सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा सांसद विजय गोयल ने ही की। हालांकि सभापति ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। साथ ही उनकी बातों को रिकॉर्ड में नहीं लिया। लेकिन इसके बाद भाजपा सांसद भूपेंद्र यादव ने शून्यकाल में इसे उठाया और कहा कि भयमुक्त चुनाव हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है, लेकिन पिछले तीन दिनों से दिल्ली के एक राजनीतिक दल की ओर से कुछ आशंकाएं व्यक्त की जा रही थीं। वह जब यह बात कर रहे थे तो सभी हतप्रभ थे क्योंकि दिल्ली का चुनाव एकदम शांतिपूर्ण होता है। जबकि उनकी इस आशंका के बाद गोली चलाने की घटना होती है। अब जब पुलिस जो कि चुनाव आयोग के अधीन है, की रिपोर्ट आने के बाद उस दल की ओर से पुलिस अधिकारियों को लीगल नोटिस देने की बात की जा रही है जो कि चुनाव आयोग को सीधे चुनौती देना है।

हालांकि जब यह बोल रहे थे तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया। इसे लेकर दोनों दलों के सांसदों के बीच नोंकझोंक भी हुई।

वहीं, प्रश्नकाल में फिर दिल्ली चुनाव की चर्चा हुई, जब एक सवाल के जवाब में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने बताया कि उन्होंने दिल्ली के लिए 'जहां झुग्गी वहीं मकान' की योजना पर काम शुरू कर दिया है। इस पर कांग्रेस सांसदों ने हो-हल्ला किया।

'चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर तदर्थ समिति की रिपोर्ट पर संसद में चर्चा हो'

नई दिल्ली, प्रेट्र : उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने बुधवार को देश में चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर चिंता जाहिर करते इस संबंध में तदर्थ समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर संसद में चर्चा की उम्मीद जताई।

राज्यसभा के सभापति नायडू ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर उच्च सदन की एक तदर्थ समिति गठित की थी। समिति का उद्देश्य बच्चों का यौन शोषण रोकना और सोशल मीडिया पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित सामग्री के प्रसार और पहुंच को रोकना था। नायडू ने मीडिया से बातचीत में कहा, 'मैं चाहता हूं कि संसद चाइल्ड पोर्नोग्राफी की रिपोर्ट पर जल्द से जल्द चर्चा करे।' राज्यसभा सदस्य व कांग्रेस नेता जयराम रमेश की नेतृत्व वाली समिति ने 40 सिफारिशें की हैं। रिपोर्ट 25 जनवरी को राज्यसभा के सभापति को सौंपी गई थी।

गौरतलब है कि राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश के नेतृत्व वाली समिति ने इस मामले में कुल 40 सिफारिशें की हैं। यह रिपोर्ट 25 जनवरी को राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को सौंपी गई थी।

इस समिति का मकसद बच्चों का यौन-शोषण रोकने के साथ-साथ सोशल मीडिया पर चाइल्ड-पोर्नोग्राफी रोकने की दिशा में कदम उठाने के लिए, सिफारिश देना था। इसी मुद्दे पर बुधवार को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा कते सभापति एम. वेंकैया नायडू ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस गंभीर मसले पर सदन में चर्चा होगी, ताकि ठोस समाधान की दिशा मे कदम उठाए जा सकें।

कानून का सवाल बड़ी पीठ को भेजने पर विचार आज

सबरीमाला मंदिर का मामला

▶ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी कर सूचित किया था

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय संविधान पीठ गुरुवार को इस बात पर विचार करेगी कि क्या शीर्ष अदालत पुनर्विचार अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए कानून का सवाल बड़ी पीठ को संदर्भित कर सकती है अथवा नहीं। यह सवाल सबरीमाला मामले की सुनवाई के दौरान उठा था जो विभिन्न धार्मिक स्थानों पर महिलाओं के खिलाफ धार्मिक भेदभाव से जुड़ा है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी कर सूचित किया था कि प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय पीठ छह फरवरी को इस बात पर दलीलें सुनेगी कि पुनर्विचार याचिका पर यह अदालत कानून का सवाल बड़ी पीठ को संदर्भित कर सकती है अथवा नहीं। सुप्रीम कोर्ट की इस संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में जस्टिस आर. भानुमति, अशोक भूषण, एल. नागेश्वर राव, एमएम शांतानागौदर, एसए नजीर, आर. सुभाष रेड्डी, बीआर गवई और सूर्य कांत शामिल हैं। गौरतलब है कि इससे पहले शीर्ष अदालत के कई वरिष्ठ वकीलों ने तीन फरवरी को दलील दी थी कि पुनर्विचार अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट को कानून का सवाल बड़ी पीठ को संदर्भित करने का अधिकार नहीं है।

इन वकीलों में फली एस. नरीमन, कपिल सिब्बल, श्याम दीवान, राजीव धवन और राकेश द्विवेदी शामिल हैं। उनका कहना था कि पिछले साल 14 नवंबर को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ 2018 के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका पर फैसला करते समय विस्तृत रूपरेखा संदर्भित करते समय गलत थी। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी उम्र की महिलाओं को केरल के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी थी। पिछले साल के फैसले ने अदालत ने सबरीमाला के अलावा मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद और दरगाह में प्रवेश और गैरपारसी से शादी करने वाली पारसी महिलाओं के पवित्र अग्निस्थल पर जाने पर पाबंदी के मसले का भी जिक्र किया था।

'सबरीमाला मंदिर के आभूषणों की सुरक्षा के उपाय सुझाए केरल'

नई दिल्ली, प्रेट्र : सबरीमाला मंदिर के पवित्र आभूषणों के संरक्षक पंडालम शाही परिवार में आंतरिक कलह और मुकदमेबाजी पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केरल सरकार से आभूषणों की सुरक्षा के उपाय सुझाने को कहा। शीर्ष अदालत ने कहा कि ये आभूषण किसी परिवार के नहीं बल्कि भगवान अयप्पा के हैं। वह विवाद के निपटारे तक आभूषणों को कस्टडी में रखने के लिए किसी जिम्मेदार व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है।

संसद प्रश्नोत्तर

जम्मू-कश्मीर में पीएसए के तहत हिरासत में 389 लोग

▶ सरकार ने राज्यसभा को दी जानकारी

गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी। फाइल

नई दिल्ली, प्रेट्र : जम्मू-कश्मीर में नागरिक सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत फिलहाल 389 लोग हिरासत में हैं। गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने बुधवार को राज्यसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी मामलों की एक-एक कर समीक्षा की जा रही है और एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर हिरासत अवधि बढ़ाने या छोड़ने का निर्णय लिया जा रहा है।

गृह राज्यमंत्री के अनुसार अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पीएसए के तहत 444 लोगों को हिरासत में लिया गया। एक सवाल के लिखित जवाब में रेड्डी ने कहा, पीएसए के तहत फिलहाल 389 लोगों को हिरासत में रखा गया है।

जम्मू-कश्मीर व सीएए के बारे में अंतरराष्ट्रीय समुदाय को बताया गया : जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के बारे में सरकार ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को जानकारी दी है। विभिन्न देशों ने इन मुद्दों पर भारत की स्थिति को समझा है। लोकसभा में बुधवार को एक लिखित जवाब में विदेश राज्यमंत्री वी. मुरलीधरन ने बताया कि भारत की कोशिशों के बाद कई देशों ने पाकिस्तान से उसकी धरती का इस्तेमाल किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधि के लिए न होने देने को कहा है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और सीएए की जरूरत के बारे में तथ्यों के साथ अवगत कराया गया है। मुरलीधरन ने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार मामलों के कमिश्नर की सीएए को लेकर की गई टिप्पणी के लिए आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि कमिश्नर की टिप्पणी अनुपयुक्त और अवांछित थी।

पिछले पांच वर्षों में 233 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा : पिछले पांच वर्षों में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में कम से कम 233 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें सबसे ज्यादा असम और झारखंड में 37-37 मामले दर्ज किए गए हैं। इसी अवधि में हरियाणा में 29 मामले दर्ज किए गए। रेड्डी ने राज्यसभा में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के हवाले से बताया कि वर्ष 2018 में 70, 2017 में 51, 2016 में 35, 2015 में 30 और 2014 में 47 लोगों पर देशद्रोह के मुकदमे दर्ज किए गए।

संसद में गूंजा गुदड़ी हत्याकांड का मामला

राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड के पश्चिम सिंहभूम के गुदड़ी प्रखंड के बुरुगुलीकेरा गांव में सात पत्थलगड़ी विरोधियों की हत्या का मामला बुधवार को संसद में गूंजा। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इसे सदन में उठाया। इससे पूर्व राज्य के भाजपा सांसदों ने संसद भवन परिसर में घटना के विरोध में धरना दिया और झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गांधी प्रतिमा के समक्ष धरना दे रहे सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। भाजपा सांसदों ने इस दौरान 'आदिवासियों की हत्या करना बंद करो, यूपीए सरकार शर्म करो-शर्म करो' के नारे लगाए। वहीं, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस प्रकरण को लेकर झारखंड सरकार को घेरा। कहा, नक्सलवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस व झामुमो की सरकार को बर्खास्त किया जाए।

मारे गए आदिवासियों के लिए न्याय की मांग। प्रेट्र

भागलपुर, भोपाल सहित अब पांच ट्रिपल आइटी भी दे सकेंगे डिग्री

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : भागलपुर, भोपाल सहित देश के पांच और ट्रिपल-आइटी भी अब बाकी ट्रिपल आइटी की तरह बीटेक, एमटेक और पीएचडी की डिग्री दे सकेंगे। सार्वजनिक-निजी साझेदारी यानी पीपीपी मोड पर स्थापित इन संस्थानों को इसके साथ ही राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने की भी मंजूरी मिल गई है। गौरतलब है कि मौजूदा समय में वैसे तो देश में कुल 20 ट्रिपल आइटी है, लेकिन इनमें से सिर्फ 15 संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिला था। साथ ही इन्हें ही डिग्री देने का भी अधिकार था।

प्रधानमंत्री मोदी की अगुआई में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ट्रिपल आइटी के कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इससे जुड़ा बिल अब संसद में पेश होगा, जहां से पारित होने के बाद बाकी के पांच ट्रिपल आइटी भी राष्ट्रीय महत्व के घोषित हो जाएंगे। फिलहाल जिन पांच ट्रिपल आइटी को इसमें शामिल करने की मंजूरी दी गई है, उनमें भागलपुर, भोपाल के साथ सूरत, अगरतला और रायचूर (कर्नाटक) शामिल हैं। संसद से इससे जुड़ा बिल पारित होने के बाद देश के सभी 20 ट्रिपल आइटी राष्ट्रीय महत्व के घोषित हो जाएंगे। इन पांच संस्थानों में से भागलपुर, भोपाल और सूरत स्थित ट्रिपल आइटी का संचालन 2017-18 से किया जा रहा है, जबकि अगरतला स्थित ट्रिपल आइटी का संचालन वर्ष 2018-19 से और रायचूर (कर्नाटक) स्थित संस्थान का संचालन 2019-20 से शुरू हुआ है। अब इन्हें भी राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया जाएगा, जिससे संबंधित बिल को संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा।

जेल सुधार

जेलों में सुधार के लिए दो हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट देगा आदेश, जिससे देश की 1,341 जेलों की दशा में सुधार आएगा

जेलों में कैदियों की भीड़ के लिए अदालतें भी जिम्मेदार

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेलों में कैदियों की ज्यादा भीड़ होना अदालतों की कार्यप्रणाली से जुड़ा मामला है। वह जल्द ही इस मामले में दिशानिर्देश जारी करेगा जिससे देश की 1,341 जेलों की दशा में सुधार आएगा। इन जेलों में 3.83 लाख सजायाफ्ता या विचाराधीन कैदी रखने की क्षमता है लेकिन इनमें मौजूदा समय में 4.68 लाख कैदी रह रहे हैं। शीर्ष अदालत ने जेलों में अराजकता की स्थिति पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही है।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, दिशानिर्देश में जेल स्टाफ की कमी को खत्म करने के लिए भी सरकार को निर्देश होगा। जेलों में स्वीकृत कर्मियों की संख्या से 30 से 40 प्रतिशत कम कर्मी कार्यरत हैं। इसका भी जेल से व्यवस्थाओं पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। जेल में कैदियों की ज्यादा संख्या की समस्या सीधे तौर पर अदालतों के कामकाज से जुड़ी है, इसलिए उसमें सुधार के लिए कदम उठाए जाएंगे।

पीठ ने केंद्र सरकार के प्रतिनिधि एडीशनल सॉलिसिटर जनरल एएनएस नाडकर्णी से पूछा कि जेलों में खाली पदों को अविलंब भरने के लिए वह किस संस्था को सीधे निर्देश दें। यह कार्य सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अमित्व रॉय की अध्यक्षता वाली कारागार सुधार समिति की देखरेख में पूरा हो। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की भागीदारी वाली पीठ ने कहा, जेलों में कैदियों की ज्यादा संख्या और कर्मचारियों के खाली स्थानों को भरने के संबंध में वह दो सप्ताह बाद आदेश जारी करेगी। ये कार्य समयबद्ध होंगे और इन्हें पूरा न करने पर जिम्मेदार लोग अवमानना के दोषी होंगे। जेलों की खराब दशा पर 2013 में लिखे गए एक पत्र पर स्वतः संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है। पत्र में देश की जेलों में कैदियों की अमानवीय दशा की ओर शीर्ष न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया गया था।

देश में पुलिस सुधार की प्रक्रिया की जाएगी तेज

▶ समितियों की सिफारिशों में से केंद्र ने 49 का किया चयन

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र ने पुलिस सुधार के लिए की गई विभिन्न समितियों की 49 सिफारिशों का चयन किया है। इन्हें अमल में लाने के लिए राज्यों के गृह मंत्रियों की एक बैठक शीघ्र होने जा रही है। केंद्र ने राज्यसभा को बुधवार को यह जानकारी दी।

प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक सवाल के जवाब में गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा, पुलिस को प्रभावी व पारदर्शी बनाने के लिए समय-समय पर चार समितियां गठित की गई हैं। इनकी सिफारिशों में से 49 को चुना गया है। इन सिफारिशों के क्रियान्वयन पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि हाल में होने वाली राज्यों के गृहमंत्रियों की बैठक में इन चयनित सिफारिशों को अमल में लाने के साथ-साथ दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) व भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) में संशोधन पर विचार किया जाएगा। गृह राज्यमंत्री रेड्डी ने कहा कि देश में नई पुलिस प्रणाली लाई जाएगी। पुलिसकर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है।

उन्होंने सदन को बताया कि सभी राज्यों के पुलिस विभाग में पुलिसकर्मियों के कुल 25,95,435 पद हैं। इनमें से 5,28,165 पद खाली हैं। पिछले एक साल में लगभग एक लाख पदों पर भर्ती की गई है। केंद्रीय गृहराज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि पुलिस राज्य का विषय है। प्राथमिक तौर पर यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह पुलिस को प्रभावी और पारदर्शी बनाए। केंद्र सरकार राज्यों के इस प्रयास में मदद करती है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

1404 लोगों पर एक डॉक्टर है देश में। आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक डॉक्टरों को मिलाएं तो 848 लोगों पर एक डॉक्टर है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 6 फरवरी 2020

शाह रुख की कंपनी ने ईडी की कार्रवाई के बाद दी सफाई

जागरण संवाददाता, कोलकाता

बहुचर्चित रोजवैली चिटफंड घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से अभिनेता शाह रुख खान की कंपनी कोलकाता नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (केआरएसपीएल) पर भी कार्रवाई किए जाने पर सफाई दी गई है। शाह रुख खान के स्वामित्व वाली आइपीएल फ्रेंचाइची केकेआर का कहना है कि रोजवैली के साथ जर्सी के अलावा और कोई डील नहीं थी।

गौरतलब है कि ईडी ने केआरएसपीएल समेत तीन कंपनियों की 70 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की थी। जब्त संपत्ति में केआरएसपीएल की 11.87 करोड़ रुपये की बैंक में जमा राशि भी शामिल है। हालांकि, केकेआर ने साथ ही उम्मीद जताई है कि ईडी द्वारा इस मामले को तेजी से हल किया जाएगा। केकेआर के

केकेआर ने कहा–रोजवैली से जर्सी के अलावा और कोई डील नहीं थी

सीइओ वेंकी मैसून ने बुधवार को बयान में कहा, 'रोजवैली होटल्स 2012 और 2013 में आइपीएल की जर्सी का प्रायोजक था। 11.87 करोड़ रुपये प्रायोजन फीस है। इसके अलावा केकेआर का रोजवैली समूह से कोई वित्तीय लेनदेन नहीं हुआ है।'

उल्लेखनीय है कि केआरएसपीएल के निदेशकों में शाह रुख खान की पत्नी गौरी खान, बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला, उनके पति जय मेहता और केकेआर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वेंकी मैसूर शामिल हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक, रोजवैली ग्रुप के बैंक खातों से केआरएसपीएल को भुगतान किया गया था। ईडी ने केआरएसपीएल के अलावा कोलकाता स्थित सेंट जेवियर्स कॉलेज और मल्टीपल रिजाट्र्स के बैंक खाते सीज किए गए हैं।

बजट से पहले राजभवन से रिश्ते सुधारने में जुटी बंगाल सरकार

जागरण संवाददाता, कोलकाता

बीते साल 30 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने जब बंगाल के राज्यपाल के तौर पर शपथ ली थी तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके बीच काफी सद्भाव नजर आया था, लेकिन चंद महीने बाद ही दोनों आमने-सामने आने लगे। वर्तमान परिस्थितियां भी इससे अधिक जुदा नहीं हैं। अलबत्ता, सात फरवरी से बंगाल विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। 10 फरवरी को बंगाल का बजट पेश होना है। ऐसे में केरल से सबक लेते हुए जहां बंगाल सरकार राजभवन के साथ रिश्ते सुधारने में जुट गई है, वहीं राज्यपाल ने सरकार के अभिभाषण पर आपत्ति जाहिर करते हुए इसमें बदलाव की बात कहकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। तीन दिन में मंत्री से लेकर मुख्य सचिव तक राजभवन पहुंचे हैं।

मंत्री से लेकर मुख्य सचिव तक पहुंच रहे हैं राजभवन

ममता बनर्जी फाइल

राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने की अभिभाषण में बदलाव की बात

जगदीप धनखड़ फाइल

राजभवन सूत्रों की मानें तो राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बजट सत्र की शुरुआत में होने वाले अपने अभिभाषण में बदलाव की मांग की है। राज्यपाल का जो भाषण होना है उसकी कॉपी राजभवन में भेज दी गई थी। राज्यपाल ने उसे पढ़ा है और उसमें कई बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज कराई है। उसमें से कुछ मुद्दे केंद्र सरकार के विरोध में हैं, जबकि कुछ राज्य सरकार के वे दावे हैं, जिनका तथ्यात्मक प्रमाण नहीं है। राज्यपाल ने इनको बदलने की बात कही है।

केरल से लिया सबक : नियमानुसार बजट सत्र के अभिभाषण के दौरान राज्यपाल राज्य सरकार द्वारा लिखे गए भाषण को पढ़ते हैं। इसमें सरकार अपनी उपलब्धियों को रेखांकित करती है। हाल ही में केरल विधानसभा में जब वहां के राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान ने अभिभाषण पाठ किया था तो उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों संबंधी दावे पर विधानसभा में ही आपत्ति दर्ज कराई थी और कह दिया था कि मुख्यमंत्री चाहते हैं, इसलिए वह पढ़ रहे हैं। इससे वह सहमत नहीं हैं। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि बंगाल विधानसभा में भी अभिभाषण के दौरान राज्यपाल जगदीप धनखड़ इसी तरह से कुछ कह सकते हैं। गौरतलब है कि पहले ही बंगाल विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो चुका है, जबकि राज्यपाल खुलकर सीएए का समर्थन करते रहे हैं।

डैमेज कंट्रोल में जुटे राज्य सरकार के प्रतिनिधि

डैमेज कंट्रोल के लिए तीन दिनों से राज्य सरकार के प्रतिनिधि लगातार राजभवन पहुंच रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और संसदीय कार्यमंत्री पार्थ चटर्जी रविवार को राजभवन पहुंचे थे। इसके अगले दिन सोमवार को पार्थ के साथ वित्त मंत्री अमित मित्रा राजभवन पहुंचे। सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्ष में बजट पर राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर तकरीबन डेढ़ घंटे तक चर्चा हुई। इसके बाद मंगलवार शाम मुख्य सचिव राजीव सिन्हा दो घंटे तक राजभवन में ही रहे। और तो और बीरभूम जा रहे राज्यपाल को इस बार राज्य सरकार ने हेलीकॉप्टर भी मुहैया करा दिया है, जबकि पहले ऐसा करने से इन्कार करती रही है।

न्यूज गैलरी

एचआइसी में एम्स रायपुर को प्रथम पुरस्कार

रायपुर : रायपुर एम्स को हाईजीन एंड इंफेक्शन कंट्रोल (एचआइसी) चैंपियनशिप-2020 के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार पुडुचेरी में आयोजित कार्यक्रम में दिया गया। संक्रमण नियंत्रित करने के लिए सबसे बेहतर व्यवस्था को लेकर देशभर के अस्पतालों में एम्स, रायपुर सबसे आगे रहा। इसके अलावा भी अन्य कई व्यवस्थाएं एम्स रायपुर में बेहतर दिखीं, जिन पर पुरस्कार दिया गया है। दूसरा पुरस्कार महाराष्ट्र के महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वर्धा, तीसरा पटना एम्स को मिला है। गौरतलब है कि 31 जनवरी और एक फरवरी को केंद्र की कायाकल्प की टीम ने एम्स का दौरा किया था। देश के सभी एम्स को रैंकिंग के आधार पर पुरस्कार दिया जाता है। (नईदुनिया)

खनिज रायल्टी बढ़ाने के लिए छग के सीएम ने लिखा पत्र

रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय कोयला खान मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखकर एमएमडीआर एक्ट 1957 के तहत मुख्य खनिजों की रायल्टी दरों को तीन वर्ष की अवधि के बाद संशोधित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि तीन वर्ष के बाद खनिज की रायल्टी दरों में वृद्धि नहीं होने से छत्तीसगढ़ को खनिज राजस्व की हानि हो रही है। इससे राज्य द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन के लिए वित्तीय प्रबंधन में कठिनाई आ रही है। (नईदुनिया)

41 हजार टैब से हटेंगे रघुवर के वीडियो, खर्च होंगे 20 करोड़

बदलाव ▸ झारखंड के शिक्षा मंत्री ने टैब से वीडियो हटाने का दिया आदेश

13 हजार रुपये में खरीदे गए टैब, हटाने पर खर्च होंगे चार हजार से अधिक

राज्य ब्यूरो, रांची

झारखंड के सरकारी स्कूलों को दिए गए 41 हजार टैब से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के वीडियो हटाए जाएंगे। प्रदेश के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगरनाथ महतो ने सभी टैब से पूर्व मुख्यमंत्री का वीडियो हटाने का आदेश दिया। विभाग ने उनकी स्वीकृति के बाद इससे संबंधित फाइल मुख्य सचिव को भेज दी है।

बताया जाता है कि निर्माण के समय में ही वीडियो शामिल किए जाने के कारण उक्त वीडियो हटाने में प्रति टैब चार हजार रुपये से अधिक का खर्च आ सकता है। ऐसे में वीडियो हटाने पर ही 16 करोड़ रुपये से अधिक का बोझ राज्य सरकार पर पड़ सकता है। टैब लगभग 13 हजार रुपये की दर से खरीदे गए थे और अब वीडियो हटाने पर प्रत्येक पर चार हजार रुपये से अधिक खर्च होंगे। टैब स्कूलों से मंगाकर कंपनी को भेजने तथा वापस स्कूलों को भेजने पर जो खर्च आएगा वह अलग है।

सूत्रों की मानें, तो टैब आपूर्ति करने वाली कंपनी से जब वीडियो हटाने को लेकर मंतव्य मांगा गया तो कंपनी ने इसमें बड़ी राशि खर्च होने की बात कही है। हालांकि, यह राशि कितनी होगी यह स्पष्ट नहीं बताया गया है। कंपनी ने इसे टाइम टेकिंग भी बताया है। ऐसे में टैब स्कूलों से वापस मंगाकर कंपनी को भेजने, वहां सभी में वीडियो हटाने तथा वापस मंगाकर दोबारा स्कूलों को भेजने में छह माह से अधिक समय लग सकता है। यदि ऐसा होता है तो इस दौरान ई-विद्यावाहिनी के तहत स्कूलों की रिपोर्टिंग तथा शिक्षकों की उपस्थिति ठप हो जाएगी।

जगरनाथ महतो फाइल

जिम्मेदार पदाधिकारियों पर होगी कार्रवाई : जगरनाथ महतो

मंत्री जगरनाथ महतो ने अपने आदेश में इस पर सवाल उठाया कि कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में हमेशा नहीं रह सकता, ऐसे में मुख्यमंत्री का वीडियो टैब में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा कि जिस पदाधिकारी के लिखित या मौखिक आदेश से ऐसा किया गया तथा जो इसके लिए जिम्मेदार होंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी। मंत्री ने कहा कि उन्होंने स्वयं टैब खोलकर देखा है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नजर आते हैं।

वीडियो हटाने में खराब हो सकते हैं 10 फीसद टैब

बताया जाता है कि कंपनी ने यह भी कहा है कि टैब से वीडियो हटाने के क्रम में बड़ी संख्या में टैब खराब भी हो सकते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे लगभग 10 फीसद टैब खराब हो सकते हैं। ऐसे में सरकार को इतने और टैब खरीदने पर लगभग पांच करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं। इस तरह वीडियो हटाने, परिवहन और नए टैब की खरीद में करीब 20 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। टैब खरीद पर रघुवर सरकार ने करीब 53 करोड़ खर्च किए थे।

पीके की सूची ने बढ़ाया तृणमूल पार्षदों का तनाव

जागरण संवाददाता, कोलकाता : बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले इस वर्ष कोलकाता नगर निगम का चुनाव होना है। इसे लेकर सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस के पार्षद तनाव में हैं। उन्हें तनाव टिकट को लेकर है। इस बार उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं, इसे लेकर पार्षद असमंजस में हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार, इस बार प्रशांत किशोर (पीके) ने कामकाज एवं व्यवहार के आधार पर सत्तारूढ़ दल के पार्षदों की रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही मौजूदा पार्षदों की उम्मीदवारी पुनः तय की जाएगी।

सूत्रों के अनुसार, कई पार्षदों के नाम सूची से गायब हैं। ऐसे में उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। हालांकि, इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन पीके की सूची को लेकर पार्षदों में डर है।

प्रशांत किशोर की सूची की जानकारी के लिए पार्षद पार्टी के नेता एवं सांसदों को बार-बार फोन कर रहे हैं। वे इतनी बार फोन कर रहे हैं कि इससे नेता एवं सांसद भी परेशान हो गए हैं। कई पार्षद तो अपना नाम मालूम करने के लिए काली घाट पहुंच रहे हैं। उम्मीदवारी की सूची में नाम शामिल कराने के कई पार्षद नेताओं, मंत्रियों एवं सांसदों के घर भेटकी, गलदा मछली एवं झींगा लेकर पहुंच रहे हैं।

तृणमूल के एक नेता ने बताया कि पार्षदों को बताया गया है कि किसी की उम्मीदवारी पार्टी प्रमुख ही तय करेंगी। बाकी किसी सूची का कोई अर्थ नहीं है। इसके बाद भी पार्षदों के दिमाग से पीके का भूत नहीं निकल पा रहा है। सूत्रों के अनुसार, निगम चुनाव के पहले पीके द्वारा पार्षदों के कामकाज एवं उनके व्यवहार के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है।

एक हजार करोड़ के घोटाले में सीबीआइ ने दर्ज किया केस

नईदुनिया, बिलासपुर

छत्तीसगढ़ में भाजपा शासनकाल के दौरान समाज कल्याण विभाग के अधीन कागजी संस्था बनाकर किए गए करीब एक हजार करोड़ रुपये के घपले में सीबीआइ ने भोपाल कार्यालय में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमें में किसी को नामजद नहीं किया गया है। ज्यों-ज्यों जांच में आरोपित अधिकारियों की संलिप्तता सामने आएगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसकी जानकारी सीबीआइ ने हाई कोर्ट को दी है। इधर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करने वाले आरोपित अधिकारियों को फौरी तौर पर राहत जरूर मिल गई है।

गौरतलब है कि समाज कल्याण विभाग में संविदा कर्मचारी कुंदन सिंह ने की याचिका पर हाई कोर्ट ने सीबीआइ को सात दिनों में आरोपित अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू करने का निर्देश दिया था। कुंदन ने अपनी याचिका में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मिली सूचनाओं को प्रमुख दस्तावेज के रूप में शामिल किया। बताया कि वर्ष 2004 से 2018 के बीच राज्य निःशक्तजन स्रोत संस्थान फिजिकल रेफरल रिहेब्लिटेशन सेंटर के नाम से कागजी एनजीओ बनाकर सरकारी खजाने से करीब एक हजार करोड़ रुपये का घोटाला तत्कालीन आइएएस व राज्य सेवा संवर्ग के अधिकारियों ने किया है। जनहित याचिका की सुनवाई जस्टिस प्रशांत मिश्रा व जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच में हुई थी। डिवीजन बेंच ने सात आइएएस सहित 12 अधिकारियों के खिलाफ एक सप्ताह के भीतर एफआइआर

हाई कोर्ट ने सीबीआइ को दिया था सात दिन का समय

दर्ज करने का निर्देश सीबीआइ को दिया था। इन अधिकारियों में पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड, रिटायर्ड आइएएस व वर्तमान में सूचना आयुक्त एमके राउत, पूर्व सीएस सुनील कुजूर, बीएल अग्रवाल, आलोक शुक्ला, सतीश पांडेय, अशोक अग्रवाल, एमएल पांडेय, हेरमन खलखो व समाज कल्याण विभाग के संचालक पंकज वर्मा, अशोक तिवारी और पीसी सोठी आरोपित हैं।

नाटकीय घटनाक्रम के तहत बुधवार को राज्य शासन ने घोटाले में फंसे अफसरों के खिलाफ हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए पुनर्विचार याचिका पेश कर दी है। इधर बुधवार को ही जस्टिस प्रशांत मिश्रा व जस्टिस पीपी साहू की स्पेशल डिवीजन बेंच में पूर्व आइएएस अधिकारी बीएल अग्रवाल व राज्य सेवा संवर्ग के अधिकारी सतीश पांडेय की रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई प्रारंभ हुई। याचिकाकर्ता पूर्व आइएएस ने अपनी याचिका में कहा कि जिस वक्त समाज कल्याण विभाग में घोटाला हुआ उस दौरान वे विभाग में कार्यरत नहीं थे। राज्य सेवा संवर्ग के अधिकारी सतीश पांडेय ने भी इस घोटाले से अपनी संलिप्तता होने से साफतौर पर इन्कार किया है। दोनों याचिकाओं पर सुनवाई के बाद स्पेशल डिवीजन बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जबकि राज्य शासन द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को जस्टिस मिश्रा व जस्टिस साहू की स्पेशल डिवीजन बेंच ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। मामले की सुनवाई के लिए सात फरवरी की तिथि तय कर दी है।

भाजपा नेताओं के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत का 11 घंटे तक मंथन

राज्य ब्यूरो, भोपाल

एक सप्ताह के भोपाल प्रवास पर आए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने बुधवार को मध्य प्रदेश भाजपा और एक दर्जन से ज्यादा संघ के अनुषांगिक संगठन के नेताओं के साथ 11 घंटे तक मंथन किया। दो दिवसीय इस बैठक में मप्र के विधानसभा चुनाव में मिली पराजय से लेकर सीएए और राम मंदिर निर्माण को लेकर देश में अनुकूल माहौल बनाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। बैठक का गुरुवार को समापन होगा।

भोपाल के शारदा विहार विद्यालय में मोहन भागवत तीन दिन से रुके हुए हैं। पहले दो दिन जिला प्रचारकों और विभाग प्रचारकों से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का फीडबैक लेने के बाद उन्होंने संगठन के नेताओं के साथ बातचीत की। इस दौरान सीएए को लेकर प्रदेश में जागरूकता का माहौल बनाने से लेकर मोदी सरकार के अहम फैसलों को आम जनता तक पहुंचाने के कदमों पर भी मंथन किया गया। बैठक में सीएए पर प्रदेश में भाजपा और अन्य संगठनों द्वारा किए गए कार्यक्रमों का जिलेवार ब्योरा भी संघ प्रमुख ने लिया। संघ और बाकी संगठनों के बीच समन्वय में आ रही दिक्कतों पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में समाज में ज्वलंत मुद्दों के अलावा सामाजिक समरसता बनी रहे, परिवार को जोड़कर रखने के लिए प्रेरित किया जाए, गोवंश की रक्षा और स्वच्छता अभियान जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। संघ प्रमुख भागवत ने युवाओं और महिलाओं पर विशेष फोकस करने का निर्देश दिया।

कई दिग्गज नेता शामिल हुए : बैठक में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई दिग्गज भाजपा नेता शामिल हुए। इनमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा, संगठन महामंत्री सुहास भगत, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, विधायक दल के मुख्य सचेतक डॉ. नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश महामंत्री अजय प्रताप सिंह, प्रदेश महामंत्री बंशीलाल गुर्जर, राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे शामिल हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली चुनाव में व्यस्त होने से शामिल नहीं हुए। वे गुरुवार को बैठक में शामिल हो सकते हैं।

रात शिविर में ही बिताएंगे नेता: दो दिन तक चलने वाली संघ की समन्वय बैठक में शामिल सारे नेता रात्रि विश्राम भी शारदा विहार विद्यालय में ही करेंगे। बुधवार रात नौ बजे बैठक खत्म होने के बाद सभी ने संघ प्रमुख के साथ भोजन किया। सभी की दिनचर्या गुरुवार सुबह पांच बजे से शुरू हो जाएगी। प्रातः शाखा में शामिल होने के बाद फिर बैठक शुरू होगी। गुरुवार दोपहर को बैठक समाप्त होगी।

राज्य विस चुनाव में मिली पराजय के बाद पहली बार हुई समीक्षा

डॉ. मोहन भागवत फाइल

झारखंड–बिहार सीमा पर तेज होगा नक्सलियों के विरुद्ध अभियान

राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड और बिहार की सीमा पर नक्सलियों के विरुद्ध अभियान तेज होगा। इसमें दोनों राज्यों की पुलिस आपसी समन्वय से अभियान चलाएगी। यह निर्णय बुधवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित इंटर स्टेट पुलिस को-आर्डिनेशन कमेटी की बैठक में लिया गया। इस बैठक में बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय भी मौजूद थे।

इंटर स्टेट पुलिस को-आर्डिनेशन कमेटी की बैठक में सहमति बनी है कि बिहार-झारखंड के सीमावर्ती जिले गिरिडीह-जमुई, चतरा-गया, हजारीबाग-गया, पलामू-औरंगाबाद में संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। इसमें दोनों राज्य अपनी खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे, ताकि कारगर अभियान चलाकर नक्सलियों का सफाया किया जा सके। बैठक में बताया गया कि इसके लिए एक कार्ययोजना तैयार की गई है।

बैठक में पूर्व के अभियानों की समीक्षा भी की गई। दोनों राज्यों के अधिकारियों ने यह स्वीकारा कि उनके आपसी संपर्क और समन्वय का बेहतर असर पड़ा है। आपसी समन्वय से ही बेहतर अभियान चलाया गया है। इससे पूर्व में सफलताएं हाथ लगी हैं। बेहतर परिणाम सामने आए हैं।

लालू से बोल रहा पोस्टर वाला जिन्न अब मैं आपकी बात में आने वाला नहीं

राज्य ब्यूरो, पटना

बिहार में जदयू और राजद के बीच चल रही पोस्टर वार में अब जिन्न भी उतर आया है। अरसे बाद पोस्टर पर हाजिर हुआ जिन्न लालू से कह रहा कि 'अब मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला।' दरअसल, यह जदयू व राजद के बीच चल रहे पोस्टर वार का नया संस्करण है।

इस पोस्टर के निचले हिस्से पर आम लोग बैठे हुए दिख रहे हैं। इनमें से कुछ दुखी और निराश तो कुछ मजाक के मूड में हैं। दुखी आदमी कह रहा है, 'क्या कीजिएगा, जब रखवाले ही चोरी करें और चोरी करके तुमसे ही सीनाजोरी करें, तब क्या कहना?'

पोस्टर के दूसरे हिस्से में इसका जवाब भी दिया गया है। दिखाया गया है कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद, पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन और पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव जेल में बंद हैं। पोस्टर में इसे न्याय का उदाहरण बताया गया है। इसी तरह स्कूलों में दोपहर के भोजन करते बच्चे, परेड करतीं महिला पुलिसकर्मी, स्कूल जातीं बालिकाएं और अस्पताल की खूबसूरत तस्वीर के जरिये राज्य सरकार की उपलब्धियां भी दर्शाई गईं हैं। गौरतलब है कि लालू प्रसाद अति पिछड़ा वर्ग के अपने समर्थकों को जिन्न कहते थे। इनके अपार समर्थन से ही 1995 के विधानसभा चुनाव में तत्कालीन जनता दल को शानदार जीत हासिल हुई थी। उन दिनों हरेक आकलन में लालू की पराजय की आशंका जाहिर की जा रही थी, लेकिन लालू प्रसाद का जवाब होता था, 'इस बार बक्से (बैलेट बॉक्स) से मेरा जिन्न निकलेगा और सबको फेल कर देगा।' लंबे समय से गायब चल रहा यह जिन्न अब पोस्टर पर फिर हाजिर हुआ है।

पहले की तरह ही इस पोस्टर का भी कोई दावेदार नहीं है, लेकिन सरकार की उपलब्धियों की तारीफ से पता चलता है कि इसका ताल्लुक कहीं न कहीं जदयू से है। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार कहते हैं, यह नागरिकों की पहल हो सकती है। जिन लोगों ने लालू प्रसाद के कुशासन को झेला है, यह उनकी पीड़ा की अभिव्यक्ति हो सकती है।

पटना में लगाए गए पोस्टर, जिनमें राजद प्रमुख लालू प्रसाद पर निशाना साधा गया है। जागरण

यू-टर्न

रणजीत चौटाला बोले, जेल में गुरमीत सिंह को नहीं कोई खतरा, जुबान फिसल गई थी, अकाली दल ने भाजपा हाईकमान के पास पहुंचाया मामला तो मंत्री बोले गलती से लिया गया इस दल का नाम

डेरा प्रमुख की सुरक्षा पर बढ़ा विवाद तो बयान से पलटे जेल मंत्री

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित सुनारियां जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की सुरक्षा को लेकर बवाल खड़ा हो गया। जेल में प्राकृतिक खेती की शुरुआत करने पहुंचे जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने जब बयान दिया कि डेरा प्रमुख की जान को बब्बर खालसा और अकाली दल सरीखे संगठनों से खतरा है तो सियासत में भूचाल आ गया।

पंजाब में भाजपा व अकाली दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं। जेल मंत्री रणजीत चौटाला के इस बयान के बाद अकाली दल ने इस मामले को भाजपा हाईकमान के समक्ष पहुंचाया तो पड़ताल शुरू हो गई। भाजपा हाईकमान इस समय दिल्ली विधानसभा के चुनाव में व्यस्त है। दिल्ली में अकाली दल और भाजपा मिलकर चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में भाजपा को लगा कि अगर मामला नहीं सुलझा तो बड़ा नुकसान हो सकता है।

भाजपा हाईकमान के हस्तक्षेप के बाद बुधवार को ही जेल मंत्री रणजीत चौटाला अपने बयान से पलट गए। चौटाला सिरसा जिले की रानियां विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक हैं। भाजपा ने उन्हें अपनी कैबिनेट में जेल व बिजली मंत्री बनाया है। रणजीत चौटाला के बयान को कवर करने के लिए खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल को हस्तक्षेप करना पड़ा।

जेल बदलने की कोई योजना नहीं : जेल मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ने हरियाणा की जेलों को पूरी तरह से सुरक्षित करार देते हुए कहा कि गुरमीत सिंह पूरी तरह से सुरक्षित है और उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। जेल मंत्री ने कहा कि रोहतक में कार्यक्रम के दौरान उनकी जुबान फिसल गई थी और गलती से अकाली दल का नाम लिया गया। अकाली दल कुर्बानियों से पैदा हुई पार्टी है। उन्होंने कहा कि गुरमीत सिंह सुनारियां जेल में पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उनकी जेल बदलने की कोई योजना नहीं है।

रणजीत सिंह चौटाला जागरण

क्या है मामला

गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के सहयोग से बीते दिनों सुनारियां जेल में जीरो बजट खेती कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम में सभी कैदी शामिल हुए, लेकिन गुरमीत सिंह को इससे दूर रखा गया, जिसके बाद जेल मंत्री ने सुरक्षा का हवाला देते हुए कहा था कि गुरमीत सिंह को बब्बर खालसा व अकाली दल से खतरा है। इसी के चलते उसे बाहर नहीं निकाला गया है। जेल मंत्री के इस बयान के बाद अकाली दल आक्रामक हो गया और भाजपा की घेराबंदी शुरू कर दी थी। अकाली नेताओं ने भाजपा हाईकमान पर इस बात के लिए दबाव बनाया कि हरियाणा के जेल मंत्री को यह साफ करना चाहिए कि जेल में बंद गुरमीत सिंह को किस अकाली दल से खतरा है।

हरियाणा में जेलों की सुरक्षा पूरी तरह से मजबूत है। हमारी पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करती है। पड़ोसी राज्यों की जेलों के मुकाबले हरियाणा की जेल पूरी तरह से महफूज हैं। राम रहीम के जेल में रहते समय उनकी जान को खतरे के संबंध में कोई सूचना नहीं है। अन्य कैदियों की तरह ही राम रहीम है। उसे किसी तरह का अलग से ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। जेल मंत्री ने मीडिया में जो बयान दिया, वह उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है।

–मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा

'70 साल में बेरोजगारी सबसे ऊंचे स्तर पर'

नईदुनिया, भोपाल: पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं समाजवादी नेता शरद यादव ने आरोप लगाया है कि पिछले 70 साल में बेरोजगारी सबसे ऊंचे स्तर पर है। फिर भी सदन में रोजगार, उद्योग-धंधों की स्थिति पर बात नहीं होती, बल्कि मजाक उड़ा रहे हैं कि राहुल गांधी फिर पूछेंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी देश ने एक साथ जनता की इतनी संपत्ति पूंजीपतियों को नहीं बेची होंगी। यादव बुधवार को भोपाल में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जीडीपी साढ़े चार फीसद बताई जा रही है, लेकिन मेरे ख्याल से दो फीसद से ज्यादा नहीं है। यह अब तक का सबसे निम्न स्तर है। उन्होंने कहा कि सरकार सड़क, पानी, बिजली, विकास को छोड़कर सारी बातें कर रही है। देश में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इन कमियों को छुपाने और लोगों का ध्यान हटाने के लिए लव जिहाद, गोरक्षा, अनुच्छेद 370, सीएए और एनआरसी लाए गए हैं।

88 दिन लगे सरकार को ट्रस्ट गठित करने में। 27 वर्ष और दो माह बाद तंबू से निकलकर रामलला अब जल्द ही भव्य मंदिर में विराजेंगे। गत नौ नवंबर को रामलला के हक में आए सुप्रीम फैसले से भव्य मंदिर के निर्माण की संभावना प्रशस्त हो गई थी।

॥ श्रीराम ॥

ट्रस्ट की स्वतंत्रता का किया गया है पर्याप्त प्रबंध

नियम कायदे बनाने और वित्तीय मामलों में पूरी छूट, पर ट्रस्ट के मूल ढांचे से छेड़छाड़ का अधिकार नहीं, के. परासरन आजीवन बने रहेंगे ट्रस्ट के सदस्य

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सरकार ने 'श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' ट्रस्ट को सरकारी हस्तक्षेप से दूर रखने और कामकाज में पूरी आजादी देने का पुख्ता बंदोबस्त कर दिया है। ट्रस्ट को सारी वित्तीय स्वायत्तता दी गई है, लेकिन इसकी किसी भी अचल संपत्ति को किसी भी स्थिति में बेचने का अधिकार नहीं होगा। सरकार ने फिलहाल ट्रस्ट के सदस्यों की घोषणा की है। ट्रस्ट के सदस्यों को अपने बीच से अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष के चयन की छूट दी गई है। फंड जुटाकर भव्य राम मंदिर का निर्माण करने से लेकर पूरे तीर्थ के विकास और रखरखाव के प्रशासनिक तंत्र के विकास और पुजारियों की नियुक्ति ट्रस्ट के विशेषाधिकार में रखा गया है। हिंदू पक्ष के वकील के. परासरन ट्रस्ट के आजीवन सदस्य बने रहेंगे।

जगह खाली होने पर ट्रस्टी ही करेंगे नए सदस्य का चुनाव: डीड के अनुसार पदेन व सरकार की ओर से मनोनीत सदस्य के अलावा 10 सदस्यों में से किसी की मौत होने, इस्तीफा देने या किसी कारणवश हटाए जाने के बाद उनके स्थान पर नए सदस्यों के चयन का अधिकार ट्रस्ट के सदस्यों को ही होगा। इसके लिए विशेष बैठक बुलाकर शेष बचे नौ सदस्य बहुमत के आधार योग्य व्यक्ति को सदस्य के रूप में चयन कर सकेंगे। लेकिन नए सदस्य का भी हिंदू धर्मावलंबी होना अनिवार्य है। लेकिन दलित सदस्य का स्थान खाली होने की स्थिति में किसी दलित को ही इसके लिए चयन किया जा सकेगा। वहीं निर्मोही अखाड़ा के प्रतिनिधि की जगह खाली होने पर उसे भरने का विशेष प्रावधान किया गया है। चूंकि निर्मोही अखाड़े के एक प्रतिनिधि का होना सुप्रीम कोर्ट ने फैसले ने अनिवार्य कर दिया है। इसीलिए इसमें उनकी जगह खाली होने की स्थिति में निर्मोही अखाड़े को अपनी ओर से तीन नामों का सुझाव भेजना होगा। ट्रस्ट इनमें से एक को सदस्य के लिए चयन करेगा। इसी तरह केवल छह स्थितियों में किसी सदस्य को ट्रस्ट के बाहर किया जा सकता है। मौत और इस्तीफे के अलावा इसमें किसी सदस्य के पागल, दिवालिया, अपराधी या फिर अयोग्य घोषित होने पर उसकी सदस्यता खत्म की जा सकती है। ट्रस्ट के हित में किसी सदस्य को हटाने का फैसला मतदान द्वारा दो-तिहाई बहुमत के आधार पर होगा। लेकिन के परासरन को हटाने का अधिकार अन्य सदस्यों को नहीं होगा, वे मृत्यु पर्यंत इसके सदस्य रहेंगे।

तीर्थ नगरी के विकास की जिम्मेदारी: ट्रस्ट को अयोध्या को एक तीर्थ नगरी के रूप में विकासित की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक सुविधाओं का भी इंतजाम हो। बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रियों के आवागमन को देखते हुए बड़े पार्किंग स्थल, यात्रियों के रहने-ठहरने के लिए आवासीय परिसर, खाने-पीने के इंतजाम, यात्रियों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम, अयोध्या की परिक्रमा वाले पथ की देखभाल शामिल है। इसके साथ ही ट्रस्ट अयोध्या में भगवान राम से संबंधित प्रदर्शनी और संग्रहालय भी स्थापित करेगी।

नहीं बदला जा सकेगा ट्रस्ट का मूल ढांचा: वैसे सरकार ने ट्रस्ट को अपने क्रियाकलापों और उद्देश्यों को बदलने का पूरा अधिकार दिया है। वे अपने नियम और और कायदे खुद तय करेंगे। लेकिन मंदिर में धार्मिक परंपराओं के पालन और उसके उल्लंघन पर पुजारियों को हटाने का अधिकार भी उनके पास होगा। लेकिन वे ट्रस्ट के सदस्यों की मौजूदा संरचना में कोई बदलाव नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्हें ट्रस्ट के मौलिक ढांचे को बदलने का अधिकार नहीं होगा। डीड में साफ कर दिया गया है कि इसके सदस्य ट्रस्ट से कोई भी वेतन या भत्ते के रूप में कोई आर्थिक लाभ नहीं लेंगे। वह केवल ट्रस्ट के काम के सिलसिले में किए गए सही खर्चे को वापस मांग सकते हैं। इसी तरह ट्रस्ट की बैठक में भाग लेने के सिलसिले में यातायात व्यय को सदस्य वापस मांग सकते हैं। सदस्यों को ट्रस्ट में वित्तीय फैसले लेने की खुली छूट दी गई है। धन जुटाने से लेकर उसके निवेश करने तक वे कोई भी फैसला ले सकते हैं, लेकिन उन्हें ट्रस्ट की अचल संपत्ति को किसी भी स्थिति में बेचने का अधिकार नहीं होगा।

बोर्ड के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर तीन महीने पर ट्रस्ट्र की बैठक होगी, जिनमें कम-से-कम आधे ऐसे सदस्यों का उपस्थित रहना अनिवार्य होगा, जिन्हें मतदान का अधिकार दिया गया है।

25 मार्च

समझा जाता है कि यह प्रक्रिया पूर्ण होने में कुछ दिन लग जाएंगे और मंदिर का शिलान्यास 25 मार्च से शुरू हो रहे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर दो अप्रैल को राम जन्मोत्सव के बीच संभव हो सकता है।

तारीखों के आईने में

1992 **छह दिसंबर**: विवादित ढांचे को ढहाया गया।

1993 **तीन जनवरी**: विवादित स्थल में जमीन अधिग्रहण के लिए केंद्र ने अयोध्या में निश्चित क्षेत्र अधिग्रहण कानून पारित किया।

1994 **24 अक्टूबर**: सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक इस्माइल फारूकी मामले में कहा कि मस्जिद इस्लाम से जुड़ी हुई नहीं है।

2002 **अप्रैल**: हाई कोर्ट में विवादित स्थल के मालिकाना हक को लेकर सुनवाई शुरू।

2003 **13 मार्च**: सुप्रीम कोर्ट ने असलम उर्फ भूरे मामले में कहा, अधिग्रहीत स्थल पर किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं है।

2010 **30 सितंबर**: हाई कोर्ट ने विवादित क्षेत्र को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच तीन हिस्सों में बांटने का आदेश दिया।

2011 **9 मई**: सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद में हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई।

2016 **26 फरवरी**: सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विवादित स्थल पर राममंदिर बनाए जाने की मांग की।

2017 **21 मार्च**: सीजेआइ जेएस खेहर ने संबंधित पक्षों के बीच अदालत के बाहर समाधान का सुझाव दिया।

सात अगस्त: सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यीय पीठ का गठन किया जो 1994 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

आठ अगस्त: उप्र शिया केंद्रीय वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि विवादित स्थल से उचित दूरी पर मुस्लिम बहुल इलाके में मस्जिद बनाई जा सकती है।

11 सितंबर: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिया कि दस दिनों के अंदर दो अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करें, जो विवादित स्थल की यथास्थिति की निगरानी करे।

20 नवंबर: यूपी शिया केंद्रीय वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मंदिर का निर्माण अयोध्या में किया जा सकता है और मस्जिद का लखनऊ में।

2018 **आठ फरवरी**: सिविल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू की।

14 मार्च: सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका सहित सभी अंतरिम याचिकाओं को खारिज किया।

29 अक्टूबर: सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई उचित पीठ के समक्ष जनवरी के पहले हफ्ते में तय की, जो सुनवाई के समय पर निर्णय करेगी।

2019 **आठ जनवरी**: सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने की। इसमें न्यायमूर्ति एसए बोबड़े, न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना, न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ शामिल।

25 जनवरी: सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए पांच सदस्यीय संविधान पीठ का पुनर्गठन किया। नई पीठ में प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एसए नजीर शामिल।

दो अगस्त: सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता नाकाम होने पर छह अगस्त से रोजाना सुनवाई का फैसला किया।

छह अगस्त: सुप्रीम कोर्ट ने रोजाना के आधार पर भूमि विवाद पर सुनवाई शुरू की।

चार अक्टूबर: अदालत ने कहा कि 17 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी कर 17 नवंबर तक फैसला सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा।

16 अक्टूबर: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा।

नौ नवंबर: सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने एकमत से रामलला के हक में फैसला सुनाया।

2020 **पांच फरवरी**: राममंदिर निर्माण के लिए श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन।

ये हैं ट्रस्ट के सदस्य

वकालत के पितामह परासरन

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष के.परासरन ने सुप्रीम कोर्ट में रामलला विराजमान की ओर से पक्ष रखकर इस केस को जिताया था। 92 साल के परासरन को इंडियन बार का पितामह कहा जाता है। पदम भूषण (2003) व पदम विभूषण (2011) से सम्मानित और हिंदू शास्त्रों के अच्छे जानकार परासरन दो बार देश के अटर्नी जनरल रह चुके हैं।

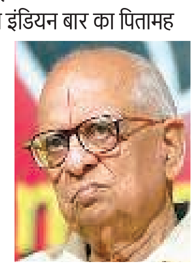

उन्हें बीएल (अब बीए-एलएलबी) के दौरान हिंदू लॉ में गोल्ड मेडल मिला था। 1958 में सुप्रीम कोर्ट में वकालत शुरू की। आपातकाल में तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल व 1980 में देश के सॉलिसिटर जनरल बने।

कामेश्वर चौपाल ने राम मंदिर की रखी थी पहली ईंट

कामेश्वर चौपाल ने 09 नवंबर 1989 को अयोध्या में राममंदिर के लिए पहली ईंट रखी थी। सुपौल जिले के कोसी तटबंध के बीच बसे गांव कमरैल के निवासी चौपाल अब राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य बन गए हैं। जब राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था, उस समय वह विश्व हिन्दू परिषद का सह संगठन मंत्री थे। बिहार के सुदूर ग्रामीण इलाके से आने के बावजूद विहिप के अधिकारियों ने इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उन्हें सौंपी, यह उनके लिए गर्व का क्षण था। चौपाल भाजपा कोटे से 2002 से 2014 तक विधान पार्षद रह चुके हैं। 1991 में रोसड़ा लोकसभा से इन्होंने रामविलास पासवान के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जिसमें पराजित हो गए। 2014 का लोकसभा चुनाव ये अपने गृहक्षेत्र सुपौल से लड़े जहां भी इन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब राम मंदिर बनाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएंगे।

स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज कारसेवा में लिया था बढ़ चढ़कर हिस्सा

ज्योतिषपीठ के स्वामी शांतानंद के शिष्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज का आश्रम प्रयागराज के अलोपीबाग में हैं। 78 वर्षीय स्वामी वासुदेवानंद श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या आंदोलन में शुरू से ही सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। मंदिर आंदोलन के दौरान उन्होंने कारसेवा में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। ज्योतिषपीठ बद्रिकाश्रम को लेकर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से विवाद है, मामला हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीमकोर्ट में है। स्वामी वासुदेवानंद उप्र के जौनपुर जिले के बदलापुर तहसील क्षेत्र के मूल निवासी हैं। सन्यास से पहले उनका नाम सोमनाथ द्विवेदी था।

बिमलेंद्र मोहन कहे जाते हैं अयोध्या के राजा

अयोध्या राजपरिवार के मुखिया बिमलेंद्र मोहन मिश्र (64) को आध्यात्मिक-सांस्कृतिक संस्कार विरासत में मिले हैं और वह अपनी सरलता-शालीनता के लिए जाने जाते हैं। उनका यह मिजाज ताजा जिम्मेदारी मिलने के मौके पर भी परिलक्षित हुआ। ट्रस्ट में शामिल किए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह के प्रति आभार जताया। कहा कि मैं भाग्यवान हूं, जो अयोध्या में पैदा हुआ। रामलला की सेवा का जो अवसर मिला है, उसे पूरी निष्ठा से निभाऊंगा।

धन्नीपुर में सुन्नी वक्फ बोर्ड को भूमि

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट के गठन का एलान करने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने भी बुधवार को सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ भूमि देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। सुन्नी वक्फ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत अयोध्या के ग्राम धन्नीपुर में पांच एकड़ जमीन आवंटित की गई है। यह भूमि लखनऊ-अयोध्या राजमार्ग पर जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर थाना रौनाही के 200 मीटर पीछे है। सोहावल तहसील में पड़ने वाली इस जमीन के आसपास मुस्लिम आबादी है।

प्रदेश सरकार ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में पांच एकड़ जमीन देने के लिए तीन स्थानों का चयन किया था। यह तीनों विकल्प सहमति के लिए केंद्र सरकार को भेजे गए थे। केंद्र से सहमति मिलने के बाद योगी कैबिनेट ने बुधवार को रौनाही की जमीन पर मुहर लगा दी। प्रदेश सरकार इस जमीन को हर लिहाज से उपयुक्त मान रही है। आवागमन के लिए सड़क मार्ग, जन सुविधाओं के साथ सांप्रदायिक सौहार्द व कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी इसे उचित स्थान माना जा रहा है।दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ भूमि आवंटित करने का फैसला किया था। इसके लिए तीन माह की समय सीमा दी थी। यह समय सीमा नौ फरवरी को पूरी हो रही है। इससे पहले ही योगी सरकार ने बुधवार को पांच एकड़ भूमि सुन्नी वक्फ बोर्ड के नाम आवंटित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी।

अहम स्थान

- केंद्र की सहमति मिलने के साथ ही योगी कैबिनेट ने लगाई मुहर
- जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर है यह भूमि

सुन्नी वक्फ बोर्ड बैठक में लेगा निर्णय: सुन्नी वक्फ बोर्ड के सीइओ सैयद मो. शोएब कहते हैं कि प्रदेश सरकार की तरफ से भूमि आवंटन का कोई प्रस्ताव अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। जब प्रस्ताव आएगा, तब इसे बोर्ड मीटिंग में रखा जाएगा। अगली बोर्ड बैठक 24 फरवरी को प्रस्तावित है। भूमि लेने या न लेने के साथ ही इसमें मस्जिद बनाने के अलावा और क्या-क्या किया जा सकता है, इसका फैसला बोर्ड करेगा। सूत्रों के अनुसार, सुन्नी वक्फ बोर्ड यहां इंडो इस्लामिक कल्चर ट्रस्ट बनाने जा रहा है। इसके जरिए पांच एकड़ जमीन पर अस्पताल, विद्यालय, संस्थान, लाइब्रेरी सहित अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जा सकते हैं। वहीं, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर फारूकी शहर से बाहर हैं। इस कारण उनसे संपर्क नहीं हो सका। हालांकि वह पहले ही कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करेंगे।

मंदिर से 25 किमी दूर

आनंदमोहन • अयोध्या

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपालन में सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव रौनाही थाने के बगल कृषि विभाग के फार्म में किया गया है। कृषि विभाग का यह फार्म लखनऊ-अयोध्या हाईवे से लगा राजस्व ग्राम धन्नीपुर का हिस्सा है। मंदिर से इसकी दूरी करीब 25 किमी है। यह सोहावल ब्लॉक/ तहसील के मुस्लिम बहुल गांव रौनाही व शेखपुर जाफर से लगा है। रौनाही में प्रतिष्ठित मदरसा अल जामियातुल इस्लामिया है, जिसमें देश के कई राज्यों से छात्र तालीम के लिए आते हैं। प्राइमरी (तहतानिया) से लेकर इंटर (आलिया) तक की तालीम लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रशासन ने मस्जिद के लिए जिस भूमि का प्रस्ताव किया था, उसमें रौनाही थाना के बगल कृषि फार्म की भूमि को हाईवे व मुस्लिमों की आबादी की दृष्टि से सबसे उपयुक्त माना जा रहा था। सोहावल तहसील के धन्नीपुर के अलावा बीकापुर तहसील के नंदरौली, सदर तहसील के मलिकपुर व चांदपुर हरवंश राजस्व गांव की भूमि को भी प्रस्तावित किया गया था।

मस्जिद के लिए प्रस्तावित कृषि विभाग के फार्म का कुल रकबा 6.625 हेक्टेयर है। सुन्नी वक्फ बोर्ड को प्रस्तावित पांच एकड़ भूमि देने के बाद कृषि फार्म के पास लगभग पांच एकड़ भूमि रह जाएगी। इसमें 1.279 हेक्टेयर आम का बाग है। आम के करीब 142 वृक्ष बताए गए हैं। इनकी उम्र 20 वर्ष से अधिक कृषि विभाग ने बताई है। कृषि विभाग की मानें तो फार्म का रकबा पहले ज्यादा था। वर्षों से बंद सहकारी शीतगृह, रौनाही थाना, पशु चिकित्सालय का भवन कृषि फार्म से दी भूमि पर है।

प्रसिद्धि की ओर

- लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर शेखपुर जाफर के करीब है भूमि
- यहां है प्रसिद्ध अल जामियातुल इस्लामिया शिक्षा केंद्र

शाह गदाशाह रहमतउल्लाह अलैह की मजार

कृषि फार्म में ही शाह गदाशाह रहमतउल्लाह अलैह की मजार है। दलमीरपुर निवासी मो. सलीम खां के अनुसार वह सूफी संत रहे। सभी संप्रदाय में उनके आज भी कद्रदान हैं। उनकी मजार पर तीन दिवसीय उर्स प्रति वर्ष 28 अप्रैल से होता है। उर्स में लोग मजार पर मन्नत मांगने व श्रद्धासुमन अर्पित करने आते हैं।

किसी भी मस्जिद की जमीन के बदले में जमीन नहीं दी जा सकती है न ली जा सकती है। यह इस्लामी शरीयत और कानून दोनों के ही खिलाफ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले से ही जमीन लेने के पक्ष में नहीं है। हालांकि जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दी गई है। उसे तय करना है कि जमीन लेनी है या नहीं? यह फैसला 1993 के एक्ट के खिलाफ है। साथ ही 1994 में दिए गए कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी है।

एडवोकेट जफरयाब जिलानी, सचिव ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एवं संयोजक बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर इस मुद्दे को समाप्त कर दिया है। मुस्लिम तो पहले से ही कहते रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, वह सभी को मान्य होगा। इस समय देश को मंदिर-मस्जिद से अधिक जरूरत स्कूलों और कॉलेजों की है। मेरी राय तो यह है कि जो पांच एकड़ जमीन मुस्लित पक्ष को दी गई है, उस पर शिक्षा संस्थान खुले और उसके करीब छोटी मस्जिद बन जाए। जितने भी धर्म है उनकी सबसे बड़ी तालीम ये है कि किसी भी इंसान के साथ जुल्म और अन्याय नहीं होना चाहिए। ये वो पाप हैं जिसे अल्लाह भी माफ नहीं करता है।

मौलाना डॉ. कल्बे सादिक, उपाध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया था। सरकार ने तीन महीने के अंदर मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने की मंजूरी कैबिनेट में देकर वर्षों से चल आ रहे मुद्दे का अंत कर दिया है। मंदिर-मस्जिद विवाद में बहुत सियासत हो चुकी है। पीएम के इस फैसले से अब सियासत का मौका नहीं मिलेगा।

मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, इमाम ईदगाह, ऐशबाग

आपातकाल में संघ का थामा दामन

डॉ. अनिल मिश्र मूलत: अंबेडकरनगर जिले के हैं। करीब साढ़े चार दशक पूर्व आरएसएस से जुड़ाव के साथ वह अयोध्या शहर आ गए। डॉ. मिश्र ने समाजसेवा के साथ 1981 में बीएचएमएस करने के बाद चिकित्सक के रूप में भी खूब ख्याति अर्जित की। वह लंबे समय से आरएसएस के अहम पदों का निर्वहन करते आ रहे हैं।

स्वामी अखंडानंद के शिष्य हैं महाराज

अखंड परमधाम के परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर युग पुरुष **स्वामी परमानंद महाराज** का जन्म 26 अक्टूबर 1935 को हुआ था। स्वामी अखंडानंद को गुरु बनाया। 2000 में सुर्खियों में आए, जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में दुनियाभर के आध्यात्मिक गुरुओं के विश्व शांति शिखर सम्मेलन में न सिर्फ भारत का प्रतिनिधित्व किया, बल्कि सम्मेलन को संबोधित भी किया।

बाल्यावस्था में ही साधु बने

अयोध्या जिला के ही ग्राम रामपुर बैहारी में पैदा हुए निर्मोही अखाड़ा के 50 वर्षीय **महंत दिनेंद्रदास** बाल्यावस्था में ही साधु बन गए। वाणिज्य से परास्नातक दिनेंद्रदास ने चार साल पूर्व निर्मोही अखाड़ा की महंती संभाली। इससे पूर्व उप सरपंच के तौर पर भी अखाड़ा में उनकी अहमियत रही।

देश-विदेश में करते हैं प्रवचन

स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज महाराष्ट्र के अहमद नगर में 1950 में जन्म हुआ। महाराष्ट्र के विख्यात आध्यात्मिक गुरु पांडुरंग शास्त्री अठावले के शिष्य हैं। कांचि कामकोटि के शंकराचार्य के प्रिय शिष्य भी रहे हैं। 2006 में हरिद्वार में स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि से परमहंस संन्यास की दीक्षा मिली।

उडुपी के जगतगुरु माधवाचार्य

जगतगुरु माधवाचार्य स्वामी विश्व प्रसन्नतीर्थ जी महाराज कर्नाटक के उडुपी स्थित पेजावर मठ के 33वें पीठाधीश्वर हैं। दिसंबर 2019 में पेजावर मठ के पीठाधीश्वर स्वामी विश्वेशतीर्थ के निधन के बाद पदवी संभाली।

पर्यटन स्थल राममंदिर के साथ ही धार्मिक ही नहीं, पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक इमारतें भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेंगे, स्थापत्य कला के हैं बेजोड़ नमूने

इक्ष्वाकु के रूप में विकसित होकर भव्य-दिव्य दिखेगी राम की अयोध्या

सामाजिक समरसता के रंग में रंगी रही है अयोध्या, विकसित होने से श्रद्धालुओं की बढ़ेगी भीड़

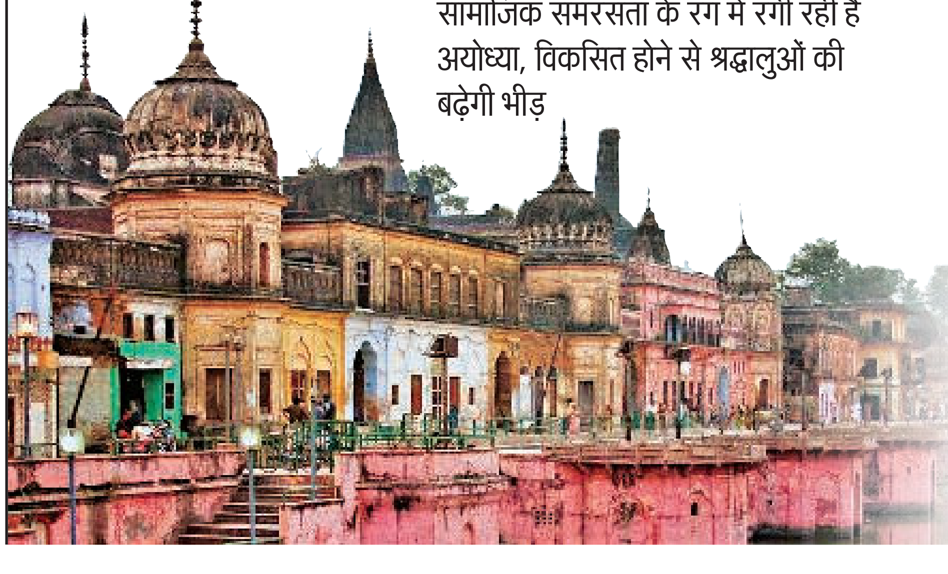

मुकेश पांडेय • अयोध्या

राममंदिर निर्माण के साथ रामनगरी इस कदर भव्यता एवं दिव्यता को प्राप्त होगी कि वह देश और दुनिया को मोह लेगी। यह यूं ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे सामाजिक सद्भाव का वह ताना-बाना है, जो सदियों पहले पगा था और अब आधुनिक तरक्की के विविध आयाम से आच्छादित हो रहा है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह ट्रस्ट के गठन का एलान संसद में किया है, वैसे ही पूर्व में खींचे गए पर्यटन विकास के नक्शे को इक्ष्वाकु नगरी की तर्ज पर विस्तृत ढंग से उकेरा जाएगा। आने वाले वक्त में देश के सबसे बड़े धार्मिक केंद्रों माता वैष्णो देवी, तिरुपति बालाजी, उज्जैन में महाकाल, स्वर्ण मंदिर की तरह दुनियाभर के श्रद्धालु यहां पहुंचने लगेंगे।

यह महज कल्पना नहीं, बल्कि इसके पीछे अयोध्या का पौराणिक महत्व और इतिहास छिपा है। अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि तमाम बंदिशों और मुश्किलों के बावजूद गत वर्ष अयोध्या में करीब 1.5 लाख श्रद्धालु बाहर से पहुंचे। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर अयोध्या को बड़ी धार्मिक नगरी के रूप में विकसित कर दिया जाए तो यहां पर्यटकों की संख्या रोजाना ही 40 से 50 हजार के बीच पहुंच जाएगी। इसके लिए बुनियादी ढांचे के साथ ही अयोध्या को पौराणिक स्वरूप में ढालने पर चर्चा शुरू हो गई है। यातायात के साधनों समेत विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित करने की दिशा में योजना तैयार की जा रही है।

ये भी होंगे पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र: पर्यटन सर्किट के रूप में अयोध्या को विकसित करने की योजना रफ्ता-रफ्ता आगे बढ़ रही है। अब इसे और पंख लगने की उम्मीद है। राममंदिर के साथ ही धार्मिक ही नहीं, पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक इमारतें भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेंगी। इसमें मणिपर्वत, सुग्रीवकिला, जैनमंदिर, कनकभवन, हनुमानगढ़ी, राजप्रासाद राजसदन, भरतकुंड, दशरथसमाधि, श्रृंगी ऋषि आश्रम, कामाख्यादेवी मंदिर के अलावा बेगम मकबरा, गुलाबबाड़ी आदि शामिल हैं। सभी स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने हैं।

इन योजनाओं से भी बदलेगी सूरत

- एयरपोर्ट एवं अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप अयोध्या-फैजाबाद रेलवे स्टेशन का विकास।
- अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट कांप्लेक्स का निर्माण, अयोध्या के बाहरी हिस्से में रिंगरोड के साथ सरयू पर नया पुल।
- बैराज का निर्माण एवं 251 मीटर ऊंची भव्य राम की मूर्ति की स्थापना, दस किमी लंबे सरयूघाट का निर्माण।

05 लाख नौकरियां कश्मीर में इंटरनेट बंदी की वजह से खत्म हुई हैं। कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की रिपोर्ट के अनुसार, इंटरनेट बंदी से कश्मीर में 18 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 6 फरवरी 2020

'राम मंदिर ट्रस्ट का दिल्ली चुनाव से कोई वास्ता नहीं'

बोले जावडेकर ▸ यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, पूरे देश में चुनाव नहीं हो रहा इसलिए स्थिति को उलझाना नहीं चाहिए

चुनाव आयोग ने कहा, ट्रस्ट की घोषणा के लिए उसकी अनुमति जरूरी नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए स्वतंत्र ट्रस्ट के गठन के मोदी कैबिनेट के फैसले को दिल्ली चुनाव से जोड़ने को गलत बताया है। वहीं, चुनाव आयोग ने कहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट की घोषणा के लिए सरकार को उसकी अनुमति की जरूरत नहीं थी।

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए जावडेकर ने संवाददाताओं से कहा, 'यह फैसला अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए लिया गया है। दिल्ली से इसका कोई लेना-देना नहीं। पूरे देश में चुनाव नहीं हो रहा है। हमें स्थिति को उलझाना नहीं चाहिए।' उन्होंने उस सवाल के जवाब में यह बात कही कि यह फैसला दिल्ली चुनाव के बाद क्यों नहीं लिया गया।

यह पूछे जाने पर कि इस फैसले से पहले चुनाव आयोग की अनुमति ली गई थी, जावडेकर ने कहा, 'यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इसलिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट नाम से भी सुप्रीम है।' उन्होंने फैसले

प्रकाश जावडेकर। फाइल

के समय को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब देने से इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट से संबंधित सवालों का जवाब गृह मंत्री अमित शाह देंगे। उन्होंने साफ कहा कि इसकी विस्तृत जानकारी गृह मंत्री के पास ही है।

इस बीच, इस सवाल पर कि क्या इस घोषणा से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ है, चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि श्रीराम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की घोषणा के लिए सरकार को उसकी अनुमति की जरूरत नहीं थी। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को वोट डाले जाएंगे।

स्वामी परमानंद ने कहा– रामनवमी को रखी जाएगी आस्था की ईंट

जासं, फतेहपुर : अयोध्या में भगवान श्रीराम मंदिर के भव्य मंदिर निर्माण के लिए बुधवार को घोषित ट्रस्टी में शामिल युग पुरुष स्वामी परमानंद महाराज ने कहा कि रामनवमी के दिन ही नींव रखी जाएगी। भगवान श्रीराम के जन्मदिन से ज्यादा शुभमूहूर्त और क्या होगा। शीघ्र ही ट्रस्ट की बैठक कर रणनीति बनाई जाएगी।

मूलरूप से फतेहपुर के मवईधाम निवासी स्वामी पंरमानंद ने दैनिक जागरण से दूरभाष पर बातचीत में ट्रस्ट में शामिल सदस्यों के नामों पर हर्ष जताया और केंद्र सरकार की सराहना भी की। उन्होंने बताया कि सभी सदस्यों का मंदिर निर्माण के संघर्ष में बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने बताया कि जल्द ही ट्रस्ट के सदस्यों की बैठक में पांच अन्य लोगों को शामिल करने के लिए नामों पर आम सहमति से निर्णय लिया जाएगा। अखंड आश्रम हरिद्वार के प्रमुख स्वामी परमानंद ने कहा कि भगवान राम किसी एक के नहीं संपूर्ण विश्व व राष्ट्र के आराध्य हैं।

हरेक भारतीय का राम मंदिर का सपना होगा पूरा : नड्डा

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर के ट्रस्ट के गठन की घोषणा करने के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हरेक भारतीय का अयोध्या में राम मंदिर का सपना पूरा होने वाला है।

भाजपा अध्यक्ष ने बुधवार को कहा कि यह ऐतिहासिक दिन है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन की घोषणा के साथ ही प्रधानमंत्री ने सभी भारतीयों का सम्मान किया है। इसी तरह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट के गठन की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भव्य राम मंदिर के निर्माण का फैसला दिया है। विहीं महाराष्ट्र में भाजपा नेता देवेंद्र फड़नवीस ने कहा कि विश्व भर में करोड़ों रामभक्तों की इच्छा पूरी हो रही है। वहीं एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि राम मंदिर निर्माण को तेज गति दी जाएगी।

मेरी इच्छा पूरी हुई, पर ट्रस्ट में ओबीसी भी हो : कल्याण सिंह

जासं, अलीगढ़ : उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह ने कहा कि ट्रस्ट बनने से अब अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण जल्द शुरू होगा। मेरे जीवन की यही इच्छा थी। मगर, ट्रस्ट में एक सदस्य ओबीसी से भी जरूर रखना चाहिए।

बुधवार देर शाम फोन पर हुई बातचीत में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को बधाई दी। कहा, प्रसन्नता की इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि उनके जीवनकाल में श्रीराम मंदिर निर्माण का सपना पूरा हो रहा है। ट्रस्ट में दलित ही क्यों ओबीसी को भी लेना चाहिए। श्रीराम मंदिर के लिए पिछड़े समाज का भी बड़ा योगदान है। उनसे पूछा गया कि क्या आपको ट्रस्ट में शामिल किया जाना चाहिए, इस पर उन्होंने साफ इन्कार कर दिया। कहा, मेरी श्रीराम मंदिर निर्माण ट्रस्ट में स्थान पाने की कोई इच्छा नहीं है। ओबीसी में 54 जातियां हैं, उनमें से किसी को भी शामिल किया जा सकता है।

कांग्रेस ने किया राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट की घोषणा का समर्थन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ इसमें कुछ गलत नहीं, सरकार का कदम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप : गोगोई

▸ भाजपा को भगवान राम के नाम पर वोट मांगने की राजनीति बंद करने की नसीहत

कांग्रेस ने कहा है कि राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट बनाने की सरकार की घोषणा में कुछ गलत नहीं है क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप है। पार्टी के अनुसार सर्वोच्च अदालत ने मंदिर निर्माण के अपने फैसले में ट्रस्ट समेत अन्य प्रक्रियाओं की रूपरेखा तय कर रखी है जिनका पालन करना सरकार की जिम्मेदारी है।

कांग्रेस प्रवक्ता गौरव गोगोई ने पार्टी की आधिकारिक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के साथ ही हमने इसका सम्मान और स्वागत करते हुए राममंदिर निर्माण का समर्थन किया था। जहां तक ट्रस्ट के गठन से लेकर अन्य प्रक्रियाओं का सवाल है तो ये सभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हिस्सा हैं जिन पर अमल करना सरकार का कर्तव्य है। दिल्ली चुनाव की गहमागहमी के बीच लोकसभा में मंदिर निर्माण ट्रस्ट के गठन की प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा में सियासत छिपे होने से जुड़े सवाल पर गोगोई ने यह बात कही।

कांग्रेस प्रवक्ता ने इसमें राजनीतिक एंगल नकारते हुए मंदिर निर्माण की दिशा में सरकार के उठाए कदमों का जहां पूरा समर्थन किया, वहीं भाजपा को अब धर्म के नाम पर राजनीति करने से बाज आने की नसीहत भी दी। गोगोई ने कहा कि भाजपा से हम यही कहेंगे कि भगवान राम के नाम

गौरव गोगोई। फाइल

पर वोट मांगने की राजनीति अब बंद होनी चाहिए ताकि देश में अमन चैन और शांति का वातावरण आए। कांग्रेस का मानना रहा है कि भगवान राम हमारे लोगों की आस्था से जुड़े हैं। आस्था और विश्वास से जुड़े मसलों पर लोगों को भाजपा के उपदेश की जरूरत नहीं है।

कांग्रेस प्रवक्ता गौरव गोगोई ने यह भी कहा कि चुनाव में लोगों ने भाजपा को वोट धर्म के नाम पर नहीं बल्कि विकास के नाम पर दिया है। ताकि सरकार उनकी जिंदगी में बेहतर बदलाव ला सके।

राममंदिर में कारसेवकों के स्मरण के लिए बने स्मारक

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली

▸ विहिप ने मंदिर निर्माण के लिए बने ट्रस्ट को दिए कई सुझाव

▸ कहा– सरकार नहीं, जनता की भागीदारी से बने भव्य राममंदिर

केंद्र सरकार द्वारा राममंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट के गठन पर हर्ष जताते हुए विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने आग्रह किया है कि मंदिर परिसर में मंदिर आंदोलन से जुड़े कारसेवकों की याद में योग्य स्मारक बनाया जाना चाहिए। विहिप के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि सैकड़ों वर्षों तक मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन चला। विहिप ने 1984 से इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी शुरू की और विहिप के जरिये आंदोलन से जुड़कर बहुत से लोगों ने बलिदान दिया। ऐसे में ट्रस्ट से आग्रह है कि कारसेवकों के स्मरण के लिए योग्य स्मारक बनना चाहिए। इसमें नामों को प्रदर्शित करने के लिए आधुनिक मल्टीमीडिया तकनीकी का इस्तेमाल हो सकता है।

उन्होंने सरकार की सहायता के बजाय जनभागीदारी से मंदिर निर्माण का सुझाव भी ट्रस्ट को दिया है। इसमें आर्थिक सहायता के साथ कारसेवा भी शामिल है। इससे विश्व में रहने वाले हर हिंदू को मंदिर निर्माण में भागीदारी का मौका मिलेगा। सोमनाथ मंदिर मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के मामले में महात्मा गांधी ने उनसे मिलने गए तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल व केएल मुंशी से कहा कि मंदिर का पुनर्निर्माण सरकारी पैसे से नहीं होना चाहिए। यही हम भी चाहते हैं। इसके लिए ट्रस्ट एक निश्चित राशि तय कर सकता है। पहले आंदोलन में 1.25, 5 और 10 रुपये की आर्थिक सहायता रामभक्तों से ली गई थी, जिससे तकरीबन सवा आठ करोड़ रुपये जुटे थे।

इसके साथ ही उन्होंने 30 साल पहले विहिप द्वारा तैयार कराए गए नक्शे के आधार पर ही मंदिर निर्माण का आग्रह किया है। ये मॉडल सर्वप्रथम 1989 में प्रयागराज के कुंभ में रखा गया था। इसे चंद्रकांत सोमपुरा ने तैयार किया था। यह मॉडल अष्टकोणीय आकार में नागर शैली में पत्थरों से दो मंजिला भवन का है माना जाता है भगवान विष्णु को इस शैली के मंदिर बहुत प्रिय लगते हैं। मंदिर में पांच प्रखंड होंगे।

नौ फरवरी से पहले गठित किया जाना था ट्रस्ट

प्रथम पृष्ठ से आगे

इस ट्रस्ट का गठन नौ नंवबर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप और 1993 में संसद से पारित 'अयोध्या भूमि अधिग्रहण कानून' के प्रावधान के तहत किया गया है। सदियों पुराने विवाद पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में विवादित स्थल पर रामलला के पक्ष में फैसला दिया था और सरकार को तीन महीने के भीतर इसके लिए ट्रस्ट बनाने को कहा था। नौ फरवरी को तीन महीने पूरे होने के चार दिन पहले ही सरकार ने ट्रस्ट बना दिया। अब भविष्य में यह ट्रस्ट ही राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण और उसकी रोजमर्रा की व्यवस्था से लेकर देश-विदेश से आने वालेश्रद्धालुओं के आने-जाने, ठहरने और खाने-पीने के इंतजाम की जिम्मेदारी संभालेगी। वैसे तो अयोध्या में राम मंदिर के आंदोलन चलाने वाली विहिप ने मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट बना रखा रखा है, जिसने उसका नक्शा भी बना रखा है और उस नक्शे के अनुरूप पत्थरों की तराशने का 70 फीसदी काम पूरा भी हो चुका है। लेकिन नए ट्रस्ट को भव्य राम मंदिर के निर्माण के नक्शे के चयन की छूट होगी। वह चाहे तो राममंदिर न्यास ट्रस्ट के नक्शे और निर्माण सामग्री का उपयोग कर सकता है या फिर नए सिरे से नक्शे भी बनवा सकता है।

विहिप ने इस बार व्यापक स्तर पर पूरे देश में रामोत्सव मनाने का निर्णय लिया है। यह महोत्सव 25 मार्च से आठ अप्रैल तक चलेगा। मंदिर आंदोलन की अगुआ विहिप इस उत्सव में खासकर उन तीन लाख गांवों में शोभायात्रा, सभा व हनुमान चालीसा के साथ अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करवाएगी जहां से मंदिर निर्माण के लिए रामशिला अयोध्या गई थीं। इसी तरह 18 करोड़ से अधिक उन कारसेवकों को भी सम्मानित किया जाएगा, जो 1989 से शुरू हुए इस आंदोलन से जुड़े थे।

राम मंदिर का एक अध्याय पूरा, अब रामराज्य लाना होगा : उमा भारती

राज्य ब्यूरो, भोपाल

▸ भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने मीडिया में दिया बयान

▸ पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा– 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ूंगी

राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट के गठन के एलान का स्वागत करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमा भारती ने कहा, 'राम मंदिर निर्माण का एक अध्याय पूरा हो गया है, अब राम राज्य का नया अध्याय शुरू करना होगा। मोदीजी को यह समझना होगा, अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटना ही रामराज्य होगा।' इस दौरान उन्होंने एलान किया कि वे अगला लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि मैंने 2019 में चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन 2024 का चुनाव लड़ूंगी।

उमा भारती ने बुधवार को भोपाल में मीडिया से बातचीत में कहा कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट के फैसले से पूरा देश खुश है। सुन्नी वक्फ बोर्ड को जमीन देने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले से देश में सद्भाव कायम होगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय मुसलमानों ने अपना योगदान दे दिया। उन्होंने फैसले को

उमा भारती। फाइल

स्वीकार किया, किसी के बहकावे में वे नहीं आए, यही उनका असली योगदान है। मप्र की कांग्रेस सरकार द्वारा श्रीलंका में सीता मंदिर और मध्य प्रदेश में राम वनगमन पथ बनाए जाने पर कहा कि भगवान राम सबके हैं, उन पर किसी का एकाधिकार नहीं। भारती ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में हमने हिंदू-मुस्लिम मुद्दा नहीं बनाया, वह शाहीन बाग से बना है।

सीएए पढ़ा नहीं इसलिए विरोध : कमलनाथ कैबिनेट द्वारा सीएए निरस्त करने का संकल्प पारित करने के सवाल पर उमा भारती बोलीं कि मध्य प्रदेश की सरकार हो, केरल की सरकार हो या सीएए का विरोध कर रहे शाहीन बाग में बैठे लोग हों, उन्होंने सीएए को पढ़ा नहीं है, इसीलिए विरोध कर रहे हैं। सीएए के विरोध करने का कोई औचित्य ही नहीं है, यह सिर्फ वोट बैंक के लिए विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा, 'औवेसी से भी मैंने कहा कि वे आएं, मैं उन्हें अपने साथ राम मंदिर निर्माण के लिए लेकर जाऊंगी। कांग्रेस धर्म की राजनीति करती है।'

राहुल-प्रियंका पर हमला : कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर उमा भारती ने हमला करते हुए कहा कि टीआरपी में बने रहने के लिए दोनों भाई-बहन बोलते रहते हैं।

अब मध्य प्रदेश में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित

राज्य ब्यूरो, भोपाल : मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने भी नागरिकता संशोधन कानून-2019 (सीएए) के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार से इसे निरस्त करने का आग्रह किया है। बुधवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस आशय का शासकीय संकल्प पारित किया गया। इसमें कहा गया कि यह कानून देश के संविधान के प्रावधान और आदर्शों के मुताबिक नहीं है। यह पहला मौका है जब धर्म के आधार पर विभेद करने के प्रावधान वाला कोई कानून देश में लागू किया गया है। इससे देश का पंथनिरपेक्ष स्वरूप और सहिष्णुता का ताना-बाना खतरे में पड़ जाएगा। संकल्प को अब केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। गौरतलब है कि केरल, पंजाब, बंगाल और राजस्थान सरकार पहले ही इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुकी हैं। मप्र के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि कैबिनेट में रखे गए संकल्प प्रस्ताव में कहा गया कि सीएए में ऐसे प्रावधान क्यों किए गए हैं, यह लोगों की समझ से परे हैं।

सीएए से मुस्लिमों को कोई खतरा नहीं एनपीआर बेहद जरूरी : रजनीकांत

चेन्नई, प्रेट्र : सुपरस्टार रजनीकांत ने बुधवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का समर्थन करते हुए कहा कि इस कानून से मुस्लिमों को कोई खतरा नहीं है, जबकि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को उन्होंने बेहद जरूरी बताया।

सीएए पर पहली बार प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रजनीकांत ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के बारे में भी गलतफहमियां दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सरकार को अभी इस पर विचार करना बाकी है। सीएए को लेकर आश्चर्य जताते हुए उन्होंने कहा कि विभाजन के बाद जिन मुस्लिमों ने भारत में रुकने का फैसला किया उन्हें देश से बाहर कैसे भेजा जा सकता है। उन्होंने भारत में जीने-मरने का फैसला किया क्योंकि यह उनकी जन्मभूमि है और उन्हें इस देश में सभी अधिकार हासिल हैं। रजनीकांत ने

▸ कहा, एनआरसी पर सरकार ने अभी नहीं किया विचार

▸ तमिलनाडु में आगामी विस चुनाव से पहले कर सकते हैं अपनी पार्टी लांच

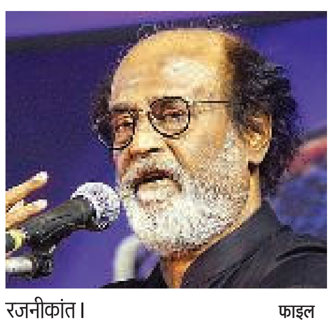
रजनीकांत। फाइल

कहा, 'इस तरह का भय पैदा किया गया कि सीएए मुस्लिमों के लिए खतरा है। यह कैसे मुस्लिमों के लिए खतरा है? सीएए कतई मुस्लिमों के लिए खतरा नहीं है, अगर उन्हें कोई भी परेशानी (इस कानून के कारण) हुई तो उनके लिए आवाज उठाने वाला मैं पहला व्यक्ति होउंगा।'

तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले रजनीकांत अपनी पार्टी लांच कर सकते हैं। उन्होंने सीएए के मसले पर कमल हसन के नेतृत्व वाली मक्कल निधि मय्यम (एमएनएम) के विपरीत रुख अपनाया है। सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वालों में एमएनएम भी शामिल है। सीएए में तमिल शरणार्थियों के लिए नागरिकता का प्रावधान नहीं होने के बारे में पूछे जाने पर रजनीकांत ने कहा कि उन्हें निश्चित तौर पर दोहरी नागरिकता दी जानी चाहिए। उनका यह रुख सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक के अनुरूप है। जबकि विपक्षी द्रमुक तमिल शरणार्थियों को शामिल नहीं किए जाने के कारण सीएए का विरोध कर रही है।

परासरन के घर में खुला श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का कार्यालय

जासं, नई दिल्ली : अयोध्या में भगवान श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत ट्रस्ट का गठन कर दिया। इसका नाम श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट रखा गया है। इसका कार्यालय दक्षिणी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट-1 में रखा गया है। यह रामलला विराजमान की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने वाले वरिष्ठ वकील के परासरन का घर है। इसके बेसमेंट में के परासरन का चेंबर है। बुधवार को इसे ट्रस्ट का कार्यालय बनाए जाने की घोषणा के बाद इसके आसपास की सुरक्षा-व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जीके-1 के आर ब्लॉक के मुख्य गेट पर भी सुरक्षाकर्मियों को तैनात कर दिया गया। वहीं, शाम को परासरन के घर के बाहर मीडियाकर्मियों का जमावड़ा लग गया।

हालांकि, परासरन के ऑफिस की ओर से बताया गया कि गुरुवार को सबरीमाला मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। वह उसी केस की तैयारी कर रहे हैं इसलिए मीडिया से बिलकुल बात नहीं कर सकेंगे।

अपने आप में अनूठी है विदिशा की चलित रामलीला

▸ पूर्व राष्ट्रपति स्व. शंकरदयाल शर्मा सहित कई हस्तियां कर चुकी हैं अभिनय

▸ 119वां वर्ष : बीते एक माह से चल रही लीला, सात को है समापन

मध्य प्रदेश के विदिशा के ऐतिहासिक रामलीला प्रांगण में राम, लक्ष्मण और हनुमान की भूमिका निभाते कलाकार। नई दुनिया

अपना देस खुशबू माटी की

राजेंद्र शर्मा, विदिशा

विदिशा (मप्र) की ऐतिहासिक श्रीरामलीला संभवतः देश में इकलौती रामलीला है, जहां करीब एक माह तक चलने वाली लीलाओं की प्रस्तुति मंच के बजाय विशाल मैदान में चलित रूप में दी जाती है। इसलिए इसे चलित रामलीला भी कहा जाता है। रामलीला इस साल 119वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। इस साल भी शानदार आयोजन हुआ, जिसका समापन सात फरवरी को होने जा रहा है।

इस रामलीला में पूर्व राष्ट्रपति स्व. शंकरदयाल शर्मा सहित अन्य शख्सियत भी अभिनय कर चुकी हैं। खास बात यह है कि यहां सभी पदों से लेकर अभिनय करने वाली निश्शुल्क सेवाएं देते हैं। रामलीला की शुरुआत विदिशा (मप्र) के धर्माधिकारी पंडित विश्वनाथ शास्त्री ने वर्ष 1901 में मकर संक्रांति पर्व पर अपने कुछ सहयोगियों के साथ की थी। वे ही रामलीला के प्रथम प्रधान संचालक थे। इसकी प्रस्तुति विदिशा-अशोकनगर मार्ग पर बेतवा नदी के पास स्थित मैदान में दी जाती है।

संचालन के लिए वर्ष 1956 में बना था रामलीला का एक्ट : इस रामलीला की कई खासियत हैं। रामलीला का विधिवत एक्ट भी बना हुआ है। वर्ष 1956 में शासन द्वारा बनाए गए एक्ट का राजपत्र में भी प्रकाशन किया गया था। रामलीला मेला समिति के पूर्व मानसेवी सचिव पंडित सुरेश शर्मा शास्त्री बताते हैं कि उस समय एक्ट बनवाने में मध्य भारत के मुख्यमंत्री रहे स्व. तखतमल जैन, पूर्व राज्यसभा सदस्य स्व. बाबू रामसहाय, पूर्व सांसद स्व. निरंजन वर्मा, स्व. रामकृष्ण सिलाकारी का विशेष योगदान रहा। इसी एक्ट के कारण मेला समिति के मानसेवी सचिव की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। जबकि कलेक्टर पदेन अध्यक्ष होते हैं। यहां लीला का मंचन नहीं किया जाता, बल्कि कलाकार पूरे प्रांगण में चारों तरफ घूमते हुए लीला की प्रस्तुति देते हैं। हर लीला का समापन प्रांगण के बीच बने मंच पर होता है। रामलीला मेला समिति के प्रथम प्रधान संचालक पंडित विश्वनाथ शास्त्री द्वारा लिखे गए संवादों का ही अब तक उपयोग किया जाता है। वर्तमान में उनकी चौथी पीढ़ी के पं. चंद्रकिशोर मिश्र प्रधान संचालक हैं।

स्टेडियमनुमा लीला परिसर : शुरुआती दौर में रामलीला प्रांगण वाला क्षेत्र ऊबड़-खाबड़ था। रामलीला समिति के तत्कालीन सदस्यों ने ही श्रमदान और अपने खर्च से इस स्थान को विकसित किया। कालांतर में इस प्रांगण के एक तरफ अयोध्या भवन और दूसरी तरफ लंका भवन बनाया गया। फिर दर्शकों के बैठने के लिए दो तरफ सीढ़ियां बनाकर स्टेडियम जैसा रूप दे दिया।

दूर-दूर से जुटते हैं श्रद्धालु : इस रामलीला में विदिशा के दर्जनों परिवार करीब पांच पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। रामलीला के प्रति उनके दिलों में इतनी गहरी आस्था है कि वे देश-दुनिया में कहीं भी हों, रामलीला के समय एक माह के लिए अपना काम छोड़कर विदिशा आ जाते हैं। पूर्व में यहां श्रीराम की भूमिका निभा चुके चुके सॉफ्टवेयर इंजीनियर वैभव शर्मा वर्तमान में हैदराबाद में रहते हैं, लेकिन इस अवधि में विदिशा आ जाते हैं। हाल ही में उनके बेटे प्रभव ने श्रीराम के बाल रूप का अभिनय किया था। इसी प्रकार रावण का किरदार निभाते आ रहे जगदीश शर्मा अवकाश लेकर विदिशा आए हैं। दर्शकों में भी कई परिवार दूर-दराज से यहां जुटते हैं।

भाजपा नेता को पीटने वाली कलेक्टर ने पुलिस वाले को भी मारा था थप्पड़

नईदुनिया, भोपाल

सीएए के समर्थन में रैली के दौरान भाजपा नेता को पीटने वाली मध्य प्रदेश के राजगढ़ की कलेक्टर निधि निवेदिता ने ड्यूटी के दौरान एएसआइ (असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर) नरेश शर्मा को भी थप्पड़ मारा था। पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारने की शिकायत पुलिस जांच में सही पाई गई है। गृह विभाग को पुलिस महानिदेशक वीके सिंह ने रिपोर्ट सौंपी है। इसमें कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। गृह विभाग रिपोर्ट का अध्ययन कर अपनी सिफारिश के साथ मुख्यमंत्री कमलनाथ को भेजेगा। उधर, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि मुख्य सचिव को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए।

गौरतलब है कि पिछले दिनों राजगढ़ जिले के ब्यावरा में भाजपा की ओर से सीएए के समर्थन में रैली निकाली गई थी। इस दौरान कलेक्टर निधि निवेदिता ने एक भाजपा नेता को तमाचा मार दिया था। एएसआइ शर्मा को थप्पड़ मारने की घटना भी उसी समय की है। शर्मा ने कलेक्टर द्वारा थप्पड़ मारे जाने को लेकर पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी। इसकी एसडीओपी से जांच कराई गई, जिसमें शिकायत की पुष्टि

> कलेक्टर पर कार्रवाई को लेकर पूरा मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी है। कानून अपना काम करेगा।
>
> **–बाला बच्चन, प्रदेश के गृहमंत्री (मीडिया से चर्चा में)**

हुई। गृह विभाग को सौंपी नौ पेज की रिपोर्ट में बताया गया कि शर्मा की ड्यूटी रैली में लगाई गई थी। वे गाड़ी में बैठकर रिकॉर्डिंग कर रहे थे। उसी समय कलेक्टर वहां पहुंचीं और रैली को लेकर पूछताछ करने लगीं। इस दौरान उन्हें नाराजगी जताते हुए शर्मा को थप्पड़ मार दिया।

उधर, रिपोर्ट मिलने के बाद गृह विभाग हरकत में आ गया है। मंगलवार देर शाम मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ गृह विभाग के अधिकारियों ने रिपोर्ट पर अनौपचारिक चर्चा की। बुधवार को भी इसका अध्ययन किया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि गृह विभाग से अभी रिपोर्ट नहीं मिली है।

जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद भाजपा भी हमलावर हो गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जब भाजपा के कार्यकर्ता को थप्पड़ मारा था, तब पुलिस ने कुछ नहीं किया, लेकिन एएसआइ के थप्पड़ की जांच हो रही है।

एनआरसी का असर सभी धर्मों पर होगा, इसे नहीं लागू होने देंगे : उद्धव

मुंबई, प्रेट्र : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उनकी सरकार प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) को राज्य में लागू नहीं होने देगी क्योंकि इसका 'असर सभी धर्मों पर' पड़ेगा।

मुख्यमंत्री ने शिवसेना के मुखपत्र 'सामना' में अपने तीसरे साक्षात्कार में कहा कि बांग्लादेशी और पाकिस्तानी शरणार्थियों को देश से बाहर निकालना शिवसेना की पुरानी मांग रही है। शिवसेना अध्यक्ष ने कहा, 'मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सीएए भारतीय नागरिकों को देश से बाहर निकालने के लिए नहीं है, लेकिन एनआरसी का असर हिंदुओं पर भी पड़ेगा।'

उन्होंने कहा कि भारत को पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों की संख्या जानने का अधिकार है जिन्होंने अपने देशों में सताए जाने के बाद भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन दिया। उन्होंने सामना के कार्यकारी संपादक और शिवसेना सांसद संजय राउत को दिए साक्षात्कार में कहा, 'जब वे यहां आते हैं तो क्या उन्हें 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत मकान मिलेंगे? उनके

उद्धव ठाकरे। फाइल

बच्चों के रोजगार और शिक्षा का क्या? ये सभी मुद्दे महत्वपूर्ण है और हमें जानने का अधिकार है।' ठाकरे ने कहा, 'मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे यह जानना चाहिए कि इन लोगों को मेरे राज्य में कहां पुनःस्थापित करेंगे। हमारे खुद के लोगों के पास रहने की पर्याप्त जगह नहीं है। क्या ये लोग दिल्ली, बेंगलुरु या कश्मीर जाएंगे क्योंकि अनुच्छेद 370 हट गया है।'

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कई कश्मीरी पंडित परिवार अपने ही देश में शरणार्थियों की तरह रह रहे हैं। सीएए नागरिकों को देश से बाहर करने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा, 'हालांकि एनआरसी से हिंदुओं और मुसलमानों पर असर पड़ेगा और राज्य सरकार इसे लागू नहीं होने देगी।' ठाकरे ने दावा किया कि एनआरसी के तहत सभी को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। असम में 19 लाख लोग नागरिकता साबित नहीं कर पाए। इनमें से 14 लाख हिंदू थे। अपने चचेरे भाई और मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर तीखा हमला करते हुए शिवसेना अध्यक्ष ने कहा कि एनआरसी वास्तविकता नहीं है और इसके समर्थन या इसके खिलाफ 'मोर्चे' की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि राज ठाकरे नौ फरवरी को मुंबई में सीएए और एनआरसी के समर्थन में रैली करेंगे।

उद्धव ठाकरे ने कहा, 'अगर एनआरसी लागू होता है तो जो इसका समर्थन कर रहे हैं उन पर भी इसका असर पड़ेगा।' उन्होंने पाकिस्तानी मूल के संगीतकार अदनान सामी को पद्मश्री पुरस्कार देने के केंद्र के फैसले पर भी निशाना साधा।

उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा, 'एक प्रवासी केवल प्रवासी होता है। आप उन्हें पद्मश्री से सम्मानित नहीं कर सकते। अवैध शरणार्थियों को बाहर करना (दिवंगत शिवसेना सुप्रीमो) बालासाहेब ठाकरे का रुख था।'

10 में से एक भारतीय अपने जीवनकाल में कैंसर की बीमारी से ग्रसित होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने अपनी हालिया रिपोर्ट में यह दावा किया है। रिपोर्ट के अनुसार, हर 15 में एक भारतीय की मृत्यु इस बीमारी के कारण होगी।

दुनिया के बड़े हिस्से में मानवता की सुरक्षा का जिम्मा हमारा : मोदी

रखे विचार ▸ प्रधानमंत्री ने किया डिफेंस एक्सपो-2020 का उद्घाटन, 40 देशों के रक्षा मंत्रियों की मौजूदगी में कहा-पड़ोस के मित्र देशों की सुरक्षा का दायित्व भी हम पर

भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बताया रोडमैप

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

एशिया में रक्षा उत्पादों की सबसे बड़ी प्रदर्शनी 'डिफेंस एक्सपो 2020' का बुधवार को उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प दोहराया, बल्कि इसकी वजहें भी बताईं। चालीस देशों के रक्षा मंत्रियों, देश-विदेश के रक्षा विशेषज्ञों और उद्यमियों की मौजूदगी में उन्होंने कहा- 'हमारे ऊपर भारतीय महासागर क्षेत्र के साथ दुनिया के बड़े हिस्से में मानवता को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है। पड़ोस के मित्र देशों को सुरक्षा देने का दायित्व भी हमारे ऊपर है। हमारे पड़ोस में ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं जिनसे निपटने के लिए हमेशा तैयार रहने की जरूरत है।'

प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्रालय के इस आयोजन को दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपो में से एक बताते हुए कहा कि सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में भारत एक सशक्त भूमिका लेकर आगे बढ़ रहा है। भारत सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए अपार अवसर भी है। डिफेंस एक्सपो 'मेक इन इंडिया' के जरिये देश की सुरक्षा बढ़ाएगा, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करेगा। एक्सपो में आए उद्यमियों से उन्होंने रक्षा क्षेत्र में यह कहते हुए निवेश का आह्वान किया कि यहां लगा एक-एक पैसा आपको बड़ा रिटर्न देगा। मोदी ने देश के प्रमुख औद्योगिक संगठनों को सुझाव दिया कि वे रक्षा उत्पादन का एक कॉमन प्लेटफार्म बनाएं। इससे पहले रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद यशो नाईक ने अतिथियों का स्वागत किया। उद्घाटन सत्र की शुरुआत जोशीले अंदाज में हुई। स्क्रीन पर आधुनिक आयुध के चलचित्र थे और मंच पर सेना के जवान कभी सैल्यूट तो कभी पास्ट करते नजर आए। एयरोस्पेस पर एक शार्ट फिल्म भी दिखाई गई। मोदी ने कहा कि सुरक्षा की चिंताएं अब तकनीक पर आधारित होती जा रही हैं। टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल, आतंकवाद और साइबर हमले विश्व के लिए बड़ी चुनौती है। इनसे निपटने के लिए भारत भी नई तकनीकें ईजाद कर रहा है। इसलिए देश के रक्षा उत्पादन में इंटरनेट ऑफ मिलिट्री थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सेक्योरिटी जैसी तकनीकों के इस्तेमाल का रोडमैप तैयार किया गया है।

पांच साल की कार्ययोजना

पीएम ने कहा कि अगले पांच वर्षों में रक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के 25 उत्पाद विकसित करने का लक्ष्य है। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु व मध्यम दर्जे के उद्योगों की संख्या को बढ़ाकर 15 हजार के पार पहुंचाने का भी इरादा है। नवप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए 2018 में शुरू इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस के तहत 200 नये स्टार्ट अप शुरू करने का निर्णय किया गया है। कोशिश होगी कि इसके जरिये अगले पांच वर्षों में 50 नई टेक्नोलॉजी विकसित की जा सके। आगामी पांच वर्षों में रक्षा उत्पादन से जुड़े 5000 आयातित कंपोनेंट का निर्माण भी देश में ही शुरू करने की योजना है। देश का डिफेंस एक्सपोर्ट जो पिछले दो वर्षों के दौरान 17000 करोड़ रुपये रहा है, अगले पांच वर्षों के दौरान उसे 35 हजार करोड़ रुपये तक बढ़ाने का लक्ष्य है। कहा कि हमारी महत्वाकांक्षा किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं है। न कभी किया है, न ही ऐसा करने की हमारी इच्छा है।

आयात पर निर्भर रहकर कैसे देखते सपना

पूर्ववर्ती सरकारों का जिक्र किये बगैर प्रधानमंत्री ने उन्हें कटघरे में खड़ा किया कि आजादी के बाद हमने अपनी ताकत का उपयोग उस गंभीरता से नहीं किया। हमारी नीति-रणनीति रक्षा उत्पादों का आयातक बनने तक सीमित रही। सिर्फ आयात से हम भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना कैसे देख सकते थे?

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बुधवार को डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ में हैं (बाएं से) रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और दाएं से दूसरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एएनआइ।

25 उत्पाद आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित रक्षा क्षेत्र में विकसित करने का लक्ष्य है अगले पांच वर्षों में

35 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य है देश का डिफेंस एक्सपोर्ट अगले पांच वर्षों में

उप्र बनेगा रक्षा उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र

प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आने वाले समय में देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। दो साल पहले देश में दो डिफेंस कॉरिडोर का एलान किया गया था, एक तमिलनाडु और दूसरा उत्तर प्रदेश में। तमिलनाडु के डिफेंस कॉरिडोर में जहां अब तक 3100 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है, वहीं उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में 3400 करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है। इन दोनों डिफेंस कॉरिडोर से देश को काफी उम्मीदे हैं। इनके बन जाने से रोजगार के काफी अवसर पैदा होंगे।

डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा भारत : राजनाथ

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगले कुछ वर्षों में भारत दुनिया का बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। भारत ने साझेदारी के लिए जो हाथ बढ़ाया है, वह सभी की जरूरत है। लखनऊ में एक्सपो के आयोजन को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच का परिणाम बताया। रक्षामंत्री ने कहा कि एक्सपो तकनीक, सूचना और व्यापारिक संभावनाओं को साथ लाने का आयोजन है। यह नए भारत के विजन को दर्शाता है।

यूपी सरकार करेगी 23 एमओयू : योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि डिफेंस एक्सपो में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ 23 एमओयू होने जा रहे हैं, जिनसे 50 हजार करोड़का निवेश होने की उम्मीद है। उन्होंने इससे तीन लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद भी जताई।

इत्मीनान से लौटे 'चौकीदार', बड़े जांबाज हैं 'पहरेदार'

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

▸ प्रधानमंत्री मोदी ने देखा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के दमखम का 'लाइव डेमो'

▸ जमीं पर गरजे अर्जुन और टी-90 तो आसमान में सुखोई व चिनूक का रोमांच

देश की सेना यूं तो कितनी ही बार अपने शौर्य और पराक्रम से भारतवासियों का सीना चौड़ा कर चुकी है लेकिन, मौका उसके 'डेमो' का आया तो वहां मौजूद हर शख्स को रोमांच और गौरव की अनुभूति से भर दिया। खुद को देश का 'चौकीदार' कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिफेंस एक्सपो में थल सेना, नौ सेना और वायु सेना के 'लाइव डेमो' को इत्मीनान से देखा और हौसलाअफजाई करते रहे कि सरहद के पहरेदार कैसे जांबाज हैं।

वृंदावन योजना परिसर में डिफेंस एक्सपो के शुभारंभ के बाद आधुनिक हथियार और संसाधनों के साथ सेना के पराक्रम का लाइव डेमो आयोजित किया गया। एक्सपो का शुभारंभ करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोल्फकार्ट से डेमो स्थल पर पहुंचे। सबसे पहले आठ हजार फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से वायुसेना की आकाशगंगा टीम के पैराट्रूपर्स कूदे। तिरंगा लहराते हुए उन्होंने जमीन पर पैर रखा तो परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसके बाद बारी-बारी से लड़ाकू विमानों ने साहस और तकनीक का आकाश छू लेने का संदेश दिया। भारतीय वायुसेना के भारी भरकम ट्रांसपोर्टर विमान सी-17 ग्लोब मास्टर की अगवानी दोनों तरफ चल रहे सुखोई सू-30 विमानों ने की। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की फार्मेशन के साथ सूर्य किरण की टीम ने कई शानदार करतब दिखाए। तब माहौल ऐसा बन गया कि आसमान से नजरें हटाने का दिल ही न हो। इसी बीच वह चिनूक हेलीकॉप्टर गुजरा, जो आतंकवादी सरगना ओसामा बिना लादेन को मारने वाले ऑपरेशन में शामिल था और अब भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल है। इसे आम जन भी पहचान गए और देखते ही तालियां भी बजाईं।

इस फ्लाई पास्ट के बाद थलसेना के स्वदेशी टैंक अर्जुन व टी-90 जैसे टैंकों की बमबारी की गूंज ने दिल की धड़कनें बढ़ा दीं। थलसेना के शौर्य के साथ ही गोमती रिवर फ्रंट से नौसेना के जवानों ने अपने साहस, ताकत और तकनीक का प्रदर्शन किया, जो स्क्रीन पर प्रधानमंत्री ने देखा। उन्होंने जवानों की प्रशंसा भी की।

लखनऊ में बुधवार को आयोजित डिफेंस एक्सपो में शौर्य का प्रदर्शन करते पैराट्रूपर। हृदेश चंदेल

मोदी ने खुद भी साधा निशाना

लाइव डेमो से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक्सपो में लगे इंडिया पैवेलियन का निरीक्षण किया। यहां प्रदर्शित किए गए आधुनिक हथियारों की जानकारी ली। इसी बीच एक राइफल हाथ में लेकर वहां बनाई गई वर्चुअल फायर स्क्रीन पर उन्होंने एक के बाद एक कर कई निशाने भी साधे।

एक साथ ही होगी निर्भया के दोषियों को फांसी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▸ हाई कोर्ट ने फांसी पर रोक लगाने के फैसले को बरकरार रखा

▸ सभी दोषियों को एक सप्ताह के अंदर सभी कानूनी उपाय पूरे करने के दिए आदेश

निर्भया के दोषियों की फांसी पर रोक के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा दायर याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने ठुकरा दिया। न्यायमूर्ति सुरेश कैट की पीठ ने निचली अदालत के फैसले को रद करने से इन्कार करते हुए कहा कि दोषियों को फांसी अलग-अलग देने के बजाय एक साथ ही दी जाएगी। पीठ ने सभी दोषियों को निर्देश दिया कि वे एक सप्ताह के अंदर सभी कानूनी उपाय पूरे करें। पीठ ने कहा कि इस समयावधि के बाद प्राधिकारी कानून के हिसाब से कार्रवाई कर सकते हैं।

पीठ ने कहा कि निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला एक समान आदेश से तय हुआ है। ऐसे में पीठ इस विचार से सहमत है कि सभी दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट एक साथ जारी होना चाहिए, न कि अलग-अलग। पीठ ने कहा कि निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने का कोई उचित आधार नहीं है।

17 जनवरी को निचली अदालत ने दोषी मुकेश कुमार सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय कुमार के खिलाफ एक फरवरी के लिए दूसरी बार डेथ वारंट जारी किया था। हालांकि, दोषियों की याचिका पर एक फरवरी के लिए जारी डेथ वारंट पर निचली अदालत ने 31 जनवरी को अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। डेथ वारंट पर रोक लगाने के फैसले को गृह मंत्रालय ने हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए आरोप लगाया था कि दोषी कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे में समाज और कानून के हित के लिए निर्भया के गुनहगारों की फांसी में और विलंब नहीं होना चाहिए। वहीं, दोषी के अधिवक्ता ने दलील दी थी कि सभी दोषियों की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक फांसी की कार्रवाई न की जाए और सभी को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति दी जाए।

2017 में एसएलपी खारिज होने के बाद प्राधिकारी सोते रहे : हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए प्राधिकारियों को भी आड़े हाथ लिया। पीठ ने कहा कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट से विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज होने के बाद डेथ वारंट जारी करने के संबंध में प्राधिकारी सोते रहे और इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया।

न्यायमूर्ति सुरेश कैट की पीठ ने कहा कि सभी जिम्मेदार प्राधिकारी नौ दिसंबर, 2019 तक दोषी अक्षय द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का इन्तजार करते रहे। पीठ ने कहा कि अक्षय की पुनर्विचार याचिका 18 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई। पीठ ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि निर्भया के साथ दोषियों ने युवती के साथ जो कुछ किया वह बेहद अमानवीय, बर्बर, क्रूर और संगीन अपराध था। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर कर रख दिया था। पीठ ने कहा कि हमें ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि दोषियों ने मामले को लंबा खींचा और अपील व पुनर्विचार याचिका दाखिल करने में भी देरी की। पीठ ने कहा दोषी लगातार जीने के अधिकार का हवाला देकर बचते रहने की कोशिश करते रहे हैं।

फांसी होने पर ही मिलेगी खुशी : हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद निर्भया की मां ने कहा कि वह फैसले से संतुष्ट हैं, लेकिन सभी दोषियों को फांसी पर लटकाए जाने के बाद ही उन्हें खुशी मिलेगी।

विधायक कुलदीप सेंगर की तरफ से बहस पूरी

जासं, नई दिल्ली : उन्नाव पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में आरोपित कुलदीप सेंगर की तरफ से बहस पूरी हो चुकी है। अब उसके भाई अतुल की तरफ से बहस शुरू होगी। मामले में गवाहियां पूरी होने के बाद अंतिम बहस शुरू हो गई थी। सीबीआइ की तरफ से बहस होने के बाद अब आरोपित के वकीलों ने बहस की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। इस मामले में जब सभी आरोपितों की तरफ से बहस पूरी हो जाएगी तो अदालत अपना फैसला सुनाएगी। तीस हजारी अदालत के सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने उन्नाव पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में कुलदीप सेंगर व अन्य आरोपितों के खिलाफ आरोप तय किए थे। इस मामले में कुलदीप सेंगर के अलावा उसका भाई अतुल सेंगर, माखी थाने के तत्कालीन प्रभारी अशोक सिंह भदौरिया, एसआइ कामता प्रसाद, सिपाही आमिर खान सहित कुल 10 आरोपित हैं। आरोपपत्र में कहा गया है कि पीड़िता के पिता को मारा गया था। इस दौरान उनके शरीर पर 18 जगह चोट आई। इस वजह से घटना के चौथे दिन पुलिस हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई थी।

इल्तिजा से छिन सकता है एसएसजी सुरक्षा कवच

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

▸ सुरक्षा प्रोटोकाल बार-बार तोड़ने को प्रशासन ने गंभीरता से लिया

▸ उनके मामा तस्सदुक मुफ्ती को भी भेजा गया है नोटिस

सुरक्षा कवच और सुरक्षा प्रोटोकाल को बार-बार तोड़ने वाली इल्तिजा मुफ्ती और उनके मामा तस्सदुक मुफ्ती को मिला सुरक्षा कवच हटाया जा सकता है। इस संबंध में प्रशासन गंभीरता से विचार कर रहा है। इन दोनों को स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप यानी एसएसजी का सुरक्षा कवच मिला है। प्रशासन ने इस संदर्भ में नोटिस भी जारी किया है। एसएसजी सुरक्षा हटने के बाद उन्हें सामान्य श्रेणी का सुरक्षा कवच दिया जा सकता है। वह भी दोनों पर आतंकी खतरे के आकलन के बाद ही मिलेगा।

उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि निदेशालय एसएसजी ने पीडीपी अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा द्वारा बार-बार सुरक्षा प्रोटोकाल तोड़ने और जानबूझकर एसएसजी जवानों के लिए दुविधापूर्ण स्थिति पैदा करने का संज्ञान लेते हुए 23 जनवरी को गृह विभाग को पत्र लिखा है। इसमें निदेशक एसएसजी ने सुरक्षा कवच हटाने का आग्रह किया है। इसके साथ ही लिखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा खुद ही इस सुरक्षा कवच को हटवाना चाहती है। वहीं, तस्सदुक मुफ्ती को भी 10 जनवरी को नोटिस दिया गया है। जिस दिन एसएसजी निदेशालय ने यह पत्र भेजा, उसी दिन इल्तिजा ने आतंकियों संग पकड़े गए डीएसपी देविंदर सिंह का हवाला देते हुए अपनी मां के ट्विटर हैंडल पर लिखा था, कश्मीर में अवैध रूप से हिरासत में रखे जाने और प्रताड़ित किए जाने के बाद अब मुझे दिल्ली में एसएसजी द्वारा तंग किया जा रहा है। एसएसजी सीधे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। मेरी स्वतंत्रता और निजता के अधिकार को सुरक्षा की आड़ में भंग किया जा रहा है।

छह महीने बाद सज्जाद लोन और वहीद पारा सबजेल से रिहा, घर में नजरबंद

राज्य ब्यूरो, जम्मू

▸ एमएलए हॉस्टल में अब सिर्फ 13 नेता ही रह गए हिरासत में

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की घोषणा के छह महीने बाद बुधवार को प्रशासन ने जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कांफ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के युवा नेता वहीद उर रहमान पारा को सबजेल एमएलए हॉस्टल से रिहा कर उनके घरों में नजरबंद कर दिया है। हालांकि, जम्मू-कश्मीर के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों की जल्द रिहाई की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। यह लोग अपनी रिहाई के लिए कोर्ट जाने के मूड में भी नहीं हैं। हिरासत में रखे गए अन्य नेता भी कोर्ट का सहारा लेने से बच रहे हैं, क्योंकि जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) का डर है। अगर पीएसए लगा तो फिर तीन माह तक किसी भी कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी और प्रशासन अधिकतम दो साल तक कैद में रख सकता है।

प्रशासन ने भाजपा को छोड़ विभिन्न सियासी दलों के लगभग 500 नेताओं को एहतियातन हिरासत में लिया या फिर उन्हें नजरबंद किया गया था। हालात सुधरने के बाद इन्हें समय-समय पर रिहा करने की प्रक्रिया शुरू की गई। फिलहाल, सबजेल एमएलए हॉस्टल में 13 वरिष्ठ नेता ही हिरासत में रह गए हैं। इनमें पीडीपी के नईम अख्तर, सरताज मदनी, अब्दुल रहमान वीरी, पीरजादा मंसूर, जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट के शाह फैसल और नेकां के अली मुहम्मद सागर और मुबारक गुल प्रमुख हैं। मंगलवार को भी प्रशासन ने जम्मू-कश्मीर में सुधरते हालात को देखते हुए पीडीपी के पूर्व विधायक एजाज अहमद मीर और ट्रेड यूनियन नेता डॉ. शकील कलंदर को रिहा किया था। हालांकि, जिन नेताओं व अन्य लोगों को रिहा किया गया है, उन सभी से एक बांड लिया गया है। इस बांड में संबंधित लोगों ने कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में सहयोग का पूर्ण यकीन दिलाया है।

फारूक, उमर और महबूबा पर अभी फैसला नहीं : गृह विभाग के सूत्रों की माने तो प्रशासन ने नेकां उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पीडीपी अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबाा मुफ्ती की रिहाई के लिए उनके मामलों की समीक्षा के संदर्भ में कोई कार्रवाई बुधवार दोपहर तक शुरू नहीं की थी। इन दोनों को अलग-अलग सबजेलों में रखा गया है। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला भी चार अगस्त 2019 को हिरासत में लिए गए थे, लेकिन उन्हें 17 सितंबर को पीएसए के तहत बंदी बनाया गया था। फारूक के मामले की समीक्षा पीएसए मामलों पर गठित सलाहकार समिति करेगी। यह समिति उनके पीएसए की अवधि अगर नहीं बढ़ाती है तो सामान्य परिस्थितियों में मार्च के अंत में उनकी रिहाई हो जाएगी। वहीं, राज्य प्रशासन अपने स्तर पर उन्हें पहले भी रिहा कर सकता है।

जमानत पर जेल से रिहा हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर : छात्रा से दुष्कर्म के आरोपित पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद बुधवार को जेल से रिहा हो गए। जेल से बाहर आने के बाद चिन्मयानंद सीधे हनुमत धाम पहुंचे जहां पूजा अर्चना की। उसके बाद मुमुक्षु आश्रम पहुंचे। बुधवार सुबह चिन्मयानंद की जमानत का आदेश उनके वकील ने एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट एडीजे तृतीय किरनपाल सिंह को दिया। जहां से उनकी दो-दो लाख रुपये की दो जमानत तय करते हुए जमानतदारों की सत्यापन रिपोर्ट मांगी गई। रिपोर्ट पहुंचने के बाद शाम करीब चार बजे चिन्मयानंद की रिहाई का परवाना जेल प्रशासन के पास पहुंचा। इसके बाद औपचारिकताएं पूरी कर शाम करीब पांच बजे चिन्मयानंद को रिहा कर दिया गया। मुख्य गेट के बाहर आते ही बाहर खड़े समर्थकों ने जयश्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। उन्हें फूल देने के साथ ही माला पहनाने की होड़ मच गई।

चिन्मयानंद से ब्लैकमेलिंग के आरोपित संजय सिंह ने अपने ऊपर जानलेवा हमले का आरोप लगाया है। संजय ने अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। संजय सिंह ने बताया कि मंगलवार रात वह अपने तीन साथियों के साथ शाहजहांपुर एक शादी समारोह में गया था। वहां से दोस्त को छोड़ने तिलहर जा रहा था। रात करीब 11 बजे तिलहर से पहले एक धार्मिक स्थल के पास पीछे से स्कार्पियो ने कार में टक्कर मार दी। उसने आरोप लगाया कि स्कार्पियो में सवार दो अन्य लोगों ने राइफल निकालकर फायर करने का प्रयास किया। चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने का आरोपित संजय 30 जनवरी को जेल से जमानत पर छूटा था। प्रभारी निरीक्षक तिलहर सुनील अहलावत ने बताया कि डायल 112 ने कार से चार लोगों को बाहर निकाला था। जांच कराई गई तो कार के डिवाइडर से टकराने की बात सामने आई। चारों के मेडिकल में एल्कोहल की पुष्टि हुई है। तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है।

सरोकार

राजस्थान के ट्री-मैन नागौर निवासी हिम्मताराम भांभू को हाल ही में मिला है पद्मश्री सम्मान, 1975 से अब तक साढ़े पांच लाख पौधे रोप चुके हैं, साढ़े तीन लाख बन चुके पेड़

पर्यावरण संरक्षण

हिम्मताराम की मेहनत और हिम्मत को मिला है पद्मश्री सम्मान

मनीष गोधा, जयपुर

राजस्थान के नागौर जिले के रहने वाले हिम्मताराम भांभू 1975 से अब तक साढ़े पांच लाख पौधे रोप चुके हैं। यही नहीं, इनमें से साढ़े तीन लाख पेड़ बन चुके हैं। इसमें छह एकड़ में 11 हजार वृक्षों वाला एक जंगल भी शामिल है। पर्यावरण को समर्पित इस अहम योगदान के लिए उन्हें हाल ही में पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया।

पर्यावरण के प्रति प्रेम उन्हें संस्कारों के रूप में मिला। नागौर जिले के सुखवासी गांव के रहने वाले हिम्मताराम जब 18 साल के थे तो उनकी दादी ने उनसे पीपल का एक पौधा लगवाया था और इस पौधे का पूरा ध्यान रखने के लिए कहा था। उस दिन दादी से मिली प्रेरणा का नतीजा यह है कि 1975 से अब तक हिम्मताराम राजस्थान के कोने-कोने में करीब साढ़े पांच लाख पौधे रोप चुके हैं।

हिम्मताराम ने नागौर के नजदीक हरिमा गांव में छह एकड़ जमीन खरीदी और उस पर 11 हजार पौधे रोपकर एक समृद्ध जंगल तैयार कर दिया। यहां 300 मोर और पशु-पक्षी प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं। जागरण समूह के प्रकाशन नईदुनिया से बातचीत में हिम्मताराम ने कहा, इंसान की जिंदगी अधिक से अधिक 100 वर्ष होती है, लेकिन पेड़ सैकड़ों साल तक रहते हैं। बस इसी सोच और दादी से मिली प्रेरणा ने मुझे यह काम करने के लिए प्रेरित किया। मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने जो कुछ किया, उससे आज सैकड़ों पशु-पक्षियों को रहने के लिए प्राकृतिक वातावरण मिल पाया और मैं पर्यावरण को बचाए रखने में भी एक छोटा सा योगदान दे पाया।

69 साल के हिम्मताराम भांभू का गृह जिला नागौर रेगिस्तानी इलाके की शुरुआत का जिला माना जाता है। अधिकांश इलाके में पानी खारा है। खुद हिम्मताराम जब जंगल बसा रहे थे और इसके लिए नलकूप खुदवाया तो 250 फीट की गहराई पर खारा पानी आ गया। हिम्मताराम ने इस खारे पानी का इस्तेमाल तो किया ही साथ ही बारिश के पानी को खेत में रोककर जमीन में नमी पैदा की और इससे पेड़ उगाए। आज उनका उगाया-बसाया जंगल पर्यावरण का अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए एक संस्थान की तरह है। हिम्मताराम कहते हैं कि खारे पानी में भी पौधे पनप सकते हैं। यह हमने यहां किया है। इस जंगल में हर तरह के पेड़ हैं।

हिम्मताराम बताते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया अपनी पूंजी और पुरस्कारों के रूप में प्राप्त धनराशि से किया। कहते हैं, वन विभाग से पौधे खरीदकर लोगों को देता था और उनसे संपर्क में रहता था। जो पौधे लगाए गए, उनकी वृद्धि के बारे में पूछता रहता था, इसीलिए पौधे पेड़ बन पाए। पर्यावरण के साथ ही पशु-पक्षियों से भी प्रेम बढ़ा। वे मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल से भी जुड़े हैं और अब तक 13 शिकारियों को जेल पहुंचा चुके हैं।

उनके काम को राज्य और केंद्र सरकार ही नहीं विभिन्न संस्थाओं ने भी सराहा है। वर्ष 2015 में राजस्थान सरकार ने उन्हें राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया था। 1999 में पर्यावरण श्रेणी में यूनेस्को द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। उनके बसाए जंगल 'हरिमा' को अब कृषि-वानिकी के एक सफल मॉडल के रूप में देखा जाता है। आसपास के स्कूलों के छात्र यहां प्रेक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आते हैं।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें www.jagran.com/topics/positive-news

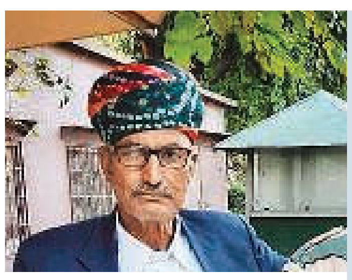

पद्मश्री हिम्मताराम। नईदुनिया

पेशे से मिस्त्री हैं...

हिम्मताराम बहुत अधिक पढ़े-लिखे नहीं हैं। गोगेलाव गांव के स्कूल में कक्षा छह तक पढ़ाई की है। उन्होंने खेती के मशीनीकरण के शुरुआती दौर में ट्रैक्टर की मरम्मत का काम सीखा और कुशल मिस्त्री बन गए। खेती और इस काम से अपना परिवार चलाते हैं। एक बेटा है जो व्यापार करता है। पौधे रोपने और जंगल उगाने का काम वे अपना पैसा लगाकर करते हैं।

राजस्थान के नागौर स्थित हरिमा गांव में हिम्मताराम द्वारा तैयार जंगल। नईदुनिया

दैनिक जागरण

पूर्ण एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है

राष्ट्रीय आकांक्षा की पूर्ति

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए एक स्वायत्त ट्रस्ट के गठन की घोषणा के साथ ही वह प्रतीक्षा पूरी हुई जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही की जा रही थी। संसद में प्रधानमंत्री की ओर से श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन की घोषणा किए जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि इसमें 15 ट्रस्टी होंगे, जिसमें एक दलित समाज से होगा। यह आश्चर्यजनक है कि कुछ दलों ने प्रधानमंत्री की घोषणा पर इस बहाने आपत्ति जताई कि इसके माध्यम से दिल्ली में चुनावी लाभ लेने की कोशिश की गई है। यह विरोध के नाम पर विरोध जताने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह निर्देशित किया था कि तीन माह के अंदर यानी 9 फरवरी के पहले सरकार को राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन कर देना चाहिए और दूसरे, कम से कम अब तो विपक्षी दलों को यह समझ आ जाना चाहिए कि अयोध्या में मंदिर निर्माण की पहल राजनीति या चुनावी प्रश्न नहीं था। यह तो राष्ट्रीय आकांक्षा थी कि अयोध्या में राम के नाम का मंदिर बने। यह अच्छा नहीं हुआ कि इस आकांक्षा की न केवल अनदेखी की गई, बल्कि उसका उपहास भी उड़ाया गया।

चूंकि श्री राम जन्म भूमि तीर्थ ट्रस्ट अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा इसलिए यह भी स्पष्ट है कि मंदिर निर्माण में सरकार की कहीं कोई भूमिका नहीं होगी। यही उचित भी है। वैसे भी भाजपा प्रारंभ से यही कहती रही कि उसका काम अयोध्या में मंदिर निर्माण करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि वहां ऐसा हो। दुर्भाग्य से भाजपा जब-जब यह कहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए तब-तब विपक्ष की ओर से उस पर निशाना साधा जाता था। अंततः एक ऐसी स्थिति बनी कि करीब-करीब सभी दल यह कहने को विवश हुए कि अयोध्या में राम के नाम का मंदिर बनने पर उन्हें आपत्ति नहीं। इस स्थिति का निर्माण इसीलिए हुआ, क्योंकि जनमानस की आस्था के साथ ही हर तरह के साक्ष्य भी यह इंगित कर रहे थे कि जिसे विवादित स्थल कहा जाता था वही राम का जन्म स्थान है। अंततः सुप्रीम कोर्ट भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचा। अब जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है तब अपेक्षित केवल यही नहीं है कि वहां एक भव्य मंदिर निर्मित हो, बल्कि इसकी भी है कि वह राष्ट्रीय एकता-अखंडता और समरसता के साथ उन मूल्यों का प्रसार करे जिनके लिए भगवान राम जाने जाते हैं।

सतर्कता की आवश्यकता

हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य के मोर्चे पर लगातार लापरवाहियां उजागर हो रही हैं जबकि स्वस्थ समाज की परिकल्पना तभी साकार हो सकती है जब लोग स्वस्थ हों। लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ही सरकार हर स्तर पर अस्पताल खोलती है और उसमें सुविधाएं जुटाई जाती हैं, लेकिन स्वास्थ्य से जुड़े मामले में किसी भी स्तर पर बरती गई थोड़ी सी लापरवाही भी लोगों के जीवन पर भारी पड़ जाती है। अस्पताल की प्रयोगशाला में बीमारी की जांच की जाती है जबकि ब्लड बैंक में एकत्र किया गया रक्त रखा जाता है। इस रक्त को जरूरतमंद को दिया जाता है। लोग रक्तदान भी इसी भावना से करते हैं कि उनके रक्त से किसी जरूरतमंद की जान बच सकती है, लेकिन यदि मरीज को अगर गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ाया जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। इस तरह की लापरवाही कतई नहीं की जानी चाहिए, जिस तरह का मामला बिलासपुर में सामने आया है। यहां जिले के निजी अस्पताल में एक प्रसूता को रक्त की जरूरत पर जिला अस्पताल से रक्त लाया गया। जब मरीज को रक्त चढ़ाने से पहले देखा गया कि उस पर एक्सपायरी डेट अंकित है। इस कारण उसे नहीं चढ़ाया गया। इस मामले की जांच करने पर पाया गया कि रक्त की पैकिंग पर गलत तिथि अंकित हो गई थी। सवाल यह है कि इस तरह की लापरवाही कैसे हो गई? इस तरह की शिकायतें अन्य अस्पतालों से भी आती रही है जहां पर किसी की ब्लड सैंपल रिपोर्ट ही गलत बता दी गई या किसी मरीज की रिपोर्ट किसी और मरीज को दे दी गई। पिछले दिनों शिमला में भी एक महिला को इसी तरह की गलत रिपोर्ट के कारण जान गंवानी पड़ी थी। महिला को एचआइवी पॉजिटिव बता दिया। यह खबर सुनने के बाद महिला अवसाद में चली गई और फिर हालत बिगड़ने पर अगले ही दिन उसकी मौत हो गई। हालांकि बाद में पता चला कि रिपोर्ट गलत थी, लेकिन एक लापरवाही ने महिला की जान ले ली। हमें यह समझना होगा कि किसी भी व्यक्ति का जीवन बहुत कीमती है। स्वास्थ्य संस्थानों में लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए जाते हैं और यदि वहां पर किसी तरह की लापरवाही हो जाए तो किसी के जीवन पर भारी पड़ सकती है। लोगों में विश्वास की नींव तभी मजबूत हो पाएगी जब स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग गंभीरता से कार्य करें। लोगों को भी चाहिए कि अस्पताल में जब भी किसी सैंपल इत्यादि की रिपोर्ट ली जाती है तो उस रिपोर्ट पर मरीज का नाम व अन्य जानकारी अवश्य देख लें।

अस्पतालों में ब्लड जांच के दौरान लापरवाही किसी के जीवन को लील सकती है, लिहाजा इसमें और सतर्कता की जरूरत है

हार की मानसिकता से ग्रस्त कांग्रेस

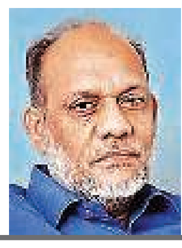

प्रदीप सिंह

कांग्रेसियों को इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि नेहरू-गांधी परिवार अब उसका भविष्य नहीं है

कहते हैं कि आपकी हार उस समय नहीं होती जब आप हारते हैं। हार उस समय होती है जब लड़ने का जज्बा खत्म हो जाता है। चुनाव दर चुनाव कांग्रेस पार्टी और उसका नेतृत्व इसी बात के प्रमाण दे रहा है कि जीतना तो छोड़िए, उसमें लड़ने का ही माद्दा खत्म हो गया है। दिल्ली विधानसभा का चुनाव इस धारणा को एक बार फिर पुष्ट कर रहा है। कांग्रेस अपने विरोधी, भाजपा की एक आंख फोड़ने के लिए अपनी दोनों आंखें फोड़ने को तैयार है। कांग्रेस चुनाव लड़ नहीं रही। लड़ने का स्वांग कर रही है। चिकित्सा विज्ञान कहता है कि कैंसर जैसे रोग से भी व्यक्ति लड़ सकता है अगर उसमें जिजीविषा यानी जीने की इच्छा हो। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, वंशवाद और हकदारी (एनटाइटलमेंट) के कैंसर से ग्रस्त है। कांग्रेस ऐसा संगठन बन गई है जिसमें नेता अपने निजी हित से आगे देखने-सोचने को तैयार ही नहीं हैं। पार्टी की कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया गांधी को देश की कभी चिंता थी, यह कहना कठिन है। अब उनकी चिंता का एक ही विषय है कि संगठन की सत्ता कैसे परिवार के हाथों में रहे। बेटे राहुल गांधी को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया तो कहा कि 'सत्ता जहर' है। फिर भी बेटे को 'जहर' पिला दिया। सत्ता सरकार की हो या संगठन की, वह जिम्मेदारी और जवाबदेही की मांग करती है। राहुल गांधी पिछले सात साल में इसके लिए तैयार नहीं हो पाए हैं। जवाबदेही की मांग होने लगी तो डेढ़ साल में अध्यक्षी छोड़कर किनारे हो गए, पर सोनिया गांधी उन्हें 'जहर' की और खुराक देने की तैयारी कर रही हैं। इस परिवार से जो भी राजनीति में आता है उसे तुरुप का पत्ता बताया जाता है। पहले राहुल गांधी को बताया गया और लोकसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी को। सर्वे छपवाए गए कि प्रियंका असर सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में पड़ेगा, पर हुआ यह कि परिवार का अभेद्य दुर्ग मानी जाने वाली अमेठी भी हाथ से निकल गई। प्रियंका का असर कितना होने वाला था, इसका अंदाज शायद राहुल गांधी को पहले से था और इसीलिए वह वायनाड, केरल चले गए। प्रियंका ने एक काम जरूर किया कि उन्होंने साबित कर दिया कि सोनिया गांधी का उनके बजाय राहुल गांधी को आगे करने का फैसला ठीक था।

बहुत पुरानी कहावत है 'करत-करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान।' राहुल गांधी इस कहावत को गलत साबित करने में पूरी सरह सफल रहे हैं। 16 साल में उनका राजनीतिक सफर जहां से शुरू हुआ था उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ा है। हर हार के बाद वह एक खीझे हुए व्यक्ति की तरह आचरण करते हैं। पार्टी और पार्टी से बाहर उनका माखौल उड़ाने वालों की तादाद कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर तो अब वह एक ट्रोल की तरह व्यवहार करने लगे हैं।

अवधेश राजपूत

सवाल है कि पार्टी के दूसरे नेता यह सब बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? पार्टी में दो वर्ग और तीन गुट हैं। परिवार के तीनों सदस्यों के अपने-अपने गुट हैं। तीनों गुटों के सदस्य एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं। दिसंबर, 2018 में तीन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी तो तीनों गुट अति सक्रिय हो गए। सोनिया और प्रियंका गुट ने मिलकर राहुल गुट को किनारे लगा दिया। मुख्यमंत्री वे लोग बने जिन्हें राहुल विरोधी गुट चाहता था। नतीजा यह हुआ कि मोदी-शाह युग में तीन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने का श्रेय पार्टी अध्यक्ष को नहीं मिला। पार्टी अध्यक्ष के रूप में राहुल की नैतिक और सांगठनिक शक्ति उसी समय खत्म हो गई। पूरी पार्टी को पता चल गया कि पार्टी अध्यक्ष के ऊपर भी एक सत्ता केंद्र है और वही बड़े और निर्णायक फैसले करता है।

जहां तक दो वर्गों की बात है तो उसमें से एक है पार्टी के बुजुर्ग नेताओं का। वे पार्टी पदों पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। इन्हें मालूम है कि इनका समय चला गया है, पर इन्हें अपने बेटे-बेटियों को पार्टी में एडजस्ट करना है। इस मुद्दे पर इनमें बड़ा एका है। जनार्दन द्विवेदी ने बुद्धिमत्तापूर्ण काम यह किया कि अपने बेटे के स्वतंत्र फैसला लेने में रोड़ा नहीं अटकाया। दूसरा वर्ग युवा नेताओं का है। जिन्हें भविष्य की राजनीति करनी है। सवाल है कि ये लोग इस पारिवारिक प्रहसन को क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? मां जाएगी तो बेटा आएगा। बेटा जाएगा तो मां आएगी। कभी अगर दोनों को हटना पड़े तो बेटी तैयार है। दामाद और दूसरे सदस्य प्रतीक्षा सूची में हैं। दरअसल इन युवा नेताओं में जोखिम लेने का साहस नहीं है। ये सब एक संरक्षित वातावरण में पले बढ़े हैं। ज्यादातर को जो मिला है बिना ज्यादा संघर्ष के मिला है। इन्होंने कोई आंदोलन किया नहीं, कोई लड़ाई लड़ी नहीं, कभी जेल गए नहीं और न ही पुलिस की लाठियां खाईं, जो तमाम गैर कांग्रेस दलों के नेताओं और पार्टियों ने किया। ये राजनीति के सुकुमार हैं। इन्हें अभी तक जो मिला वह माता-पिता से मिला या फिर गणेश परिक्रमा से।

क्या कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता? ऐसा नहीं है। उम्मीद पर दुनिया कायम है, पर असल मुद्दा तो यह है कि क्या कांग्रेस के लोगों को उम्मीद है? यह तय मानिए कि जैसा चल रहा है वैसा चलता नहीं रह सकता और चलता रहा तो कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। तो फिर इसकी शुरुआत कैसे हो? जिन्हें भविष्य में भी कांग्रेस में रहकर राजनीति करना है उन्हें पार्टी के अतीत की ओर देखना चाहिए और कुछ घटनाओं की ओर भी। कांग्रेसजन सीताराम केसरी को भूले नहीं होंगे। कांग्रेस के समर्पित नेता-कार्यकर्ता थे। कभी निजी हित को पार्टीहित पर तरजीह नहीं दी, पर उन्हें अध्यक्ष पद से किस तरह हटाया गया? क्या पार्टी के युवा नेताओं में परिवार के किसी नेता को इस तरह पद से हटाने की हिम्मत है? कहने का यह अर्थ नहीं कि वैसा ही करना जरूरी है, लेकिन यदि यह इरादा भी जाहिर कर दिया कि ऐसा कर सकते हैं तो बदलाव आ जाएगा।

यदि कांग्रेस को देश का मुख्य विपक्षी दल बने रहना है तो दो चीजों से छुटकारा पाना होगा। पहला, पराजय की मानसिकता से, क्योंकि इस मानसिकता से ग्रस्त व्यक्ति किसी भी बिंदु पर स्वयं सोच-विचार करने में असमर्थ होता है। इसके साथ ही कांग्रेसियों को इस वास्तविकता को स्वीकार करना होगा कि नेहरू-गांधी परिवार उसका अतीत था। यह मान लेने में भी हर्ज नहीं कि अतीत सुनहरा था, पर अब यह परिवार उसका भविष्य नहीं है। यह भूत बेताल के कंधे से उतर जाए, इसी में कांग्रेस की भलाई है।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

उपयोगी बने फसल बीमा योजना

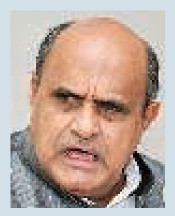

केसी त्यागी

सरकार को यह देखना होगा कि बीमा कंपनियों को किसानों के बीच साख कायम करने की जरूरत है

हाल में पेश की गई आर्थिक समीक्षा में यह स्वीकारोक्ति की गई है कि फसल बीमा योजना किसानों को बहुत ज्यादा रास नहीं आ रही। समीक्षा में यह भी कहा गया है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने जैसे लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में क्रेडिट, इंश्योरेंस कवरेज तथा सिंचाई की सुविधाओं आदि जैसी बुनियादी चुनौतियों का गंभीरता से समाधान किए जाने की त्वरित आवश्यकता है। समीक्षा में 50 प्रतिशत किसानों को फसल बीमा के दायरे में लाए जाने का भी उल्लेख है। आम बजट में फसल बीमा योजना के लिए 15,695 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो गत वर्ष की तुलना में 1695 करोड़ रुपये अधिक है। यह दर्शाता है कि सरकार इस योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर गंभीर है। हालांकि पिछले तीन वर्षों के दौरान किसानों के बीच इस योजना को लेकर पनपी उदासीनता चिंताजनक है।

जब जनवरी 2016 में 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' शुरू हुई तब किसानों में भारी उत्साह का संचार हुआ था, लेकिन धीरे-धीरे उसे लेकर नकारात्मक तथ्य सामने आने लगे। राहत की बात यह है कि केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक सात सदस्यीय समूह गठित किया है। यह समूह बीमा योजना की समीक्षा करके इसे और बेहतर बनाने की दिशा में सुझाव देगा। यह ध्यान रहे कि कई राज्यों द्वारा मौजूदा योजना में बदलाव की मांग की जा चुकी है। कई राज्य सरकारों द्वारा इस योजना से दूरी बनाने के कारण भी केंद्र को इस योजना में संशोधन के लिए उन्मुख होना पड़ा। पिछले तीन वर्षों से फसल बीमा योजना में बीमित किसानों की संख्या और खेती का दायरा लगातार घटा है। प्रीमियम के रूप में सरकारी-गैर सरकारी बीमा कंपनियों के मुनाफे में तेज बढ़ोतरी भी योजना की सफलता पर सवाल खड़े करती है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016-17 में कंपनियों को 21,892 करोड़ रुपये बतौर प्रीमियम मिले जबकि 16,659 करोड़ रुपये के क्लेम दिए गए। इसी तरह 2017-18 में 25,461 करोड़ रुपये का प्रीमियम जमा हुआ और 21,680 करोड़ रुपये का क्लेम किसानों को भुगतान किया गया। इससे स्पष्ट है कि योजना से कंपनियों को फायदा हुआ। वहीं किसानों को अपेक्षित लाभ नहीं हुआ। एक रिपोर्ट के अनुसार उप्र, मप्र, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा बंगाल द्वारा 2017-18 के प्रीमियम का अपना हिस्सा अभी तक अदा नहीं किया गया है। इससे इतर बिहार एवं पंजाब सरकार इस योजना के बजाय अपनी ही बीमा योजना संचालित कर रही हैं। जून 2018 तक बिहार में अन्य बीमा योजना समेत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही थी, लेकिन मुआवजे की राशि कम होने और सभी किसानों को इसका लाभ न मिल पाने की वजह से राज्य में फसल सहायता योजना की शुरुआत की गई जिसके तहत फसल की वास्तविक उपज दर में 20 फीसद तक की कमी होने पर 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 15 हजार और 20 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 20 हजार रुपये दिए जाने का प्रावधान है।

प्राकृतिक आपदाओं, कीट, रोगों के परिणामस्वरूप अधिसूचित फसल में से किसी भी विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लोकप्रिय रही। इस योजना के तहत किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए केवल दो प्रतिशत एवं सभी रबी फसलों के लिए 1.5 फीसद का एक समान प्रीमियम का भुगतान किए जाने का प्रावधान है। शेष प्रीमियम केंद्र व राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन किए जाने की व्यवस्था है। किसानों की आमदनी दोगुनी करने की दिशा में इस योजना का अहम योगदान भी अपेक्षित था। किसानों की आय को स्थायित्व प्रदान करने, कृषि में नवाचार एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने, इस क्षेत्र में ऋण के प्रवाह सुनिश्चित करने आदि की दिशा में यह कल्याणकारी भी है और खेती को घाटे से उबारने की दिशा में उपयोगी भी। काफी समय से मांग हो रही है कि किसानों के लिए यह बीमा योजना स्वैच्छिक हो और अधिक प्रीमियम वाली फसलों को इससे बाहर रखा जाए। कुछ संगठनों की यह भी मांग है कि पूरा प्रीमियम सरकार अदा करे। वैसे भी यह ठीक नहीं कि ऐसी योजना से निजी कंपनियां मालामाल हों। यह जरूरी है कि इस योजना का उचित क्रियान्वयन हो। चूंकि यह योजना खेती को लाभप्रद बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेश के लिए बनाई गई थी, तो इसे निजी कंपनियों के मकड़जाल से बचाने की जरूरत है।

तमाम प्राकृतिक आपदाएं किसानों की परेशानियां बढ़ाती रही हैं। इससे इतर फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिल पाना भी एक समस्या है। इससे किसानों की आय में वृद्धि तो दूर स्थिरता भी नहीं बन पाती है। हालांकि ऐसे दुष्प्रभावों से किसानों की रक्षा के प्रयास में 1972 में ही फसल बीमा योजना चलाई गई थी। 1985 में व्यापक फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। यह पहली राष्ट्रव्यापी योजना थी। 1999 तक यह योजना 15 राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों में मूर्त रूप भी लेने लगी, लेकिन यह मुख्य रूप से कर्जदार किसानों के लिए थी। 1999 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भी चलाई गई, लेकिन इन योजनाओं में किसानों के बड़े समूहों की कोई दिलचस्पी नहीं रही। आंकड़ों पर गौर करें तो 2012-13 में देश के मात्र सात प्रतिशत किसानों ने अपनी एक फसल की बीमा कराया था। 2002-2003 में यह आंकड़ा चार प्रतिशत हो गया। एक अध्ययन की मानें तो लगभग 66 प्रतिशत किसानों को बीमा योजनाओं की जानकारी नहीं है। स्पष्ट है कि बीमा कंपनियों को किसानों के बीच अपनी साख कायम करने की जरूरत है। योजनाओं की संरचना किसानोन्मुखी हो, नुकसान की भरपाई अविलंब हो तथा प्रीमियम के अनुपात में भुगतान की राशि उत्साहवर्धक हो।

(लेखक जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

दया भाव

दया को मानवीय गुणों में सर्वोत्तम की संज्ञा दी जाती है। वास्तव में यह वह भाव है जो मानवीयता को पोषित करता है। दया दैवीय गुण है। दया के बिना मनुष्यता परिभाषित नहीं की जा सकती। मानव जीवन में दया के कारण ही मानवता का भाव संरक्षित है। जो दयालु नहीं, उसमें मनुष्यता नहीं है, उसमें मानवता भी कहां है? किसी के प्रति द्रवित हो जाना। उसकी पीड़ा का अनुभव करना। यही तो दया का प्रभाव है। यह भाव ही है जो हमारे हृदय को स्पंदित कर देता है। हमें परोपकार के लिए उद्वेलित करता है। हमें किसी की सुरक्षा के लिए जागृत करता है। दयालुता और निर्दयता के भावों में ही किसी के मनुष्य और दानव होने के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। दयालुता आपको श्रेष्ठ बना देती है। वहीं निर्दयता मनुष्य के मलिन मन को प्रदर्शित करती है। हमारा समाज आपसी सहयोग और स्नेह से ही दीर्घजीवी बना हुआ है। इसके मूल में भी दया का भाव सुरक्षित है। अगर इसके मूल को विखंडित किया जाएगा तो समाज का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा।

दया का गुण मां से शिशु में संस्कारित होता है। शिशु को तरुण, युवक बनने पर ये भाव जितना सबल होगा उसकी श्रेष्ठता उतनी ही अधिक होगी। दया का भाव विनम्रता को पोषित करता है। दया जीव मात्र के प्रति स्नेह को प्रेरित करती है। ये गुण हमें किसी के भी अहित से रोकता है। समाज के भीतर अगर ये गुण संचारित हो जाएं तो हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। सामाजिक वैमनस्य के मूल में कहीं न कहीं दया के भाव का लुप्त होना है। राष्ट्र की अखंडता के लिए सामाजिक तानेबाने को मजबूत रखना अनिवार्य है। आपसी सौहार्द ही समाज की एकता का अनिवार्य तत्व है और इस तत्व के पीछे दया, करुणा जैसे गुणों का भाव। दया के लक्षण मनुजता के द्योतक हैं। दया का गुण शास्त्रों एवं पुराणों में भी पूजित है। दया देवत्व को प्राप्त करने का मार्ग है। इस मार्ग का पथिक श्रेष्ठ जीवन यापन करता है।

ललित शौर्य

जान का दुश्मन बनता खानपान

रवि शंकर

कभी-कभार फास्टफूड खाने में भले कोई बुराई न हो, लेकिन इस पर निर्भरता कई बीमारियों का कारण बन सकती है

व्यस्त जीवनशैली के साथ ही जंकफूड-फास्टफूड का चलन भी तेजी से बढ़ा है। आपाधापी में लोग पोषक खाद्य पदार्थ न खाकर उस जंकफूड को तरजीह दे रहे हैं जिसमें जरूरी विटामिन और मिनरल्स का अभाव होता है। इससे तमाम बीमारियों का जोखिम बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हमें यह समझना होगा कि जीवन को सिर्फ आसान बनाने वाली चीजों की तलाश ही करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि जीवन को स्वस्थ बनाने वाली चीजों को प्राथमिकता देना भी जरूरी है। मजबूरन जंकफूड का कभी-कभार उपभोग कर लेने में कोई खराबी नहीं, लेकिन पूरी तरह इस पर निर्भरता अवश्य खतरनाक है। आप शायद इनके लेबल पढ़कर खुद को संतुष्ट कर लेते होंगे जहां यह लिखा होता है कि इसमें ट्रांसफैट, प्रिजर्वेटिव या मोनोसोडियम ग्लूटामेट नहीं मिलाया गया है, लेकिन इनमें ऐसे कई और भी तत्व होते हैं जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक होते हैं।

मौजूदा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड-पैकेजिंग व लेबलिंग रेगुलेशंस, 2011 बेहद कमजोर और अप्रभावी है। यहां तक कि नमक जैसे बुनियादी तत्व के बारे में भी अनिवार्यतः जानकारियां नहीं दी जातीं। ऐसे परिवारों की संख्या भी कम नहीं है जो पूरी तरह से पैक्ड फूड या रेडी टू ईट फूड पर निर्भर हो चुके हैं। अधिकांश घरों में बच्चे इनके अलावा कुछ और खाना भी नहीं चाहते हैं। इसमें उनका कोई कसूर भी नहीं है। इसमें गलती बच्चों से ज्यादा हमारे माहौल की है जिसमें उन्हें यही रास आता है। बड़ी संख्या में बच्चे और युवा जरूरत से ज्यादा कैलोरी ले रहे हैं और बचपन या युवावस्था में ही मधुमेह, बीपी, गठिया और यहां तक कि हृदय रोग जैसी बीमारियों के शिकंजे में फंस रहे हैं। पहले ये सभी बीमारियां अमूमन बड़ी उम्र में होती थीं।

भारत में वैश्विक खाद्य मानकों का पालन बहुत कम ही होता है, ऐसा फूड सोर्स मॉनिटरिंग कंपनी 'फूड सेंट्री' का कहना है। अधिकांश खाद्य पदार्थ जिनमें मानकों का उल्लंघन होता है, वे या तो कच्चे होते हैं या उन्हें प्रोसेस्ड किया गया होता है। यह मसला इसलिए बेहद गंभीर है, क्योंकि मिलावटी खाने का इंसानी सेहत पर असल प्रभाव अब भी पूरी तरह ज्ञात नहीं हो पाया है। कई प्रकार की खाने से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं और दुनिया भर में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में इनका अनुपात बढ़ता जा रहा है।

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की एक रिपोर्ट कहती है कि बीते एक दशक में पैकेटबंद खानपान की चीजों की बिक्री में करीब 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। साथ ही इनकी पैकिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक से भी पर्यावरण प्रदूषण का जोखिम बढ़ता जा रहा है। विदेश से आए फास्टफूड ने हमारे देश पर जैसे कब्जा कर लिया है, जबकि भारतीय खाने में पहले से ही व्यापक विविधता कायम है। विभिन्न क्षेत्रों में तरह-तरह के पकवान भारत के लोगों के इतिहास और उनकी संस्कृति का आईना होते हैं, फिर भी हम फास्टफूड-जंकफूड को अपना रहे हैं।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

विभाजनकारी राजनीति

'असामान्य आचरण की पराकाष्ठा' शीर्षक लेख के तहत राजीव सचान ने शाहीन बाग में जो सीएए, एनपीआर और एनआरसी को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, उससे वहां आसपास के क्षेत्र के लोगों को जो असुविधा हो रही, उसका विश्लेषण किया है। वैसे तो लोकतंत्र में हर किसी को हक है कि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करे, लेकिन हमारे देश में सरकार के प्रति नाराजगी के लिए विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं, उससे आम लोगों को ही परेशानी होती है और आर्थिक नुकसान भी देश को ही होता है। सरकारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभिव्यक्ति की आजादी का घातक इस्तेमाल तब तक होता रहेगा, जब तक देश में हर मुद्दे पर संकीर्ण राजनीति होती रहेगी और इस आजादी का दोहन करने वालों के लिए सख्त कानून नहीं बनाया जाता। अब तो सीएए के विरोध को लेकर जो एक खुलासा हुआ है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय को यह जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश में सीएए के खिलाफ हाल ही में जो हिंसक प्रदर्शन हुए उनका पीएफआइ के साथ आर्थिक लेनदेन था, इसने सीएए विरोध को शक के घेरे में ला दिया। शाहीन बाग में जो नागरिकता संशोधन के लिए विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसके संदर्भ में जो एक वीडियो सामने आया है उसमें एक युवक कह रहा है कि यहां महिलाओं को बैठने के पैसे दिए जा रहे हैं और ये महिलाएं शिफ्ट में काम कर रही हैं और एक निश्चित संख्या में अपनी मौजूदगी सुनिश्चित रखती हैं। सरकार, खुफिया एजेंसियों को इसकी निष्पक्ष और उचित जांच गंभीरता से करनी चाहिए, क्योंकि अगर इस युवक द्वारा कही गई बातों में जरा भी सच्चाई है तो निश्चित ही विपक्ष की भूमिका संदेह के घेरे में है। ऐसे में उसका असली चेहरा सामने लाना बेहद जरूरी है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

वायरस से निपटने के हों पुख्ता इंतजाम

चीन के वुहान में फैले कोरोना वायरस के खतरे ने दुनिया को चौंका दिया है। दुनिया भर से कोरोना वायरस के मामले लागातार सामने आ रहे हैं। यह वायरस दिसंबर में चीन से शुरू हुआ था। इसके संक्रमण से बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना, गले में खराश जैसी समस्या उत्पन्न होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने इसे अंतरराष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है, जिससे दुनिया के कई देश सतर्क हो गए हैं और पड़ोसी देश होने के नाते भारत पर भी इस वायरस का खतरा मंडरा रहा है। कुछ लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि भी हो चुकी है। जब भी कोई वायरस फैलता है तो तत्काल उसका तोड़ पता लगा पाना संभव नहीं होता है, इसलिए बचाव ही इसका साधारण सा उपाय है। भारत में कोरोना से लोग दहशत में हैं, इसलिए जुकाम, सिरदर्द जैसी समस्याओं से पीड़ित मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ रही है। फिलहाल कोरोना वायरस से निपटने के लिए कोई टीका या वैक्सीन नहीं विकसित हुआ है। पहले भी कई ऐसे खतरनाक वायरसों ने दुनिया को डराया है और आगे भी ऐसे वायरस आते रहेंगे। इसलिए ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र को सदैव सावधान रहने की जरूरत है।

प्रशांत यादव, दिल्ली

निजीकरण का विकल्प तलाशें

अबकी बार बजट में सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआइसी में विनिवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह ठीक है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कई कंपनियां अपनी लचर कार्यपद्धति के कारण जर्जर हालत में पहुंच चुकी हैं, जिनमें महानगर टेलीफोन निगम, भारत संचार निगम, एयर इंडिया और कई अन्य कंपनियां शामिल हैं। सरकार धीरे-धीरे इन सबको प्राइवेट सेक्टर में लाना चाह रही है। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में अंधाधुंध निजीकरण को स्वीकार करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि एकाधिकार के बाद प्राइवेट सेक्टर भी मनमानी पर उतर सकता है। उसका मुख्य लक्ष्य निजी हित और ज्यादा मुनाफा होता है। सरकारी नियंत्रण में होते हुए भी कई कंपनियां जैसे भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, जीवन बीमा निगम आदि अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं तो दूसरी क्यों नहीं। जरूरत सिर्फ उनके मैनेजमेंट पर ध्यान देने की है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

चंद्र प्रकाश शर्मा, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

14.1 प्रतिशत था आपराधिक छवि के उम्मीदवारों का आंकड़ा वर्ष 2008 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में। वर्ष 2013 में यह 16.2 प्रतिशत हो गया जो 2015 में 16.9 फीसद और इस बार 19.8 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

आजकल

छूट नहीं रहा दागी प्रत्याशियों से पीछा

दिल्ली विधानसभा के लिए चुने जाने की दौड़ में जो 672 उम्मीदवार शामिल हैं, इनमें 20 प्रतिशत से ज्यादा पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह बात किसी छानबीन से पता नहीं चली है, बल्कि यह बात इन्होंने खुद बताई है। दरअसल पिछले एक दशक के दौरान राजधानी दिल्ली में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में, इस बार सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार हैं। खुद से घोषित इन दागी उम्मीदवारों में से करीब 20 प्रत्याशी तो ऐसे हैं जो कम से कम एक मामले में दोषी पाए जा चुके हैं

नौशाबा परवीन
स्वतंत्र टिप्पणीकार

आगामी आठ फरवरी को होने जा रहे दिल्ली विधानसभा चुनाव के संदर्भ में एक तथ्य सामने आया है कि करीब 20 फीसद उम्मीदवार आपराधिक छवि के हैं। यह तथ्य एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा चुनाव आयोग के समक्ष इन प्रत्याशियों द्वारा दाखिल किए गए शपथपत्रों की पड़ताल से सामने आया है। एडीआर का यह भी कहना है कि पिछले एक दशक के दौरान इस चुनाव में करोड़पतियों, उच्च शिक्षितों, महिलाओं व बुजुर्ग प्रत्याशियों का हिस्सा भी सबसे ज्यादा है।

वर्ष 2008 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में दागी प्रत्याशियों का प्रतिशत 14.1 था और तब से हर चुनाव में इसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। वर्ष 2013 में यह प्रतिशत बढ़कर 16.2 हुआ जो 2015 में 16.9 प्रतिशत हो गया और 2020 में यह 19.8 प्रतिशत तक पहुंच गया है। हालांकि सभी प्रत्याशियों पर गंभीर अपराध दर्ज नहीं हैं, लेकिन गंभीर अपराध के आरोपी प्रत्याशियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है जो वर्ष 2008 में 4.1 प्रतिशत था, वर्ष 2013 में 11.7 प्रतिशत, वर्ष 2015 में 11 प्रतिशत और 2020 में 15.5 प्रतिशत हो गया है। वैसे यह राजनीति के अपराधीकरण के राष्ट्रीय ट्रेंड से कुछ अलग नहीं है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में दागी उम्मीदवारों की हिस्सेदारी दशक में सबसे ज्यादा थी, इसलिए वर्तमान लोकसभा में भी 539 सांसदों में से 233 ऐसे हैं जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है यानी इन्होंने अपने ऊपर अपराधिक मामले दर्ज होने घोषित किए हैं।

यह सब इसके बावजूद हो रहा है कि इस अवधि के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के उद्देश्य से अनेक सराहनीय प्रयास किए हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि उन्हें लागू नहीं किया गया और नतीजा सिफर रहा, जैसा कि दागी प्रत्याशियों की बढ़ती संख्या से स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने अतीत में जो कुछ प्रमुख आदेश इस संदर्भ में दिए, वे इस प्रकार हैं कि यदि किसी जन-प्रतिनिधि को अदालत से दो वर्ष या उससे अधिक की सजा हो जाए तो तुरंत प्रभाव से उसकी सदन सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही मार्च 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि राजनीतिक नेताओं के खिलाफ जो विभिन्न अदालतों में आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, उनका निपटारा एक वर्ष के भीतर हो जाना चाहिए। लेकिन इस पर अमल न हो सका। हालांकि इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने सियासत को अपराधियों से मुक्त करने के लिए अपने प्रयासों को नहीं छोड़ा है। उसके इन प्रयासों में एक यह भी शामिल है कि नवंबर 2017 में उसने ना केवल यह जानकारी तलब की थी कि तब यानी 2014 से 2017 तक नेताओं के विरुद्ध कितने नए मामले दायर किए गए हैं और अदालतों में उनकी स्थिति यानी स्टेटस क्या है, बल्कि केंद्र सरकार से यह भी कहा कि वह नेताओं पर चल रहे आपराधिक मुकदमों को जल्द निपटाने के लिए विशेष अदालतें गठित करने की योजना बनाए। यह भी नहीं हुआ। स्थिति यह है कि अब जो दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं, उनमें हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, दुष्कर्म व महिलाओं के विरुद्ध अन्य अपराधों के आरोपी विधायक बनने के इच्छुक हैं। इस वर्ष 32 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन पर महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें एक दुष्कर्म का भी है। यही नहीं, चार प्रत्याशियों के विरुद्ध हत्या के प्रयास के मामले भी हैं। आठ उम्मीदवारों के खिलाफ नफरत फैलाने व भड़काऊ भाषण देने के मामले दर्ज हैं।

लगभग 20 प्रतिशत दागी प्रत्याशियों का आंकड़ा इस तथ्य को ओझल कर देता है कि अधिकतर दागी उम्मीदवार बड़ी पार्टियों से संबंधित हैं, जैसे 60 प्रतिशत आम आदमी पार्टी से, 39 प्रतिशत भाजपा से और 27 प्रतिशत कांग्रेस से। अरविंद केजरीवाल पर भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस संबंध में आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल सहित उसके प्रत्याशियों के विरुद्ध जो मामले दर्ज हैं वे केंद्र सरकार की राजनीतिक साजिश के कारण हैं। 'आप' की दिल्ली इकाई के संयोजक गोपाल राय का कहना है, 'यह बात दिल्ली की जनता से छुपी नहीं है कि वर्ष 2015 में हमारे सत्ता में आने के साथ ही केंद्र हमारे पीछे पड़ा हुआ है। उसने केजरीवाल व अन्य मंत्रियों जैसे सत्येंद्र जैन व कैलाश गहलोत और अनेक 'आप' विधायकों के खिलाफ झूठे मुकदमे कायम किए हैं। केजरीवाल के घर पर छापा मारा, पर हर प्रयास नाकाम रहा, क्योंकि अदालत में कोई केस न टिक सका।'

दिल्ली विधानसभा के लिए जो पिछले चार चुनाव हुए हैं, उनकी तुलना में इस बार सबसे ज्यादा करोड़पति भी चुनाव लड़ रहे हैं। कुल प्रत्याशियों में से 36 प्रतिशत करोड़पति हैं। इनमें तीन बड़ी पार्टियों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। कांग्रेस 83 प्रतिशत, आम आदमी पार्टी 73 प्रतिशत और भाजपा 70 प्रतिशत। सबसे रईस प्रत्याशी हैं 'आप' के धर्मपाल लाकड़ा जो मुंडका से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास 292 करोड़ रुपये मूल्य के एसेट्स हैं। लाकड़ा के बाद जो दूसरे नंबर के रईस प्रत्याशी हैं उनके एसेट्स इससे लगभग चार गुणा कम हैं। आरके पुरम से 'आप' की उम्मीदवार प्रमिला टोकस के पास 81 करोड़ रुपये मूल्य के एसेट्स हैं, लेकिन इस बार 2008 के बाद से महिला प्रत्याशी (11.8 प्रतिशत) सबसे ज्यादा हैं। कांग्रेस की 15 प्रतिशत प्रत्याशी महिला हैं, जबकि 'आप' की 13 प्रतिशत और भाजपा की नौ प्रतिशत।

इस बार युवा प्रत्याशी यानी 30 वर्ष से कम उम्र के मात्र 8.5 प्रतिशत हैं। 27.5 प्रतिशत 31 से 40 वर्ष आयु वर्ग में हैं और शेष 41 वर्ष से ऊपर के हैं। दूसरे शब्दों में बुजुर्ग प्रत्याशी भी सबसे ज्यादा इसी बार हैं। एक अच्छी बात इस बार यह है कि उच्च शिक्षित प्रत्याशियों का हिस्सा बढ़ा है। वर्ष 2008 में जहां स्नातक प्रत्याशियों का प्रतिशत 32 था, वह अब बढ़कर लगभग 45 प्रतिशत हो गया है, लेकिन दागी व करोड़पति प्रत्याशियों में निरंतर हो रहे इजाफे से यही प्रतीत होता है कि डंडे व पैसे को अब भी चुनावों से अलग नहीं किया जा सका है जिससे शरीफ व गरीब के लिए विधायक बनना अभी सपना ही है। - ईआरसी

अवधेश राजपूत

चुनाव सुधार पर ठोस पहल का वक्त

लालजी जायसवाल

चुनाव सुधार की अपेक्षा दशकों से की जा रही है। आपके जेहन में यह प्रश्न कौंध रहा होगा कि आखिर चुनाव सुधार पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया? जब चुनाव नजदीक आए या चुनावी प्रक्रियाओं के चलते इस समय ज्यादा ही चुनाव में सुधारात्मक कदम उठाने की बात की जाती है। अब प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इन मसलों का हल चुनाव से पहले क्यों नहीं निकाल लिया जाता? इसका उत्तर यह कदापि नहीं कि चुनाव आयोग शक्तिहीन हो चुका है। आज भी चुनाव आयोग में संपूर्ण शक्तियां विद्यमान हैं। चुनाव सुधार के महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान दें तो बीती सदी के आखिरी दशक में मुख्य चुनाव आयुक्त रहे टीएन शेषन का वह दौर था जब चुनाव सुधार पर विशेष कदम उठाए गए। लेकिन कुछ दशकों से यह देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तो सदैव चुनाव में सुधार की बात करता है, लेकिन राजनीतिक दल इसमें पर्याप्त सहयोग करते नहीं दिख रहे हैं।

शायद यह कयास लगाना गलत नहीं होगा कि चुनाव सुधार से राजनीतिक दलों को यह भय सता रहा होगा कि उनके मनमानी और आपराधिक संलिप्तता तथा धन के अथाह उपयोग पर रोक लग जाएगा। वैसे भी भारत में होने वाले चुनावों में बड़ी मात्रा में धन की जरूरत एक कड़वी सच्चाई है, जिसके लिए निर्धारित खर्च की सीमा निरर्थक साबित होती रही है और जिसका शायद ही कभी पालन किया जाता है। नतीजन आज एक शिक्षित और ईमानदार नागरिक के लिए चुनाव लड़ना तथा जीतना नामुमकिन सा होता जा रहा है। इससे ही राजनीतिक हलकों में भ्रष्टाचार मजबूती से अपनी जड़ें जमा लेता है, जो अंततः सारी व्यवस्था को अपनी लपेटे में लेकर भ्रष्ट और कमजोर बना देता है।

चुनाव तो प्रजातंत्र का आधार है, और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता ही प्रजातांत्रिक वैधता का केंद्र है। चुनाव के संरक्षक को आज स्वयं की स्वायत्तता की रक्षा की आवश्यकता आन पड़ी है, इस पर तुरंत ही कोई कदम उठाए जाने की दरकार है। अगर, चुनाव में खर्च की बात की जाए तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक उम्मीदवार को चुनाव प्रचार और यातायात वगैरह पर लाखों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। चुनाव आयोग के दिशानिर्देश के अनुसार एक उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए अधिकतम 70 लाख रुपये खर्च कर सकता है। हालांकि कई छोटे राज्यों में यह सीमा 28 लाख रुपये तक ही है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा और सिक्किम में खर्च की अधिकतम सीमा 54 लाख रुपये है। दिल्ली के लिए यह सीमा 70 लाख रुपये और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 54 लाख रुपये है। पिछले कुछ वर्षों में कानून-सम्मत और असल खर्चों के बीच अंतर काफी बढ़ा है।

राजनीतिक दल न केवल नियमों का उल्लंघन करते रहे हैं, बल्कि नियम-कानून के साथ खिलवाड़ भी करते रहे हैं। अगर हम चुनाव में धन कुबेरों के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो पता चलता है कि वर्ष 2014 के चुनाव में 27 फीसद यानी 2,208 प्रत्याशी करोड़पति थे। पर इससे पहले वर्ष 2009 के चुनाव में कुल 16 प्रतिशत ही करोड़पति की श्रेणी में थे। इस आंकड़े के बढ़ते क्रम से जाहिर है कि वर्तमान स्थिति क्या होगी। बहरहाल, चुनाव सुधारों की प्रक्रिया का मुख्य फोकस लोकतंत्र के मूल अर्थ को व्यापक बनाना और इसे नागरिकों के अधिक अनुकूल बनाना है।

यह सही है कि चुनाव भ्रष्टाचार का बड़ा स्रोत बन चुका है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से करोड़ों की नकदी जब्त होना परंपरा बन गई है। चुनाव लड़ने के लिए तय की गई रकम से कहीं अधिक धन उम्मीदवार वास्तव में खर्च करते हैं। तमाम तरह से अवैध धन का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीदवार खर्च की सीमा बढ़ाने की मांग करते हैं। अगर कालेधन के इस्तेमाल को रोकना है तो निर्वाचन आयोग को तर्कसंगत तरीके से सोचना होगा, क्योंकि लोकतंत्र अब धीरे-धीरे अमीरों का तंत्र बनता जा रहा है, इसमें गरीब या ज्यादा धन खर्च न कर पाने वाले उम्मीदवार इन धन कुबेरों के आगे पानी के बुलबुले प्रतीत हो रहे हैं।

(लेखक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शोध छात्र हैं)

खरी-खरी

जनता के साहब और उनके कारनामे

सुनील जैन 'राही'

साहब का ट्वीट। फिर किसी ने मानो दुखती रग पर हाथ रख दिया। दुखती रग को न छेड़े, तब तक साहब अजगर भूमिका में रहते हैं। साहब दो प्रकार के होते हैं। एक खुद साहब बनते हैं। खुद साहब बनने के लिए पढ़ा-लिखा होना जरूरी है। दूसरे, जनता द्वारा बनाए जाते हैं। इन साहब का पढ़ा-लिखा होना जरूरी नहीं। ये जनता द्वारा साहब बनाए जाने पर मोगैंबो की तरह खुश होते हैं। खुद बने साहब, जनता द्वारा बनाए साहबों के आगे-पीछे घूमते हैं।

बहरहाल, दूसरे वाले साहब ऐसा दिखाते हैं कि वे जनता के लिए मर मिटने को हमेशा तैयार हैं। बिजली खराब हो तो वे खंभे पर चढ़ जाते हैं। वे जानते हैं, वे ठीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन जनता समझती है कि साहब बिजली ठीक कर ही देंगे। जैसे ही दो सीढ़ी चढ़ते हैं, बिजली विभाग का कर्मचारी उनसे औजार ले लेता है। साहब से औजार लेते समय वह कर्मचारी गर्व से फूल जाता है। साहब उसे माफ कर देते हैं। इससे उनका जनाधार बढ़ता है। कुर्सी पर पकड़ मजबूत होती है।

साहब को गंदगी पसंद नहीं है। यह जनता नहीं जानती। जनता को जागरूक करना साहब का काम है। इसलिए वे स्वच्छता अभियान की शुरुआत करते हैं। यह उनका गोपनीय कार्यक्रम होता है। सचिव के अलावा सभी जानते हैं। साहब झाड़ू लगाने वाले हैं। किस मोहल्ले में लगाएंगे, यह कार्यकर्ता तय करते हैं। जिस मोहल्ले से साहब को अधिक समर्थन मिला, वहां। कार्यकर्ता कचरा मंगवाते हैं। उसे डिटॉल से धोया, सुखाया जाता है। उसकी डॉक्टरी जांच की जाती है। बच्चे अस्पताल में मर जाएं, उनकी जांच जरूरी नहीं। जांच में देखा जाता है, कचरे में विपक्ष के कीटाणु तो नहीं हैं। कचरे में पार्टी विरोध की बू तो नहीं आ रही है। कचरा फेकने से पहले जगह को फिनाइल से धोया जाता है। तेज पानी की धार से मिट्टी हटाई जाती है। साहब के कपड़ों पर धूल न लग जाएं। चरित्र की कोई बात नहीं है।

अब कचरा डाला जाता है, जिसे साहब साफ कर सकें। कुर्ते के दाग कचरे के दाग समझ जनता खुश हो जाती है। कुर्ते पर जो दाग थे, वे किसी भी डिटर्जेंट से साफ होने वाले नहीं हैं, क्योंकि वे कचरे के दाग ही नहीं। इन दाग की चर्चा मीडिया नहीं करता।

ट्वीट-ट्वीट

क्या सरकार देश भर में एनआरसी लागू करने के फैसले से पीछे हट रही है? यह अच्छी बात है कि सरकारों को जनभावनाओं का आदर करना चाहिए और जनता की भावनाएं फिलहाल एनआरसी के पक्ष में नहीं हैं।
संजय निरुपम@sanjaynirupam

अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारत के किसी भी कोने में आसानी से बस सकते हैं, लेकिन भारतीय नागरिक शाहीन बाग नहीं जा सकते। यही सड़क पर पसरा सेक्युलरिज्म है।
दिव्य कुमार सोती@DivyaSoti

बुधवार को राम मंदिर ट्रस्ट के एलान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से आभार। यह हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा क्षण है। राम भारत और भारतीय सभ्यता की आत्मा हैं। मैं मंदिर निर्माण में योगदान के लिए अपने परिवार को भेजने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही हूं।
साध्वी खोसला@sadhavi

एयर इंडिया 70,000 करोड़ रुपये और बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड 90,000 करोड़ रुपये के नुकसान में हैं। इनके अलावा सरकारी बैंक, स्टील और कोयला कंपनियां भी दलदल में फंसी हैं। कुछ मूर्ख ऐसे बोझ को बड़ी संपत्ति मानते हैं और उनसे भी बड़े महामूर्खों की नजर में ये किसी रत्न से कम नहीं।
राम@ramprasad_c

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या प्रधानमंत्री का यह कहना सही है कि शाहीन बाग धरना-प्रदर्शन कोई संयोग नहीं, बल्कि प्रयोग है?

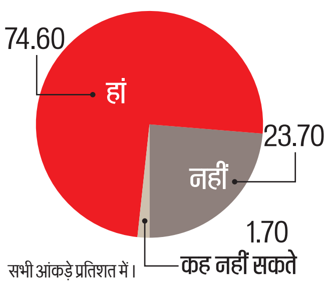

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

एनआरसी पर संसद में सरकार के लिखित जवाब के बाद अब इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन बंद हो जाने चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

इतनी कच्ची 'गोलियां' खेल रहे हो 'आप',
पकड़े जाते हो तुरत जनता जाती भांप।
जनता जाती भांप आपकी उड़ती खिल्ली,
यह नौटंकी देख आप पर हंसती दिल्ली।
खुद गोली चलवाय मूर्खता करते जितनी,
पब्लिक कतई मूर्ख नहीं है भाई इतनी!!
- ओमप्रकाश तिवारी

देश की छवि भी गढ़ते हैं विदेशी पर्यटक

नवनीत शर्मा
राज्य संपादक, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश डायरी

बचपन में एक कहानी पढ़ी थी। कालखंड और चरित्रों के नाम स्पष्टता के साथ याद नहीं, लेकिन चरित्र नहीं मिटते। एक भारतीय का जापान पहुंच कर केले खाने का मन हुआ। जब केले नहीं मिले तो उन्होंने कहा शायद जापान में केले मिलते ही नहीं। अचानक एक व्यक्ति कहीं से केले लाया और बोला, 'कृपया भारत जाकर किसी से यह न कहिएगा कि जापान में केले नहीं मिलते।' अपने देश के बारे में इतनी सी बात सुनना भी उससे सहन नहीं हुआ। अब ऐसे चरित्र धुंधलाने लगे हैं।

अब इसके बरक्स उस ब्रितानवी पर्यटक एंड्रयू फ्रॉस्ट के परेशान चेहरे की कल्पना करें जो अपने देश से ही शिमला में होटल की ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद बीते सप्ताह पहुंचा तो उसे होटल नहीं मिला। पत्नी और दो बच्चों के साथ जिस व्यक्ति का आधा दिन होटल तलाशने में निकल गया, इसके बावजूद होटल नहीं पा सका, वह भारत और खासतौर पर शिमला की कैसी छवि लेकर जाएगा? डिजिटल इंडिया के इस दौर में पर्यटन राज्य हिमाचल में उसका अनुभव कतई मीठा नहीं हो सकता। इस खबर के पार जाना इसलिए जरूरी है, क्योंकि शिमला में इस प्रकार का साइबर क्राइम पहली बार हुआ है। शिमला वॉक्स कंपनी के सुमित राज आदि ने उनकी दूसरी व्यवस्था करवा दी, लेकिन हस्तीमल हस्ती ने यूं तो नहीं कहा है :

गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हों या डोर, लाख करें कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है।

इसी बहाने यह समय सोचने का है कि यह प्रवृत्ति आती कहां से है। बहुत वर्ष नहीं हुए हैं जब पालमपुर के चाय बागान में एक विदेशी युवती के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। क्या यह उन दुकानदारों को देखने का समय नहीं है कि जिनकी दुकानों पर सामग्री रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं, खरीदार की गाड़ी के नंबर, चमड़ी के रंग या भाषा पर निर्भर करती है? हिमाचल को कभी विधानसभा में पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ब्रांड बनने का सूत्र दे गए थे। उस ब्रांड को खोजना होगा। हाल में हरियाणा के सूरजकुंड मेले में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी हिमाचलियों के दिल को बड़ा बताया है। यह और बात है कि पर्यटकों को भी पर्यटकों वाले अदब सीखने चाहिए। कई पुलिस वाले उनकी बदसलूकी के शिकार होते हैं। हरियाली के आंगन में प्लास्टिक की बोतलें और पहाड़ पर शराब की बोतलें फेकना भी उतना ही गलत है, लेकिन वह अंतरराज्यीय मामले हैं, पर्यटक विदेशी हो तो मामला साख तक पहुंचता है।

हिमाचल प्रदेश में आने वाले विदेशी पर्यटकों की प्रतीकात्मक तस्वीर।

तबादला एक्ट का दीर्घायु जिन्न : जिन्न केवल कहानियों में नहीं होते, राजनीतिक भी होते हैं। 'सुविज्ञ सूत्रों' के हवाले से फिर शिक्षकों के तबादला एक्ट का जिन्न बाहर आ रहा है। आदर्श प्रारूप है। आदर्श होने का पहला संकेत यह है कि तबादले सिफारिश के बिना होंगे। स्थानांतरण हो या सेवानिवृत्ति, सत्र के मध्य कुछ नहीं होगा। शिक्षकों के तबादले से पहले उनसे पसंद के पांच स्थान पूछे जाएंगे। तबादला एक्ट बन जाए तो पारदर्शिता रहेगी, इसमें संदेह नहीं लेकिन कुछ सवाल हैं। क्या डीओ नोट बन कर हर कार्यालय में छा जाने का सौभाग्य पाने वाले माननीयों के लैटर पैड सूने नहीं हो जाएंगे? क्या ज्वाइनिंग लेने और रिलीव करते समय संस्थान के मुखिया स्वतंत्र नहीं हो जाएंगे? जनप्रतिनिधियों को कौन पूछेगा? पूरी आशंका है कि दशकों से जिंदा यह जिन्न फिर सो जाएगा। सवाल ये भी हैं कि तबादला एक्ट केवल अध्यापकों के लिए क्यों? क्या केवल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों का अर्थ ही सरकारी कर्मचारी है? थोड़ा सा ध्यान उन स्कूली बस्तों पर भी जाना चाहिए जो बंटे तो निशुल्क थे, लेकिन उनके छीजने की शिकायत बच्चे कर रहे हैं। उन अध्यापकों की भी पहचान हो जो उत्कृष्ट काम कर रहे हैं, पर पुरस्कार के लिए आवेदन नहीं करते। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए साक्षात्कार खत्म करने का भी विरोध हुआ था, क्योंकि कुछ के हाथ बंध रहे थे।

सरकार पुत्र नामालूम स्थानीय वासी : हिमाचल प्रदेश सरकार और भाजपा संगठन के सभी महत्वपूर्ण लोग दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। इस बीच सदियों से चली आ रही सरकारी भाषा (खासतौर पर राजस्व विभाग) के दर्शन हुए। एक हाकिम ने बेहद दिलचस्प एंट्री जमाबंदी में डाली है। भाषा के हलके में जो भी गुल खिलें, पुराने गुलों की महक ही अलग है। एक जमाबंदी में एक कोष्ठक का शीर्षक है, 'नाम पत्ती या तरफ मय नंबरदार तदाद मुआमला।' इसके नीचे नंबरदार का नाम है। अगले कोष्ठक का शीर्षक है, 'नाम मालिक व अहवाल।' इसके नीचे जो लिखा है, वह बेहद दिलचस्प है। लिखा है, 'सरकार हि.प्र. स्वयं सरकार हि.प्र. पुत्र नामालूम स्थानीय वासी।' इतने वर्षों में लिपि तो देवनागरी हो गई, लेकिन तेवर वही हैं जो विभाग के अलावा कोई समझे तो पुरस्कृत हो जाए।

समस्या-समाधान

सुगम और सुरक्षित हो गर्भपात

देश भर में सुरक्षित गर्भपात की सुविधाओं को बढ़ाने के साथ स्वास्थ्य केंद्र तक महिलाओं की पहुंच सुगम होनी चाहिए। निजी स्वास्थ्य केंद्रों में भी यह सुविधा किफायती दरों पर उपलब्ध होनी चाहिए

अलका आर्य
स्वतंत्र टिप्पणीकार

प्रतीकात्मक

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (संशोधन) विधेयक-2020 को मंजूरी देकर महिलाओं को राहत दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि यह विधेयक महिला केंद्रित है और इसके मुख्य लक्ष्यों में एक महिलाओं को प्रजनन अधिकार देना है। गर्भपात की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव वाला यह बिल संसद के चालू बजट सत्र में रखा जाएगा और इसके पारित होने की पूरी उम्मीद है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित होने से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (एमटीपी) एक्ट-1971 में संशोधन का रास्ता साफ हो गया है। इस प्रस्तावित बिल में अबॉर्शन यानी गर्भपात कराने की समय सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दी है। इसके अलावा भी कई उल्लेखनीय बदलाव किए गए हैं। एमटीपी एक्ट-1971 के अनुसार गर्भपात कराने की समय सीमा 20 सप्ताह तक है और एक अविवाहित महिला गर्भपात के लिए गर्भनिरोधक के फेल होने की वजह नहीं बता सकती यानी इस आधार पर मौजूदा एमटीपी कानून उसे इसकी इजाजत नहीं देता और ऐसी महिलाओं पर गर्भपात कराने का सामाजिक दबाव अधिक रहता है, कानून और सामाजिक हालात उन्हें गर्भपात के असुरक्षित ठिकानों पर जाने को विवश कर देते हैं, जहां स्वास्थ्य संबंधी अनेक जटिलताओं के जकड़न में आने व जिंदगी जाने का जोखिम भी मंडराता रहता है। प्रस्तावित विधेयक में इस प्रतिगामी क्लॉज को खत्म कर दिया गया है।

मौजूदा एमटीपी एक्ट-1971 में संशोधन की मांग पुरानी है। वजह जब यह कानून बना था, उसके बाद विज्ञान ने काफी प्रगति कर ली है और उसका लाभ इस संदर्भ में महिलाओं को मिलना चाहिए। नाबालिग दुष्कर्म पीड़ितों के लिए भी मौजूदा कानून दिक्कतों को बढ़ाने वाला ही साबित हुआ। कई मामलों में तो गर्भवती होने का पता ही 20 सप्ताह के बाद पता चला और ऐसे में अदालत भी कानून के द्वारा तय समय सीमा का हवाला देते हुए गर्भपात की इजाजत देने से मना कर देता है। कई ऐसे मामले भी सामने आए जिनमें ऐसी पीड़िताओं ने 20 सप्ताह वाले गर्भ से पहले अदालत से गर्भपात की इजाजत मांगी, लेकिन लंबी कानूनी कार्रवाई के चलते तय समय सीमा अदालती कार्रवाई में ही पूरी हो गई, नतीजन ना चाहते हुए भी उन्हें बच्चे को जन्म देना पड़ा।

एक बात और ध्यान देने वाली है कि गर्भस्थ शिशु के विकारग्रस्त पैदा होने के बारे में अधिकतर जानकारी गर्भ के 20 सप्ताह के बाद ही मिलती है। वर्ष 2016 के बाद से 70 महिलाओं को 20 सप्ताह की गर्भावस्था के बाद गर्भपात के लिए अदालत जाना पड़ा। इनमें अधिकतर मामलों में गर्भस्थ शिशु में गंभीर विकार था। डॉक्टरों का कहना है कि कुछ विकार ऐसे होते हैं जो गर्भधारण के 20वें सप्ताह तक पता नहीं चलते। ऐसे में गर्भावस्था के 24वें सप्ताह में भी गर्भस्थ शिशु को गिराना जरूरी हो जाता है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि 20 सप्ताह में गर्भपात कराने पर मां की जान जाने के कई मामले सामने आए हैं। 24 सप्ताह में गर्भपात कराना सुरक्षित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस कदम से दुष्कर्म पीड़िताओं और नाबालिगों को मदद मिलेगी। दरअसल एमटीपी (संशोधन) विधेयक-2020 के दायरे में दुष्कर्म पीड़िता, पारिवारिक व्याभिचार पीड़िता, एकल महिला को भी शमिल किया गया है।

यह एक उल्लेखनीय कदम कहा जा सकता है, क्योंकि इस बिल के मौलिक मसौदे में सिर्फ शादीशुदा महिलाओं के लिए ही गर्भनिरोधक फेल होने की वजह के चलते गर्भपात की इजाजत वाला प्रावधान था, लेकिन बाद में स्वास्थ्य मंत्रालय ने महसूस किया कि इससे अविवाहित महिलाओं के लिए खतरा बढ़ सकता है। लिहाजा मंत्रालय ने ऐसी महिलाओं के लिए भी अबॉर्शन कराने के लिए गर्भनिरोधक के फेल होने की वजह पर सहमति दी। महिला की मर्जी के बिना गर्भपात कराया जाना अपराध है। दोषी को ऐसे मामले में कड़ी सजा का प्रावधान है।

इस बिल के संबंधित सरकारी बयान में इसे महिलाओं की सुरक्षा और कुशलता की दिशा में उठाया गया कदम बताया गया है, और बहुत सी महिलाएं इससे लाभान्वित होंगीं। गर्भपात की अवधि में प्रस्तावित वृद्धि ऐसी महिलाओं की गारिमा, स्वायत्तता, गोपनीयता और न्याय को सुनिश्चित करेगी जिन्हें गर्भपात की जरूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि गर्भपात की अवधि बढ़ाने की मांग बहुत पुरानी है और यह समय की मांग भी है। मुल्क में असुरक्षित गर्भपात मातृत्व मृत्युदर का एक अहम कारण भी हैं। 'इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स' की वर्ष 2015 के एक अध्ययन के अनुसार भारत में होने वाली मातृत्व मौतों में से 10 से 13 प्रतिशत की वजह असुरक्षित गर्भपात हो सकती है। इसके अलावा इस सच्चाई की ओर जिसे आंकड़े हमारे सामने पेश करते हैं, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उम्मीद है कि एमटीपी (संशोधन) विधेयक-2020 मातृत्व मृत्युदर को घटाने में मदद करेगा।

भारत में गर्भनिरोधक उपायों को लेकर जबरदस्त लैंगिक पूर्वाग्रह देखने को मिलता है। गर्भनिरोधकों के इस्तेमाल का अधिक सामाजिक दबाव महिलाएं ही झेल रही हैं। एमटीपी (संशोधन) विधेयक-2020 जिसे महिला केंद्रित बताया जा रहा है, जब वह मुल्क में लागू होगा, उससे महिलाओं के प्रजनन अधिकार कितने सुरक्षित होंगे और एकल महिलाएं कितनी लाभान्वित होंगी, आदि इस पर भी निर्भर करता है कि सरकार इस बावत महिलाओं को कितनी जागरूक करेगी।

2019 में यूट्यूब का एड रेवेन्यू 36 फीसद बढ़कर एक लाख करोड़ रुपये रहा। 2018 में यह 79 हजार करोड़ रुपये था।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 6 फरवरी 2020

झारखंड

लाभार्थियों को समय पर मिले राशन

देश के अनेक इलाकों से अक्सर यह खबर आती है कि तकनीकी कारणों से बड़ी संख्या में वैध लोगों को भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये बांटे जाने वाले अनाज से कई बार वंचित रहना पड़ता है। ऐसे में कई बार उन तकनीकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया जाता है और उसका समाधान भी किया जाता है ताकि लोगों को समय से राशन मुहैया कराया जा सके। लेकिन कई बार कई राज्यों में बड़े पैमाने पर ऐसा नहीं हो पाता है और इसमें अनियमितता भी सामने आती है।

खुद को जनता की सरकार के रूप में प्रस्तुत करनेवाली हेमंत सोरेन सरकार के सामने जन वितरण प्रणाली को लेकर कोल्हान से आई पड़ताल बड़ी चुनौती है। वहां हजारों ऐसे परिवार हैं जिन्हें इनके राशन पर सिस्टम की नजर लग गई है। विभिन्न कारणों से वे सरकार से मिलनेवाले खाद्यान्न से तो वंचित हैं ही, उनमें यह डर भी बना रहता है कि यदि किसी भी वजह से दो महीने तक राशन का उठाव नहीं हो सका तो उन्हें मिली यह सुविधा स्वतः बंद हो जाएगी। यह स्थिति कमोबेश पूरे राज्य में है। यह शासन-प्रशासन के संज्ञान में है। राजनीतिक दल भी अनजान नहीं हैं। ऐसा नहीं कि इसे दुरुस्त करने की कवायद नहीं की गई। अफसोसजनक बात यह रही कि व्यवस्था की गड़बड़ियों को दूर करने के लिए जो भी उपाय किए गए, वे सैद्धांतिक ही ज्यादा प्रतीत हुए। ऐसा नहीं होता तो आधार कार्ड के इस्तेमाल या अंगूठे के निशान से राशन उठाव की व्यवस्था में विभिन्न तरह के छिद्र सामने नहीं आते। राशन लेने-देने में तकनीक का जितना ज्यादा इस्तेमाल होने लगा, पेचीदगियां भी उतनी बढ़ती चली गईं। कारण यह रहा कि तकनीक को तो आत्मसात कर लिया गया, लेकिन उसे पूरी तरह से मूर्त रूप देने को जिस आधारभूत संरचना की जरूरत थी या जैसे फिर जिस तरह के संसाधन होने चाहिए थे, उसकी समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी। नतीजा यह निकला कि जिस आम जनता को सही मात्रा और सही तरीके से राशन उपलब्ध कराने की नेक परिकल्पना की गई वह इन विसंगतियों की भेंट चढ़ गई। अब राज्य में नई सरकार आई है। जनता से जुड़े मुद्दों को नए नजरिये से देख रही है। उनके समाधान को लेकर प्राथमिकता तय कर रही है। उम्मीद बंधी है कि जन वितरण प्रणाली को कारगर बनाने के लिए ठोस पहल होगी। इस क्रम में निगरानी समिति के गठन पर सरकार को खास ध्यान देना चाहिए।

> राशन लेने-देने में तकनीक का इस्तेमाल तो होने लगा लेकिन उसकी पेचीदगियां दूर नहीं हुई। लाभुक राशन से वंचित हो गए।

पूर्ववर्ती सरकार के शासन में यह बात आई थी कि यदि हर लाभुक को राशन दिलाना सुनिश्चित करना है तो व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के साथ उसकी निगरानी भी मुकम्मल होनी चाहिए। जन वितरण प्रणाली की दुकान को उसके लाभुकों की निगरानी में डाल दिया जाए तो इसकी खामियों को बहुत हद तक दुरुस्त किया जा सकता है। इससे सही लाभुक की आसानी से पहचान हो सकेगी। सही मात्रा में वितरण सुनिश्चित होगा और दुकानदार भी तकनीकी पेच फंसाकर लाभुकों को उनके हक से वंचित करने का प्रयास नहीं कर सकेंगे।

बंगाल

परंपरा पर पहरा बिठाने की कोशिश

देश के पूर्वी राज्यों, खासकर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में वसंत पंचमी के दिन स्कूलों, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों आदि में विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा-अर्चना करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। इस दिन संबंधित शिक्षण संस्थान के ना केवल छात्र, बल्कि शिक्षक भी पूजा-अर्चना में भागीदारी निभाते हैं।

ऐसी परिस्थितियों के बीच यदि बंगाल में स्कूलों में सरस्वती पूजा ना होने देने का मामला अपने आप में बड़ी चिंता का विषय है। दरअसल बंगाल में स्कूलों में सरस्वती पूजा पर इस बार रोक लगा दी गई। बंगाल के स्कूलों में सरस्वती पूजा बंद कराए जाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। मंगलवार को बंगाल के सभी 18 भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर इस पर हस्तक्षेप की मांग की है। बंगाल के स्कूलों में पिछले 50 वर्षों से सरस्वती पूजा का पर्व धूमधाम से मनाया जाता रहा है। इसे बंद कराए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने सीधे सरकार को घेरा है। सांसदों ने पर्व और परंपरा पर अंकुश लगाए जाने के मुद्दे को राष्ट्रपति तक पहुंचाकर कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कानून-व्यवस्था के मामले को भी प्रमुखता से उठाया है। राष्ट्रपति भवन तक पहुंची यह आवाज संसद में भी गूंजी। भारतीय जनता पार्टी सांसद लॉकेट चटर्जी ने लोकसभा में सरस्वती पूजा की अनुमति न देने पर ममता बनर्जी सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। अब सरकार इस पर चाहे जितने तर्क गढ़े, लेकिन यह सही है कि बंगाल में वोट की राजनीति ने पर्व और परंपराओं पर भी पहरा बिठा दिया है। सीएए और एनआरसी के बहाने एक खास वर्ग के वोट की गोलबंदी में जुटे राजनीतिक दलों, खासकर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को लगता है कि वोट बटोरने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। स्कूलों में सरस्वती पूजा मनाने से बच्चों में प्रेरणा के साथ-साथ अपने संस्कारों को समझने का अवसर मिलता है। आखिर इस पर रोक लगाकर सरकार क्या संदेश देना चाहती है? वोट के लिहाज से भी एक बड़ा वर्ग प्रभावित हो सकता है, लेकिन सरकार समझती है कि ऐसे आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले लोग भाजपा के अलावा दूसरे के नहीं हो सकते हैं। ऐसे में वह दूसरे वर्ग को साधने का मौका चूकना नहीं चाहती है। लेकिन इस प्रयास में लोगों का आक्रोश भी बढ़ रहा है।

मां सरस्वती

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दिलीप घोष खुलकर आरोप लगाते हैं कि बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने राष्ट्रपति को इस मसले के साथ राज्य की कानून व्यवस्था से भी अवगत कराया और यह भी कहा कि राज्यपाल जहां भी जाते हैं उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए सांसदों ने यह जता दिया है कि राज्य में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दुर्गा पूजा के दौरान जय श्रीराम के नारे पर हुए विवाद ने भी सरकार में बैठे लोगों की छवि को प्रभावित किया। हालांकि बाद में ममता बनर्जी ने अतिवादियों के खिलाफ बयान देकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। अब सरस्वती पूजा का मामला भी उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है।

उत्तराखंड

एहतियात के साथ कदम बढ़ें आगे

पहाड़ी राज्य उत्तराखंड को अस्तित्व में आए 19 वर्ष हो चुका है, मगर प्रदेश के दोनों मंडलों को राज्य के भीतर सीधे आपस में जोड़ने को एक अदद सड़क का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि, आजादी से पहले से ही गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाला वन मोटर मार्ग (कंडी रोड) है, लेकिन यह पर्यावरणीय कारणों समेत तमाम झंझावातों में घिरा हुआ है।

एक दौर में कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व से होकर गुजरने वाली यह कंडी रोड (रामनगर-कालागढ़- चिलरखाल- लालढांग) यहां की लाइफलाइन से कम नहीं थी। इसे देखते हुए ही कंडी रोड को आम यातायात के लिए खोलने की मांग समय-समय पर उठती रही है। प्रदेश की मौजूदा सरकार ने भी कंडी रोड को अपनी प्राथमिकता में रखते हुए पहले चरण में इसके राजाजी टाइगर रिजर्व के बफर जोन से सटे गैर विवादित लालढांग-चिलरखाल हिस्से के निर्माण का फैसला लिया। लगभग 11 किमी लंबे इस मार्ग के निर्माण के लिए वन भूमि हस्तांतरण कर लोक निर्माण विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई। छह

प्रतीकात्मक फोटो

किलोमीटर सड़क का डामरीकरण भी हुआ, लेकिन बाद में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट की इंपावर्ड कमेटी ने इसका संज्ञान लिया। अदालत ने निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए सरकार को निर्देश दिए कि वह नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से अनुमति लेकर ही इस सड़क का निर्माण करा सकती है। अब नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने लालढांग- चिलरखाल रोड का निर्माण राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की गाइडलाइन के अनुरूप कराने की सशर्त अनुमति दे दी है।

बोर्ड ने साफ किया है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की गाइडलाइन के अनुरूप सड़क का निर्माण इस प्रकार से हो, जिससे वन्यजीव प्रबंधन और वन्यजीवों की आवाजाही में किसी प्रकार का खलल न पड़ने पाए। वन्यजीवों की आवाजाही सुगम बनाने के लिए स्कबर और करीब साढ़े सात सौ मीटर एलिवेटेड रोड बनाने को कहा गया है। इसके अलावा अन्य शर्तें भी लगाई गई हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की गाइडलाइन के अनुरूप यह सड़क बनाने के लिए सरकार को फूककर कदम उठाने होंगे। इस सिलसिले में सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके आधार पर सड़क का रास्ता प्रशस्त होगा। सर्वे में पर्यावरणीय व वन्यजीवों से संबंधित सभी पहलुओं को समाहित करना होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि राज्य सरकार व वन्यजीव महकमा इस सड़क के निर्माण लिए पूरी एहतियात के साथ आगे कदम बढ़ाएंगे।

बिहार

उजागर हो चूहों के पीछे का खेल

कई बार चूहे खलनायक के रूप में सामने आते रहे हैं। पारिस्थितिकी संतुलन के लिए चूहे महत्वपूर्ण हैं। इस ख्याल से इन्हें पूरी तरह नष्ट नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर इस बेजुबान प्राणी के नाम पर कई बड़े खेल भी चलते रहते हैं। कभी सरकारी गोदाम के अनाज का बड़ा हिस्सा चट कर जाते हैं तो कभी पुलिस द्वारा जब्त शराब पी जाते हैं। कई बार नदी नालों पर बने बांधों को भी ध्वस्त कराने में इनकी भूमिका खलनायक के रूप में सामने आती है। यहां तक कि रेल पटरियों के मजबूत आधार को भी कभी-कभी कमजोर करने में इनकी भूमिका सामने आती रही है। भारतीय रेलवे को चूहों के कारण सालाना कई करोड़ रुपये की चपत लगती है। कई बार तो चूहों द्वारा सिग्नल टेलिकॉम विभाग के तारों-केबल आदि काट देने के कारण ट्रेनें भी विलंब हो जाती हैं। कुल मिलाकर चूहों के कारण अनेक विभागों में मुश्किलें सामने आती रहती हैं। भारत ही नहीं, दुनिया के अन्य कई देशों से भी अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं कि चूहों के कारण अन्न या फिर किसी दूसरे प्रकार की बरबादी से देश के लोगों को कठिनाई हुई है।

> दस्तावेज की सुरक्षा संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है। चूहे व बाढ़ के पानी के खेल का सच सामने आना चाहिए। नियोजित शिक्षकों की फाइलों की जांच जरूरी है।

अब इनका एक नया कारनामा सामने आया है। फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी पाने वाले नियोजित शिक्षकों के दस्तावेज कुतर देने में इनकी भूमिका सामने आई है। गौर करें तो शिक्षा के आधार को हिला देने में इनके उपयोग का खेल शुरू हो गया है। ऐसे एक लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों के फोल्डर नहीं मिल रहे। इल्जाम बाढ़ के पानी के साथ-साथ चूहों पर है। हाई कोर्ट के आदेश पर नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच पिछले पांच साल से चल रही है। इसे त्वरित और पारदर्शी तरीके से निष्पादित करने के लिए प्रत्येक जिले में निगरानी ब्यूरो ने अपना कार्यालय खोला। इतनी लंबी अवधि गुजर जाने के बाद भी एक लाख से ज्यादा ऐसे शिक्षकों के फोल्डर नहीं मिल पाए हैं। हालांकि शिकायत मिलने के बाद सभी 3,52,812 नियोजित शिक्षकों की जांच शुरू हुई थी। इनमें 1,09,638 के फोल्डर अब तक उपलब्ध नहीं कराए जा सके। जिला और प्रखंड स्तर की नियोजन इकाइयों ने फोल्डर उपलब्ध न होने का कारण फाइलों को चूहों द्वारा कुतर दिया जाना या फिर बाढ़ के पानी से बर्बाद होना बताया है। हालांकि शिक्षा विभाग ऐसी नियोजन इकाइयों पर एफआइआर करने का मन बना चुका है। यदि ये कारण सही हैं तो इसे बड़े नुकसान के रूप में देखा जाना चाहिए। अन्य योजनाओं संबंधित फाइलों की भी सुरक्षा और तहकीकात की ओर ध्यान जाना चाहिए। चूहे सिर्फ नियोजित शिक्षकों की फाइल ही चिन्हित कर कुतरें, ऐसा तो हो नहीं सकता।

दस्तावेज के रखरखाव पर भी यह बड़ा सवाल है। जितनी जल्दी हो इस मामले में ठोस निर्णय लेने की जरूरत है। इससे उन नियोजित शिक्षकों को भी राहत मिलेगी जिनकी साख सही प्रणाम पत्र देने के बाद भी फंसी है। बेवजह बदनाम चूहे के खेल के पीछे का खेल उजागर होना चाहिए।

मथुरा सुधारेगा देशभर में बकरियों की नस्ल

मनोज चौधरी, मथुरा

▸ पांच नस्लों के बकरों के सीमन स्ट्रॉ तैयार करने में मिली कामयाबी

कान्हा की नगरी के नाम एक बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान एवं विश्वविद्यालय और गो अनुसंधान संस्थान (दवासु) ने बकरी के कृत्रिम गर्भाधान के लिए बकरे की पांच नस्लों के सीमन स्ट्रॉ तैयार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। इन स्ट्रा से देशभर में बकरी की नस्ल में सुधार होगा।

केंद्र की राष्ट्रीय कृषि योजना के तहत संस्थान को बकरी नस्ल सुधार का काम सौंपा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर, 2019 में मथुरा आगमन पर सीमन स्ट्रा तैयार किए जाने की घोषणा की थी। इसके लिए संस्थान में जमुनापारी, सिरोही, बीटल, ब्लैक बंगाल और बरबरी नस्ल के बकरे पाले गए। उनसे सीमन स्ट्रा तैयार किए गए।

संस्थान के प्रयोगशाला प्रभारी डॉ. मुकुल आनंद ने बताया कि 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच दो प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें देशभर के 40 वेटरनेरी अफसर को सीमन स्ट्रॉ की जानकारी और उसके इस्तेमाल के बारे में बताया जाएगा। वह जिला और मंडल स्तर पर लोगों को प्रशिक्षित करेंगे।

ऐसे बिगड़ी नस्ल : अलग-अलग नस्ल के बकरों से गर्भाधान कराने से बकरी की नस्ल बिगड़ गई। इसका असर बकरी के दूध की गुणवत्ता पर भी पड़ा, साथ ही मृत्यु दर भी बढ़ गई। अब अच्छी नस्ल के बकरे के सीमन से कृत्रिम गर्भाधान कराए जाने से बकरी का ग्रोथ रेट अधिक होगा, बच्चे भी स्वस्थ होंगे। मृत्यु दर में भी कमी आने की संभावना है।

ये भी जानिए

देशभर में बकरियों की 36 प्रजातियां पाई जाती हैं। मथुरा में उत्तर भारत (पहाड़ों को छोड़कर) और पठारी क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाई जाने वाली जमुनापारी, बीटल, बरबरी, सिरोही और ब्लैक बंगाल की नस्ल के लिए काम किया जा रहा है। पहले पालक बकरे से गर्भाधान कराते थे। वर्तमान समय में महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक में कृत्रिम गर्भाधान कराया जा रहा है, लेकिन वहां एक-दो नस्ल के सीमन के स्ट्रा ही हैं। मथुरा में पहली बार एक साथ पांच नस्लों के स्ट्रा तैयार किए गए हैं।

सीमन स्ट्रा तैयार होने लगे हैं। शुरुआत के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत धनराशि मिली थी। अब योजना बकरी फार्म खुद ही चलाएगा। स्ट्रॉ से होने वाली आय से ही योजना संचालित होगी।

– प्रो. जीके सिंह, कुलपति, दवासु, मथुरा

चिंताजनक : उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के तट पर खड़ा हो रहा कूड़े का पहाड़

शैलेंद्र गोदियाल, उत्तरकाशी

भागीरथी (गंगा) नदी के उत्तर में बसे उत्तरकाशी शहर के शीर्ष पर वरुणावत पर्वत विराजमान है, लेकिन बीते एक साल से भागीरथी के किनारे एक दूसरा पहाड़ आकार ले रहा है। यह पहाड़ है उत्तरकाशी शहर और आसपास की आबादी से निकलने वाले कूड़े का, जो धीरे-धीरे भागीरथी की ओर फैल रहा है। हालांकि, इस कूड़े के प्रबंधन के लिए प्रशासन ने पालिका क्षेत्र में करीब डेढ़ नाली (360 वर्ग गज) भूमि उपलब्ध कराई थी, जिस पर पालिका को कूड़ा प्रबंधन के लिए संयंत्र स्थापित करना था, लेकिन बजट के अभाव में यह संभव नहीं हो पाया। अब पालिका ने कूड़ा प्रबंधन संयंत्र लगाने के लिए शासन से एक करोड़ की धनराशि मांगी है।

बाड़ाहाट (उत्तरकाशी) नगर पालिका क्षेत्र से हर दिन 20 से 25 क्विंटल कूड़ा एकत्र होता है। यहां घर-घर से कूड़ा एकत्र करने की जिम्मेदारी जीरो वेस्ट कंपनी की है, जबकि शहर में सफाई की व्यवस्था पालिका स्वयं संभालती है। शहर से निकलने वाला सारा कूड़ा तांबाखाणी के पास भागीरथी नदी से 20 मीटर की दूरी पर डंप किया जा रहा है। इसके चलते उत्तरकाशी बाजार के एक छोर से दूसरे छोर तक कूड़े का पहाड़ खड़ा हो रहा है। हां, इतना जरूर है कि जीरो वेस्ट कंपनी के कर्मियों ने इस कूड़े से कुछ प्लास्टिक एकत्र कर उसे कॉम्पेक्ट किया।

उत्तरकाशी में भागीरथी के निकट तांबाखानी सुरंग के बाहर इस तरह से बना है कूड़े का पहाड़। जागरण

कूड़ा प्रबंधन संयंत्र की डीपीआर शासन को भेजी है। इसके तहत कूड़े की छंटनी, खाद बनाने का काम, किल वेस्ट मशीन और कॉम्पेक्टर लगाया जाएगा। इस पूरे संयंत्र को लगाने में एक करोड़ की धनराशि खर्च होगी। धनराशि मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल कूड़ा तांबाखाणी के पास ही डाला जा रहा है।

– रमेश सेमवाल, पालिकाध्यक्ष बाड़ाहाट (उत्तरकाशी)

कूड़े के प्रबंधन के लिए प्रशासन की ओर से पालिका को भूमि उपलब्ध करा दी गई है। कूड़ा प्रबंधन की जिम्मेदारी पालिका की है। हां, शहर के निकट लगे कूड़े के ढेर को जल्द वहां से हटवाया जाएगा। इसके लिए मैं अपने स्तर से प्रयास करूंगा।

– डॉ. आशीष चौहान, जिलाधिकारी उत्तरकाशी

इसे पालिका ने 19 हजार रुपये में बेचा। अगर पालिका समय पर कूड़ा प्रबंधन संयंत्र लगाती तो कई गुना कमाई भी करती, लेकिन मुश्किल यह है कि पालिका के पास संयंत्र लगाने का बजट ही नहीं है।

निर्मल गंगा अभियान को भी पलीता : भागीरथी के किनारे कूड़े का पहाड़ खड़ा होने से नदी के अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। दरअसल, बारिश होने पर यह कूड़ा सीधे भागीरथी में पहुंचता है। इससे नदी तो प्रदूषित हो ही रही है, निर्मल गंगा अभियान को भी पलीता लग रहा है।

14 हजार किमी फायर लाइन सफाई पांच हजार किमी की

केदार दत्त, देहरादून

फायर सीजन (अग्निकाल) की उलटी गिनती शुरू होने के साथ ही उत्तराखंड में वनों को आग से बचाने के मद्देनजर महकमा तैयारियों में जुट गया है, मगर इस राह में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। जंगल की आग पर काबू पाने की दिशा में फायर लाइन सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी तक करीब पांच हजार किमी फायर लाइन ही साफ हो पाई है। प्रदेशभर में फायर लाइनों की कुल लंबाई 13917.1 किलोमीटर है।

क्या होती है फायर लाइन : वन क्षेत्रों में आग पर नियंत्रण के मद्देनजर फायर लाइन बनाई जाती हैं। यह एक प्रकार से चौड़े रास्ते हैं, जिन्हें पूरी तरह साफ रखा जाता है। वहां उगी झाड़ियों, जमा पत्तियों को फूंककर इनकी सफाई होती है। फायर लाइन साफ रहने से आग एक से दूसरे हिस्से में नहीं जा पाती। प्रतिवर्ष फायर सीजन में इन्हें साफ रखना होता है।

फायर लाइनों की सफाई चुनौती : राज्य में 13917.1 किमी लंबी फायर लाइनें हैं। इन्हें साफ रखना बड़ी चुनौती है। मैदानी क्षेत्रों में तो सफाई में दिक्कत नहीं, लेकिन पहाड़ की विषम परिस्थितियों को देखते हुए वहां यह काम आसान नहीं है।

जल्द क्लीयर होंगी फायर लाइनें : नोडल अधिकारी (वनाग्नि) बीके गांगटे के अनुसार, अभी तक मैदानी क्षेत्रों में 5000 किमी फायर लाइन क्लीयर हो चुकी हैं। पहाड़ में बर्फबारी-बारिश के मद्देनजर फायर लाइन क्लीयर करने में फिलवक्त दिक्कत है। अलबत्ता, मौसम के साथ देने पर इन्हें क्लीयर करने को युद्ध स्तर पर कदम उठाए जाएंगे।

उत्तराखंड में ये किए उपाय

- **40** मास्टर कंट्रोल रूम किए स्थापित
- **175** वॉच टावरों से होगी निगरानी
- **1437** क्रू-स्टेशन में 24 घंटे कर्मियों की मौजूदगी

हर साल भारी क्षति : उत्तराखंड में हर साल फायर सीजन (15 फरवरी से मानसून के आगमन तक) में बड़े पैमाने पर वन संपदा आग की भेंट चढ़ती है। वर्ष 2010 से 2019 तक के आंकड़े देखें तो इस अवधि में 19945 हेक्टेयर वन क्षेत्र तबाह हुआ। यानी औसतन प्रतिवर्ष 1994 हेक्टेयर जंगल आग से झुलस रहा है।

फिलहाल मौसम का साथ : नियमित अंतराल में बर्फबारी-बारिश से जंगलों में अच्छी-खासी नमी बनी है। ऐसे में माना जा रहा कि कुछ दिन आग के लिहाज से सुकून रहेगा। अलबत्ता, चिंता भी साल रही कि मौसम के करवट बदलने के साथ ही पारे ने उछाल भरी तो क्या होगा।

बीट तक पहुंचेगी सूचना : फायर अलर्ट की सूचना बीट तक पहुंचाने के मद्देनजर वायरलेस नेटवर्क सशक्त करने का दावा है। 35 रिपीटर, 506 वायरलेस सेट, 1631 हैंड सेट, 199 मोबाइल सेट की तैनाती है।

केसर के खेतों के बीच फिर जवां होगी छतलम झील

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

केसर की क्यारी के नाम से विख्यात पांपोर में स्थित छतलम झील के दिन फिरने वाले हैं। प्रशासन ने इसे डल झील की तर्ज पर विकसित करने की कार्ययोजना बनाई है। पांपोर में केसर के खेतों में स्थित इस झील के लिए डेढ़ करोड़ रुपये जारी कर काम भी शुरू कर दिया गया है।

श्रीनगर-पहलगाम हाईवे पर पांपोर के निकट लालपोरा गांव के बाहरी छोर पर स्थित छतलम झील दक्षिण कश्मीर की चार प्रमुख झीलों और वेटलैंड में एक है। कभी यह लगभग डेढ़ वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। इसमें हजारों की तादाद में प्रवासी पक्षी सर्दी में डेरा डालते थे। समय की मार, पर्यावरण प्रदूषण और भूमाफिया के चलते यह लगातार सिकुड़ती गई और प्रवासी पक्षियों का आना भी कम हो गया। छतलम में 56 प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं।

ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल पांपोर के चेयरमैन मोहम्मद अल्ताफ मीर ने बताया कि छतलाम में एक एक्वेरियम, पार्क, कैफेटेरिया भी बनाया जाएगा। यहां

छतलम झील कभी अपने सौंदर्य पर इठलाती थी। आज यह सरकारी उपेक्षा के बीच भूमाफिया के जाल में फंसी है। इसके बावजूद यहां 56 प्रजातियों के विदेशी पक्षी आते हैं। अब इसे श्रीनगर की डल झील की तर्ज पर विकसित करने की कार्ययोजना बनाई गई है। कामरान रशीद बट

वर्ड वाचिंग की सुविधा भी होगी। झील के सौंदर्यीकरण और इसके पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करने के लिए विशेषज्ञों से भी मदद ली जा रही है। झील के संरक्षण और विकास के लिए करीब डेढ़ करोड़ रुपये भी जारी कर दिए गए हैं।

वर्तमान स्थिति अत्यंत दयनीय : स्थानीय युवक तारिक अहमद ने कहा कि यह झील वर्तमान अत्यंत दयनीय स्थिति में है। चारों तरफ भूमाफिया का कब्जा है। इसके बावजूद सर्दी में यहां बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। यहां तक कि गर्मी में भी कई दुर्लभ प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। अगर झील का संरक्षण हो और इसका पारिस्थितिकी संतुलन किसी तरह बहाल किया जाए तो यहां का माहौल पूरी तरह बदल जाएगा। फिश एक्वेरियम बना तो सोने पर सुहागा होगा।

खोया गौरव फिर हासिल होगा : प्रशासन ने एक बार फिर छतलम झील को उसका खोया गौरव वापस दिलाने की कार्ययोजना पर काम शुरू कर दिया है। प्रशासन इसके लिए वन एवं पर्यावरण विभाग, मछली पालन विभाग, फ्लोरीकल्चर और पर्यटन विभाग के साथ समन्वय के साथ, इसके संरक्षण और विकास की कार्ययोजना बना रहा है। इस झील को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा।

छतलम में बेशक हाउसबोट नहीं होंगे, लेकिन इसमें शिकारा की सैर जरूर होगी। इसे डल की तर्ज पर ही विकसित करने की हमारी योजना है। इस संदर्भ में संबंधित प्रशासन और उपराज्यपाल से भी हमारी बातचीत हो चुकी है।

– मोहम्मद अल्ताफ मीर, चेयरमैन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल पांपोर

केसर के खेतों के बीच है झील : छतलम झील केसर के खेतों के बीच में ही स्थित है और हाईवे से सटी हुई है। इसलिए यह कश्मीर में आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का एक बड़ा केंद्र साबित होगी। स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को इससे फायदा पहुंचेगा।

मलबा बिगाड़ रहा नैनी झील की सेहत

जागरण संवाददाता, नैनीताल

सरोवरनगरी की पहाड़ियों के कटाव समेत नालों से आ रहा मलबा नैनी झील की सेहत बिगाड़ रहा है। कुमाऊं विवि के शोध अध्ययन में सामने आया है कि पहाड़ियों से औसतन हर साल एक सेंटीमीटर गाद नैनी झील में समा रही है। 140 वर्षों से झील में करीब 130 सेमी मिट्टी जमा हो चुकी है।

शोध के अनुसार नैनी झील में हर साल भीमताल झील से 30 गुना अधिक मलबा समा रहा है। शोध में इसके लिए कंक्रीट के रास्तों व सड़क के निर्माण पर सख्ती से रोक लगाने की सिफारिश की गई है।

दरअसल 2016 में झील का जलस्तर काफी गिर गया था, जिससे झील में टापू उभर आए थे। तब तीन मई 2016 को कुमाऊं विवि के भूगर्भ विज्ञानी प्रो. बहादुर सिंह कोटलिया द्वारा अध्ययन के मकसद से तल्लीताल आर्मी होली-डे होम के समीप जेसीबी से खोदाई कराई। प्रो. कोटलिया ने नमूनों की जांच के बाद निकले निष्कर्ष को बेहद चौंकाने वाला बताया। उन्होंने बताया कि 50 हजार साल पूर्व बनी नैनी झील की तलहटी में 20 मीटर तक मिट्टी जमा हो चुकी है। दूसरी झीलों में एक हजार साल में 30 सेमी गाद भरती है, जबकि नैनी झील में एक साल में एक सेमी गाद भर रही है।

- कुमाऊं विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अध्ययन में आया सामने
- झील में हर साल गिर रही है एक सेमी गाद
- 140 वर्षों में जमा हुई 130 सेमी गाद

नैनी झील में भीमताल झील से 30 गुना अधिक मलबा समा रहा। फाइल

तल्लीताल तक था भूस्खलन का प्रभाव : प्रो. कोटलिया के अनुसार, 1880 के आल्मा लॉज की पहाड़ी में हुए भूस्खलन का जबरदस्त प्रभाव तल्लीताल क्षेत्र में भी था। उन्होंने कहा कि झील का अस्तित्व बनाए रखने के लिए नैनीताल में कंक्रीट के रास्तों का निर्माण पूरी तरह बंद करना होगा। सीसी मार्ग की वजह से बारिश का पानी व्यर्थ बह रहा है।

सूखाताल में 10 फुट मलबा जमा : प्रो. बहादुर सिंह कोटलिया के अनुसार, सूखाताल में करीब 10 फुट मलबा जमा हो चुका है। उन्होंने कहा कि सूखाताल में केएमवीएन की पार्किंग के दो मंजिले तक झील का कैंचमेंट है। पंप हाउस से लेकर करबला शरीफ तक झील का हिस्सा है। सूखाताल झील क्षेत्र के दायरे में करीब ढाई दर्जन निर्माण हैं। यहां बता दें कि लोनिवि, पालिका व प्राधिकरण के संयुक्त सर्वे में भी सूखाताल में डूब क्षेत्र में तीन दर्जन निर्माण होने की पुष्टि हुई है।

दैनिक जागरण
सबरंग
साहित्य के...
नई दिल्ली, गुरुवार, 6 फरवरी, 2020
सुझाव व प्रतिक्रिया के लिए लिखें : sabrang@nda.jagran.com
https://www.facebook.com/jagransabrang/

स्टोन ग्लास में हुनर की कारीगरी

स्टोन की मूर्ति ही नहीं, यहां तो वॉल लैंप और झूमर में भी गजब का आकर्षण हैं। जागरण

काम की दुकान

स्टोन, ग्लास और सीप पर इतनी अद्भुत और भव्य कलाकारी। रंग और डिजाइन का ऐसा समायोजन कि आंखें एकटक उन्हें निहारती रह जाती हैं। नक्काशी और शिल्पकारी का इससे बेहतर उपयोग और क्या हो सकता है। झूमर और टेबल लैंप से निकल रही नीली, सफेद, पीली रोशनी देख न चाहते हुए भी उसे खरीद ही लेंगे। चांदनी चौक स्थित मेक इन इंडिया कस्टमाइज्ड लाइटिंग बुटीक की सजावटी वस्तुएं एकबारगी दुकान में आने को मजबूर कर ही देती हैं। उम्दा कलाकारी ही तो है, जिसकी बदौलत 65 वर्षों से बुटिक ग्राहकों के बीच अपनी पैठ बनाए हुए है।

वर्ष 1955 में स्वर्गीय गोपी चंद जिंदल ने इस काम की शुरुआत की थी। आज उनकी चौथी पीढ़ी विरासत को संभाल रही है। इनकी नायाब कारीगरी ही है कि देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग झूमर व लैंप की खरीदारी करने यहां आते हैं। बुटीक के मालिक गोपाल जिंदल कहते हैं पांच वर्ष पहले तक दुकान का नाम रवि कुमार एंड संस था, लेकिन मेक इन इंडिया की धारणा से प्रेरित होकर उन्होंने अपने बुटीक का नाम मेक इन इंडिया रख दिया। इसके पीछे तर्क भी है। माल भले ही बाहर से आता है, पर यहां के सभी कारीगर भारतीय हैं। इसलिए यह नाम बिल्कुल उपयुक्त है।

पर्शिअन स्टोन से बने झूमर का आकर्षण : दुकान पर नेचुरल स्टोन, मोजेक, सीप, ग्लास स्टोन, एजिप्शन स्टोन, ब्रास, गन मेटल आदि धातुओं से बनाई गई एक से बढ़कर एक कलाकृतियां मिल जाएंगी। इसके लिए टर्की, यूएई, छत्तीसगढ़, कोलकाता, पटना, पुणे, श्रीनगर व गुवाहटी से पत्थर व ग्लास मंगवाए जाते हैं। जो कोई भी एक बार इनके बुटीक पर आ जाता है वह बिना सामान लिए वापस नहीं जाता। बुटीक में रखे पर्शिअन स्टोन से बने झूमर ग्राहकों को खूब आकर्षित करते हैं। दिल्ली व नोएडा में जिंदल की फैक्ट्रियां हैं, जहां दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि जगहों से आए करीब 60 कारीगर सजावटी वस्तुएं तैयार करते हैं।

ऐसे पहुंचे : चांदनी चौक या लाल किला मेट्रो स्टेशन से बुटीक तक पैदल पहुंचा जा सकता है।
खुलने का समय : सुबह 10 :30 से रात 8 बजे तक यहां खरीदारी कर सकते हैं। रविवार को बुटीक बंद रहता है।

अपने बजट में महल सी सजावट: टेबल लैंप, झूमर, वॉल लैंप, गेट लाइट, कप, मग, दीवार घड़ी, मूर्ति, नेम प्लेट, शीशे आदि तमाम तरह की सजावटी वस्तुएं यहां आप अपने बजट में खरीद सकते हैं। अगर घर में छोटी मोटी पार्टी के लिए लाइटिंग ट्री चाहिए या क्रिसमस ट्री तो आप ऑर्डर देकर उसे भी बनवा सकते हैं। यहां 200 से लेकर 20 लाख रुपये तक के झूमर उपलब्ध हैं। तभी तो यहां हर आय वर्ग के ग्राहक खरीदारी करते नजर आते हैं। मात्र छह से सात दिन में ग्राहकों को आर्डर तैयार करके दे दिया जाता है।

राष्ट्रपति भवन को भी लगा रहे चार चांद: मेक इन इंडिया की सजावटी वस्तुएं केवल आम लोगों के घरों की ही शोभा नहीं बढ़ा रही हैं। प्रसिद्ध क्रिकेटर विरेंद्र सहवाग से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, महाराजा एक्सप्रेस व पंजाब स्थित गोल्डन टेंपल में भी इनकी लाइटें लगी हुई हैं। बेहतरीन कारीगरी के लिए इन्हें कई पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। 2018 में इन्हें बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द इयर अवॉर्ड मिल चुका है।

रितु राणा

लेखन ने मुझे दिल्ली का बना दिया

उपन्यासकार और कहानीकार डॉ. भगवती शरण मिश्र वयस्क पाठकों के बीच तो लोकप्रिय हैं ही साथ ही बाल-मन के भी ये अद्भुत ज्ञाता हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक उच्चाधिकारी के रूप में कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त होकर भी इन्होंने ऐसा लेखन किया कि आज साहित्य जगत में भी बहुत बड़ी पहचान बना चुके हैं। 81 वर्ष में भी यह लेखन के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। प्रस्तुत है ऐसे विलक्षण प्रतिभा से संपन्न भगवती शरण मिश्र से रितु राणा की बातचीत के प्रमुख अंश :

शब्दों की बाजीगरी ही थी जिसने भगवती शरण मिश्र को साहित्य जगत का सितारा बना दिया। जागरण

बातचीत

● **बिहार में जन्म वहीं पढ़ाई और फिर दिल्ली कैसे आना हुआ?**
-हां, जन्म भी बिहार में हुआ, पढ़ाई भी वहीं हुई। फिर 1959 में आइएएस की परीक्षा पास की उसके बाद प्रशिक्षण के लिए नैनिताल गया और बिहार में ही जिलाधिकारी व आयुक्त के पद पर नियुक्त हुआ। इसके बाद अगला पड़ाव आता है सन् 1992 में...जब दिल्ली तबादला हुआ। यहां रेल मंत्रालय के राजभाषा विभाग में निदेशक के पद पर नियुक्त हुआ। बस तभी से मैं दिल्ली का होकर रह गया। अब मैं बिहार बिल्कुल नहीं जाता मुझे इस साहित्यिक नगरी ने पूरी तरह से अपना बना लिया है।

● **आपके साहित्यकार मित्र के साथ जुड़ा कोई रोचक किस्सा साझा करेंगे?**
-दिल्ली में एक शाम कादंबिनी पत्रिका के संपादक राजेंद्र अवस्थी ने मुझे पत्रिका के लिए किसी विषय विशेष पर लेख लिखने की फरमाइश की और शर्त रखी कि दो घंटो में मिल जाना चाहिए। मैंने कहा इतनी जल्दी कैसे कोई लिख सकता है कुछ समय तो दीजिए उन्होंने कहा नहीं अभी चाहिए तुरंत पत्रिका छपने के लिए जाने वाली है। मैं अपने मित्र डॉ. वचन देव कुमार के साथ वहां गया था जो बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में पूर्व प्रोफेसर थे। मैंने कुछ देर सोचा और फिर वचन देव को पकड़ा और बैठाया। मैं बोलने लगा और वो लिखने लगे। बिना किसी संदर्भ-ग्रंथ, बिना किसी चिट पुर्जे मैं एक धाराप्रवाह में बोलता गया और वह लिखते गए।

● **साहित्यिक गोष्ठियों में जाते रहे हैं, उससे जुड़े कुछ संस्मरण?**
-हां, पहले तो साहित्यिक गोष्ठी के लिए सभी बड़े साहित्यकार एक ही जगह जुटते थे। वो थी कनॉट प्लेस स्थित कॉफी हाउस व टी हाउस। मैं भी अक्सर वहां जाता था। साहित्यिक गोष्ठी से एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा मिलती थी जिससे लेखन को एक दिशा मिल जाती थी। साहित्यकार आपस में मिलकर वाद-विवाद व भाषणबाजी भी करते थे। वहीं, पश्चिमी दिल्ली में राजेंद्र अवस्थी के घर पर भी उन दिनों खूब गोष्ठियां होती थीं मैं वहां भी जाता था।

● **उम्र के इस पड़ाव पर भी लगातार लेखन कर रहे हैं?**
-मुझे बचपन से ही पढ़ाई-लिखाई का शौक रहा है। जब हाईस्कूल में आया तो मैंने अपने विद्यालय के पुस्तकालय में रखी सभी पुस्तकें पढ़ डाली थीं। उसके बाद लिखना शुरू किया। स्कूली शिक्षा लेने के दौरान ही एक लेख लिखा था ये भी कोई चाल है....ये लोगों की अलग-अलग तरह की चाल पर लिखा था। जैसे कोई हिलकर चलता है तो कोई बिल्कुल सीधा, कोई दाएं चलता है तो कोई बायं। मेरा यह लेख बाद में प्रयागराज से प्रकाशित होने वाली मनोरमा पत्रिका में भी छपा था।

● **इस शहर में भी बहुत कुछ देखा होगा?**
-बिहार से जब दिल्ली आया तो मेरे घर खूब रिश्तेदार आते थे। वह सोचते थे जब अपने रिश्तेदार दिल्ली में हैं तो होटल में रहने का खर्चा क्यों उठाएं। वह लोग सारा सामान लेकर मेरे घर आ जाते थे और कहीं भी घूमना होता था तो सुबह खाना खाकर निकल जाते थे और शाम को वापस आ जाते थे। कुछ रिश्तेदार तो हरिद्वार भी मेरे ही घर से जाते थे। लेकिन हंसी तो मुझे यह सोचकर आज भी आती है कि मेरे रिश्तेदार खाली हाथ ही आते थे हम सोचते थे कि कुछ लाए होंगे दूसरों के घर खाली हाथ कौन जाता है। एक बार तो ऐसा किस्सा हुआ कि एक रिश्तेदार आए और वो अपने साथ एक बड़ा-सा सेब लेकर आए वो उन्होंने मेरे पलंग के पास रख दिया और बातें करने लगे फिर लौटते हुए वह जो सेब लाए थे उसे उठाकर साथ ही ले गए। एक बार तो कुछ रिश्तेदार दिल्ली घूमने आए थे उन्हें याद आया कि भई रेल मंत्रालय में भगवती जी हैं हमारे जानने वाले हैं क्यों न उनसे ही मिलने चला जाए। वह आए मेरे दफ्तर में मुझसे मिले और बताया कि हम घूमने आए थे तो सोचा आपसे मिल लेंगे और इसी बहाने रेल मंत्रालय भी देख लेंगे।

● **दिल्ली में 8 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान है? कुछ चुनावी अनुभव बताइए, मतदाता के लिए कुछ कहना चाहेंगे?**
–दिल्ली में हमेशा से ही जनता के चुनावी मुद्दे एक जैसे रहे हैं। पहले बैलेट पेपर से मतदान होता था, बहुत ही मुश्किल था लेकिन ईवीएम मशीन के आ जाने से जनता को बहुत सुविधा हुई है। पहले चुनावों में मतदान केंद्र में भी इतनी सुरक्षा नहीं थी जितनी अब है। चुनाव बहुत सुविधा व व्यवस्था जनक हो गए हैं इसलिए आजकल युवा भी चुनावों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, वहीं पहले दिल्ली में सिर्फ दो ही पार्टियों कांग्रेस और भाजपा के बीच चुनावी दंगल होता था लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में आप ने इन दोनों पार्टियों को ऐसी टक्कर दी कि उसने बहुमत से सरकार बनाई और इन दोनों पार्टियों को पीछे छोड़ दिल्ली की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। एक बार का किस्सा याद आया हमारे यहां दो पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव प्रचार के लिए पहुंच गए तो दोनों आपस मे झगड़ने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टी के कार्यकर्ताओं व नेताओं को शांति बनाए रखकर चुनाव प्रचार करना चाहिए। मुद्दों की बात की जाए तो पहले अनाज, पानी जैसे मुद्दे होते थे लेकिन अब असुरक्षित माहौल है, हर तरफ भय का वातावरण है, इसलिए दिल्ली में सुरक्षा का मुद्दा सबसे अहम है। महिला सुरक्षा, स्वस्थ व शिक्षा की आज सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं दिल्लीवासियों से अपील करूंगा अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। सही निर्णय के साथ मतदान करें, किसी से प्रभावित होकर नहीं, शहर के हित में अपने मत का प्रयोग करें।

● **बिहार से हैं तो दिल्ली में छठ से जुड़ी यादें भी रही होंगी?**
-हां, बिहार का तो सबसे बड़ा पर्व ही छठ है, लेकिन अब दिल्ली में भी यह खूब धूमधाम से मनाया जाने लगा है। मुझे भी छठ पर बड़ी उत्सुकता रहती है। छठ का प्रसाद खाए बिना तो यह त्योहार ही अधूरा होता है। मैं जब शुरुआत में दिल्ली आया था तो यमुना नदी के किनारे बने छठ घाट पर जाता था। वहां मेले का खूब आनंद लेता था और ठेकुआ का प्रसाद खाता था। अब भी त्योहार तो नहीं मना पाता लेकिन छठ का प्रसाद लेने घाट पर जरूर जाता हूं।

● **इस उम्र में पत्नी पटना में और आप यहां?**
-दिल्ली जब आए थे तो लाल किला व कुतुबमीनार घूमने का बड़ा शौक होता था अब तो अधिक उम्र हो जाने के कारण कहीं आना जाना नहीं होता। मैं अपने घर में किताबों में ही खोया रहता हूं। एक लेखन ही है जिसने मुझे दिल्ली का बना दिया। लेखन तो बचपन से ही कर रहा था लेकिन दिल्ली में आकर एक दिशा मिली। मेरे दफ्तर में भी साथी कहते थे कि तुम इतना समय कैसे निकाल लेते हो दफ्तर के काम के बाद भी लेखन के लिए इतना समय कैसे निकाल लेते हैं क्या कोई जादू की छड़ी है आपके पास। रही बात पत्नी की तो वह काफी बीमार है यहां उसकी सेवा के लिए कोई नहीं है मेरी भी उम्र हो गई है इसलिए वह पटना में बेटी के पास चली गई हैं। बेटी उनकी खूब सेवा करती है और मेरा अब दिल्ली के अलावा कहीं और मन नहीं लगता है। मैं अपने घर में किताबों के बीच ही समय व्यतीत करता हूं और कुछ न कुछ पढ़ता व लिखता रहता हूं।

● **पहले और अब के साहित्यिक परिवेश में क्या अंतर देखते हैं?**
-पहले अच्छा लेखन होता था हर बड़ा लेखक नए लेखकों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था लेकिन अब वैसा माहौल नहीं रहा। लेखक आपस में बंट गए हैं। आज साहित्य के क्षेत्र में विकृत मानसिकता की राजनीति प्रवेश कर गई है। साहित्य शिविरबद्ध हो गया है। एक साहित्यकार दूसरे साहित्यकार को प्रतिष्ठापित होने में बाधा डालता है। साहित्य का सम्मना करना तो अब स्वभाव में ही नहीं रह गया है। पहले इस तरह गुटबाजी नहीं होती थी। बड़े-बड़े लेखकों को भी अगर किसी नए लेखक की रचना अच्छी लगती थी तो वह उसकी खूब तारीफ करते थे और प्रोत्साहन भी बढ़ाते थे।

● **बढ़ती आबादी के बीच दिल्ली के विकास को आप कैसे देखते हैं?**
-जब मैं दिल्ली में आया तब यहां बहुत शांति थी। लोग कम थे और सड़कें दूर-दूर तक खाली नजर आती थीं। लेकिन आज हम देखें तो सड़कों पर लोगों व वाहनों की भी भीड़ लगी रहती है। लोग सड़कों पर दौड़ते-भागते नजर आते हैं। एक-दूसरे से आगे निकलने की ऐसी होड़ मच गई है कि सड़कों पर भी लोग एक-दूसरे को धक्का मारते हुए चलते हैं। दिल्ली के विकास के साथ इसका नाश भी हुआ है। पेड़ों को काटकर बड़ी-बड़ी इमारतें बना दी गई हैं, जिससे पार्यावरण असंतुलित हुआ है। यही वजह है कि आज दिल्ली में प्रदूषण चरम पर पहुंच गया है। हालांकि दिल्ली वालों को मेट्रो के आने से काफी सुविधा हुई है। इससे लोग बसों की भीड़भाड़ से बच रहे हैं और समय की भी बचत हो रही है।

● **युवा लेखकों को क्या संदेश देंगे?**
-आज युवा जो लिख रहे हैं उसमें गुटबाजी हो गई है। इसलिए मैं युवा लेखकों को थोड़ा ही पढ़ता हूं। सभी युवा लेखक अपने साथियों को आगे लाने के बजाय खुद आगे भाग रहे हैं। मेरी आज के युवा लेखकों को यही राय है कि वह तटस्थ होकर लिखें। वह आदर्शवादी लेखन करें जिससे समाज तक अच्छा संदेश पहुंचे।
ऐसा लेखन करें जो उद्देश्यपरक व मुल्यपरक हो। सच्चा और अच्छा लेखन वही है, जिससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष को कोई ठेस न पहुंचे। ऐसा सत्य बोलना चाहिए जो प्रिय हो लेकिन ऐसा सत्य न बोलें जो किसी को प्रिय न लगे। यही अच्छे व सच्चे लेखक की पहचान है।

● **कोई पुस्तक आने वाली है उसके बारे में बताना चाहेंगे।**
-हां, मैं लगातार लेखन तो कर ही रहा हूं। हाल में भी मेरी एक पुस्तक जनकसुता का प्रकाशन हुआ है। इसके अलावा तीन पुस्तकें जल्द ही पाठकों को पढ़ने के लिए मिलेंगी। इनमें से एक पुस्तक विष्णु चरित्रम आत्मराम संस प्रकाशन व शैलपुत्री राजेश प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की जाएगी। मेरी भगवान में खूब आस्था है इसलिए ज्यादातर धार्मिक रचनाएं भी लिखता हूं।

साढ़े बारह रुपये का पास, एक बीड़ी का बंडल और दिल्ली विवि का वो कमरा

दिल्ली मेरी यादें

अशोक चक्रधर ने बाल साहित्य, प्रौढ़ एवं नवसाक्षर साहित्य, समीक्षा, अनुवाद, पटकथा आदि अनेकों विधाओं में लेखन किया। फिल्म, धारावाहिक में लेखन, निर्देशन के साथ कवि सम्मेलनों के लोकप्रिय व्यक्तित्व रहे। हिंदी सलाहकार समिति, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, हिमाचल कला संस्कृति और भाषा अकादमी के भूतपूर्व सदस्य के पदों पर रह चुके हैं।

वैसे तो पहला परिचय इस शहर से दस वर्ष की उम्र में सन् 61 में हुआ था। जब मैं मेरठ से अपने पिता के साथ इस नायाब शहर को देखने आया था। हम मेरठ से खासकर गोलचा सिनेमा में फिल्म देखने आए थे। तभी कनॉट प्लेस, बाल भवन की रेलगाड़ी, डॉल म्यूजियम, आकाशवाणी पर हम घूमे थे। बिलकुल अपने नाम के अनुकूल ये इंद्रप्रस्थ मुझे इंद्रलोक ही लगा था। फिर कुछ साल बाद जब जिंदगी में प्रवेश परीक्षाओं का दौर आया तो अपने चाचा जी के यहां जो जंगपुरा में रहते थे, वहां आ गए। वो वहां किराए के मकान में रहते थे। यहां जंगपुरा में मुझे सबसे खास लगा निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास स्थित अब्दुल रहीम खान-ए-खाना का मकबरा। मुझे यहां हर तरफ रहीम की मौजूदगी नजर आती थी, उनके दोहे। संघर्ष के उस दौर का शांति और सुकून वहीं तलाशता था। अभी कल की ही बात है रहीम के मकबरा के सामने से गुजर रहा था तो देखा कि वहां पुनरुद्धार का काम चल रहा है, एक कमी महसूस हुई, उसमें रहीम के दोहे...उनकी रचनाओं को भी रेखांकित करना चाहिए। कितना अद्भुत साहित्य रचा उन्होंने जो सदियों से साथ चल रहा है...दोहराया जा रहा है। रहिमन धागा प्रेम का...मत तोड़ो चटकाए...। दिल्ली को इन प्रेम के धागों में गुंथा रहना चाहिए इन्हें चटकाना नहीं चाहिए। इन्हें स्मृतियों के पटल पर सजाकर रखना जरूरी है। मैंने दिलों से दिलों को मिलाती दिल्ली देखी है, पुरानी दिल्ली देखी है...बढ़ती...बदलती... संवरती दिल्ली देखी है। उत्तम नगर की ओर बढ़ती दिल्ली देखी है और इस छोर पर आजादपुर के बाद शालीमार बाग से आगे को चलती दिल्ली देखी है। पूरी दिल्ली धीरे-धीरे नन्हे पांवों से उम्र के साथ पली और बढ़ी है।

बहरहाल 1971 में मैं दिल्ली आ गया था और सन् 72 में मैंने सत्यवती कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक सब ठीक था लेकिन तब उम्र ऐसी थी... और तब वामपंथी विचारधारा...सामाजिक मुद्दों से जुड़ी होती थी। बन गए थे क्रांतिकारी। कॉलेज में यह बात रास नहीं आई। सामाजिक मुद्दों पर कॉलेज की अव्यवस्थाओं पर आवाज उठाने के साथ थियेटर भी किया करता था। फिर कुछ समय बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट फैकल्टी का रूम नंबर 22 ऐसी जगह बन गया जहां साहित्यकारों का जमघट लगने लगा। प्रगति नाम की गोष्ठी होने लगी। यह सिलसिला सन् 75 तक चला था। उन्हीं दिनों हरियाणा के अध्यापकों ने बहुत बड़ी हड़ताल की थी, देशभर के शिक्षक उनके समर्थन में आए थे। मैंने भी मन बना लिया वहां जाने का। उन दिनों सत्यवती कॉलेज के प्रिंसिपल थे डॉ हलधर, उन्होंने मेरे जाने पर विरोध जताया लेकिन मैं वहां चला गया। और इसी पर उन्होंने मुझे आगे कॉलेज में पढ़ाने का अवसर नहीं दिया।

अब यह मेरे संघर्ष का दौर था लेकिन मुझे वह अपना स्वर्णकाल लगता है क्योंकि उसने इतना कुछ सिखाया, लिखाया जिसका आज तक धनी हूं। पैसे की थोड़ी तंगी थी तो उन दिनों रहने का ठिकाना भी दिल्ली विवि में ही होता था। कई सारे अध्यापक थे। अब सभी अविवाहित थे तो एक ही साथ रहते थे। कभी वहां नागार्जुन आ रहे हैं कभी कोई बड़े लेखक आ रहे हैं। सुधीश पचौरी मेरे अच्छे मित्र थे। मुझे बीड़ी पीने की बहुत तगड़ी तलब थी। रोज का एक बंडल तो होता ही था, इसका जिम्मा था सुधीश जी पर क्योंकि वो कमा रहे थे। वो मेरा महीने का कोटा यानी एक पैकेट दे देते थे, उसमें बंडल होते थे 25 महीने में दिन हुए 30, शुरू में तो पूरा कोटा चलता था बस जब माह के पांच दिन बचते तो डोज थोड़ी कम कर देता था ताकि कोटा महीने के अंत तक चला सकूं। अद्भुत दिन थे वो। अरे जामा मस्जिद पर बढ़िया-बढ़िया पुराने कपड़ों की दुकान लगती थीं, वहां से मैं एक बार 5 रुपये का कोट ले आया था बढ़िया पीस था उसे कभी नागार्जुन पहनते, कभी मैं और सुधीश जी। कोई भी अभाव में नहीं था सब मस्तमगन होकर जीते थे। एक दिन मेरे पास विवि के उस रूम की चाबी नहीं थी और बाकी मित्र सब बाहर थे, तो मैं वहां विवि के बाहर फुटपाथ पर ही सो गया। लेकिन उस जिंदगी में अभाव के बावजूद आनंद था।

मुझे दिल्ली की बसों से बेहद लगाव है। मैंने अध्यापक रहते भी बस से ही वो छात्रों वाला पास बनवाया हुआ था। सन् 75 की बात होगी जामिया में मेरी अध्यापक की नौकरी लग गई थी मैं जनकपुरी से तीन बसें बदल कर आता था। बेहद रोमांचित होता था बस का सफर। तभी तो कई सारे कविताएं मेरी इन्हीं बसों की यात्राओं पर भी हैं। तब कनॉट प्लेस को सेंटर मानकर एक सुगम बस सेवा भी शुरू हुई थी जिसका मकसद था केंद्र से परिधि से छूने वाली सेवा। और दूसरी मुद्रिका, वृत्त बनाने वाली मुद्रिका सेवा। आपको एक और दिलचस्प बात बताता हूं, यह श्रेय लेने की बात नहीं, मुद्रिका बस सेवा को मुद्रिका नाम मैंने ही दिया था। दरअसल एक लेखक थे रमेश कौशिक वो कमलापति त्रिपाठी को भी जानते थे। एक दिन उनके यहां एक गोष्ठी थी तो तभी मैंने बातों-बातों में मैंने उन्हें यह मुद्रिका नाम सुझाया और उन्होंने कमलापति जी को बता दिया उन्होंने तय कर दिया। उन दिनों बसों के नंबर भी 1 से 10 नंबर तक ही होते थे।

मनु त्यागी से बातचीत पर आधारित

तन्मयता से करें परीक्षा की तैयारी

फुर्सत का ज्ञान

किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आठ से दस घंटे पूरी तन्मयता के साथ पढ़ाई करना जरूरी है। तब कहीं जाकर बेहतर परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन घर पर ऐसी तैयारी संभव नहीं। इसके लिए तो शांत वातावरण की जरूरत होती है ताकि आपका पूरा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित हो सके। साथ ही कुछ ऐसी किताबें भी उपलब्ध हो जाए जिससे आप और अधिक जानकारी जुटा सकें तो इससे बेहतर और क्या होगा। आपकी इसी जरूरत को पूरा करने के लिए तो तख्ती लाइब्रेरी है। जनकपुरी ए-2 ब्लॉक स्थित इस पुस्तकालय में हर उम्र व हर वर्ग के पाठकों की रुचि व आवश्यकता के अनुसार पुस्तकें मिल जाएंगी। अधिक से अधिक पाठकों को पुस्तकों से जोड़ने के लिए पुस्तकालय संस्थापक आशीष शिकारा ने हाल ही में बुक माय लाइब्रेरी ऑनलाइन साइट की शुरुआत की है। तीन वर्ष पहले शुरू हुई इस लाइब्रेरी की उपयोगिता ही है कि आज इसके साथ 100 अन्य लाइब्रेरी भी चल रही हैं, जिसका पुस्तक प्रेमी लाभ उठा रहे हैं।

सुकून व शांति का एहसास: पढ़ाई करते समय पाठकों का ध्यान न भटके, उनका पूरा ध्यान किताबों पर ही केंद्रित हो इसके लिए यहां एक रीडिंग हॉल बनाया गया है। जहां बैठ पाठक न केवल परीक्षा की तैयारी करते हैं, बल्कि सुकून और शांति के लिए भी वे यहां आते हैं। एकांत में कुछ अच्छी और चुनिंदा किताबों का साथ मिल जाए तो पुस्तक प्रेमियों को और क्या चाहिए। तभी तो पुस्तकालय में रोजाना 100-200 पाठक आते हैं। यहां पुरानी से लेकर नई किताबों के कई विकल्प छात्रों के लिए उपलब्ध हैं। शोधकर्ताओं के लिए भी यह पुस्तकालय बेहद उपयोगी है। दरअसल तख्ती लाइब्रेरी एक मिशन के साथ शुरू हुई थी। जिसका मकसद अधिक से अधिक लोगों तक ज्ञान का प्रकाश फैलाना था। दिल्ली के कई अलग-अलग क्षेत्रों में इसकी शाखा है। आप वहां जाकर भी पुस्तकालय की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

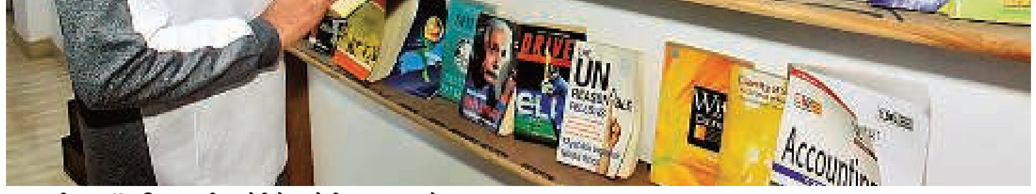

जनकपुरी ए-2 ब्लॉक स्थित तख्ती लाइब्रेरी में उपयोगी पुस्तक तलाशते पाठक। जागरण

ऐसे लें सदस्यता
यहां पढ़ाई करने वाले पाठकों को मासिक सदस्यता दी जाती है। उसके लिए पहचान पत्र जमा कराना होता है। अगर आप रोजाना छह घंटे पढ़ना चाहते हैं तो 800 रुपये देने होंगे। वहीं आठ घंटे के लिए 1000 रुपये व 12 घंटे पढ़ाई करने के लिए 1400 रुपये मालिक शुल्क देने होंगे।

ऐसे पहुंचे
जनकपुरी वेस्ट मेट्रो स्टेशन से महज 10 मिनट की दूरी पर पुस्तकालय है।

खुलने का समय
सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक यहां अध्ययन कर सकते हैं।

भले ही हम डिजिटल युग में जी रहे हों, पर किताबों से आज भी दोस्ती बरकरार है। जागरण

1200 बच्चे आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने: आशीष शिकारा कहते हैं कि पुस्तकालय में ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र आते हैं। छात्रों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए तमाम तरह की पुस्तकें यहां उपलब्ध कराई गई हैं। अगर छात्रों को किसी खास पुस्तक की जरूरत होती है तो उसे खास तौर पर मंगवाई भी जाती है।

पुस्तकें जो करती हैं आकर्षित : वैसे तो पुस्तकालय में किताबों का भंडार है। लेकिन कुछ किताबें ऐसी भी हैं, जो पाठकों को खासा आकर्षित करती हैं। जिन्हें पढ़ने को पाठक उत्सुक रहते हैं। इनमें द व्हाइट टाइगर, मैन अगेंस्ट मिथ, व्हाट इज स्प्रिचुएलिटी, हक हलाल की कमाई, बीकमिंग मिशेल ओबामा, फाइव प्वाइंट समवन चेतन भगत, द जाकिर, द अलकेमिस्ट, हांटेड मैन एंड द घोस्ट्स बरगेन, आइ एम मलाला, ब्रिटेनिका लर्निंग लाइब्रेरी, स्प्रिचुअल मदरिंग सुसान हंट, द पॉयनियर्स ऑफ साइंटिफिक स्क्रिटुएलिटी आदि पुस्तकें यहां आने वाले पाठकों को खासा लुभाती हैं। केवल ये किताबें ही नहीं और भी कई दुर्लभ किताबें भी यहां मौजूद है, जिन्हें पढ़ने दूर-दराज से लोग यहां आते हैं।

रितु राणा

भारत में अस्तित्व पर संकट : वोडाफोन

नई दिल्ली : ब्रिटेन की टेलीकॉम दिग्गज वोडाफोन ने कहा है कि भारत में आइडिया के गठजोड़ से चल रहा उसका कारोबार खतरे में है। कंपनी ने कहा कि वोडाफोन आइडिया को फिलहाल सरकार से मदद की दरकार है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) पर निर्णय दिए जाने के बाद कंपनी कर्ज के बोझ तले दब गई है। टेलीकॉम कंपनियां पहले ही सरकार से छूट दिए जाने की गुहार लगा चुकी है। (प्रेट्र)

टैक्सपेयर्स चार्टर में करदाताओं को मिले अधिकार कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगे। अगर टैक्स फाइल करने की समय-सीमा है, तो उससे संबंधित बाकी प्रक्रियाओं की भी होनी ही चाहिए।
— पीसी मोदी, चेयरमैन, सीबीडीटी

सेंसेक्स	निफ्टी	सोना (प्रति दस ग्राम)	चांदी (प्रति किलोग्राम)	डॉलर	क्रूड (ब्रेंट) (प्रति बैरल)
41,142.66	12,089.15	₹ 40,871	₹ 46,881	₹ 71.24	$ 55.61
▲ 353.28	▲ 109.50	▼ ₹396	▼ ₹179	▼ ₹0.03	

ऑटो एक्सपो में देसी-विदेशी कंपनियों ने धमक के साथ दिखाया मंदी को ठेंगा

जयप्रकाश रंजन, ग्रेटर नोएडा

- कार कंपनियों ने दिखाया दम, नई डिजाइन बनी अगली पीढ़ी की कारों का मंत्र
- सभी प्रमुख देसी-विदेशी कंपनियों ने लांच किए वाहन और नई तकनीक

पिछले दो वर्षों से मंदी से त्रस्त देसी कार कंपनियों ने दिखा दिया है कि घटती बिक्री के बावजूद भारतीय कार बाजार को लेकर उनकी उम्मीदें पहले से भी ज्यादा मजबूत हुई है। एशिया में बिक्री की सबसे बड़े ऑटोमोबाइल प्रदर्शनी 'ऑटो एक्सपो-2020' के पहले दिन देसी-विदेशी कार कंपनियों की रणनीति से साफ हो जाता है कि उनके लिए भारत संभावनाओं वाले बाजार के तौर पर कायम रहेगा। निकट भविष्य में भारतीय पैसेंजर बाजार में एसयूवी कारों का ही बोलबाला रहेगा लेकिन दो-तीन वर्ष बाद इलेक्ट्रिक कारों का दौर शुरू होगा। ऑटो एक्सपो-2020 का एक संदेश यह भी है क मारुति सुजुकी, ह्युंडई, टोटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनियों को आने वाले दिनों में चीन की कार कंपनियों की आक्रामक रणनीति का मुकाबला करने के लिए भी तैयार रहना होगा। इन सभी कंपनियों की तैयारी बताती है कि ये भारतीय ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रिक कारों को लांच करने को तैयार है। लेकिन बेहद महंगी बैट्री और चार्जिंग सुविधा की कमी इनकी राह में एक बड़ी अड़चन है।

एशिया की सबसे बड़ी ऑटो प्रदर्शनी के पहले दिन मीडिया के सामने 15 कार कंपनियों ने करीब 100 वाहनों को पेश किया। देश की दिग्गज कार कंपनियों ने अपनी तीन से पांच वर्षों की रणनीति पेश की। सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने कहा है कि वह कम प्रदूषण फैलाने वाली 10 लाख कारों की बिक्री अगले कुछ वर्षों में करेगी। इसमें इलेक्ट्रिक कारों के अलावा सीएनजी व हाइब्रिड कारें भी होंगी। मिशन ग्रीन मिलियन का घोषणा करते हुए मारुति सुजुकी के एमडी व सीईओ किनिची आयुकावा ने बताया कि कंपनी की भावी रणनीति में कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहन व डिजाइन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कंपनी ने अपनी नई कंसेप्ट डिजाइन फ्यूचरो-ई लांच किया। कंपनी ने डीजल कारों का उत्पादन भी पूरी तरह से बंद करने का एलान किया है। देश की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी ह्युंडई मोटर इंडिया ने अपनी प्रीमियम एसयूवी टस्कन को रीलांच किया है। मारुति की नई ब्रेजा व हुंडई की नई क्रेटा की लांचिंग गुरुवार को होगी। एक साल पहले ही भारतीय बाजार में उतरी किआ मोटर्स ने भारत में अपनी दूसरी कार कार्निवल को लांच किया। इसकी कीमत 24.95 लाख रुपये से 34 लाख रुपये के बीच है। लेकिन कंपनी की अगली कंपैक्ट एसयूवी सोनेट को भी दिखाया गया है जिस पर सभी ऑटोमोबाइल प्रेमियों की नजर होगी। फॉक्सवैगन ने कहा है कि वह भारत में एक अरब यूरो (करीब 7,900 करोड़ रुपये) का नया निवेश करेगी और वर्ष 2023 तक तीन फीसद हिस्सेदारी हासिल करेगी। इसके लिए कंपनी चार नए एसयूवी लांच करेगी। बहुप्रचारित एसयूवी टायगुन को अगले वर्ष लांच किया जाएगा।

इन कंपनियों के मुबाबले देसी कार कंपनियों टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा की भावी तैयारियां ज्यादा सधी हुई दिखती हैं। महिंद्रा ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी ई-केयूवी100 को लांच किया है जिससे बाजार में खासी हलचल मची है। इसकी कीमत 8.25 लाख रुपये रखी गई है जो टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक एसयूवी नेक्सन-ई की 14 लाख रुपये से काफी कम है। हांलाकि नेक्सन-ई एक बार पूरी तरह से चार्ज होने पर 300 किलोमीटर से ज्यादा चलेगी जबकि महिंद्रा की केयूवी-100 फुल चार्जिंग में एक बार में 150 किलोमीटर ही चलेगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा की दूसरी सबसे अहम घोषणा लास्ट माइल कनेक्टिविटी (घर से बस या मेट्रो स्टेशन) के लिए एटम नाम से ई-रिक्शा लांच करने और तीसरी अहम घोषणा देश में वाहन रिसाइकल प्लांट लगाने की है, जो पुराने वाहनों को पूरी तरह से नष्ट करेगी। साथ ही कंपनी ने तीन नए ईंजन भी लांच करने का एलान किया है जो प्रदूषण उत्सर्जन में कटौती के मामले में काफी उन्नत होंगी। कंपनी के एमडी पवन गोयनका ने बताया कि भारतीय वाहन बाजार में अभी 15,000 करोड़ रुपये का नया निवेश किया जा रहा है। टाटा मोटर्स ने दो दशक पहले की अपनी मशहूर एसयूवी सियारा का बिल्कुल नया इलेक्ट्रिक मॉडल लांच करने का एलान कर पूरे ऑटो एक्सपो में हलचल मचाई है। इस घोषणा से उसकी हैरियर-2020 लांच करने की घोषणा भी दब गई है। अगले वर्ष लांच की जाने वाली ग्रावितास को भी पहली बार पेश किया गया है। कंपनी कई अन्य योजनाओं के साथ एक्सपो में उतरी है।

ऑटो एक्सपो में टाटा मोटर्स का पैवेलियन। एएफपी

नई घोषणाएं

- 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगी घरेलू वाहन बाजार में महिंद्रा
- 7,000 करोड़ रुपये के करीब निवेश का वादा लेकर आई चीन की जीडब्ल्यूएम
- 7,900 करोड़ रुपये के आसपास निवेश का लक्ष्य है फॉक्सवैगन समूह का
- मारुति सुजुकी कम प्रदूषण वाली 10 लाख कारों की करेगी बिक्री
- लास्ट माइलेज के लिए महिंद्रा की एटम नाम से ई-रिक्शा लांच
- महिंद्रा ने देश का पहला व्हीकल रिसाइकल प्लांट स्थापित करने का एलान किया

ड्रैगन कार कंपनियों से रहना होगा सतर्क

जागरण ब्यूरो, ग्रेटर नोएडा

- चीन की एमजी मोटर्स और जीडब्ल्यूएम भारत पर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में
- दोनों कंपनियों की नजर भारत में तैयार हो रही नई पीढ़ी के ग्राहकों पर

ऑटो एक्सपो-2020 में चीन की कार कंपनियों ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। चीन की कम से कम चार कार कंपनियां भारत में लंबी पारी खेलने का मन बना चुकी हैं। पिछले वर्ष ही भारत में पदार्पण करने वाली कंपनी एमजी मोटर्स ने कहा है कि वह भारत में दूसरा प्लांट लगाने जा रही है। पिछले चार वर्षों से भारतीय कार बाजार का अध्ययन करने वाली एक दूसरी चीनी कार कंपनी जीडब्ल्यूएम ने बुधवार को 100 करोड़ डॉलर (करीब 7,000 करोड़ रुपये) निवेश करने का एलान किया है। ये दोनो कंपनियां मानती हैं कि भारत दुनिया के सबसे आकर्षक कार बाजारों में है और इसे कोई भी कार कंपनी नजरअंदाज नहीं कर सकती। चीन में बढ़ती लागत की वजह से ये कंपनियां यहां से दूसरे देशों को भी निर्यात करने की मंशा रखती हैं।

एमजी मोटर्स ने ऑटो एक्सपो में बताया कि मांग को देखते हुए उनकी गुजरात स्थित मौजूदा प्लांट की क्षमता कम पड़ सकती है। इसलिए कंपनी दूसरा प्लांट लगाने के बारे में गंभीरता से विचार कर रही है। कंपनी का अभी हलोल (गुजरात) में प्लांट है जो उसने जनरल मोटर्स से खरीदा था और इसकी क्षमता एक लाख यूनिट सालाना से ज्यादा नहीं है। यह क्षमता कंपनी इसी वर्ष पूरा कर लेगी। यही वजह है कि वह अगले दो वर्ष के भीतर दूसरा प्लांट शुरू करने को तैयार है। अगले वर्ष तक कंपनी के पास चार कार मॉडल की लाइन होगी। इसमें दो नई एसयूवी भी होंगी, जबकि एक इलेक्ट्रिक कार होगी।

इसी तरह से एक दूसरी चीन की कार कंपनी जीडब्ल्यूएम के निदेशक (सेल्स व मार्केटिंग) हरदीप बरार ने दैनिक जागरण को बताया कि भारत में कार ग्राहकों की नई पीढ़ी अभी तैयार हो रही है। यह युवाओं से भरपूर बाजार है जो हर तरह की कारों के लिए तैयार है। उनकी कंपनी एक अरब डॉलर का नया निवेश भारत में करेगी। यह निवेश मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट लगाने से लेकर यहां डिजाइन व आएंडडी सेंटर विकसित करने में किया जाएगा। कंपनी भारत को वह अपने वैश्विक संचालन के एक अहम हिस्से के तौर पर देख रही है। भारतीय ग्राहकों को ध्यान में रख कर कई उत्पादों को तैयार करने की रणनीति पर काम हो रहा है। बुधवार को कंपनी ने ऑटो एक्सपो में अपनी नई कंसेप्ट कार हावेल को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित किया। एमजी मोटर्स की तरह यह भी भारत में इलेक्ट्रिक कार बाजार को लेकर भी खासा उत्साहित है। इस बारे में कंपनी को भारत सरकार से स्पष्टता का इंतजार है। कंपनी ने हाल ही में जनरल मोटर्स का तालेगांव प्लांट को खरीदा है।

रूस से कच्चा तेल खरीदेगा भारत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : अमेरिका के बाद दुनिया की एक और बड़ी शक्ति रूस ने भी भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति का फैसला किया है। रूस दशकों से भारत के रक्षा उपकरणों का आपूर्ति करता रहा है और अब ऊर्जा सुरक्षा में भी उसका साथ मिला है। बुधवार को रूस की दिग्गज कंपनी रोजनेफ्ट ने भारतीय तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आइओसीएल) से हाथ मिलाया है। समझौते के मुताबिक रोजनेफ्ट भारत को सालाना 20 लाख टन कच्चे तेल का निर्यात करेगी। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में इसे एक बड़ा कदम बताते हुए कहा है कि यह भारत-रूस के रिश्तों को भी मजबूत करेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि इंडियन ऑयल और रोजनेफ्ट मिलकर तेल व गैस क्षेत्र में परस्पर सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। रोजनेफ्ट के सीईओ इगोर सेचिन के नेतृत्व में एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है।

दरअसल भारत ने पिछले कुछ वर्षों में ऑयल सेक्टर को लेकर अपनी रणनीति बदली है। उज्ज्वला, सिटी गैस वितरण समेत स्मार्ट सिटी परियोजना में क्रूड ऑयल और गैस की भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत की कोशिश है कि क्रूड ऑयल की निर्भरता सिर्फ खाड़ी देशों पर न रहे। यही वजह है कि तेल और गैस के निर्यात के लिए भी भारत ने रूस जैसे पुराने सहयोगियों के साथ सहयोग का दायरा बढ़ाया है। खास बात यह है कि इसके बदले भारत, रूस के तेल और गैस से जुड़ी परियोजनाओं में निवेश भी कर रहा है। इस सिलसिले में पिछले साल सितंबर में प्रधान ने रूस का दौरा भी किया था।

बीपीसीएल को खरीदना चाहती है रोजनेफ्ट : रोजनेफ्ट सरकारी कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के अधिग्रहण के लिए बोली लगा सकती है। कंपनी की इच्छा दुनिया के तीसरे सबसे बड़े बाजार में विस्तार करने की है। प्रधान और सेचिन की बैठक के बाद सूत्रों ने बताया कि कंपनी बीपीसीएल के लिए बोली लगाने की इच्छा रखती है। रोजनेफ्ट के पास भारत की निजी क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में अधिकांश हिस्सेदारी है। दूसरी तरफ सरकार बीपीसीएल में अपनी समूची 53 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने जा रही है।

बैंकिंग कानून में संशोधन को मंजूरी

फायदा ▶ संशोधन के बाद सहकारी बैंकों पर भी लागू होंगे आरबीआइ के बैंकिंग दिशानिर्देश

सहकारी बैंकों के प्रशासनिक मामले को-ऑपरेटिव रजिस्ट्रार ही देखेगा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सरकार ने सहकारी बैंकों में जमाकर्ताओं के धन की सुरक्षा के लिए बैंकिंग नियमन कानून में संशोधन का फैसला किया है। इस आशय के वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में मंजूरी दी गई। देश में करीब 1,540 सहकारी बैंक हैं। तकरीबन 8.60 लाख करोड़ रुपये के जमा आधार वाले इन बैंकों में जमाकर्ताओं के बचाए हुए लगभग पांच लाख लाख करोड़ रुपये जमा हैं।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि प्रस्तावित संशोधन कानून का मकसद भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के बैंकिंग दिशानिर्देशों को सहकारी बैंकों पर भी लागू करना है। हालांकि प्रशासनिक मसले तब भी रजिस्ट्रार ऑफ को-आपरेटिव द्वारा ही तय किए जाएंगे। जावडेकर ने बताया कि प्रस्तावित परिवर्तन सहकारी बैंकों में वित्तीय स्थायित्व लाने में मददगार साबित होंगे। इनके तहत सहकारी बैंकों के सीईओ की नियुक्ति के लिए योग्यता मापदंड निर्धारित किए जाएंगे तथा कॉमर्शियल बैंकों की भांति सीईओ की नियुक्ति से पहले आरबीआइ की अनुमति लेनी होगी।

इसके अलावा सहकारी बैंकों का ऑडिट भी आरबीआइ के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा। यदि किसी सहकारी बैंक के निर्णय से घाटे की स्थिति पैदा होगी तो आरबीआइ को बैंक के बोर्ड के फैसले को पलटने का अधिकार होगा। जावडेकर के मुताबिक आरबीआइ के दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए सहकारी बैंकों को पर्याप्त समय दिया जाएगा।

कैबिनेट का यह फैसला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पहली फरवरी को बजट में की गई घोषणा के अनुरूप है। वित्त मंत्री ने 2020-21 के बजट भाषण में कहा था, 'सहकारी बैंकों को मजबूती प्रदान करने, उन्हें और अधिक पेशेवर बनाने, पूंजी प्राप्ति में सक्षम बनाने, प्रशासनिक सुधार लाने तथा सशक्त बैंकिंग के लिए आरबीआइ के माध्यम से उनकी निगरानी के लिए बैंकिंग नियमन कानून में संशोधन का प्रस्ताव है।'

सरकार के इस निर्णय को पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक (पीएमसी बैंक) में हाल में सामने आए घोटाले के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस घोटाले के कारण आरबीआइ द्वारा लागू की गई बंदिशों के चलते लाखों ग्राहकों को अपनी ही जमा रकम निकालने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जावडेकर ने कहा कि बैंक जमाकर्ताओं की पूंजी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा इस सप्ताह उठाया गया यह दूसरा महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले सरकार बजट में अब तक के एक लाख रुपये की जगह पांच लाख तक की बैंक जमा को सुरक्षा देने का प्रस्ताव रख चुकी है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा था, 'मैं इस सदन को सूचित करना चाहती हूं कि सभी अनुसूचित बैंकों की हालत की निगरानी के लिए एक सशक्त व्यवस्था है और जमाकर्ताओं का पैसा सुरक्षित है। यही नहीं, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआइसीजीसी) को किसी जमाकर्ता के डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज को, जो अभी एक लाख रुपये है, बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने को कहा गया है।' अभी तक की व्यवस्था के तहत बैंक विफल होने पर जमाकर्ताओं को डीआइसीजीसी की ओर से एक लाख रुपये तक की जमा का ही भुगतान किया जाता था।

तेजी बरकरार, 353 अंक चढ़ा सेंसेक्स

मुंबई, प्रेट्र : पिछले तीन सत्रों से देश के प्रमुख शेयर बाजारों में तेजी का रुख बना हुआ है। बुधवार को बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 353.28 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 41,142.66 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई के 50 शेयरों वाले निफ्टी में भी 109.50 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह 12 हजार का मनोवैज्ञानिक स्तर पार कर 12,089.15 के स्तर पर स्थिर हुआ। पिछले तीन सत्रों के दौरान सेंसेक्स में 1,407 अंकों का इजाफा हुआ है।

- पिछले तीन सत्रों के दौरान सेंसेक्स में 1,407 अंकों का इजाफा
- सर्विस सेक्टर की गतिविधियों में तेजी से बाजार उत्साहित

सेंसेक्स पैक में टाटा स्टील के शेयरों में सबसे ज्यादा 5.14 परसेंट का उछाल देखा गया। इसके अलावा भारती एयरटेल, एचडीएफसी, टीसीएस, एलएंडटी और आरआइएल के शेयरों में भी तेजी देखने को मिली। वहीं हीरो मोटोकॉर्प, पावरग्रिड, मारुति सुजुकी, एशियन पेंट्स और एनटीपीसी के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई के सेक्टोरल इंडेक्स में मेटल, टेलीकॉम, रियल्टी, इंडस्ट्रियल्स, कैपिटल गुड्स, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, फाइनेंस, एफएमसीजी और आइटी के शेयरों में 2.90 परसेंट तक की बढ़त देखी गई।

सर्विस सेक्टर की गतिविधियों में तेजी और सकारात्मक ग्लोबल संकेतों के चलते शेयर बाजारों के उत्साह में वृद्धि हुई। इसके अलावा गुरुवार को प्रस्तावित आरबीआइ की मौद्रिक नीति की घोषणा का असर भी संवेदनशील स्टॉक्स पर देखने को मिला। बीते जनवरी में देश के सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट सात वर्षों के शीर्ष पर रही। कोरोना वायरस के सदमे से गुजर रहे चीन की ओर से नीतिगत सुधारों का आश्वासन देने के बाद चीन सहित एशिया के अन्य बाजारों में सकारात्मक माहौल रहा।

सोना-चांदी के भाव में गिरावट

नई दिल्ली, प्रेट्र : बुधवार को स्थानीय सराफा बाजारों में नरमी देखने को मिली। इस दौरान सोना 396 रुपये की गिरावट के साथ 40,871 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिका। वहीं चांदी भी 179 रुपये गिरकर 46,881 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई। जानकारों के मुताबिक घरेलू इक्विटी मार्केट में सुधार और शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में तेजी के चलते सोने के भाव में गिरावट का रुख रहा। ग्लोबल मार्केट में सोना-चांदी का भाव लगभग स्थिर रहा।

इन्वेस्टमेंट मैनेजर के योग्यता नियमों में सुधार करेगा सेबी

नई दिल्ली, प्रेट्र : पूंजी बाजार नियामक सेबी स्टॉक मार्केट के लिए इन्वेस्टमेंट मैनेजर के योग्यता नियमों में सुधार की तैयारी कर रहा है। नियमों में यह सुधार इन्फ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट के मामलों में किया जाएगा। नियमों में सुधार के जरिये राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) द्वारा प्रस्तावित 20 हजार करोड़ रुपये फंड जुटाने में मदद मिलेगी। एनएचएआइ इस समय ट्रस्ट बनाने की प्रक्रिया में है। इस ट्रस्ट के जरिये राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए फंड जुटाया जाएगा। मौजूदा नियमों के मुताबिक इस ट्रस्ट के इन्वेस्टमेंट मैनेजर को फंड मैनेजमेंट के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा उसके पास इन्फ्रा सेक्टर में पांच वर्ष अनुभव वाले कम से कम दो कर्मचारी होने चाहिए।

मध्यम वर्ग सही टैक्स विकल्प चुनने में सक्षम : नीति आयोग

- राजीव कुमार ने कहा- करदाताओं की बचत प्रभावित नहीं होने देना उद्देश्य
- जानकारों ने जताई है बचत प्रभावित होने की है आशंका

नई दिल्ली, प्रेट्र : नीति आयोग ने कहा है कि देश का मध्यम वर्ग अपने लिए सही टैक्स विकल्प चुनने के लिए पर्याप्त सक्षम है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने आम बजट में पेश नई टैक्स प्रणाली पर भरोसा जताते हुए कहा कि इसमें करदाताओं के पास रिटर्न फाइल करने के विकल्प तो होंगे ही, साथ ही उनकी बचत भी प्रभावित नहीं होगी। उन्होंने कहा कि नई प्रणाली में टैक्स प्रक्रिया को काफी आसान कर दिया गया है। इसमें लोगों के पास बिना किसी तरह की छूट का दावा किए कम दरों पर टैक्स चुकाने का विकल्प मौजूद होगा।

सरकार के दावे के विपरीत विशेषज्ञों का मानना है कि नई टैक्स प्रणाली में विकल्प चुनने का मौका देना निजी आयकरदाताओं के लिए सुविधाजनक हो सकता है। लेकिन कॉरपोरेट टैक्स के मामले में इस प्रणाली से जटिलता पैदा होने की आशंका है। कुमार ने कहा कि टैक्स विकल्प चुनने का निर्णय लोगों पर छोड़ देना चाहिए। हमारा उद्देश्य सिर्फ यह है कि लोगों की बचत प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक अर्थशास्त्री होने के नाते उन्हें टैक्स नियमों के लिए विकल्प प्रणाली काफी बेहतर लगी।

हालांकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस की इकोनॉमिस्ट इला पटनायक का कहना था कि आमतौर बुढ़ापे के लिए लोग बचत पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। पुराने तरीके में बचत का पुख्ता प्रबंध है, लेकिन नया विकल्प चुनने पर उनकी बचत प्रभावित होगी। पटनायक ने कहा कि देश के ढांचागत विकास के लिए घरेलू स्तर पर लंबी अवधि की बचतों का होना जरूरी है।

हासिल करेंगे डायरेक्ट टैक्स लक्ष्य : सीबीडीटी

नई दिल्ली, प्रेट्र : टैक्स विभाग को डायरेक्ट टैक्स का संशोधित लक्ष्य हासिल कर लेने की पूरी उम्मीद है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में 11.7 लाख करोड़ रुपये प्रत्यक्ष कर संग्रहण का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। सीबीडीटी के चेयरमैन पीसी मोदी ने बताया कि टैक्स लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए तकनीक का भरपूर सहयोग भी लिया जा रहा है। उनका कहना था कि विभाग टैक्स कलेक्शन को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है और अभी तक के परिणाम उत्साहजनक हैं। मोदी ने बताया कि पिछली तिमाही के दौरान सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन हुआ।

प्रत्यक्ष कर विवादों में नौ लाख करोड़ रुपये फंसे

नई दिल्ली, आइएएनएस : प्रत्यक्ष कर से संबंधित विवादों में फंसी रकम का आंकड़ा करीब नौ लाख करोड़ रुपये तक है। आम बजट में प्रस्तावित 'विवाद से विश्वास' योजना के जरिये अदालत से बाहर टैक्स विवादों को निपटाने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे भारी मात्रा में फंसे हुए टैक्स को हासिल करने में मदद मिलेगी। सरकार पूरे जोर-शोर से इसकी तैयारी में लगी हुई है। बुधवार को विवाद से विश्वास बिल को लोकसभा में पेश कर दिया। इसे जल्द ही संसद में पास होने की उम्मीद है। कानूनी रूप लेने से पहले ही राजस्व विभाग ने इसके लिए जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने टैक्स अधिकारियों से ऐसे करदाताओं से संपर्क करने को कहा है कि जिनके मामले अदालतों में अटके हुए हैं।

मौका

यूरोप और अमेरिका के बायर्स रद कर रहे चीन का दौरा, गारमेंट एक्सपोर्ट में भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है चीन

कोरोना ने दिया गारमेंट बाजार में चीन पर बढ़त बनाने का अवसर

यशलोक सिंह, गुरुग्राम

चीन में उत्पन्न हुए कोरोना वायरस को लेकर इस समय दुनियाभर में खौफ का माहौल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भी इसे लेकर ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर दी है। औद्योगिक विशेषज्ञों का कहना है कि चीन गारमेंट एक्सपोर्ट में भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है। यही वह समय है कि जब दुनियाभर में चीन के कपड़ा आयातकों पर भारत अपना वर्चस्व स्थापित कर सकता है। भारत में गारमेंट एक्सपोर्ट के बड़े हब में शामिल गुरुग्राम (हरियाणा) के कारोबारियों का कहना है कि कोरोना को लेकर यूरोप एवं अमेरिका सहित दुनिया के अन्य देशों के गारमेंट बायर्स ने चीन का दौरा रद करने के साथ-साथ उसे फिलहाल ऑर्डर देना भी बंद कर दिया है। यदि चीन में कोरोना का खतरा लंबे समय तक बना रहा तो चीन गारमेंट एक्सपोर्ट में काफी पिछड़ जाएगा। यही वह समय है जब विंटर सीजन के गारमेंट को लेकर बुकिंग होती है।

गुडग़ांव चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महासचिव एसके आहूजा ने कहा कि निश्चित रूप से यह कारोबारी अवसर भारत के लिए पैदा हुआ है। यदि गारमेंट एक्सपोर्टर अपने लिए नए बाजार की तलाश में जुट जाएं तो उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। इस मामले में सरकार को भी एक्सपोर्टरों की मदद करनी चाहिए। चीन में संकट को देखते हुए दुनिया भर के बड़े-बड़े बायर्स इस समय तेजी से भारत की ओर आकर्षित होंगे। ऐसा इसलिए कि भारतीय परिधानों की गुणवत्ता दुनियाभर में सबसे अच्छी है। वहीं, गारमेंट एक्सपोर्टर अनिमेश सक्सेना का कहना था कि यदि चीन में कोरोना वायरस का संकट और दो माह बना रहा तो उसके गारमेंट सेक्टर को बड़ा नुकसान होगा।

चीन व ताइवान से मुंह मोड़ने लगे दुनियाभर के उद्यमी

मुनीश शर्मा, लुधियाना : चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण हर कोई चिंता में है। उद्यमी चीन और ताइवान के दौरों से मुंह मोड़ने लगे हैं। वे कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। इससे लुधियाना में इंडस्ट्री का उत्पादन प्रभावित हो सकता है।

कोरोना वायरस के कारण कारोबारियों का चीन से संपर्क लगभग टूट गया है। चीन से भारत में भारी मात्रा में स्टील, साइकिल, मशीनरी से जुड़े उत्पादों का आयात होता है। लुधियाना से हर साल 1,200 से अधिक उद्यमी मशीन, पाट्र्स की खरीदारी और अन्य ऑर्डर लेने चीन जाते हैं। ऐसे में इसका असर साइकिल पाट्र्स, मशीन टूल, मशीनरी और हैंडटूल पर पड़ा है। उद्यमी वहां से अब मैटीरियल मंगवाने से भी कतरा रहे हैं।

भारत में चीन से छह लाख करोड़ रुपये का आयात और 1.25 लाख करोड़ रुपये का निर्यात है। शिपिंग कंपनियों ने फूड एवं प्लास्टिक से जुड़े उत्पादों की खेप लेने से मना कर दिया है। वहीं अन्य उत्पादों की देरी के साथ-साथ व्यापार के लिए दोनों देशों में होने वाले दौरे भी प्रभावित हो रहे हैं। एवन साइकिल लिमिटेड के सीएमडी ओंकार सिंह पाहवा के मुताबिक हर इंडस्ट्री के पास एक महीने का स्टॉक रहता है। वैसे भी चीन में जनवरी में न्यू ईयर हॉलिडे सीजन रहता है। अगर 15 फरवरी के बाद भी कोरोना वायरस का प्रकोप रहा तो इंडस्ट्री की प्रोडक्शन कुछ उत्पादों में प्रभावित हो सकती है। इसमें साइकिल के कुछ पाट्र्स के साथ-साथ इलेक्ट्रिक एवं ई-स्कूटर शामिल हैं। फोपसिया के चेयरमैन बदीश जिंदल के मुताबिक चीन में फैले कोरोना वायरस के कारण उद्यमी वहां जाने से कतराने लगे हैं। कई कारखानों में तो आयात के कंटेनर लाने के लिए भी गुरेज किया जा रहा है। फैंसी साइकिलों की बिक्री भी चीन से आयात के बिना संभव नहीं है।

सूरत में 8,000 करोड़ रुपये के हीरा कारोबार पर खतरे की घंटी

- वायरस के कारण हांगकांग में लागू है आपातकाल
- प्रतिवर्ष 50,000 करोड़ रुपये के हीरों का हांगकांग को होता है निर्यात

सूरत, प्रेट्र : कोरोना वायरस के चलते सूरत के हीरा कारोबार को अगले दो महीनों में करीब 8,000 करोड़ रुपये का नुकसान होने की आशंका है। चीन में कोरोना वायरस फैलने के बाद हांगकांग ने आपातकाल घोषित कर दिया है। सूरत के हीरा व्यवसायी हांगकांग को बड़ी मात्रा में हीरा निर्यात करते हैं। जानकारी के मुताबिक मार्च के पहले सप्ताह तक हांगकांग के स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। इस दौरान कारोबार भी बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है।

जेम्स एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (जीजेईपीसी) के रीजनल चेयरमैन दिनेश नवाडिया के मुताबिक प्रति वर्ष सूरत से हांगकांग को करीब 50,000 करोड़ रुपये कीमत के पॉलिश हीरे निर्यात किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि हांगकांग में छुट्टी घोषित होने के कारण करीब 37 परसेंट हीरा निर्यात खतरे में पड़ गया है। हांगकांग में कार्यालय बनाकर काम कर रहे गुजराती कारोबारी अपने देश वापस लौट रहे हैं।

नवाडिया के अलावा कई अन्य कारोबारियों ने चिंता जताई कि अगर हालात में जल्द सुधार नहीं हुआ तो सूरत का हीरा कारोबार खतरे में पड़ जाएगा। गौरतलब है कि कुल हीरा निर्यात का करीब 99 परसेंट हिस्सा सूरत में ही पॉलिश किया जाता है।

1000 मरीजों की बिना आवश्यकता के सर्जरी करने के आरोप में ब्रिटेन में एक सर्जन को गिरफ्तार किया गया है। इयान पैटरसन नाम के सर्जन ने अपने मरीजों को पहले उपचार के नाम पर गंभीर घाव दिए फिर कैंसर के नाम पर डराकर उनका ऑपरेशन किया।

कोरोना से निपटने को चीन ने वुहान में तैनात की सेना

बढ़ रहा प्रकोप ▶ जान गंवाने वालों की संख्या 500 के करीब, 24 हजार से ज्यादा संक्रमित

27 देशों में कोरोना वायरस के 230 मामलों की पुष्टि

बीजिंग, एजेंसियां : चीन ने तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में सेना तैनात कर दी है। इसी शहर से पूरे चीन समेत दुनिया के करीब 27 देशों में यह रहस्यमय वायरस फैल गया है। इन देशों में भी करीब 230 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। चीन में जान गंवाने वालों की संख्या 500 के करीब पहुंच गई है। अब तक 24 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। चीन से बाहर हांगकांग और फिलीपींस में भी एक-एक मौत हो चुकी है।

महामारी का केंद्र माने जा रहे वुहान में महज नौ दिन में बनाए गए अस्थायी हुओशेनशान अस्पताल को चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। सेना ने सोमवार से शुरू हुए एक हजार बेड की क्षमता वाले इस अस्पताल में 1400 स्टाफ की तैनाती की है। शहर के कई अन्य अस्पतालों में भी सेना के मेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई है। सेना के कई चिकित्सा शोध संस्थान अध्ययन और वैक्सीन तैयार करने में जुट गए हैं। गत 29 जनवरी को राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने पीएलए को महामारी की रोकथाम में अपनी भूमिका निभाने का आदेश दिया था।

ताइवान ने चीन से आने वालों पर लगाई रोक : स्वायत्तशासी ताइवान ने चीन से आने वालों पर रोक लगा दी है। ताइवान की सरकार ने कहा है कि चीन में रहने वाले लोग गुरुवार से ताइवान में दाखिल नहीं हो सकेंगे।

ड्रोन से दे रहे कोरोना से बचाव की जानकारी : चीन में महामारी का रूप लेते जा रहे कोरोना वायरस के संक्रमण पर काबू पाने के लिए सभी तरह के संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मध्य चीन के हुबेई प्रांत की इस तस्वीर में पुलिस अधिकारी कोरोना वायरस से बचाव और नियंत्रण के लिए ड्रोन के माध्यम से लोगों को जानकारियां दे रहे हैं। चीन में संक्रमण खत्म करने के लिए दवाओं का छिड़काव भी ड्रोन से किया जा रहा है। रायटर

दो क्रूज पर फंसे हजारों पर्यटक, 13 में वायरस की पुष्टि

कोरोना वायरस का डर इस कदर बढ़ गया है कि दो क्रूज जहाजों से हजारों यात्रियों को उतरने नहीं दिया जा रहा। एक क्रूज जापान तट के पास रोका गया है। उस पर करीब 3700 लोग सवार हैं। जापानी अधिकारियों ने डायमंड प्रिंसेज क्रूज पर सवार दस लोगों में वायरस पाए जाने की पुष्टि की है। हांगकांग में भी एक क्रूज पर 1800 से ज्यादा लोग फंसे हैं। वहां भी तीन लोगों में वायरस की पुष्टि हुई है।

कैथे पैसिफिक एयरलाइंस ने स्टाफ को छुट्टी पर भेजा

हांगकांग की एयरलाइन कैथे पैसिफिक ने अपने सभी स्टाफ को तीन हफ्ते की अवैतनिक छुट्टी पर भेज दिया है। कोरोना वायरस के मद्देनजर एयरलाइन के सीईओ ने बुधवार को यह एलान किया। इस एयरलाइन के करीब 27 हजार कर्मचारी हैं।

30 घंटे पहले जन्मा शिशु भी वायरस की चपेट में आया

वुहान में जन्म के महज 30 घंटे बाद ही एक शिशु को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। इस वायरस की चपेट में आने वाला शिशु सबसे कम उम्र का पीड़ित बताया जा रहा है। शिशु के जन्म से पहले ही महिला में वायरस की पुष्टि हुई थी।

हरियाणा में कोरोना के 136 संदिग्ध, आइसोलेशन वार्ड में भर्ती

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : चीन से फैले कोरोना वायरस के हरियाणा में 136 संदिग्ध मिले हैं, जिन्हें जिला मुख्यालयों पर स्थापित आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। चीन से लौटे इन संदिग्ध मरीजों में से अभी तक किसी में भी कोरोना की पुष्टि नहीं हुई है। कुल सात सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें पांच की रिपोर्ट निगेटिव आई है। बुधवार को करनाल, गुरुग्राम और हिसार में एक-एक नए संदिग्ध मरीज अस्पतालों में दाखिल हुए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक हिसार में सर्वाधिक संदिग्ध हैं, जबकि सिरसा दूसरे और करनाल तीसरे नंबर पर है। कुल बारह जिलों में संदिग्ध मरीजों को निगरानी में रखा गया है। बीमारी से पीड़ित संदिग्ध लोगों की सूचना के लिए प्रदेश सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 8558893911 शुरू किया गया है। इस पर 70 कॉल आ चुकी। पहली जनवरी के बाद चीन से लौट रहे सभी लोगों से स्वघोषित प्रमाणपत्र लिया जा रहा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि एहतियात के तौर 151 अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, जिनमें 54 सरकारी और 97 निजी अस्पताल हैं। रोहतक मेडिकल यूनिवर्सिटी में गंभीर मरीजों के लिए टर्शरी सेंटर बनाते हुए डॉ. ध्रुव चौधरी को नोडल अफसर की जिम्मेदारी दी गई है।

कोरोना वायरस से अधिक खतरनाक थे सार्स और मर्स वायरस, जानें एक्सपर्ट की जुबानी

आम धारणा के विपरीत दिल्ली के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फेफड़े और श्वसन मामलों के एक्सपर्ट डॉक्टर विवेक सिंह बता रहे हैं कि कोरोना वायरस उतना खतरनाक नहीं है जितना सार्स और 2012 का मर्स वायरस।

अब देखें कोरोना वायरस से जुड़ी खास खबर ऊपर छपी तस्वीर को Google Lens से स्कैन करके

वीडियो देखने के लिए

1. अपने मोबाइल पर Google Lens App डाउनलोड करके OPEN करें. Go to goo.gle/lens, or use the Google Lens App on Android/Google App on iOS
2. ऊपर छपी तस्वीर को Google Lens के साथ स्कैन करें
3. छपी तस्वीर पर आधारित विश्लेषणात्मक वीडियो देखें

न्यूज गैलरी

विलियम ने चखा आइसक्रीम का स्वाद : ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी ड्यूक ऑफ कैंब्रिज केट बुधवार को वेल्स के मुंबल्स स्थित आइसक्रीम पार्लर पहुंचे। इस दौरान प्रिंस ने आइसक्रीम का स्वाद चखा। उन्हें आइसक्रीम खाता देखकर मुस्कुराती केट मिडलटन। उनके छोटे भाई हैरी ने हाल ही में अपना राजशाही का दर्जा छोड़ दिया है और आम आदमी की भांति कनाडा के एक द्वीप में जीवन-यापन शुरू कर दिया है। एएफपी

केटी पेरी बनीं प्रिंस चार्ल्स के ट्रस्ट की भारत से जुड़ी दूत

केटी पेरी। फाइल

वाशिंगटन : ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने अमेरिकी गायिका केटी पेरी को ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के भारत से जुड़े बाल संरक्षण कोष का नया दूत नियुक्त किया है। वर्ष 2007 में स्थापित ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट एक चैरिटी संस्था है। प्रिंस चार्ल्स ने दक्षिण एशियाई परिवारों की गरीबी और कठिनाईयां देखने के बाद इस ट्रस्ट की स्थापना की थी। पेरी को दूत बनाने की घोषणा लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान की गई। इस मौके पर प्रिंस चार्ल्स ने केटी पेरी और नताशा पूनावाला समेत ट्रस्ट के कई समर्थकों से मुलाकात की। प्रिंस चार्ल्स से पेरी की पहली मुलाकात मुंबई में ब्रिटिश एशियाई ट्रस्ट की एक बैठक के दौरान हुई थी। पेरी ने कहा, 'यूनिसेफ की सद्भावना दूत के तौर पर मैंने दुनिया के कई हिस्सों की यात्रा की। इस दौरान बच्चों की हालत देखकर मेरी आंखें खुल गईं। बाल तस्करी में कमी लाने की प्रिंस चार्ल्स की दृढ़ योजना है।' (एएनआइ)

प्रिंस हैरी को अपार्टमेंट किराये पर देना चाहती हैं मैडोना

न्यूयॉर्क : पॉप गायिका मैडोना ने प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन को न्यूयॉर्क का अपना अपार्टमेंट किराये पर देने का प्रस्ताव रखा है। हैरी और मेगन के ब्रिटिश शाही परिवार से अलग होने और उत्तरी अमेरिका में रहने की इच्छा जताने के बाद मैडोना की तरफ से यह प्रस्ताव दिया गया है। मैडोना ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने हैरी-मेगन और उनके बेटे आर्ची को मैनहट्टन स्थित अपार्टमेंट में रहने का प्रस्ताव दिया है। शीशे के सामने बैठीं मैडोना कैमरे की तरफ देखती हुईं कहती हैं, हैरी कनाडा मत जाओ, वह जगह बहुत उबाऊ है। सेंट्रल पार्क वेस्ट में मेरा दो बेडरूम का अपार्टमेंट किराये पर खाली है। इसकी बालकनी तो अपने आप में अद्भुत है। वहां से पूरा मैनहट्टन नजर आता है। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए यह बहुत अच्छी डील होगी।' वीडियो के कैप्शन में मैडोना ने लिखा है कि क्या मेगन और प्रिंस हैरी सेंट्रल पार्क स्थित मेरा अपार्टमेंट किराये पर लेना चाहेंगे। मेगन और उनका बेटा आर्ची इस साल की शुरुआत से ही कनाडा के वेंकूवर द्वीप में रह रही हैं। (आइएएनएस)

आयोवा प्राइमरी चुनाव में सबसे आगे रहे युवा बटीगीग

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका में विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी चुनाव का रोचक आगाज हुआ है। राष्ट्रपति उम्मीदवारी की दौड़ में जिन बड़े नामों को आगे माना जा रहा था, वे आयोवा प्रांत से शुरू हुए पार्टी के आंतरिक चुनाव में पिछड़ गए। इस चुनाव में अमेरिका के एक छोटे से शहर के पूर्व मेयर पेट बटीगीग (38) अप्रत्याशित विजेता बनकर उभरे।

डेमोक्रेटिक पार्टी में राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया के तहत सोमवार को आयोवा में चुनाव कराया गया। तकनीकी खामी के कारण देर से आए नतीजों में पार्टी डेलीगेट्स ने 78 साल के बर्नी सैंडर्स और 77 वर्षीय जो बिडेन की जगह इंडियाना के साउथ बेंड शहर के मेयर रह चुके युवा नेता बटीगीग को तवज्जो दी। उन्हें 26.9 फीसद मत मिले। सैंडर्स (25.1 फीसद) दूसरे और सीनेटर एलिजाबेथ वारेन (18.3 फीसद) तीसरे स्थान पर रहीं। उम्मीदवारी के प्रबल दावेदार बताए जा रहे बिडेन 15.6 फीसद वोट के साथ चौथे स्थान पर पिछड़ गए। आयोवा से ही ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के प्राइमरी चुनाव की शुरुआत हुई है। इसमें ट्रंप के पक्ष में 97 फीसद मत पड़े।

पूर्व मेयर पेट बटीगीग। फाइल

यह है प्राइमरी चुनाव की प्रक्रिया : अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव व्यवस्था में दोनों प्रमुख सियासी पार्टियां रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक अपने उम्मीदवार चुनने के लिए सभी 50 राज्यों में बारी-बारी से प्राइमरी चुनाव कराती हैं। इन चुनावों में राज्यों के पार्टी प्रतिनिधि मतदान करते हैं। प्राइमरी चुनाव जीतने वाले को ही दोनों पार्टियां अपना उम्मीदवार घोषित करती हैं।

प्रत्यर्पण से बचने को संजीव चावला पहुंचा यूरोपीय कोर्ट

लंदन, प्रेट्र : लंदन हाई कोर्ट में प्रत्यर्पण के खिलाफ अर्जी खारिज होने के बाद संजीव चावला ने भारत जाने से बचने के लिए मानवाधिकारों की यूरोपियन कोर्ट में याचिका दायर की है। कारोबारी संजीव क्रिकेट मैच फिक्सिंग मामले का आरोपी है और भारत में उसके खिलाफ मामला दर्ज है। मामले की भारतीय अदालत में सुनवाई से बचने के लिए वह प्रत्यर्पण का विरोध कर रहा है।

50 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक संजीव चावला ने ब्रिटेन के गृह मंत्री रहे साजिद जावीद के प्रत्यर्पण आदेश को लंदन हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन 23 जनवरी को हाई कोर्ट ने उसकी वह अर्जी खारिज कर दी थी। उसके 28 दिनों के भीतर उसे भारत भेजा जाना था। लेकिन उससे पहले ही संजीव ने फ्रांस के स्ट्रासबर्ग स्थित यूरोपियन कोर्ट में बचाव के लिए अर्जी दे दी है। यूरोपीय देशों के बीच मानवाधिकारों को लेकर हुए समझौते में ब्रिटेन भी शामिल है। कोर्ट की प्रवक्ता ने बताया है कि संजीव चावला ने 29 जनवरी को अपना प्रत्यर्पण रोकने के लिए अर्जी दी है। कोर्ट ने उसकी अर्जी पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया है।

कोरोना वायरस के इलाज में एचआइवी-रोधी दवा के सीमित इस्तेमाल को मंजूरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत के औषधि महानियंत्रक (डीजीसीआइ) ने कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज में एचआइवी संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दवाओं के कांबिनेशन के सीमित प्रयोग को मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य संबंधी शोध कार्यों की शीर्ष संस्था भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) ने सांस संबंधी इस बीमारी के इलाज में दो दवाओं के कांबिनेशन के सीमित इस्तेमाल के लिए डीजीसीआइ से आपात अनुमति मांगी थी। ये दवा हैं-लोपिनेवियर और रिटोनेवियर।

आइसीएमआर के एक अधिकारी ने बताया कि हमने इन दवाओं को लेकर कुछ अध्ययन किए हैं और पाया है कि कोरोना वायरस के इलाज में इन दवाओं का कांबिनेशन कारगार साबित हो सकता है। इस कंबिनेशन का कुछ अन्य दवाओं के साथ चीन में भी प्रयोग किया जा रहा है। थाइलैंड में इसके इस्तेमाल से कोरोना वायरस के एक मरीज का सफलतापूर्वक इलाज भी हो चुका है। सूत्रों ने बताया कि इन दोनों दवाओं के इस्तेमाल से पहले डॉक्टर को मरीज की मंजूरी लेनी पड़ती है।

बता दें कि भारत में अब तक तीन मरीजों के कोरोना वायरस से पीड़ित पाया गया है। ये तीनों ही मामले केरल में सामने आए हैं। इनमें एक छात्रा और दो छात्र हैं, जो कोरोना वायरस के केंद्र चीन के वुहान शहर में पढ़ाई कर रहे थे और हाल ही में वहां से लौटे थे। इन्हें विभिन्न अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और उनकी हालत स्थिर बताई गई है। इसके अलावा कोरोना वायरस के लक्षण वाले कई लोगों को भी चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है, हालांकि, तीन को छोड़कर देश में कोरोना वायरस का कोई दूसरा मामला सामने नहीं आया है।

केरल के कांग्रेस सांसदों ने केंद्र से राज्य के लिए वित्तीय मदद मांगी: लोकसभा में बुधवार को केरल से कांग्रेस के सदस्यों ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्र से राज्य सरकार को वित्तीय मदद मुहैया कराने की मांग की। शून्य प्रहर के दौरान कांग्रेस की राम्या हरिदास ने कहा कि यद्यपि कि केरल सरकार निवारक कदम उठा रही है, इसके बावजूद और अधिक सतर्कता बरते जाने की जरूरत है। इसके लिए वित्तीय इंसेंटिव की जरूरत है। वो केंद्र सरकार से केरल को स्पेशल पैकेज देने और वहां एक विशेष टीम भेजने का अनुरोध करती हैं।

केंद्र सरकार ने फिर जारी की एडवाइजरी: इस बीच, केंद्र सरकार ने चीन से आने वाले लोगों को लेकर एक नई एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि चीन से आने वाले सभी लोगों को पहले से जारी वीजा को अवैध घोषित कर दिया गया है। इसमें चीन के नागरिकों के साथ ही विदेश नागरिक भी शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में देश के लोगों से भी चीन की यात्रा करने से बचने की सलाह दी है।

फिनलैंड देगा सात माह का पितृत्व अवकाश

हेलसिंकी, रायटर : यूरोपीय देश फिनलैंड की सरकार मातृत्व अवकाश की तरह ही पितृत्व अवकाश को भी सात महीने करने पर विचार कर रही है। स्वास्थ्य और सामाजिक मामलों की मंत्री आइना केसो पेकोनेन ने बुधवार को कहा, इस घोषणा का मुख्य उद्देश्य लैंगिक समानता के साथ ही देश में गिरती जन्मदर को सुधारना है। इससे माता-पिता और परिवारों के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित होगा। उन्होंने बताया कि 2010 से 2018 के बीच देश में बच्चों की जन्मदर में पांच गुना तक कमी आई है।

इस दौरान देश में सिर्फ 47,577 बच्चे जन्मे थे। स्वीडन, आइसलैंड जैसे अन्य देशों ने भी पितृत्व अवकाश देकर अपनी जन्मदर में सुधार किया है। फिनलैंड में पांच दलों की गठबंधन सरकार है और पांच बड़े मंत्रालयों की कमान महिलाओं के हाथ में है। खास बात यह है कि इन सर्वाधिक शक्तिशाली पांच महिलाओं में से चार की उम्र 35 साल से भी कम है। पिछले महीने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में प्रधानमंत्री सना मारिन ने सरकारों और कंपनियों से महिलाओं के साथ उचित व्यवहार करने का आह्वान किया था।

'हिंदू राष्ट्रवाद का जिन्न बोतल से बाहर, अब वापस नहीं जाएगा'

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से कश्मीर राग अलापते हुए कहा है कि अनुच्छेद 370 हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घातक गलती की है। जम्मू-कश्मीर को लेकर यह ऐसी गलती है, जिससे मोदी अब कदम पीछे नहीं खींच सकते। भारत में हिंदू राष्ट्रवाद का जिन्न बोतल से बाहर आ गया है और अब वह वापस उसमें नहीं जा सकता।

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की विधानसभा को संबोधित करते हुए इमरान ने कहा, जम्मू-कश्मीर में मोदी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह पाकिस्तान का विरोध कर चुनाव जीते हैं। इमरान ने दावा किया कि इस तरह के फैसलों का अंतिम परिणाम कश्मीर की आजादी होगा। पांच अगस्त, 2019 के मोदी के कदम से कश्मीर आजादी की दिशा में आगे बढ़ गया है।

मोदी ने अगर यह कदम न उठाया होता तो हम कश्मीर मसले को इतनी मजबूती से दुनिया के सामने नहीं रख पाते। मोदी के फैसले के बाद हमारी जिम्मेदारी बन गई कि हम पूरे वाकये से दुनिया को जानकार बनाएं। इमरान का यह बयान पाकिस्तान के कश्मीर एकजुटता दिवस पर आया। पाकिस्तान कश्मीरी लोगों को समर्थन देने के लिए हर साल पांच फरवरी को यह दिवस मनाता है। इस दिन बड़े नेता भारत के साथ संबंधों में तनाव बढ़ाने वाले बयान देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पाकिस्तान को सात से दस दिन के भीतर जीत लेने के बयान पर इमरान ने कहा, कोई भी सामान्य व्यक्ति इस तरह की बात नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, पाकिस्तान मोदी को कोई भी ऐसा मौका नहीं देगा जिससे वह कश्मीर से दुनिया का ध्यान हटा सकें। भले ही वह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर मामूली कार्रवाई ही क्यों न कर डालें।

इमरान खान। फाइल

ट्रंप ने हाथ नहीं मिलाया, स्पीकर ने भाषण की प्रति फाड़ी

अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस के दौरान काफी अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो गई। दरअसल, दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधन से पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैंसी पोलेसी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया, परंतु ट्रंप ने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और अपनी सीट की ओर बढ़ गए। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने जैसे ही अपना भाषण खत्म किया स्पीकर पेलोसी ने सबके सामने स्पीच की कॉपी को फाड़ दिया। उपराष्ट्रपति माइक पेंस भी चुपचाप देखते रह गए। एएफपी

अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक वापस बुलाएंगे : ट्रंप

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को फिर अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की बात कही। उन्होंने हालांकि इसकी कोई समयसीमा नहीं बताई है।

ट्रंप ने यह भी साफ किया है कि तालिबान के साथ शांति समझौते के बाद अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में किसी प्रकार का दखल नहीं देंगे। तालिबान के साथ नौ दौर की वार्ता के बाद ट्रंप ने पिछले साल सितंबर में एक आत्मघाती हमले में अमेरिकी सैनिक की मौत के बाद बातचीत रोक दी थी। लेकिन नवंबर में उन्होंने फिर वार्ता शुरू करने की घोषणा की थी।

अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, अफगानिस्तान में हमारे सैनिकों के प्रयासों से क्षेत्र में हमारी स्थिति मजबूत है। तालिबान के साथ शांति वार्ता चल रही है। हमारे सैनिक सबसे अच्छे हैं। वे या तो जीतने के लिए लड़ते हैं या फिर बिल्कुल नहीं लड़ना चाहते। हम अमेरिका के सबसे लंबे युद्ध को खत्म करने की हरसंभव कोशिश कर रहे हैं। हम अपने सैनिकों को वापस लाना चाहते हैं। अफगानिस्तान में अभी अमेरिका के करीब 14 हजार सैनिक हैं। अब जल्द ही इनके वापसी की कार्रवाई शुरू हो सकती है।

पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध को खत्म करने की बात दोहराई: राष्ट्रपति ट्रंप ने पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध को भी समाप्त करने की बात कही। उन्होंने कहा, तीन साल पहले आइएस का इराक और सीरिया के करीब 52 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा था। लेकिन आज आइएस सरगना बगदादी मारा जा चुका है। हमारी सरकार देश की राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही कट्टर इस्लामिक आतंकवाद का भी डटकर मुकाबला कर रही है।

अफगानिस्तान ने पाक को भारत विरोध करने से रोका

काबुल, प्रेट्र : अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक लक्जरी होटल में भारत विरोधी कार्यक्रम वहां के प्रशासन ने नहीं होने दिया। इस कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को काबुल का पाकिस्तानी दूतावास कर रहा था। यह आयोजन इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में होना था। सूत्रों के अनुसार कार्यक्रम में भारत विरोधी प्रस्तुति की जानकारी मिलने पर अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने आयोजन को लेकर दी गई अनुमति रद कर दी। इसके बाद होटल प्रबंधन ने भी इस बाबत बुकिंग को रद कर दिया। इस बाबत जारी अफगान विदेश मंत्रालय के पत्र में कहा गया है कि यह दो देशों की मित्रता से जुड़ा मामला है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान हर साल की पांच फरवरी को कश्मीरी लोगों के प्रति अपने समर्थन का इजहार करने के लिए एकजुटता दिवस मनाता है। संयोग से बुधवार को बड़ी संख्या में लोगों ने काबुल स्थित पाक दूतावास के समक्ष प्रदर्शन कर पख्तून नेता मंजूर पशतीन की रिहाई की मांग की।

मलेशिया में पूर्व पीएम की पत्नी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा शुरू

कुआलालंपुर, एएफपी: मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक की पत्नी रोसमा मंसूर के खिलाफ बुधवार से कुआलालंपुर हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। उन पर पति के सत्ता में रहने के दौरान भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप है। वर्ष 2018 में रज्जाक के चुनाव हारने के बाद पुलिस ने उनके घर पर छापा मारकर करीब दो हजार करोड़ रुपये का सामान बरामद किया था।

रोसमा पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी परियोजनाएं की मंजूरी दिलाने के एवज में रिश्वत ली। अभियोजन के अनुसार, बोर्नियो द्वीप के सरकारी स्कूलों में सोलर पावर जनरेटर का टेंडर दिलाने के लिए उन्होंने एक कंपनी से 65 लाख रिंगिट (करीब साढ़े ग्यारह करोड़ रुपये) की रिश्वत ली थी। बुधवार को रोसमा एक कार में बैठकर अदालत आईं और सीधे अंदर चल गईं। सुनवाई के दौरान उनके पति नजीब भी अदालत में मौजूद थे। नजीब पर भी मलेशिया डेवलपमेंट बरहाद (एमडीबी) के कोष से अरबों डॉलर की हेराफेरी का आरोप है। पूर्व प्रधानमंत्री इस समय जमानत पर हैं।

▶ **2018 में रज्जाक के चुनाव हारने के बाद पुलिस ने उनके घर पर छापा मारकर करीब दो हजार करोड़ रुपये का सामान बरामद किया था**

कुआलालंपुर में हाई कोर्ट से सुनवाई के बाद बाहर आती मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक की पत्नी रोसमा मंसूर। रायटर

तुर्की ने सीरियाई शहर में तैनात किए सैनिक

दमिश्क, आइएएनएस : दो दिन पहले सीरिया के सैनिकों से सीधी झड़प के बाद तुर्की ने सीरियाई शहर सराकीब में अपने सैनिक तैनात कर दिए हैं। तुर्की के इस कदम को विद्रोहियों के कब्जे वाले उत्तर पश्चिमी प्रांत इदलिब में लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रही सीरिया की सेना से मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है। बीते मंगलवार को इदलिब में तुर्की और सीरिया की सेना के बीच सीधी झड़प में दोनों देशों के कई सैनिकों की जान चली गई थी।

सीरिया की सेना ने मंगलवार को कुछ घंटों की लड़ाई के बाद सराकीब के नजदीक के 16 इलाकों पर कब्जा कर लिया था। 24 जनवरी से अब तक सीरियाई सेना इदलिब में 68 इलाकों पर कब्जा कर चुकी है। मानवाधिकार संगठन सीरियन आब्जरवेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने तुर्की के सैनिकों की तैनाती को लेकर कुछ तस्वीरें जारी की हैं। इनमें तुर्की के बख्तरबंद वाहन इदलिब के ग्रामीण इलाकों से सटे सराकीब शहर में दिख रहे हैं।

ये भी जानिए
वनडे में तीसरी बार दोनों टीमों के नंबर चार बल्लेबाजों ने शतक जड़े। अय्यर व टेलर से पहले एक मैच में 2007 में नंबर चार बल्लेबाजों डिविलियर्स व तातेंदा ने, जबकि 2017 में युवराज व मोर्गन ने ऐसा किया।

टेलर का ट्रेलर

- रॉस टेलर ने श्रेयस अय्यर के शतक पर फेरा पानी
- न्यूजीलैंड ने पहले वनडे में भारत को चार विकेट से हराया

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: पांच मैचों की टी-20 सीरीज में न्यूजीलैंड का सफाया करने वाली भारतीय टीम के लिए तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज अच्छा नहीं रहा। रनों की बारिश के बीच हैमिल्टन में खेले गए पहले वनडे क्रिकेट मैच में रॉस टेलर का शतक श्रेयस अय्यर के करियर के पहले शतक पर भारी पड़ा और मेजबान न्यूजीलैंड की टीम पहले वनडे मैच में भारत को चार विकेट से हराकर जीत की राह पर लौटी। पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवर में चार विकेट पर 347 रन का विशाल स्कोर बनाया।

अय्यर ने अपनी प्रतिभा की एक बार फिर झलक दिखाते हुए 107 गेंदों में 103 रन बनाए। अय्यर ने अपनी पारी में 11 चौके और एक छक्का जड़ा। उन्होंने राहुल के साथ चौथे विकेट के लिए 136 रन जोड़े। टी-20 सीरीज में 'मैन ऑफ द टूर्नामेंट' रहे राहुल ने 64 गेंद में नाबाद 88 रन की पारी खेली। कोहली ने 63 गेंद में 51 रन बनाए। भारत ने आखिरी 10 ओवर में 96 रन बनाए। हालांकि, न्यूजीलैंड ने 11 गेंद बाकी रहते 48.1 ओवर में छह विकेट पर 348 रन बनाकर जीत दर्ज की। इस जीत के शिल्पकार रहे टेलर ने 84 गेंद में 10 चौकों और चार छक्कों की मदद से नाबाद 109 रन बनाए। टी-20 सीरीज में दो मैच सुपर ओवर में गंवाने वाली कीवी टीम ने 46वें ओवर में दो विकेट गंवाए तो लगा कि यह मैच भी उसी दिशा में जा रहा है, लेकिन टेलर ने अकेले किला लड़ाते हुए जीत सुनिश्चित की। ऑस्ट्रेलिया के हाथों टेस्ट सीरीज और भारत से टी-20 सीरीज में क्लीन स्वीप झेलने वाली कीवी टीम को भारत की दिशाहीन गेंदबाजी का भी फायदा मिला। भारतीय गेंदबाजों ने 29 अतिरिक्त रन दिए, जिनमें 24 वाइड गेंदें शामिल थी।

पारी के दौरान जश्न मनाते अय्यर ● एपी

इस तरह भारत ने ना सिर्फ वाइड के तौर पर 24 रन अतिरिक्त दिए, बल्कि चार ओवर फालतू भी फेंके।

पृथ्वी-मयंक ने दिलाई तेज शुरुआत: पृथ्वी और मयंक ने भारत को तेज शुरुआत दी और पहले 50 रन 48 गेंद में बने। दोनों हालांकि पांच गेंद के भीतर अपने विकेट गंवा बैठे। भारत का स्कोर इस समय दो विकेट पर 54 रन था। पृथ्वी ने कोलिन डि ग्रैंडहोम की गेंद पर विकेट के पीछे कैच थमाया, जबकि मयंक ने टिम साउथी की गेंद पर प्वाइंट में ब्लंडेल को कैच दिया।

आखिरी 20 ओवर में 191 रन बने: इसके बाद कोहली और अय्यर ने बीच के ओवरों में संभलकर खेला। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 102 रन जोड़े। भारत के 150 रन 28वें ओवर में पूरे हुए। कोहली को ईश सोढ़ी ने पवेलियन भेजा। इसके बावजूद भारत की रन गति कम नहीं हुई। राहुल ने अपनी पारी में छह छक्के और तीन चौके लगाए। भारत की पारी हालांकि अय्यर के नाम रही, जो पहले 50 रन 66 गेंद में बनाने के बाद खुलकर खेले और 16वें वनडे में पहला शतक बनाया। वह साउथी का शिकार बने। अय्यर के आउट होने के बाद राहुल ने मोर्चा संभाला। उन्होंने भारत को 47वें ओवर में 300 रन के पार पहुंचाया। न्यूजीलैंड ने आखिरी 20 ओवर में 191 रन दे डाले। केदार जाधव 15 गेंद में 26 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने राहुल के साथ 27 गेंद में 55 रन जोड़े।

न्यूजीलैंड की ठोस शुरुआत: विशाल लक्ष्य के जवाब में न्यूजीलैंड की शुरुआत धीमी, लेकिन ठोस रही। सलामी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल और हेनरी निकोल्स ने पहले विकेट के लिए 85 रन जोड़े। इस साझेदारी को शार्दुल ठाकुर ने 16वें ओवर में तोड़ा। गुप्टिल (32) केदार जाधव को कैच देकर पवेलियन लौटे। अपना पदार्पण वनडे मैच खेल रहे टॉम ब्लंडेल (09) ज्यादा देर टिक नहीं सके।

विराट कोहली या जोंटी रोड्स: इसके बाद टेलर और निकोल्स ने मिलकर अपनी टीम को संकट से निकाला। निकोल्स ने 82 गेंद में 11 चौकों की मदद से 78 रन बनाए। वह 29वें ओवर में कोहली के शानदार थ्रो पर रन आउट हुए। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने बेहतरीन फील्डिंग का नमूना पेश करते हुए निकोल्स को रन आउट किया। टेलर ने बुमराह की गेंद पर आराम से शॉट खेला और एक रन चुराने के लिए निकोल्स को बुलाया। तभी कवर्स पर खड़े कोहली ने तेजी से दौड़ते हुए गेंद पकड़ी और आगे की ओर डाइव लगाकर विकेट की ओर उसे फेंक दिया। गेंद सीधे विकेट पर जा लगी और निकोल्स क्रीज से दो इंच दूर रह गए। कोहली के बेहतरीन रन आउट के बाद उनकी तुलना दक्षिण अफ्रीका के महान फील्डर जोंटी रोड्स से होने लगी। यहां तक कि आइसीसी ने भी ट्वीट कर लिखा, 'विराट कोहली या जोंटी रोड्स? विराट ने पांचवें टी-20 में एक रनआउट करके मैच का पासा पलट दिया था। हालांकि इस बार वह ऐसा करने से चूक गए।

लाथम की जबरदस्त पारी: इसके बाद टेलर को टॉम लाथम के रूप में अच्छा जोड़ीदार मिला और दोनों ने चौथे विकेट के लिए 138 रन जोड़े। लाथम ने सिर्फ 48 गेंद में 69 रन बनाए, जिसमें आठ चौके और दो छक्के शामिल रहे। वह जब आउट हुए तो उस समय न्यूजीलैंड को जीत के लिए 50 गेंद में 39 रन चाहिए थे। जिमी नीशाम को 46वें ओवर में मुहम्मद शमी ने पवेलियन भेजा। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कोलिन डि ग्रैंडहोम भी आउट हो गए। हालांकि, मिशेल सेंटनर ने 48वें ओवर में ठाकुर पर चौका और छक्का लगाकर कोई उलटफेर नहीं होने दिया। मैच में भारतीय गेंदबाजी खराब रही।

स्कोर बोर्ड

टॉस : न्यूजीलैंड (गेंदबाजी) मैन ऑफ द मैच : रॉस टेलर

भारत 347/4 (50 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
पृथ्वी शॉ का. लाथम बो. डि ग्रैंडहोम	20	21	03	00
मयंक अग्रवाल का. ब्लंडेल बो. साउथी	32	31	06	00
विराट कोहली बो. सोढ़ी	51	63	06	00
श्रेयस अय्यर का. सेंटनर बो. साउथी	103	107	11	01
लोकेश राहुल नाबाद	88	64	03	06
केदार जाधव नाबाद	26	15	03	01

अतिरिक्त : (लेबा-7, नोबॉ-1, वा-19) 27
कुल : 50 ओवर में चार विकेट पर 347 रन

विकेट पतन : 1-50 (पृथ्वी, 7.6), 2-54 (मयंक, 8.4), 3-156 (कोहली, 28.4), 4-292 (अय्यर, 45.3)
गेंदबाजी : साउथी 10-1-85-2, हैमिश बेनेट 10-0-77-0, कोलिन डि ग्रैंडहोम 8-0-41-1, जिमी नीशाम 8-0-52-0, मिशेल सेंटनर 10-0-58-0, ईश सोढ़ी 4-0-27-1

न्यूजीलैंड 348/6 (48.1 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
मार्टिन गुप्टिल का. जाधव बो. शार्दुल	32	41	01	00
हेनरी निकोल्स रन आउट (कोहली)	78	82	11	00
टॉम ब्लंडेल स्टं. राहुल बो. कुलदीप	09	10	01	00
रॉस टेलर नाबाद	109	84	10	04
टॉम लाथम का. शमी बो. कुलदीप	69	48	08	02
जिमी नीशाम का. जाधव बो. शमी	09	14	01	00
ग्रैंडहोम रन आउट (अय्यर/कोहली)	01	02	00	00
मिशेल सेंटनर नाबाद	12	09	01	01

अतिरिक्त : (लेबा-4, नोबॉ.-1, वा-24) 29
कुल : 48.1 ओवर में छह विकेट पर 348 रन

विकेट पतन : 1-85 (गुप्टिल, 15.4), 2-109 (ब्लंडेल, 19.1), 3-171 (निकोल्स, 28.3), 4-309 (लाथम, 41.4), 5-328 (नीशाम, 45.2), 6-331 (डि ग्रैंडहोम, 45.6)
गेंदबाजी : जसप्रीत बुमराह 10-1-53-0, मुहम्मद शमी 9.1-0-63-1, शार्दुल ठाकुर 9-0-80-1, रवींद्र जडेजा 10-0-64-0, कुलदीप यादव 10-0-84-2

कोच के बचाव में न्यूजीलैंड क्रिकेट

हैमिल्टन, प्रेट्र: न्यूजीलैंड क्रिकेट ने आलोचनाओं से घिरे राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच गैरी स्टीड का बचाव किया और कहा कि उन्होंने पहले ही उन्होंने छुट्टियों की योजना बना ली थी। भारत के खिलाफ चल रही घरेलू सीरीज के बीच में ब्रेक लेने के कारण स्टीड की काफी आलोचना हो रही है। न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुख्य कार्यकारी डेविड वाइट ने स्टीड का समर्थन करते हुए कहा कि मौजूदा तीन मैचों की वनडे सीरीज के दौरान सब के बीच में कोच का ब्रेक लेना पूर्व-योजना थी। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वाइट ने कहा, 'न्यूजीलैंड में किसी भी अन्य खेल की तुलना में क्रिकेट को काफी समय देना होता है। ये लड़के काफी लंबे समय तक घर से दूर रहते हैं और हमें उनके कार्यभार का प्रबंधन करना होता है।' आलोचकों ने स्टीड के इस समय ब्रेक लेने की काफी आलोचना की और कहा कि उन्होंने जरूरत के समय टीम को मझधार में छोड़ दिया। उन्होंने ऐसे समय में टीम का छोड़ा जब उनकी ज्यादा जरूरत थी।'

धीमी ओवर गति के लिए लगातार तीसरे मैच में जुर्माना: भारत पर पहले वनडे में स्लो ओवर रेट के कारण आइसीसी ने मैच फीस का 80 फीसदी जुर्माना लगाया है। टीम इंडिया पर लगातार तीसरे मैच में धीमी ओवर गति के कारण जुर्माना लगाया है। टीम इंडिया निर्धारित समय सीमा में चार ओवर कम फेंक पाई। इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे और पांचवें टी-20 मैच में भी आइसीसी ने भारत के खिलाफ यह कार्रवाई की थी। आइसीसी की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के मुताबिक तय समय में ओवर न फेंकने के कारण खिलाड़ियों पर प्रति ओवर के हिसाब से 20 फीसद का जुर्माना लगता है। इस लिहाज से भारतीय टीम के चार ओवर कम फेंकने की वजह से 80 फीसद मैच फीस कटी।

शतक लगाने के बाद कुछ इस अंदाज में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रॉस टेलर ● एपी

कप्तान के रूप में सर्वाधिक वनडे रन

कप्तान	देश	मैच	रन
पोंटिंग	ऑस्ट्रेलिया	230	8497
धोनी	भारत	200	6641
फ्लेमिंग	न्यूजीलैंड	218	6295
रणतुंगा	श्रीलंका	193	5608
ग्रीम स्मिथ	द. अफ्रीका	150	5416
अजहर	भारत	174	5239
गांगुली	भारत	148	5082
कोहली	भारत	87	5123
डिविलियर्स	द. अफ्रीका	103	4796
एलन बॉर्डर	ऑस्ट्रेलिया	178	4439

5123 रन हो गए हैं अब विराट कोहली के 87 वनडे मैचों में बतौर कप्तान। उन्होंने भारतीय कप्तानों में सौरव गांगुली (148 मैचों में 5082 रन) को इस मामले में पीछे छोड़ा

01 साल से ज्यादा समय के बाद कीवी बल्लेबाज रॉस टेलर ने वनडे में शतक जड़ा। उन्होंने पिछला शतक जनवरी 2019 में श्रीलंका के खिलाफ 137 रन की पारी खेलकर बनाया था

18 वनडे मैच और 17 पारियां खेली टेलर ने इस शतक और पिछले शतक के बीच। इस दौरान उन्होंने पांच अर्धशतक जड़े लेकिन उसे शतक में तब्दील नहीं कर सके। इस दौरान उनका सर्वाधिक स्कोर पिछले साल भारत के खिलाफ ही 93 रन रहा

भारत की वनडे में अधिक वाइड

वाइड	बनाम	स्थान	साल
31	केन्या	ब्रिस्टल	1999
28	इंग्लैंड	द ओवल	2004
26	ऑस्ट्रेलिया	मुंबई	2007
25	वेस्टइंडीज	चेन्नई	2007
24	न्यूजीलैंड	हैमिल्टन	2020

कोरोना वायरस से चिंतित ओलंपिक सीईओ

अधिकारी ने कहा, वायरस से खेलों की तैयारियों पर पड़ेगा असर

टोक्यो, एएफपी: टोक्यो ओलंपिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ने बुधवार को स्वीकार किया कि आयोजक इस साल होने वाले खेलों पर कोरोना वायरस से पड़ने वाले संभावित प्रभाव को लेकर काफी चिंतित हैं।

तोशिरो मुटो ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चीन में जल्द ही इसका निपटारा कर लिया जाएगा ताकि ओलंपिक से पहले चिंता कम हो जाए। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति (आइपीसी) के साथ बैठक से पहले कहा, 'हम इस बात से काफी चिंतित हैं कि इस वायरस के संक्रमण से खेलों की तैयारियों पर असर पड़ सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसे जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए। हम अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आइओसी), जापान सरकार और टोक्यो शहर को इस बीमारी से बचाने के लिए पूरी तरह से सहयोग करेंगे।' चीन में इस वायरस से करीब 500 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 24000 लोग इससे संक्रमित हैं। 20 से ज्यादा देशों ने कोरोना वायरस के मामलों की पुष्टि की है। जापान में हालांकि अभी तक इससे किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन 3711 लोगों को ले जा रहे क्रूज में कम से कम 10 लोग इससे संक्रमित हैं। टोक्यो के गवर्नर यूरिको कोइके ने कहा, 'हम खिलाड़ियों को बचाने के लिए सबकुछ करेंगे ताकि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें।' इससे पहले जापान के प्रधानमंत्री एबी शिंजो ने इस हफ्ते के शुरू में कहा था कि देश विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के साथ मिलकर काम करेगा ताकि टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों में बाधा नहीं पड़े। कोरोना वायरस के कारण चीन में मुक्केबाजी और बैडमिंटन की ओलंपिक क्वालीफाइंग स्पर्धाएं रद कर दी गईं थीं। टोक्यो ओलंपिक 24 जुलाई से जबकि पैरालंपिक 25 अगस्त से शुरू होंगे।

बत्रा बोले, वायरस को लेकर किसी खिलाड़ी को गलत सूचना नहीं दी : भारतीय ओलंपिक संघ (आइओए) के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने बुधवार को कहा कि वह चीन में कोरोना वायरस संक्रमण फैलने पर नजर रखे हुए हैं।

बत्रा ने कहा, 'हमें पूरी जानकारी दी जा रही है। हम सभी मेडिकल सलाह पर चल रहे हैं और खिलाड़ियों के साथ इसे साझा कर रहे हैं। किसी को भी गलत जानकारी नहीं दी गई। हम कोई भी सूचना साझा करने से पीछे नहीं हट रहे। इसे लेकर चिंतित ना हों।' टोक्यो ओलंपिक में देश के पदक संख्या को लेकर उन्होंने कहा, 'मैं कोई संख्या नहीं दे रहा हूं, लेकिन हम अपनी तालिका को दोहरे अंक में ले जाएंगे।'

पीजीए क्वालीफाइंग टूर्नामेंट चीन से हटा

बीजिंग: पीजीए टूर सीरीज को चीन ने हैकोउ से हटाकर इंडोनेशिया के लागोई में कराने की घोषणा की। चीन में फैले कोरोना वायरस के कारण इस टूर्नामेंट को स्थानांतरित करने का फैसला किया है। गोल्फ क्वालीफाइंग टूर्नामेंट का आयोजन अब लगुना गोल्फ बिंटन में अब 25 से 28 फरवरी तक होगा।

ओलंपिक क्वालीफायर की मेजबानी के इच्छुक : बृजभूषण

नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआइ) एशियाई ओलंपिक क्वालीफायर की मेजबानी का इच्छुक है जिसे कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के बाद वहां के शियान शहर में आयोजित नहीं किया जाएगा। एशियाई ओलंपिक क्वालीफायर का आयोजन चीन के शहर में 27 से 29 मार्च तक होना था लेकिन कोरोना संक्रमण फैलने के बाद कुश्ती की वैश्विक संस्था युनाइटेड विश्व कुश्ती (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) ने वहां प्रतियोगिता नहीं कराने का फैसला किया। डब्ल्यूएफआइ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, 'यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने आयोजन स्थल बदलने को लेकर हमारा नजरिया मांगा था। हमसे मेजबानी के बारे में पूछा गया तो हम ऐसा करेंगे। इस पर इस पर फैसला 10 से 12 दिन में आ जाएगा। एशियन चैंपियनशिप के बाद वे फैसला करेंगे कि हमें मेजबानी देनी है या नहीं।'

आजाद कश्मीर नाम के घोड़े से फंस सकता है पाकिस्तान

अभिषेक त्रिपाठी ● नई दिल्ली

हरकत
- घुड़सवार उस्मान ने जानबूझकर अपने घोड़े का नाम बदला
- ओलंपिक चार्टर के उल्लंघन की शिकायत कर सकता है भारत

पाकिस्तान और उसके एथलीट हमेशा से भारत की भावनाओं के साथ खेलने से से बाज नहीं आते हैं और इस बार एक पाकिस्तानी घुड़सवार ने जानबूझकर अपने घोड़े का नाम बदलकर आजाद कश्मीर रखकर यही काम किया है।

पाकिस्तानी घुड़सवार उस्मान खान ने आजाद कश्मीर नाम के घोड़े से टोक्यो ओलंपिक का कोटा तो हासिल कर लिया, लेकिन अब वह मुश्किल में फंस सकता है क्योंकि उसकी इस हरकत से भारतीय ओलंपिक संघ (आइओए) नाराज है और वह इसके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आइओसी) में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इतना ही नहीं, आइओसी के नियम 50 के तहत भी उसका ओलंपिक कोटा छिन जाएगा। उस्मान इस स्पर्धा में टोक्यो के लिए क्वालीफाई करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी घुड़सवार हैं। 12 साल का यह घोड़ा पहले ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा बेलिस्टर के पास था जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रहती थीं लेकिन, 15 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे उस्मान ने यह घोड़ा पिछले साल उनसे खरीदा और जानबूझकर इसका नाम बदलकर आजाद कश्मीर रख दिया। आइओए के एक सूत्र ने कहा कि पाकिस्तान और उसके खिलाड़ी हमेशा से ऐसे कारनामों में आगे रहे हैं और हर बार वे भारत की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। उस्मान ने भी यही किया और हम इसके खिलाफ आइओसी में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसने भारत की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। आइओसी के नियम 50 के अनुसार, किसी ऐसी चीज से किसी राष्ट्र की भावनाओं को ठेस पहुंचती है और वह इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराता है। ऐसे में उस देश का ओलंपिक कोटा रद तक किया जा सकता है।

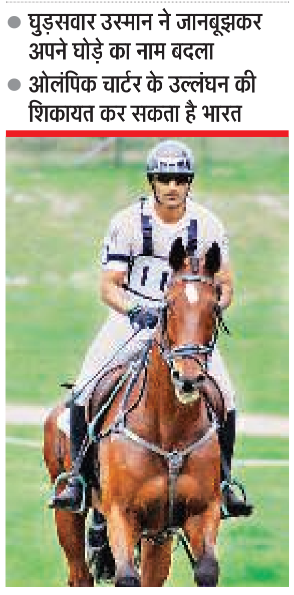
पाक घुड़सवार उस्मान खान ● ट्विटर

धौनी ने आरपी व पीयूष को खिलाए गोलगप्पे

नई दिल्ली, आइएएनएस: पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धौनी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह चम्मच की मदद से गोलगप्पे में मसाला भर रहे हैं और फिर उसे अपने हाथ से पूर्व भारतीय क्रिकेटर रुद्र प्रताप सिंह (आरपी सिंह) और भारतीय टीम के अपने पूर्व साथी पीयूष चावला को गोलगप्पे देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में इन दोनों खिलाड़ियों को भी गोलगप्पे का लुत्फ उठाते हुए देखा जा सकता है।

एक यूजर ने इस वीडियो को ट्विटर पर साझा किया और इसके साथ कैप्शन दिया, 'सीधे मालदीव से, हमारा रॉकस्टार कुछ गोलगप्पे बनाते हुए नजर आ रहा है। हमारी पसंदीदा बातचीत अब और भी ज्यादा मजेदार हो गई है।' जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई तो उसने लोगों के दिलों को जीत लिया। एक यूजर ने लिखा, 'पीयूष को धौनी के साथ देखना दिलचस्प है।' एक अन्य ने लिखा, 'बहुमुखी प्रतिभा के धनी इंसान माही।' एक प्रशंसक ने लिखा, 'वह भाग्यशाली है। मुझे जलन नहीं हो रही है।' इससे पहले धौनी का वॉलीबॉल खेलते हुए भी एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें धौनी काली टी-शर्ट पहने हुए और दोस्तों के साथ बीच पर समय बिताते हुए नजर आ रहे हैं।

लाथम ने लय छीनी : कोहली

हैमिल्टन, प्रेट्र: रॉस टेलर ने भले ही शतक जड़ा हो, लेकिन भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा कि बुधवार को यहां न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में टॉम लाथम की 48 गेंद में 69 रन की पारी ने उनकी टीम की लय छीन ली। कोहली ने मैच के बाद कहा, 'न्यूजीलैंड ने शानदार प्रदर्शन किया। हमने सोचा था कि 348 रन का लक्ष्य अच्छा होगा। रॉस अनुभवी बल्लेबाज हैं, लेकिन टॉम की पारी ऐसी थी जिसने हमसे लय छीन ली। जीत का श्रेय टेलर और टॉम को।'

मैदान में भारत का क्षेत्ररक्षण खराब रहा, जिसमें कुलदीप यादव ने एक कैच छोड़ा और गेंदबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया। कोहली ने कहा, 'देखिए, हमने मौके का फायदा नहीं उठाया, लेकिन हम ठीक थे। हमें कुछ चीजों में सुधार करते रहने की जरूरत है। हम नकारात्मक चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं लगा सकते। आज, प्रतिद्वंद्वी टीम हमसे बेहतर खेली और वे जीत के हकदार थे।' भारत के लिए श्रेयस अय्यर ने पहला वनडे शतक जड़ा। भारतीय कप्तान पदार्पण करने वाले मयंक अग्रवाल और पृथ्वी शॉ के प्रदर्शन से भी संतुष्ट दिखे, जिन्होंने 50 रन की साझेदारी की। हालांकि वे बड़े स्कोर नहीं बना सके। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि पदार्पण करने वाले खिलाड़ियों ने हमें अच्छी शुरुआत दिलाई और उम्मीद है कि वे ऐसा जारी रखेंगे। श्रेयस अय्यर ने दबाव में अपना पहला वनडे शतक बनाकर शानदार प्रदर्शन किया। राहुल ने अच्छा किया।'

ऐसा नहीं है कि भारत-ए के लिए मैंने हमेशा चौथे नंबर पर बल्लेबाजी की। स्थिति के अनुसार आपको अपने क्रम में बदलाव करते रहना पड़ता है। मुझे तीसरे से पांचवें स्थान के बीच बदलाव करना पड़ता था। निजी तौर पर भारत-ए के मैच मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण रहे, क्योंकि जब भी मैं वहां जाता था तो सुनिश्चित करता था कि इनका सर्वश्रेष्ठ फायदा उठाऊं। मैं काफी खुश हूं, लेकिन अगर हम जीत के साथ मैच का अंत करते तो मैं और अधिक खुश होता। उम्मीद करता हूं कि यह कई शतकों में से पहला शतक है और प्रयास करूंगा कि अगली बार हमारी टीम जीते। **श्रेयस अय्यर**

हमारे लिए यह दिलचस्प सत्र रहा है, स्कोर को पार करना अच्छा रहा। उन्हें 350 रन के अंदर रोकने से हमें मौका मिला। हम दायें-बायें संयोजन से भाग्यशाली रहे और हमने छोटी बाउंड्री को निशाना बनाया। टॉम ने आकर मेरे ऊपर से दबाव कम कर दिया।
रॉस टेलर, मैन ऑफ द मैच

खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। अंत में धैर्य बनाए रखना अच्छा रहा, जिससे हम स्कोर को पार कर सके। हमारे लिए साझेदारी बनाना अहम रहा। हम इतना बड़ा लक्ष्य नहीं चाहते थे, लेकिन अच्छी शुरुआत करने में सफल रहे और हमने विकेट नहीं गिरने दिए। जीत में अपना योगदान देकर खुश हूं। टेलर ने शानदार पारी खेली।
टॉम लाथम, कप्तान, न्यूजीलैंड

फुटबॉल डायरी मैनेजर जुर्जेन क्लोप की टीम लिवरपूल ने चौथे दौर के मैच में श्रेव्सबुरी को 1-0 से हराया, विलियम्स ने किया आत्मघाती गोल

एफए कप के पांचवें दौर में चेल्सी से भिड़ेगा लिवरपूल

लंदन, रायटर : लिवरपूल की युवा टीम ने यहां एफए कप के मैच में श्रेव्सबुरी को 1-0 से हराकर टूर्नामेंट के पांचवें दौर में जगह बनाई जहां उसका सामना चेल्सी से होगा।

मैनेजर जुर्जेन क्लोप ने इस मैच में टीम के सभी नियमित सीनियर खिलाड़ियों को आराम देकर नई टीम उतार दी थी और एक समय लग रहा था कि उनका यह फैसला गलत साबित हो सकता है क्योंकि मैच के गोलरहित ड्रॉ होने की उम्मीद लग रही थी लेकिन श्रेव्सबुरी के रो शॉन विलियम्स ने 75वें मिनट में आत्मघाती गोल करके लिवरपूल को मैच में 1-0 से आगे कर दिया। हालांकि इसके बाद क्लोप की टीम ने अपने डिफेंस को मजबूत करते हुए कोई गोल नहीं खाया और टीम ने इसी स्कोर से जीत हासिल की। क्लब के इतिहास में पहली बार सात बार के विजेता लिवरपूल की सबसे युवा टीम मैदान पर उतरी है। हालांकि मैच में दर्शकों की संख्या कम रही और लगभग 8000 लोग ही मैदान पर मौजूद रहे। 2015 में क्लोप ने टीम का कार्यभार संभाला था और उसके बाद पहली बार उनकी टीम पांचवें दौर में पहुंची है। मैच के बाद क्लोप ने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि हम चेल्सी के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लिवरपूल की कोई भी टीम मैदान पर शानदार प्रदर्शन करती है।' वहीं, पूर्व इंग्लिश कप्तान वेन रूनी की टीम डर्बी का सामना उनके पुराने क्लब मैनचेस्टर युनाइटेड से होगा। डर्बी ने चौथे दौर के मैच में नॉर्थंप्टन टाउन को 4-2 से हराया था जिसमें रूनी ने पेनाल्टी पर गोल किया था।

मैच जीतने के बाद जश्न मनाते लिवरपूल की टीम के सदस्य ● एपी

ग्रेनेडा ने मौजूदा चैंपियन वेलेंसिया को हराया: ग्रेनेडा ने मौजूदा चैंपियन वेलेंसिया को 2-1 से हराकर 1969 के बाद से पहली बार कोपा डेल रे टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। ग्रेनेडा ने मंगलवार देर रात को खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में अच्छी शुरुआत की और तीसरे मिनट में ही गोल करके मैच में 1-0 की बढ़त बनाई। मेजबान टीम के लिए यह गोल रॉबर्टो सोल्डेडो ने किया। वेलेंसिया ने हालांकि हाफ टाइम समाप्त होने से पहले ही मैच में बराबरी हासिल कर ली। मेहमान टीम के लिए यह गोल 40वें मिनट में रॉड्रिगो ने किया। ग्रेनेडा ने इसके बाद इंजुरी टाइम में भी गोल करके मैच को 2-1 से अपने नाम कर लिया। ग्रेनेडा के लिए दूसरा गोल भी सोल्डेडो ने किया।

रोनाल्डो और नेमार के जन्मदिन पर प्रशंसकों ने दी बधाई

नई दिल्ली : पुर्तगाल और इटली के क्लब जुवेंटस के सुपरस्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और विश्व के सबसे महंगे फुटबॉलर पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) के नेमार को उनके जन्मदिन के मौके पर प्रशंसकों ने उन्हें बधाई दी। रोनाल्डो ने बुधवार को 35वां जबकि नेमार 28वां जन्मदिन मनाया। एक प्रशंसक ने सोशल मीडिया पर लिखा, जन्मदिन की बधाई रोनाल्डो। आप ऐसे ही अपने क्लब के लिए नए रिकॉर्ड बनाते रहे। वहीं, नेमार के लिए प्रशंसक ने लिखा, ब्राजीली खिलाड़ी को उनके जन्मदिन पर बधाई। इससे पहले मंगलवार को ही रोनाल्डो ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह अभ्यास सत्र में हिस्सा ले रहे हैं और कैप्शन में लिखा, हैप्पी बर्थडे टू मी। इसके बाद एक और वीडियो शेयर किया जिसमें वह बोल रहे हैं कि आज मेरा जन्मदिन हैं और आप सभी लोगों के एक खास सरप्राइज गिफ्ट है।

रोनाल्डो ● फाइल फोटो, एपी

29 साल बाद भारत में एशियन कुश्ती में खेल सकते हैं पाक पहलवान

योगेश शर्मा ● नई दिल्ली

उम्मीद
- डब्ल्यूएफआइ व विदेश मंत्रालय ने वीजा देने का किया आश्वासन
- कोरोना वायरस के भय में भी चीनी पहलवानों को भी दिया जाएगा वीजा

भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआइ), खेल मंत्रालय और विदेश मंत्रालय यहां 18 से 23 फरवरी तक होने वाली एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के लिए चीन और पाकिस्तान के पहलवानों को वीजा देने के लिए आश्वासन दे चुके हैं। पाक के साथ भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हैं जबकि चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस के भय के बीच में भी चीनी पहलवानों को इस चैंपियनशिप में खेलने के लिए वीजा देने की तैयारी चल रही है। अगर पाकिस्तान के पहलवानों को वीजा मिल जाता है तो वह 29 साल बाद भारत में इस चैंपियनशिप में खेलने आएंगे।

पिछली बार पाकिस्तान इस चैंपियनशिप में दिल्ली में 1991 में खेला था। तब वह एक रजत पदक के साथ सबसे नीचे नौवें स्थान पर रहा था। भारत ओलंपिक चार्टर को निभाने के लिए दोनों पड़ोसी देशों के पहलवानों को वीजा देने की बात कर रहा है। भारत सरकार ने चीन के लोगों के लिए ई-वीजा की सुविधा निलंबित कर दी है क्योंकि कोरोना वायरस के फैलने का डर है। डब्ल्यूएफआइ को चैंपियनशिप के लिए चीन के 40 सदस्यीय दल के आने की उम्मीद है।

चीनी महासंघ का पत्र: डब्ल्यूएफआइ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, 'मैं विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मिला हूं। दोनों देशों के पहलवानों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि कोई समस्या नहीं होगी। चीन कुश्ती महासंघ ने आग्रह करते हुए हमें पत्र लिखा कि 40 पहलवानों का परीक्षण किया गया है और इनमें से कोई भी इस वायरस से ग्रस्त नहीं है। उन्हें अलग रखा गया है। सभी पहलवानों को भारत में भी अहतियाती कदमों से गुजरना होगा।'

प्रतिबंध के खतरे के कारण देंगे वीजा: डब्ल्यूएफआइ को कुश्ती की वैश्विक संस्था युनाइटेड विश्व कुश्ती का भी पत्र मिला है जिसमें चेताया गया है कि किसी भी देश को प्रतिनिधित्व से दूर नहीं किया जाना चाहिए। अगर भारत वीजा देने से इन्कार करता है तो देश पर टूर्नामेंटों की मेजबानी से प्रतिबंध लगने का खतरा है। पिछले साल नई दिल्ली में प्रतियोगिता के लिए दो पाकिस्तानी निशानेबाजों को वीजा देने से इन्कार किए जाने के बाद अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आइओसी) ने भविष्य में प्रतियोगिताओं की मेजबानी के लिए भारत के सभी आवेदनों को निलंबित कर दिया था।

यह एक संवेदनशील मुद्दा है लेकिन हमें अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों की मेजबानी करनी होगी। हम ओलंपिक चार्टर का पालन करेंगे। चीन और पाकिस्तान के पहलवानों के वीजा में कोई परेशानी नहीं होगी।
किरन रिजिजू, खेल मंत्री

5 राज्यों ने अभी तक नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, केरल, पंजाब, बंगाल और राजस्थान शामिल हैं।

बच्चा चोर की अफवाह में उन्मादी भीड़ ने पीटा, एक किसान की मौत

कानून-व्यवस्था ▸ धार जिले के खिरकिया का मामला, छह लोग घायल

आरोपितों ने किसानों को जिंदा जलाने का प्रयास किया

नईदुनिया, धार

मध्य प्रदेश में धार जिले के खिरकिया में उन्मादी भीड़ की हिंसा में एक किसान की मौत हो गई, जबकि छह लोग घायल हो गए। उन्मादी भीड़ ने किसानों को बच्चा चोर कहकर घेर लिया और उनसे मारपीट की। भीड़ ने हिंसा के शिकार लोगों को जिंदा जलाने का प्रयास भी किया।

पुलिस के अनुसार, सात लोग दो कारों से बुधवार सुबह करीब 11 बजे ग्राम खिरकिया पहुंचे थे। यहां उन्मादी भीड़ ने बच्चा चोर बताकर कारों पर पथराव किया और कार सवार लोगों से जमकर मारपीट की। एक कार में आग लगा दी गई। घायलों में चार की हालत गंभीर होने से उन्हें इंदौर रेफर किया गया है। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस ने कुछ नामजद के साथ बड़ी संख्या में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। दरअसल, पूरा मामला खेत में मजदूरी के लिए दी गई अग्रिम राशि से जुड़ा बताया जाता है। खेड़ागांव तहसील सांवेर (इंदौर) के छह किसानों ने छह माह पहले खेत में मजदूरी के लिए तिरला ब्लॉक के गांव खिरकिया के अवतार, जामसिंह, महेश, राजेश और सुनील को अग्रिम के तौर 50-50 हजार रुपये (कुल ढाई लाख रुपये) दिए थे। बाद में पांचों मजदूरी करने की बजाय गुजरात चले गए। बुधवार को मजदूरों के बुलाने पर ही सांवेर तहसील के सात किसान खिरकिया पहुंचे थे। गांव में पहुंचते ही 15-20 ग्रामीणों ने उनका रास्ता रोका और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। ग्रामीणों ने आसपास के गांवों में खबर फैला दी कि दो वाहनों में कुछ लोग दो बच्चों का अपहरण कर भागे हैं। इस पर उन्मादी भीड़ ने किसानों के वाहनों को रोकने का प्रयास किया। गांव बोरलाई में डेढ़-दो सौ लोगों ने बाइक अड़ा कर दोनों कारों को रोक लिया।

कार सवार जान बचाने के लिए एक दुकान में घुसे और दरवाजा बंद कर लिया। भीड़ ने दरवाजा तोड़कर उन्हें निकाला और लकड़ी-पत्थर से बुरी तरह पीटा। मारपीट में गंभीर रूप से घायल गणेश पुत्र मनोज (38) को बड़वानी रेफर किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उसकी मौत हो गई।

ऐसी घटनाएं शर्मसार करने वालीं : सीएम

मप्र के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, 'ऐसी घटनाएं मानवता को शर्मसार करने वाली हैं और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।' उन्होंने अधिकारियों को जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन का कहना है कि पैसों के लेन-देन को लेकर आपसी विवाद में यह घटना हुई है।

कानून का डर खत्म हो गया : शिवराज

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मप्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। कानून का डर बिल्कुल समाप्त हो गया है।

चौथी पास करने वाली सबसे बुजुर्ग महिला

केरल के कोल्लम जिले की निवासी 105 वर्षीय भागीरथी अम्मा देश में सबसे अधिक उम्र में चौथी कक्षा पास करने वाली बन गई हैं। उन्हें 74.5 फीसद अंक मिले हैं। केरल के साक्षरता मिशन की निदेशक पीएस श्रीकला ने बुधवार को अम्मा को उनके घर जाकर बधाई दी और मुंह मीठा कराया। अम्मा के छह बच्चे और 16 पोते-पोतियां हैं। प्रेट्र

पांच करोड़ को नहीं मिली पीएम किसान योजना की तीसरी किस्त

- सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में सरकार ने दिया जवाब,
- योजना का लाभ पाने को नौ करोड़ किसानों ने कराया है पंजीकरण

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को मिलने वाली दो हजार रुपये की किस्त अब तक पांच करोड़ से अधिक लोगों को नहीं मिल पाई। यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने दी ही।

गौरतलब है कि पहली दिसंबर 2018 से लागू हुई इस योजना के तहत पात्र किसानों को दो-दो हजार की तीन किस्तों के रूप में कुल छह हजार की आर्थिक मदद सालाना दी जानी थी। लेकिन किन्हीं कारणों से इस योजना के तहत मिलने वाली राशि समय से जारी नहीं हो सकीं।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2.51 करोड़ किसानों को दूसरी और पांच करोड़ से अधिक किसानों को तीसरी किस्त नहीं मिल पाई है। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत दिसंबर 2018 से नवंबर 2019 के बीच कुल नौ करोड़ किसानों ने अपना पंजीकरण कराया था। सूचना के अधिकार (आरटीआइ) के तहत पूछे गये सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने बताया कि पंजीकृत किसानों में से करीब 7.62 करोड़ किसानों को ही दो हजार रुपये की पहली किस्त मिल पाई। दूसरी किस्त 6.5 करोड़ किसानों और तीसरी किस्त 3.85 करोड़ को ही मिल सकी। जवाब में कृषि मंत्रालय ने आंकड़ों के तीन सेट जारी किये हैं। इन आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2018 से मार्च 2019 के बीच 4.74 करोड़ किसानों ने पंजीकरण कराया। इन किसानों में 4.22 को पहली, 4.02 को दोनों और 3.65 को तीनों किस्तें मिलीं। सरकार के पास इस बात का जवाब नहीं था कि तीनों किस्तों के वितरण में पहली बार पचास लाख, दूसरी बार 70 लाख और तीसरी बार 90 लाख किसानों को क्यों छोड़ा गया। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कोई भी पंजीकृत लाभार्थी न होने के कारण किसी को भी इस योजना का लाभ नहीं दिया गया।

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। फाइल

पुत्रवधू की लाज बचाने सामने आए ससुर को एंबुलेंस से रौंदा

जागरण संवाददाता, कोलकाता : कोलकाता में शादी समारोह में शिरकत कर देर रात लौटते वक्त बदमाशों ने पुत्रवधू का अपहरण करने का प्रयास किया तो उसकी लाज बचाने को ससुर बदमाशों से भिड़ गया। अपहरणकर्ताओं ने भागते हुए एंबुलेंस से ससुर को कुचल दिया। इससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

सूत्रों के अनुसार टेंगरा थाना अंतर्गत क्रिस्टोफर रोड निवासी गोपाल प्रमाणिक पत्नी, बेटी और पुत्रवधू के साथ मंगलवार रात गोविंद फाटक रोड स्थित पूर्वांचल प्रगति संघ में एक परिचित के यहां वैवाहिक समारोह में गए थे। देर रात समारोह से पैदल लौटते वक्त रास्ते में दो बदमाशों ने पुत्रवधू को जबरन एंबुलेंस में खींचने का प्रयास किया। ससुर ने विरोध शुरू कर दिया। साथ ही शोर मचाकर लोगों को एकत्र करने लगे। हालात को बिगड़ता देख बदमाश पुत्रवधू को छोड़कर भागने लगे तभी ससुर ने एंबुलेंस के आगे खड़े होकर रास्ता रोक लिया। इस पर बदमाश एंबुलेंस से उन्हें रौंदते हुए निकल गए। गंभीर रूप से घायल गोपाल को अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

अधिकारी के लिए मुसीबत बन गया पत्नी से हर बात साझा करना

- तलाकशुदा पत्नी की शिकायत पर रोजगार अधिकारी गिरफ्तार
- पिछले दिनों आइजी ने घोषित किया था 10 हजार रुपये का इनाम
- फर्जी अंकसूची के जरिये सरकारी नौकरी करने का आरोप

नईदुनिया, रीवा

मध्य प्रदेश में एक अधिकारी को पत्नी से हर बात साझा करना मुसीबत का सबब बन गया। फर्जी अंकसूची के जरिये नौकरी करने वाले अधिकारी का राज उसकी ही तलाकशुदा पत्नी ने उजागर कर दिया। मामले में फरार सतना के जिला रोजगार अधिकारी को क्राइम ब्रांच ने मंगलवार रात गिरफ्तार कर लिया है। जिला रोजगार अधिकारी अमित कुमार रीवा से सीधी जा रहा था। उसकी गिरफ्तारी पर आइजी ने 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।

जानकारी के अनुसार, वर्ष 2015 में अधिकारी की तलाकशुदा पत्नी शीला देवी ने भोपाल में अधिकारियों को पत्र लिखकर बताया था कि अमित कुमार की अंकसूचियां फर्जी हैं। हालांकि, विभागीय जांच में अमित कुमार बच निकला। इसके बाद शीला देवी ने अमित कुमार के खिलाफ सिटी कोतवाली में एफआइआर दर्ज कराई थी। 2017 में एक बार फिर विभाग ने अमित कुमार से उसकी मूल अंकसूची व डिग्री मांगीं। अमित कुमार पर मॉडल साइंस कॉलेज के रिकॉर्ड रूम का ताला तोड़ने का आरोप भी है। इसके बाद मॉडल साइंस के प्राचार्य ने जनवरी 2018 में सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

फरारी में की थी चुनाव ड्यूटी : एक तरफ जहां सिविल लाइन पुलिस जिला रोजगार अधिकारी अमित कुमार को लगातार फरार बता रही थी, वहीं वह 2018 के विधानसभा चुनाव व 2019 में लोकसभा चुनाव में सरकारी ड्यूटी पर तैनात रहा। विधानसभा में प्रश्न लगने के बाद रीवा आइजी ने उसकी गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।

> अमित कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ही पूरे मामले का राजफाश हो सकेगा।
> – आबिद खान, पुलिस अधीक्षक, रीवा

कांस्टेबल पति ने मुंह काला कर पत्नी को गांव में घुमाया

जासं, मोगा : करीबी रिश्तेदार युवती को सौतन बनाकर घर में लाने का विरोध किया तो पुलिस में कांस्टेबल पति ने पत्नी के साथ जानवरों जैसा सुलूक किया। वह भी 13 साल तक। दो महीने पहले पति ने पत्नी का मुंह काला किया और बाल काटकर गांव में भी घुमाया। इस पर थाना सदर पुलिस ने आरोपित कांस्टेबल पति के खिलाफ कार्रवाई के बजाय समझौता करवा दिया। एसएसपी अमरजीत सिंह बाजवा ने जांच डीएसपी सिटी को सौंप दी है।

गांव झंडेआना गरबी निवासी जसवीर कौर ने बताया कि उसकी शादी 15 साल पहले कांस्टेबल इंद्रजीत सिंह से हुई थी। दो साल सब ठीक रहा। फिर पति के जुल्म शुरू हो गए। उसने आरोप लगाया कि पति के करीबी रिश्तेदार युवती के साथ संबंध हैं। युवती की तीन बार सगाई भी हुई, जो पति ने तुड़वा दी। वह खुद उससे शादी करना चाहता है। विरोध करने पर पति 13 साल से उस पर अत्याचार कर रहा है। जसवीर ने बताया कि अत्याचार से दुखी होकर 26 दिसंबर, 2014 को पति के खिलाफ एफआइआर दर्ज करवाई, लेकिन कांस्टेबल पति ने मामला रफा-दफा करवा दिया।

गुजरात में 30 साल बाद होगी फांसी लटकाया जाएगा मासूम का गुनहगार

- सूरत की मासूम से दुष्कर्म व हत्या के दोषी को लटकाने के लिए साबरमती सेंट्रल जेल में तैयारी शुरू
- डीजीपी ने किया जेल का दौरा, जल्लाद के लिए तिहाड़ व यरवदा जेल प्रशासन से साधा गया संपर्क

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

निर्भयाकांड के गुनहगारों की फांसी भले ही कानूनी दांवपेच में उलझी हो, लेकिन सूरत की तीन वर्षीय मासूम के गुनहगार अनिल यादव को फांसी देने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य में 30 साल बाद किसी गुनहगार को फांसी दी जाएगी। गुजरात के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शिवानंद झा ने अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल पहुंचकर महात्मा गांधी व सरदार पटेल के नाम पर बनी कोठरी के बगल में स्थित फांसीघर का जायजा लिया। करीब पांच दशक से ज्यादा समय से अनुपयोगी इस फांसीघर के रंगरोगन व मरम्मत के लिए हाउसिंग बोर्ड की मदद ली जा रही है।

साबरमती जेल में 58 साल पहले हुई थी आखिरी बार फांसी : साबरमती जेल में आखिरी बार वर्ष 1962 में, जबकि राजकोट जेल में सितंबर 1989 में शशिकांत माली को आखिरी बार फांसी दी गई थी। राज्य में फांसी का यह आठवां मामला होगा। पहली बार दाराजी रादपिया को मई 1953 व इसके अगले ही महीने जून में वडोदरा जेल में माला कोदर को फांसी दी गई थी।

बिहार के बक्सर जिला का है गुनहगार अनिल यादव : सूरत के लिंबायत क्षेत्र निवासी तीन वर्षीय मासूम 14 अक्टूबर 2018 को लापता हो गई थी। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने भी बच्ची की छानबीन शुरू की। दूसरे दिन उसका शव उसकी बिल्डिंग के निचले तल पर बने एक कमरे में प्लास्टिक के थैले में मिला था। उसमें अनिल यादव (26) रहता था। बिहार के बक्सर जिले के मनिया गांव निवासी अनिल सूरत में काम के सिलसिले में आया था।

वारदात के पांचवें दिन अनिल को गुजरात पुलिस ने उसके गांव से गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ के बाद पुलिस ने बताया था कि अनिल ने बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर अपने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया था और इसके बाद उसकी गला घोटकर हत्या कर दी थी। विशेष (पॉक्सो) अदालत के जज पीएस काला ने 31 जुलाई 2019 को अनिल को फांसी की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट की जस्टिस बेला त्रिवेदी व जस्टिस एससी राव की पीठ ने विशेष अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए 27 दिसंबर 2019 को अनिल की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद विशेष कोर्ट ने गत गुरुवार को अनिल का डेथ वारंट जारी किया है।

पॉक्सो कानून के तहत फांसी का पहला मामला

अगर किसी तरह की कानूनी अड़चन नहीं आई तो अनिल को 29 फरवरी को फांसी दे दी जाएगी। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (पॉक्सो) एक्ट के तहत फांसी का राज्य में यह पहला मामला होगा। इससे पहले अन्य राज्यों की अदालतें पॉक्सो एक्ट के तहत फांसी की सजा सुना चुकी हैं।

हरियाणा में सेवा भारती के जिला अध्यक्ष की हत्या

जागरण संवाददाता, नूंह

हरियाणा के नूंह में सराफा कारोबारी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोगी संगठन 'सेवा भारती' के जिला अध्यक्ष गोविंद राम सोनी की हत्या कर दी गई। उनकी हत्या घर के निकट की गई। हत्या के बाद अपराधी गहने से भरा थैला लेकर भाग गए। हत्या के विरोध में व्यापारियों ने दुकानें बंद रखीं और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। एसपी संगीता कालिया ने लोगों को आश्वस्त किया कि अपराधी जल्द ही पकड़े जाएंगे। आश्वासन के बाद लोगों ने अंतिम संस्कार का फैसला लिया। पुन्हाना थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस तफ्तीश कर रही है।

सेवा भारती के जिलाध्यक्ष व स्वर्णकार समाज के भी जिला अध्यक्ष गोविंद राम सोनी 65 साल के थे और पुन्हाना के वार्ड नंबर आठ में रहते थे। घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर उनकी सराफा की दुकान है। रोजाना की तरह शाम छह बजे गोविंद अपनी दुकान बढ़ा कर एक थैले में गहने व नकदी लेकर घर जा रहे थे। घर से कुछ दूर पहले ही अज्ञात लोगों ने उन्हें घेर लिया व उनके हाथ से थैला छीनना चाहा। सोनी ने शोर मचा दिया।

इसके बाद बदमाशों ने धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। वह घायल होकर गिर पड़े तो बदमाश गहनों व रकम से भरा थैला लेकर भाग गए। शोर सुनकर कुछ लोग पहुंचे तो सोनी बेहोश पड़े थे। लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया जहां कुछ देर बाद डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

- लूटपाट के इरादे से की गई हत्या, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज, दुकान बंद कर जाते वक्त धारदार हथियार से वार की गई हत्या

मृतक गोविंद राम सोनी की फाइल फोटो।

> मामला दर्ज कर लिया गया है। दो स्पेशल पुलिस टीम मामले को सुलझाने में लगी हुई हैं, जल्द ही आरोपितों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लोग शांति बनाए रखें।
> – संगीता कालिया, एसपी नूंह

गैंगस्टरों से भरी पटियाला सेंट्रल जेल के अति सुरक्षित क्षेत्र में पहुंची महिला

- फोटो वायरल, न किसी पुलिसवाले की रिश्तेदार और न कैदी की
- जेल सुपरिंटेंडेंट ने माना तस्वीरें जेल के अंदर की, लेकिन पुरानी

प्रेम वर्मा, पटियाला

पंजाब की अति सुरक्षित जेलों में शामिल पटियाला की सेंट्रल जेल की सुरक्षा में एक बार फिर सेंध लगी है। एक अनजान महिला जेल के अति सुरक्षित क्षेत्र में पहुंच गई। यह महिला जेल के वेलफेयर अफसर ऑफिस व कंट्रोल रूम के आसपास घूमती देखी गई, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। कंट्रोल रूम के पास का यह वह क्षेत्र है, जहां सिर्फ जेल सुपरिंटेंडेंट व जेल वेलफेयर अफसर ही जा सकते हैं।

इस जगह से कैदियों की बैरक बीस फीट की दूरी पर है। महिला न तो किसी कैदी की रिश्तेदार है और न किसी पुलिसवाले की। हालांकि, यहां किसी को जाने की अनुमति नहीं है। अब सवाल उठ रहा है कि यह महिला कौन है? जो सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचकर चक्कर लगाती नजर आई। इतनी सुरक्षा के बावजूद उसे किसी ने रोका क्यों नहीं? इन सवालों का जवाब किसी भी अधिकारी के पास नहीं। हालांकि, मौजूदा जेल सुपरिंटेंडेंट एसपी खन्ना ने माना कि यह तस्वीरें जेल के अंदर की हैं, लेकिन तस्वीरें पुरानी है। सूत्रों के अनुसार यह महिला अक्सर यहां आती-जाती थी। ये तस्वीरें जून-जुलाई 2019 की हैं। इसकी शिकायत जेलमंत्री को भी की जा चुकी है।

राजोआणा समेत नामी गैंगस्टरों के साथी इस जेल में : महिला का इस तरह से जेल के अंदर जाना और काला चश्मा पहने अकेले ही घूमना जेल की सुरक्षा पर सवाल उठाता है। सवाल इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि जेल में गैंगस्टर गुरप्रीत गोपी, गोरू बच्चा, लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा के साथियों के अलावा पूर्व सीएम बेअंत सिंह का हत्यारा बलवंत सिंह राजोआणा भी बंद है।

जेल सुपरिंटेंडेंट को भी मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं : जेल में तैनात वेलफेयर अफसर असिस्टेंट जेलर की रैंक का होता है। उसके पास जेल की कैंटीन में बनने वाले खानपान, कैदियों के वेलफेयर के लिए होने वाली हर गतिविधि का जिम्मा होता है। ऐसे में जेल की महत्वपूर्ण ओहदे की वजह से भलाई अफसर के आसपास सुरक्षा कड़ी रखी जाती है। यहां पर किसी भी मुलाजिम तक को बिना इजाजत जाने नहीं दिया जाता। इस इलाके में जाने वाले जेल सुपरिंटेंडेंट को भी फोन इस्तेमाल करने की मंजूरी नहीं होती है।

> स्टाफ से पूछताछ की है, जिन्होंने बताया कि तस्वीरें पुरानी हैं। मामले को लेकर जांच करेंगे। सीसीटीवी फुटेज भी चेक करेंगे। पूरी पड़ताल के बाद ही एक्शन होगा।
> – एसपी खन्ना, सुपरिंटेंडेंट, सेंट्रल जेल

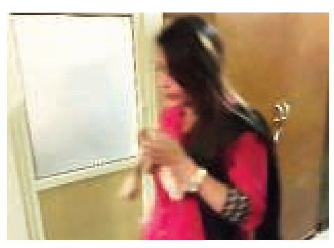

पटियाला सेंट्रल जेल में वेलफेयर अफसर के कार्यालय के पास महिला। फोटो : सोशल मीडिया

एयर इंडिया ने 'कुणाल कामरा' को पहले रोका, फिर दी अनुमति

- हमनाम होने के चलते परेशान हुए अमेरिका में रहने वाले कामरा
- तीन फरवरी को जयपुर से मुंबई के लिए पकड़नी थी फ्लाइट

नई दिल्ली, प्रेट्र : कॉमेडियन कुणाल कामरा पर ट्रैवल बैन के चलते एयर इंडिया ने गलती से अमेरिका के बॉस्टन में रहने वाले कुणाल कामरा का टिकट रद कर दिया। कुणाल कामरा को तीन फरवरी को जयपुर से मुंबई की फ्लाइट पकड़नी थी। एक वरिष्ठ अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इस वजह से उन्हें कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा।

हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि गलती का अहसास होने पर कुणाल कामरा को दोबारा उसी फ्लाइट का टिकट जारी कर दिया गया। लेकिन इससे पहले उन्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ी। दरअसल, बोस्टन में रहने वाले कुणाल अपने परिजनों से मिलने भारत आए हुए हैं। तीन फरवरी को उन्हें जयपुर से मुंबई के लिए फ्लाइट पकड़नी थी। वह जब एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उनका टिकट रद कर दिया गया। उन्होंने इसका कारण पूछा तो जयपुर एयरपोर्ट पर मौजूद स्टाफ ने बताया कि उनका नाम एयरलाइन के ब्लैकलिस्ट में है। वह सुनकर हैरान रह गए।

गौरतलब है कि इंडिगो की एक फ्लाइट में एक पत्रकार को कथित तौर पर परेशान करने के मामले में इंडिगो एयरलाइंस ने कॉमेडियन कुणाल कामरा की हवाई यात्रा पर रोक लगा दी थी। केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी की सलाह पर एयर इंडिया, स्पाइसजेट और गो एयर ने भी कॉमेडियन की यात्रा पर रोक लगा दी थी। कुणाल कामरा ने बताया कि ये उनके लिए बुरा अनुभव था। उनके पास काफी टाइम था इसलिए मसला सुलझा लिया गया। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि दोनों का नाम एक होने की वजह से यह समस्या सामने आई, जिसे बाद में सुधार लिया गया।

कामरा ने कहा, 'मुझे फ्लाइट से पहले इसकी जानकारी नहीं दी गई, न ही एयरलाइंस ने कोई सफाई दी, दिक्कत ये है कि सिर्फ एक जैसा नाम होने से आप फ्लाइट कैसे कैंसिल कर सकते हैं, कई लोगों के नाम एक जैसे हो सकते हैं' कुणाल ने बताया कि वो अपना आधार कार्ड के साथ ही अमेरिकी पहचान पत्र दिखाए तब जाकर उन्हें फ्लाइट में चढ़ने की अनुमति दी गई।

एयर इंडिया की सफाई

इस बारे में पूछे जाने पर एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि कॉमेडियन कुणाल कामरा एयर इंडिया की फ्लाइट से यात्रा नहीं कर सकते हैं। ये हमारे सिस्टम में दर्ज है, इसलिए इनका भी नाम अपने आप रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन सभी चीजें चेक करने के बाद उन्हें फ्लाइट में आने की अनुमित दे दी गई। बता दें कि कॉमेडियन कुणाल कामरा पर पाबंदी लगाने के संबंध में टाटा ग्रुप की दो एयरलाइंस-विस्तारा और एयर एशिया इंडिया ने कहा है कि वे मामले की समीक्षा कर रहे हैं।

सूरजकुंड मेला

अंतरराष्ट्रीय पहचान की ओर अग्रसर बंचारी का नगाड़ा

मेले में सराही जा रही है नगाड़े एवं ड्रम की जोड़ी, विश्वकर्मा विवि ने तैयार किया है बंचारी लोक ग्रंथ

अभिषेक शर्मा, फरीदाबाद

अरावली की वादियों में आयोजित हो रहे अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में आने वाले पर्यटक बंचारी के नगाड़ों की थाप को भली भांति पहचानते हैं। इस बार बंचारी के नगाड़ों में आधुनिकता का तड़का लगाया गया है। श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय ने नगाड़ों का ड्रम के साथ तालमेल किया है, जो कि पर्यटकों के लिए आकर्षण केंद्र बना हुआ है। पर्यटक बंचारी के नगाड़ों के नए रूप में खूब सराह रहे हैं। विश्वकर्मा विश्वविद्यालय ने नगाड़ों को विलुप्त होने से बचाने के लिए एक पाठ्यक्रम बनाया है, जो यूनिवर्सिटी के छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। बंचारी के नगाड़ों के नए स्वरूप को अब विश्व पटल पर ले जाने की भी तैयारी चल रही है।

उल्लेखनीय है कि हरियाणा की संस्कृति में बंचारी के नगाड़ों का बहुत महत्व है, लेकिन आधुनिकता की चकाचौंध में नगाड़ों की थाप फीकी पड़ने लगी हैं। तीन दशक पूर्व तक त्योहारों, उत्सवों एवं पारिवारिक समारोह बंचारी के नगाड़ों के बिना अधूरे से माने जाते थे, लेकिन बदलते समय के साथ बंचारी के नगाड़े पुराने होते जा रहे हैं और इनका स्थान डीजे और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स ने ले लिया है। बंचारी के नगाड़ों की संस्कृति अब धूमिल हो जा रही है। इसके अलावा नगाड़ों को बजाने वालों की संख्या भी कम होती जा रही है।

बंचारी लोक ग्रंथ पाठ्यक्रम किया तैयार : स्किल इंस्ट्रक्टर अमरजीत सिंह ने बताया कि बंचारी के नगाड़ों को दोबारा से जीवित करने एवं उन्हें विश्वपटल पर पहचान दिलाने के लिए बंचारी लोक ग्रंथ पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। इसमें बंचारी गांव का इतिहास, आलाह उदल की कहानियां, रसिया, पटका चौपाई सहित विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है।

युवा दिखा रहे रुचि, विदेश जाने का मिला रहा है मौका : स्किल इंस्ट्रक्टर डॉ.राजकुमार ने बताया कि पिछले वर्ष केवल बंचारी के युवाओं ने इस पाठ्यक्रम में रुचि दिखाई थी, लेकिन इस बार आसपास के गांवों के युवाओं ने पाठ्यक्रम में दाखिला लिया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी बंचारी के नगाड़ों को सीखने में रुचि दिखा रही हैं। 20 छात्रों में से सात छात्राएं हैं। अभी हाल में एक छात्र देवेंद्र को नाइजीरिया में बंचारी के नगाड़ों की थाप को प्रस्तुत करने का मौका मिला है। यूनिवर्सिटी एक साल का डिप्लोमा एवं छह महीने का सर्टिफिकेट कोर्स करा रही है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी युवाओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसा प्लेटफार्म भी दे रही है, जिसमें युवा बंचारी के नगाड़ों को बजाकर विलुप्त होती संस्कृति को दोबारा से जीवित कर सकें।

श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय ने तैयार किया है बंचारी बैंड। इसमें छात्र बंचारी के नगाड़े, छात्रा चिमटा और अमर सिंह बैंड के साथ व डॉ. राजकुमार बंचारी के लोक गीत गाते हुए। जागरण

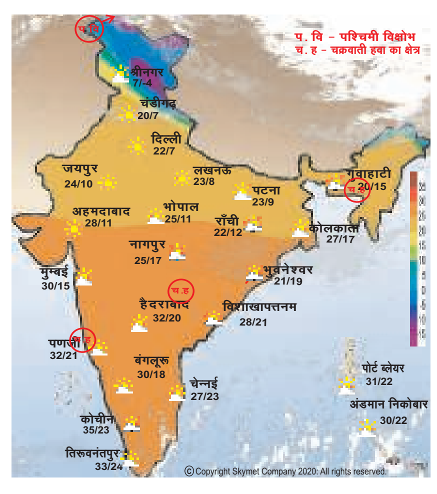

मौसम विशेष

जम्मू, दक्षिण कश्मीर, लद्दाख व हिमाचल प्रदेश में आंशिक बादलों के साथ शुष्क मौसम जारी रहेगा। उत्तरी कश्मीर में हल्की हिमपात संभव है। दिल्ली सहित मैदानी भागों में शुष्क मौसम रहेगा। ठंडी सुबह में हल्का कोहरा व कुहासा रहेगा। दिन में छिटपुट बादलों के साथ मौसम सुहावना बना रहेगा।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	31/14/व	अहमदाबाद	29/09/व
कोलकाता	22/19/आंबा	बड़ौदा	31/11/सा
चेन्नई	32/22/आंबा	नागपुर	26/16/आंबा
हैदराबाद	30/21/आंबा	इन्दौर	26/13/सा
बंगलूरू	29/19/सा	रांची	18/15/आंबा
त्रिवेन्द्रम	33/24/सा	पटना	26/12/सा
गुवाहाटी	22/13/व	जमशेदपुर	20/18/सा
गंगटोक	13/05/आंबा	पुणे	31/16/व

कोलकाता में स्थापित हुआ देश का पहला पेसमेकर बैंक

1999 में आज ही कोलकाता में देश का पहला पेसमेकर बैंक स्थापित हुआ था। चैरिटी संस्था वाला यह मेडिकल बैंक समृद्ध लोगों की मृत्यु के बाद उनके महंगे पेसमेकर सहेज लेता है फिर जरूरतमंदों को उचित दामों पर उपलब्ध करवाता है।

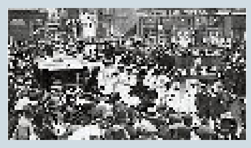

ब्रिटेन में महिलाओं को आज ही मिला मतदान का अधिकार

आज ही 1918 में तीस वर्ष से अधिक की आयु की महिलाओं को ब्रिटेन में मतदान का अधिकार मिला। वो भी ऐसी महिलाओं को जो कम से कम स्नातक हों, भू-स्वामी हों और शादीशुदा हों। ब्रिटेन में करीब एक सदी बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला।

सीमांत गांधी कहलाने वाले स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खां

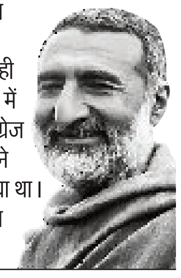

सीमांत गांधी कहे जाने वाले भारत रत्न स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खां का जन्म आज ही के दिन 1890 में पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। अहिंसा के समर्थक थे। यही कारण था कि लोग उन्हें धार्मिक नेता के तौर पर भी पहचानते थे। 1929 में खुदाई खिदमतगार आंदोलन शुरू किया। आंदोलन की सफलता से अंग्रेज शासक तिलमिला उठे। ये देश के बंटवारे के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अलग पाकिस्तान की मांग का विरोध किया था। कार्य और निष्ठा के कारण उन्हें 'बच्चा खां' और 'बादशाह खां' के नाम से भी जाना गया। 20 जनवरी 1988 को पेशावर में आखिरी सांस ली।

इधर-उधर की

शादी के तुरंत बाद निकल पड़े जान बचाने

बीजिंग, एजेंसी : चीन से निकले कोरोना वायरस ने दुनिया को चिंता में डाल दिया है। अब चीन से बाहर के देशों में भी इससे मौतों का सिलसिला चालू हो गया है। चीन में स्थिति विकट है। इसके प्रकोप को रोकने के लिए युद्धस्तर पर प्रयास चीन ने शुरू कर दिए हैं। दस दिन में इसके इलाज के लिए खास अस्पताल बनवाने के अलावा तमाम स्वास्थ्य मशीनरी आपात स्थिति में हैं। यहां के एक डॉक्टर की ऐसी ही तत्परता चर्चा का विषय बनी है। यहां के हेजी में एक डॉक्टर ने शादी की। इसके दस मिनट बाद ही वह कोरोना से पीड़ितों के इलाज के लिए निकल पड़ा। चूंकि शादी इस रोग के प्रसार से पहले ही तय थी, लिहाजा आनन-फानन में शादी निपटाकर अपने कर्तव्य पर निकलने के चलते लोग डॉक्टर की भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे हैं।

वायरस, बारूद को सूंघ लेगी कृत्रिम नाक

जागरण विशेष ▶ प्राकृतिक नाक से कई गुना अधिक क्षमता वाली है मानव कोशिकाओं से बनी बॉयोनिक नोज

अमेरिका में हुए शोध में इंदौर का युवा वैज्ञानिक भी शामिल

अभिषेक चेंडके, इंदौर

आने वाले समय में मानव चेहरे पर ऐसी कृत्रिम नाक प्रत्यारोपित हो सकेगी, जो प्राकृतिक नाक से कहीं बेहतर साबित होगी। चेहरे की जरूरत के अनुसार डिजाइन होने के साथ इसका उपयोग युद्ध और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हो सकेगा। मानव कोशिकाओं से तैयार इस नाक (बायोनिक नोज) को अमेरिका की प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। नाक पर शोध करने वाली टीम में इंदौर के युवा वैज्ञानिक डॉ. सुदीप जोशी भी शामिल है।

सुदीप ने बताया कि फिलहाल इस नाक को तीन तरह की गंध- गुलाब, विस्फोटक और इन्फ्लूएंजा वायरस को दूर से ही सूंघ सकने लायक विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि जिस गंध-दुर्गंध का पता आमतौर पर इंसान नहीं लगा पाता है, उसका पता इससे लगाया जा सके। इसकी क्षमता को और भी बढ़ाया जाएगा।

सुदीप इंदौर के वैष्णव इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र रहे हैं। इंदौर प्रवास के दौरान उन्होंने नईदुनिया को बताया कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु से मटेरियल साइंस में पीएचडी करने के बाद वे बतौर वैज्ञानिक अमेरिका के स्टीवन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यूजर्सी से जुड़ गए। 2016 में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर बायोनिक नोज पर शोध शुरू किया। सुदीप ने बताया कि इस टीम में भारत से वह एकमात्र वैज्ञानिक हैं। इसके अलावा हार्वर्ड, कैंब्रिज विवि के शोधार्थियों के रूप में अमेरिका, स्पेन, मैक्सिको, ईरान के कुल 11 वैज्ञानिक टीम में शामिल हैं।

डॉ. सुदीप जोशी का दावा है कि अभी तक जो कृत्रिम नाक बनाई गईं, वे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक नाक थीं। हमारे शोध में पहली बार मानवीय कोशिकाओं और इलेक्ट्रॉनिक्स, दोनों का उपयोग किया गया है। बायोनिक यानी बायो और इलेक्ट्रॉनिक्स का संगम। बायोनिक नाक को लैब में विकसित करने के लिए कार्टेज सेल का उपयोग किया गया है। इसमें सूंघने की शक्ति ग्राफिन के सूक्ष्म कणों के जरिए बढ़ाई गई है। नाक बनाने के लिए मृत व्यक्तियों के 10 हजार सेल लिए गए। उसमें बायोमटेरियल मिश्रित कर 10 हफ्ते तक 37 डिग्री सेल्सियस और सात प्रतिशत कार्बन डाई ऑक्साइड के साथ रखा गया ताकि सेल ज्यादा मात्रा में विकसित हो सकें। ग्राफिन के जरिए नाक में संवेदनशीलता विकसित की गई है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की मदद से किए जा रहे इस शोध को एडवांस साइंस जर्नल जर्मनी के विली पब्लिकेशन ने 10 जनवरी 2020 को प्रकाशित किया है। इससे पहले बायोनिक ईयर (कान) और बायोनिक मशरूम भी इसी तरह लैब में तैयार किए जा चुके हैं।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के वैज्ञानिकों की टीम बना रही है यह विशेष नाक

लैब में विकसित की गई बॉयोनिक नोज।

डॉ. सुदीप जोशी। (तस्वीरें, सौ. डॉ. सुदीप जोशी।)

आगे की राह...

सुदीप ने बताया कि बायोनिक नाक के लिए सबसे बड़ी चुनौती है इसे मानवीय शरीर में प्रत्यारोपित कर उपयोग हेतु बनाना। यह नाक जो गंध सूंघे, वह मानवीय मस्तिष्क तक पहुंचे और इंसान उसकी पहचान करने लगे। बिलकुल असली नाक की तरह। इससे उसके सूंघने की क्षमता बढ़ जाएगी। उम्मीद है कि इसमें भी जल्द सफलता मिलेगी। जिनकी नाक क्षतिग्रस्त हो जाती है या जो सूंघने की क्षमता खो देते हैं, ऐसे लोगों में बायोनिक नोज ट्रांसप्लांट हो सकेगी। साथ ही, बीमारियों का पता लगाने में डॉक्टर या पैथोलॉजिस्ट इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं।

पूरी दुनिया में जुगनुओं के अस्तित्व पर छाया संकट

- प्राकृतिक और विशिष्ट आवास नष्ट होने, कृत्रिम रोशनी और कीटनाशकों के प्रयोग से गहराया खतरा
- यह अध्ययन बॉयोसाइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ है

2000 से अधिक प्रजातियां फैली हैं दुनियाभर में जुगुनुओं की। प्रतीकात्मक

वाशिंगटन, पीटीआइ : पूरी दुनिया में जुगनुओं के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। हालिया अध्ययन के अनुसार, इसकी तीन बड़ी वजहें हैं- प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, कीटनाशकों का प्रयोग और प्रकाश प्रदूषण यानी चमक-दमक वाली कृत्रिम रोशनी। इससे संबंधित अध्ययन बायोसाइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ है, जो जुगनुओं की खास प्रजाति की विलुप्ति पर सवाल खड़े करता है। साथ ही, यह जैव-विविधता और ईकोटूरिज्म पर भी प्रभाव डालता है। अमेरिका की टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार, जुगनुओं को व्यापक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट समूह माना जाता है। इसकी 2000 से अधिक प्रजातियां पूरी दुनिया में फैली हैं।

शोधकर्ताओं ने जुगनुओं के अस्तित्व के खतरे के लिए जिम्मेदार कारकों को समझने के लिए जुगनू विशेषज्ञों का सर्वे किया। शोधकर्ताओं ने सर्वे के आधार पर जुगनुओं के लिए विशिष्ट खतरों और भौगोलिक क्षेत्रों में इसकी विभिन्न प्रजाति की संवेदनशीलता को रेखांकित किया। सर्वे के अनुसार, अधिकांश इलाकों में जुगनुओं के अस्तित्व को सबसे बड़ा खतरा उनके प्राकृतिक आवास के नष्ट होने से है। इसके बाद प्रकाश प्रदूषण और कीटनाशकों के प्रयोग की बारी आती है। बता दें कि रात के समय आसमान में कृत्रिम रोशनी की वजह से दिखने वाली चमक-दमक को प्रकाश प्रदूषण कहते हैं और यह वायु तथा जल प्रदूषण जितना ही खतरनाक साबित हो सकता है।

टफ्ट्स यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सारा लुईस का कहना है, 'वन्यजीवों की बहुत सारी प्रजातियां कम हो रही है, क्योंकि उनका निवास स्थान लगातार सिकुड़ रहा है।' लुईस ने बताया, 'यह कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है कि निवास स्थान नष्ट होने को सबसे बड़ा खतरा माना गया था। कुछ जुगनुओं पर इसका व्यापक असर पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपना जीवनचक्र पूरा करने के लिए विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होती है।' उदाहरण के तौर पर, मलेशियाई जुगनू (टेरोपटिक्स टेनर) अपनी चमक दिखाने के लिए मशहूर है और यह मैन्ग्रोव विशेषज्ञ है। यानी यह मैन्ग्रोव वाले इलाके में रहता है। शोधकर्ताओं ने बताया कि पहले के शोधों से साफ है कि इन जुगनुओं के मैन्ग्रोव वाले निवास स्थान को पाम ऑयल के लिए पौधरोपण और मत्स्यपालन के तौर पर प्रयोग से इनकी संख्या में भारी कमी आई है।

प्रकाश प्रदूषण दूसरा सबसे बड़ा खतरा : सर्वे के नतीजे में दूसरी चौंकाने वाली बात वैश्विक स्तर पर प्रकाश प्रदूषण की आई। इसे जुगनुओं के अस्तित्व के लिए दूसरा सबसे बड़ा खतरा माना गया। पिछली सदी के दौरान रात में कृत्रिम रोशनी काफी तेजी से बढ़ी है। कई जुगनू अपनी चमक से ही मादा जुगनुओं की खोज और उन्हें आकर्षित करते हैं। पहले के अध्ययनों से पता चला है कि अत्यधिक कृत्रिम रोशनी इसमें बाधा बन सकती है।

कीटनाशकों से खतरा : विशेषज्ञों का कहना है कि कृषि के लिए व्यापक तौर पर कीटनाशकों के प्रयोग ने भी जुगनुओं के अस्तित्व को संकट में डाल दिया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जैसे कीटनाशक कीटों को मारने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इनकी वजह से लाभकारी कीट भी मर जाते हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक इस अध्ययन से समझने में मदद मिलेगी कि भविष्य में कौन-सी प्रजातियां आवास नष्ट होने या प्रकाश प्रदूषण की वजह से खतरे में होंगी।

जलने से हुए घावों को भरेगा 3डी प्रिंटर

- घावों को भरने के साथ ही पड़ने वाले दागों से भी दिलाएगा मुक्ति
- जीवित कोशिकाओं से बनी है प्रिंटर में उपयोग की जाने वाली इंक

टोरंटो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया विकसित। प्रतीकात्मक

टोरंटो, प्रेट्र : शोधकर्ताओं ने एक नया 3डी प्रिंटर विकसित किया है जो जले हुए घावों को सही करने के लिए उसके ऊपर असली त्वचा की परत चढ़ाता है। इस नई विधि से जले हुए मरीजों को ज्यादा तेजी और कारगर तरीके से उपचार मुहैया कराया जा सकता है।

कनाडा में टोरंटो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने बताया कि इस डिवाइस से घाव पर बॉयोमैटेरियल की पट्टी दर पट्टी चढ़ाई जाती है। 'बॉयोफैब्रिकेशन' जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया कि इस 3डी प्रिंटर की बॉयो इंक अविकसित कोशिकाओं से बनी है। जब इस इंक को घाव पर चढ़ाया जाता है तो ये अविकसित कोशिकाएं अपने आस-पास के माहौल के हिसाब से विकास करके घाव को भरने में मदद करती हैं।

दरअसल बॉयो इंक जीवित कोशिकाओं से बनी होती हैं, जिसका उपयोग ऊतकों के माडल के 3डी प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। शोधकर्ताओं ने बताया कि इस बॉयो इंक की कोशिकाएं त्वचा को जल्द सही करने के साथ ही उनके दाग-धब्बे भी कम कर देती हैं।

टोरंटो यूनिवर्सिटी से इस अध्ययन के सह लेखक एक्सल गुएंथर ने कहा, 'पहले हमने सिर्फ यह परिकल्पना की थी कि हम जलने से हुए घाव पर जीवित कोशिकाओं को एकत्र कर उपचार कर सकते हैं, लेकिन अब हमने यह कर दिखाया।' वर्तमान में जले हुए घावों का उपचार स्किन ग्राफ्टिंग से किया जाता है, जिसके लिए घाव पर शरीर के अन्य हिस्सों से स्वस्थ त्वचा का प्रत्यारोपण किया जाता है।

शोधकर्ताओं का कहना है कि जलने के बड़े घावों पर प्रत्यारोपण के लिए पर्याप्त स्वस्थ त्वचा उपलब्ध नहीं होती है, जिसकी वजह से मरीज की मौत तक हो जाती है। अध्ययन के अनुसार यह 3डी प्रिंटर बेहद हल्का और हाथ में पकड़कर कहीं भी ले जाया जा सकता है। यह प्रिंटर जलने के मरीजों का जीवन बचाने में बड़ा कारगर साबित होगा। यह पूरी उपचार प्रणाली को नई दिशा की ओर ले जाएगा। इस प्रिंटर की खास बात यह है कि यह घाव भरने के साथ की जलने से पड़ने वालों दाग भी नहीं होने देता है।

धड़क रहा है प्लूटो का दिल

प्रतीकात्मक

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने एक नए अध्ययन में दावा किया है कि प्लूटो का दिल धड़क रहा है। दिल से मतलब इस ग्रह पर जमे हुए नाइट्रोजन से बनी एसी संरचना से है, जिसका आकार दिल जैसा है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि यह संरचना इस ग्रह में वायु परिसंचरण को नियंत्रित करती है। इसकी वजह से इस ग्रह की सतह पर विशेषताएं भी पनप सकती हैं।

इस दिल के आकार की संरचना को 'टॉम्बॉग रेजियो' के नाम से जाना जाता है। नासा के न्यू होरोइजंस मिशन ने 2015 में प्लूटो पर इस संरचना का पता लगाया था। वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन कर बताया था कि यह बंजर जगह नहीं है। 'जियोफिजिकल रिसर्च' नामक पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है कि यह नाइट्रोजन का दिल ही इस ग्रह में वायु का प्रवाह निर्धारित करता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक इस तरह के निष्कर्ष धरती और अरबों मील दूर स्थित इस बौने ग्रह के बीच समान और विशिष्ट विशेषताओं को इंगित करते हैं।

नाइट्रोजन गैस एक ऐसा तत्व है जो पृथ्वी पर हवा में पाया जाता है। यह प्लूटो के वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड और ग्रीनहाउस गैस मीथेन की थोड़ी मात्रा के साथ मौजूद है। शोधकर्ताओं ने बताया कि दिल के आकार में जमी यह नाइट्रोजन दिन के समय में गर्म होकर वाष्प की एक पतली सतह में बदल जाती है। रात में यह वाष्प संघनित होकर दोबारा बर्फ के रूप में जम जाती है। यह प्रक्रिया दिल की एक धड़कन की तरह है। इस प्रक्रिया में ग्रह के चारो और नाइट्रोजन फैलती और सिकुड़ती है। नए अध्ययनों से यह पता चलता है कि यह प्रक्रिया प्लूटो के वायुमंडल को ग्रह के विपरीत दिशा में घूमने के लिए प्रेरित करती है। इस अनोखी घटना को रेट्रो-रोटेशन (प्रतिगामी चाल) कहते हैं।

फोटो न्यूज

लायन फिश की संख्या कम होने से बढ़ी चिंता

यह तस्वीर बेहद खूबसूरत दिखने वाली लायन फिश की है, जो फ्लोरिडा के डेस्टिन में एक कृत्रिम रीफ में भोजन की तलाश कर रही है। कैरेबियाई और मेक्सिको की खाड़ी में लायन फिश की संख्या में तेजी से गिरावट आने से वैज्ञानिक चिंतित हैं। लायन फिश को स्वभाव से काफी आक्रामक माना जाता है। हाल में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि एक बीमारी के कारण वर्ष 2018 में उनकी संख्या में कमी आई है। हालांकि, दावा किया गया है कि अभी इस प्रजाति के विलुप्त होने का खतरा नहीं है। एपी

हानिकारक बैक्टीरिया पहचानेगी डिवाइस

शोध अनुसंधान

शोधकर्ताओं ने एक ऐसी पोर्टेबल डिवाइस विकसित की है, जो खाने के नमूनों में हानिकारक बैक्टीरिया की पहचान कर सकती है। इस तरीके से खाद्य जनित बीमारियों की रोकथाम में मदद मिल सकती है। एप्लाइड ऑप्टिक्स जर्नल में छपे अध्ययन के अनुसार, स्मार्टफोन और लैपटॉप के साथ काम करने वाली यह डिवाइस रासायनिक जांच के जरिये खाद्य नमूनों में हानिकारक ई. कोलाई बैक्टीरिया की जांच कर सकती है। अमेरिका की पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित डिवाइस खाने में ई. कोलाई की पहचान करने के लिए निम्न प्रकाश का उपयोग करती है। डिवाइस ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के जरिये डाटा स्मार्टफोन और लैपटॉप पर भेजती है। यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता इवान बाई ने कहा, 'हमारा लक्ष्य एक तकनीक और प्रक्रिया तैयार करना है, जिससे किफायती और आसान तरीके से खाद्य जनित बीमारियों के कारकों की पहचान की जा सके। हमारा यह उपकरण मौजूदा विधियों की तुलना में बेहद संवेदनशील और किफायती होने के साथ ही ज्यादा प्रभावी भी है।' -प्रेट्र

मोटापे का इलाज बच्चों की मानसिक सेहत के लिए भी फायदेमंद

कई अध्ययनों के एक विश्लेषण से यह पता चला है कि बच्चों और किशोरों में मोटापे का इलाज करना उनकी मानसिक सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। यह निष्कर्ष 64 अध्ययनों के विश्लेषण के आधार पर निकाला गया है। इसमें पाया गया कि वजन घटाने से बॉडी इमेज और खुद पर विश्वास को बेहतर किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी की प्रमुख शोधकर्ता मेगन गोव ने कहा, 'हमारे नतीजे प्रोत्साहित करने वाले हैं। इन नतीजों से जाहिर होता है कि बच्चों में मोटापे का उपचार ना सिर्फ वजन घटाने बल्कि मानसिक सेहत के लिहाज से भी अच्छा है।' -एएनआइ

स्क्रीन शॉट

आलिया में छुपी प्रतिभा पहचान नहीं पाए थे महेश भट्ट

करीब बीस साल बाद फिल्म 'सड़क 2' से निर्देशन में वापसी करने वाले निर्देशक महेश भट्ट ने अपनी फिल्मों में कई नए चेहरों को मौका दिया है। यह उनकी योग्यता है कि वह किसी में छुपी प्रतिभा को दूर से पहचान लेते हैं। पर बात की जाए उनकी अपनी बेटी आलिया भट्ट की, तो वह उनमें छुपी प्रतिभा को पहले पहचान नहीं पाए थे। आलिया भट्ट ने 'राजी', 'उड़ता पंजाब', 'हाइवे' जैसी फिल्मों में संजीदा किरदार निभाकर खुद को उन अभिनेत्रियों के बीच में ला खड़ा किया है, जहां उन्हें गंभीरता से लिया जाता है। जब महेश भट्ट से पूछा गया कि इस प्रतिभा को उन्होंने क्या पहले पहचान लिया था, तब उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसे किरदार निभाएंगी, जो उन्हें एक अलग अभिनेत्री के तौर पर स्थापित कर देगें। उन्होंने कहा कि आलिया ने उन्हें मजबूत बना दिया है। 'उड़ता पंजाब' फिल्म में आलिया ने झारखंड की एक आदिवासी लड़की का किरदार निभाया था। यह तो अभी उनकी शुरुआत है। आलिया के अंदर बहुत गहराई है।

'गुंजन सक्सेना : द कारगिल गर्ल' में 'प्रहार' के मेजर चौहान जैसा होगा अंगद बेदी का लुक

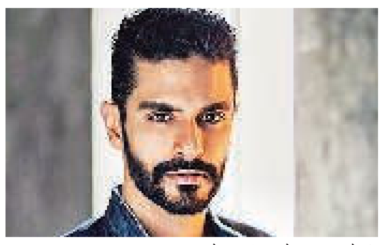

'फालतू', 'पिंक', 'सूरमा' और 'जोया फैक्टर' जैसी फिल्मों के अभिनेता अंगद बेदी आज अपना 37वां जन्मदिन मना रहे हैं। छह फरवरी, 1983 को दिल्ली में पैदा हुए अंगद अपना जन्मदिन पत्नी नेहा धूपिया और बेटी मेहर के साथ दिल्ली में ही मनाएंगे। धर्मा प्रोडक्शन के अंतर्गत बन रही फिल्म 'गुंजन सक्सेना : द कारगिल गर्ल' में अंगद, गुंजन के भाई और सैन्य अधिकारी अंशुमन सक्सेना का किरदार निभा रहे हैं। यह फिल्म कारगिल गर्ल के नाम से मशहूर महिला वायुसेना पायलट गुंजन सक्सेना की बॉयोपिक है। फिल्म में जाह्नवी कपूर, गुंजन सक्सेना का किरदार निभा रही हैं। जन्मदिन के मौके पर अंगद ने अपने किरदार के बारे में बताया कि इस फिल्म में उनका किरदार साल 1991 में रिलीज हुई फिल्म 'प्रहार' के मेजर चौहान जैसा होगा। इस फिल्म में नाना पाटेकर ने मेजर चौहान की भूमिका निभाई थी। स्क्रीन पर अंगद की उम्र 17 से 21 साल के बीच रहेगी। सैन्य अधिकारी की तरह दिखने के लिए उन्होंने मानसिक और शारीरिक रूप से काफी तैयारी की है। किरदार के लिए अंगद ने जिम में काफी पसीना बहाया। उन्होंने लखनवी बोलचाल और सेना के अनुशासनों को भी सीखा। भाई-बहन के रिश्ते में सही तालमेल के लिए अंगद और जाह्नवी ने एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताया। दोनों पर एक गाना भी फिल्माया गया है। फिल्म 13 मार्च को रिलीज होगी।

'शिकारा' के बाद बनेगी मुन्ना भाई सीरीज की अगली फिल्म

निर्माता के रूप में 'मुन्ना भाई एमबीबीएस', 'लगे रहो मुन्नाभाई', 'थ्री इडियट', 'पीके' जैसी मनोरंजक और संदेशप्रधान फिल्में देने वाले विधु विनोद चोपड़ा निर्देशित फिल्म 'शिकारा' शुक्रवार को रिलीज हो रही है। यह फिल्म करीब तीस साल पहले कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से जबरन बेदखल करने की सच्ची कहानी पर आधारित है। फिलहाल फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त चले रहे विधु विनोद चोपड़ा ने इस फिल्म के बाद मुन्ना भाई सीरीज की अगली फिल्म पर काम करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि 'शिकारा' की रिलीज के बाद वह मुन्ना भाई सीरीज की अगली फिल्म पर काम करेंगे।

वर्ष 2003 में आई 'मुन्नाभाई एमबीबीएस' में संजय दत्त और अरशद वारसी की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था। उस सीरीज की अगली फिल्म 'लगे रहो मुन्ना भाई' को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया था। दोनों ही फिल्मों का निर्देशन राजकुमार हिरानी ने किया था। उसके बाद इस सीरीज की फिल्म बनने की कई खबरें आईं, लेकिन संजय दत्त के जेल जाने के कारण मामला ठंडा पड़ गया। उनके जेल से बाहर आने के बाद संजय दत्त की बायोपिक 'संजू' को विधु विनोद चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया था। हालांकि इस बार मुन्ना भाई और सर्किट की जोड़ी में संजय दत्त और अरशद वारसी होंगे या नहीं, यह जानने के लिए करना होगा थोड़ा इंतजार।

परिवार संग जूनियर बच्चन ने मनाया अपना 44वां जन्मदिन

जूनियर बच्चन यानी अभिषेक बच्चन बुधवार को 44 साल के हो गए। इस मौके पर उन्होंने पूरे परिवार के साथ घर पर ही केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन ने सोशल मीडिया पर उनके जन्मदिन की तस्वीरें साझा की। एक तस्वीर में अभिषेक, पिता अमिताभ बच्चन, मां जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटी आराध्या बच्चन के साथ नजर आए। इसमें वह जन्मदिन का केक काटने की तैयारी में दिख रहे हैं। अभिषेक को कई हस्तियों ने शुभकामनाएं दीं।

बहन श्वेता बच्चन नंदा से मिली शुभकामना ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। श्वेता ने सोशल मीडिया पर अभिषेक के साथ बचपन की एक तस्वीर साझा की। तस्वीर में अभिषेक एक साइकिल चला रहे हैं और श्वेता उनसे साइकिल छीनने की कोशिश कर रही हैं। इस तस्वीर के साथ श्वेता ने दो पंक्ति की एक कविता भी लिखी। जिसका सार है कि आज और हमेशा, मैं सदैव आपके साथ रहूंगी। इसके अलावा, रितेश देशमुख, प्रीति जिंटा और नील नितिन मुकेश समेत कई लोगों ने अभिषेक को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। रितेश ने सोशल मीडिया पर अभिषेक के साथ फिल्म 'हाउसफुल 3' के सेट की एक तस्वीर साझा की, तो नील नितिन मुकेश ने 'प्लेयर्स' को याद करते हुए शुभकामनाएं दीं। अभिषेक मौजूदा समय में शाह रुख खान के प्रोडक्शन में बन रही फिल्म 'बॉब विश्वास' की शूटिंग में व्यस्त हैं। उनकी फिल्म 'लूडो' 24 अप्रैल को रिलीज होगी।

गुस्से में हाथ-पांव नहीं चलाती : तापसी पन्नू

अभिनेत्री तापसी पन्नू लगातार कथ्यपरक सिनेमा कर रही हैं। उनकी अगली फिल्म अनुभव सिन्हा निर्देशित 'थप्पड़' है। उसमें वह शादीशुदा महिला का किरदार निभा रही हैं। पति द्वारा सरेआम महफिल में थप्पड़ मारे जाने पर वह उसके आधार पर तलाक लेना चाहती हैं। पिछले कुछ अर्से से फिल्मों में लगातार गंभीर किरदार निभा रही तापसी असल जिंदगी में गुस्से को नियंत्रित करने के सवाल के जवाब में कहती हैं कि उनका गुस्सैल स्वभाव नहीं है। वह आमतौर पर किसी को गाली नहीं देतीं। अगर उन्हें गुस्सा आता है, तो अपनी बातों में उसे व्यक्त कर देती हैं। मगर गुस्से में अपने हाथ-पांव नहीं चलातीं। 'नाम शबाना' और 'बेबी' जैसी फिल्मों में अपने एक्शन के लिए तारीफें बटोरने वाली तापसी का कहना है कि फिल्मों में भी एक्शन करने से पहले वह यह सुनिश्चित करती हैं कि सामने वाली की पैडिंग सही से हुई हो, ताकि एक्शन करते हुए उन्हें चोट न लगे। 'थप्पड़' 28 फरवरी को रिलीज होगी।

'मलंग' में माइकल का ही किरदार निभाना चाहते थे कुणाल

'कलंक' में निगेटिव किरदार में नजर आए कुणाल खेमू अब मोहित सूरी निर्देशित 'मलंग' में नजर आएंगे। मोहित सूरी साथ कुणाल इससे पहले 'कलयुग' फिल्म कर चुके हैं। अब करीब 15 साल बाद दोनों साथ आए हैं। कुणाल का कहना है कि निर्देशक मोहित सूरी ने उन्हें यह फिल्म 'कलंक' से पहले सुनाई थी। जब उन्हें मोहित ने फिल्म सुनाई थी तब बाकी कलाकारों को साइन भी नहीं किया गया था। कुणाल के मुताबिक मोहित ने उन्हें स्क्रिप्ट पढ़ने को दी थी और पूछा था कि कौन-सा किरदार निभाना चाहते हैं। उन्होंने माइकल का किरदार निभाने की इच्छा जताई, जो स्पेशल सेल का पुलिस अधिकारी है। मोहित भी यही चाहते थे। फिल्म के ट्रेलर से लोग फिल्म की कहानी का अंदाज लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म में माइकल छोड़कर बाकी सारे किरदार ग्रे हैं। बताया जाता है कि फिल्म की कहानी यूं हैं कि क्रिसमस की रात माइकल को एक केस की पड़ताल सौंपी जाती है। दरअसल, कोई है जो पुलिस वालों को मार रहा होता है। तफ्तीश में समझ आता है कि यह मामला पांच साल पुरानी घटना से जुड़ा है। फिल्म के तीन अहम किरदार पहले मिले होते हैं। फिल्म में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न हैं। 'मलंग' सात फरवरी को रिलीज होगी।